राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का नौवां दिवस [संख्या: 04

गुरुवार,

11 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री फूल सिंह मीणा।

हिन्दुस्तान जिंक की इकाई मटून माइन्स को प्रारम्भ करने की योजना

20. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में हिन्दुस्तान जिंक की इकाई मटून माइन्स को प्रारम्भ करवाकर बेरोज़गारों को रोज़गार देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में निकट ग्राम मटून तहसील गिर्वा (वर्तमान में कुराबड़) में खनिज रॉक फास्फेट के स्वीकृत रहे खनन पट्टे की अवधि दिनांक 03.05.2020 को समाप्त हो जाने के कारण खनन कार्य बन्द है। इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा खान मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र वर्तमान में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पीछे बातें नहीं। इधर सुनिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मटून माइन्स की बहुत लम्बी-चौड़ी जमीन है और उसमें बहुत कीमती रॉक फास्फेट निकल रहा है। उसे बन्द करने के क्या कारण रहे? अभी तक उसे चालू क्यों नहीं किया गया? आज वह बेशकीमती जमीन उनके कब्जे में है। अगर उसे चालू नहीं कर सकते

(श्री फूल सिंह मीणा)

हैं तो उस जमीन को क्यों नहीं दूसरी छोटी-छोटी यूनिट्स को देकर स्थानीय लोगों को रोजगार देने का विचार किया जाये?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को रॉक फास्फेट की माइनिंग हेतु 20 साल के लिए लीज अवार्ड किया गया था, यानी 1990 तक। उनका दो बार लाइसेंस रिन्यू हुआ और 1990 से 2010 तक कर दिया गया। इन्होंने 2010 के लिए रिन्युअल की मांग की थी। एक स्पेशल कोर्ट का आर्डर आया था, जिससे इन्होंने एक नयी शर्त डाल दी थी कि खाली कैप्टिव माइनिंग वाली माइन्स को ही लाइसेंस दिया जायेगा, क्योंकि कैप्टिव माइनिंग का एक नया दौर शुरू हुआ है, चाहे वह कोल में ही हो। अपने लिग्नाइट की जो माइनिंग होती है, पिटहेड माइनिंग करके वहीं माइनिंग करते हैं और वहीं यूज करते हैं। यह जो रॉक फास्फेट है, यह बेसिकली फर्टिलाइजर्स के लिए होता है।

अगर पिटहैड माइनिंग में होता है और फर्टिलाइजर वही बनाते हैं तो उसका कोस्ट आफ ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है। वह सस्ता भी होता है और कंज्यूमर को भी सस्ती दरों पर मिलता है। यह जो पूरा इश्यू है, यह कैप्टिव माइनिंग का आर्डर आया है गवर्नमेंट आफ इंडिया से, 2015 माइन्स एंड मिनरल्स एक्ट से, उसकी वजह से यह पूरा मामला सबजुडिस हो गया है। अभी जो मामला है, वह कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश हैं कि एक रिविजनरी अथोरिटी गवर्नमेंट आफ इंडिया की अपीलेट अथोरिटी है, उनसे अपील की जाये और उनका जो निर्णय होगा, वह मान्य होगा। अभी तक यह मामला कोर्ट में सबजुडिस है, इसलिए सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोर्ट स्टे का तो कोई ब्यौरा नहीं दिया, पर अगर मंत्री महोदय कह रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से उनसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं सरकार एक अच्छा वकील करके इस स्टे को हटवाकर इन माइन्स को चालू करवाये और वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दे? बुहत बड़ी माइन्स हैं। इन्हें चालू करने से वहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं मांग करता हूं कि तुरन्त प्रभाव से इन माइन्स को चालू करवाकर युवाओं को रोजगार दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल हिन्दुस्तान जिंक का ही घाटा नहीं हो रहा है, हमारी जो रायल्टी है, उसका भी नुकसान हो रहा है। उसके अन्दर स्टेट भी सफर कर रहा है, हिन्दुस्तान जिंक कम्पनी भी सफर कर रही है, एम्प्लायमेंट भी प्रभावित हो रहा है। हमारा डिपार्टमेंट इसकी फास्ट फारवर्ड और अर्ली हियरिंग के लिए प्रयत्नशील है।

श्री अध्यक्ष: कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाइये और जल्दी करवाइये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लास्ट हियरिंग अक्टूबर, 2023 में थी। हम इसे फास्ट फारवर्ड करने के पूरे प्रयास करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि अभी रॉक फास्फेट का काम राजस्थान में कौनसा विभाग कर रहा है? इससे जो कब्जा लिया है, वह अभी किसके पास है?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हिन्दुस्तान जिंक ही मालिक है, वही कोर्ट में गयी है। अब उसने किसके साथ क्या एग्रीमेंट्स किये हैं, यह part of the question नहीं है। उसने किसके साथ इन्वेस्टमेंट्स किये हैं, किसके साथ उसकी साझेदारी है...

श्री अध्यक्ष: यह तो मैटर कोर्ट में है, इसलिए इस पर कोई ज्यादा चर्चा का औचित्य नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): It is not in the purview of the question.

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये माइन्स चलनी चाहिये। मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि जब सरकार के पास इसका कब्जा है और रॉक फास्फेट का पूरा काम राजस्थान में आर एस एम एम कर रही है तो इसका भी काम सरकार चलाये और सरकार ही लोगों को रोजगार दे। किसी प्राइवेट को देने का क्या मतलब है?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मामला कोर्ट में है, इसमें सरकार क्या कर सकती है?

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा में सड़क सुविधा से वंचित गांव

21. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पांच सौ से अधिक आबादी वाले सभी गांव सड़क से जोड़े जा चुके हैं? यदि नहीं, तो वर्तमान में कौन-कौन से गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने के पश्चात् भी उक्त गांवों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़े जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (डॉ. मंजू बाघमार): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक आबादी के चार गांव क्रमश: भटगांव (773), सिजन्या (661), जयनगर (524), नवाबपुरा (504) सड़क सुविधा से वंचित हैं। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त गांवों को जोड़ने वाले मार्ग वन क्षेत्र में होने के कारण इन गांवों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मंत्री जी, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगी कि जब फोरेस्ट एरिया में ये चारों गांवों की सड़कें आ रही हैं तो फिर इनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां किस आधार पर जारी की गईं? मेरी जानकारी के अनुसार अगर इनका फोरेस्ट क्लियरेंस तीन साल तक नहीं होता है तो ये सड़कें डैफर कर दी जाएंगी। पिछली सरकार के समय भी हमारे क्षेत्र के साथ इस प्रकार का धोखा किया गया। मंत्री थे भजनलाल जी जाटव। उन्होंने भी यही कहा था कि आपकी ये सड़कें स्वीकृत कर दी गयी हैं और शीघ्र चालू हो जाएंगी। आज तक वे चालू नहीं हुई हैं। अब आप यह बताएं कि फोरेस्ट क्लियरेंस कब तक हो जायेगा और किस दिनांक तक ये सड़कें चालू हो जाएंगी?

दूसरा, एक तो मेरे क्षेत्र की बींदाराड़ा से पीपलिया सड़क है, एक खजूरी रोड से खलगपुरा सड़क, तीसरी है गणेशपुरा से कोहनी सड़क और चौथी है हमारी नोन-पेचेबल सड़क है। इनके बारे में भी आप कुछ आश्वासन देने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया, ये जो चार गांव थे, इनके जो क्वेश्चंस थे उनके अनुसार, चूंकि ये वन क्षेत्र में थे, इनकी सड़कें नहीं बन पाईं। अभी हमने इनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है, लेकिन वन भूमि में होने के कारण वन विभाग द्वारा प्रत्यावहन की कार्यवाही की जा रही है और जैसे ही वन विभाग द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि प्रत्यावहन की स्वीकृति मिलने की कोई समय-सीमा तय नहीं है, यह परिस्थितिजन्य है और वन भूमि से जैसे ही स्वीकृति मिल जायेगी, उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): स्वीकृति कब तक मिल जायेगी? एक तो यह बताने की कृपा करें। जहां तक जयनगर का सवाल है, वह सड़क फोरेस्ट एरिया में नहीं आती है। जो पुराना गांव है, वह फोरेस्ट एरिया में नहीं है। कुछ वहां पर ट्राइबल लोगों ने, जयनगर जो मुख्य गांव है, उससे कोई 400-500 मीटर दूर फोरेस्ट लैंड है, उसमें कुछ मकान उन्होंने बना लिये हैं। मेरा आपसे सीधा-सीधा सवाल है कि जयनगर की 500 की आबादी होते हुए भी और फोरेस्ट क्षेत्र में नहीं आने के बावजूद भी अब तक इसे सड़क से नहीं जोड़ने का क्या कारण रहा?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): सर, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जैसे ही इनके प्रस्ताव हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर उन्हें सड़कों से जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): राजस्थान के सभी 500 से अधिक आबादी वाले गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। मेरे क्षेत्र के चार गांव अब तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। यह चर्चा का विषय नहीं है। आपके दो पूरक प्रश्न हो गये, अब आप विराजें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

करणपुर में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

22. **श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर** (करणपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर)

(1) विधान सभा क्षेत्र करणपुर में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक विधायक कोष से स्वीकृत कितने कार्यों का निर्माण पूर्ण हो चुका है व कितने अपूर्ण हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या विधायक कोष से स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने की समय सीमा निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री ओटाराम जी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: विराजें। आप बैठिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, मंत्री जी कोई उत्तर नहीं देंगे। बैठिये अब। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजें। दो पूरक प्रश्न हो गये। आप डिस्टर्ब न करें। आप विराजिये। (व्यवधान) आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। मंत्री जी, अपना उत्तर बोलिये।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): (1) श्रीकरणपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक विधायक कोष से स्वीकृत 347 कार्यों में से 288 कार्य पूर्ण, 58 कार्य अपूर्ण तथा 01 कार्य अप्रारम्भ है।

(2) जी हां। ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के बिन्दु संख्या 22.10 के अनुसार कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निर्धारित समय-सीमा का प्रावधान निम्नानुसार है:-

22.10.1 भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिए

क्र.सं.	**स्वीकृत राशि**	**कार्य सम्पादित करने की अधिकतम अवधि**
1.	रु. 2 लाख तक	4 माह
2.	रु. 2 लाख से रु. 5 लाख तक	6 माह
3.	रु. 5 लाख से अधिक	9 माह

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास)

22.10.2 खरंजा निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिए

क्र.सं.	**स्वीकृत राशि**	**कार्य सम्पादित करने की अधिकतम अवधि**
1.	रु. 2 लाख तक	3 माह
2.	रु. 2 लाख से रु. 5 लाख तक	4 माह
3.	रु. 5 लाख से अधिक	6 माह

22.10.3 तालाब/एनिकट निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिए

क्र.सं.	**स्वीकृत राशि**	**कार्य सम्पादित करने की अधिकतम अवधि**
1.	रु. 2 लाख तक	4 माह
2.	रु. 2 लाख से रु. 5 लाख तक	6 माह
3.	रु. 5 लाख से अधिक	9 माह

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मेरे पास आ गया है, मैंने पढ़ लिया है। मैं आपकी आज्ञा से दो पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न करिये।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, कि 58 कार्य अधूरे हैं, एक काम चालू नहीं हुआ है, जिसकी ए एस और एफ एस वर्ष 2022 में जारी हो चुकी है। ये काम निर्धारित समय-सीमा में अभी तक नहीं हो पाये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, सरकार से जानना चाहता हूं कि उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, जिन्होंने निर्धारित समय में काम नहीं किया, उन पर क्या सरकार कोई कार्रवाई करने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस तरह से बताया है कि करणपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक 347 कार्यों में से 288 कार्य पूर्ण हो गये हैं,

(श्री ओटा राम देवासी)

58 कार्य अभी अपूर्ण हैं और एक कार्य आरम्भ होना है। इसमें आचार संहिता के कारण विलम्ब हुआ है।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ए एस व एफ एस...

श्री अध्यक्ष: एक बार पूरा उत्तर आने दें। आप उसके बाद पूछना।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): एक कार्य जल्दी ही आरम्भ करके उसका सम्पादन कर देंगे। दूसरा, निवेदन था कि जिस कार्य को पूर्ण कराये जाने की अवधि निर्धारित है, वह 2 लाख के लिए 4 माह है और 2 लाख से 5 लाख के लिए...

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): यह जवाब तो आ गया है, मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह उत्तर तो आ गया है। ये जो पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दीजिये। ये मेरा काम है।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): हां, थैंक यू। जिस तरह से इन्होंने बताया है, मैं समझता हूं कि ये 58 कार्य हैं, हम उन कार्यों को जल्दी ही पूर्ण करेंगे और एक कार्य जो अब हुआ है, उसे जल्दी ही समाप्त करेंगे।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय मंत्री जी, जो कार्य 2022 से पेंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बैठिये। दूसरा पूरक प्रश्न है।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): जी।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो कार्य 2022 से पेंडिंग हैं, उसका जवाब ही नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: आप दूसरा प्रश्न पूछो।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या लापरवाह अधिकारी, कर्मचारियों पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मैं यह कह रहा हूं कि जो कार्य मेरे पास आये हैं, उनमें 347 काम थे।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): मंत्री जी, वह तो पढ़ लिये हैं। जो काम अधूरे हैं, वे लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों की वजह से निर्धारित समय-सीमा में नहीं हो पाये, एक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप इनके कामों की समीक्षा कर इनके काम सही हो तो करवा देना।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): जी, थैंक यू, सर।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): दूसरा, मेरा प्रश्न है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय जी, इतना सिम्पल सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: यह पी डब्ल्यू डी का सिम्पल-सा प्रश्न है। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। श्री लक्ष्मण।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सर, वे सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। मैं पूछता हूं, उनकी जगह।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने दो प्रश्न पूछ लिये हैं। उन्होंने कह दिया जांच करवाकर कर देंगे। उसमें कुछ बचा ही नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर प्रश्न है। सारे माननीय विधायक जो हैं, वे अभिशंसा भेजते हैं, उसकी तय सीमा है, तय सीमा में जो अधिकारी काम पूरे नहीं कर रहे हैं, उन पर सरकार एक्शन लेगी या नहीं लेगी? इतना ही तो पूछा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया है, एक्शन लेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप फरमा दें। आप इनको आदेश दें।

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है। उसके बाद क्या बचता है?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल जो पूछा था, यह वर्ष 2022-23 का है और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इनके अधिकारियों ने नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। माननीय मंत्री महोदय, बैठिये। You are not supposed to disturb. आप तो समझदार हैं। श्री लक्ष्मण। बैठिये, बीच में बोलेंगे तो जब आपका प्रश्न आयेगा तो मैं नहीं पुकारूंगा। मैंने उनको बैठा दिया है। यह मेरा काम है।

श्री लक्ष्मण।

बस्सी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण

23. श्री लक्ष्मण (बस्सी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडवा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपाहेडी व कांशीपुरा के भवनों के निर्माण की स्वीकृति होने के पश्चात् भी अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगढ़, भटेरी, बूड़थल तथा दुधली के भवनों के निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडवा के भवन निर्माण हेतु राज्य निधि बजट मद वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 536.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके विरुद्ध निविदा टेंडर कर कार्यादेश दिनांक 06-10-2023 को जारी किया जा चुका है। दिनांक 04.07.2024 को संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने हेतु अन्तिम नोटिस जारी किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपाहेडी के निर्माण हेतु राज्य निधि बजट मद वर्ष 2023-24 में राशि रु. 143.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त स्वीकृति के विरुद्ध नियमानुसार निविदा कर दिनांक 06.10.2023 को कार्यादेश जारी किया गया। दिनांक 04.07.2024 को संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने हेतु अन्तिम नोटिस जारी किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांशीपुरा के भवन के निर्माण हेतु राज्य मद वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत राशि रुपये 143.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 06-10-2023 को प्राप्त है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार निविदा कर कार्यादेश दिनांक 06-10-2023 को जारी की गई व भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगढ़ के भवन निर्माण हेतु 15वें वित्त आयोग वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत राशि रुपये 159.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 14-03-2024 को प्राप्त है। प्राथमिक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वास्थ्य केन्द्र, भटेरी, बूड़थल तथा दुधली का भवन निर्माण पर विचार भूमि, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार किया जा सकेगा।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया है। मैं एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: जी, पूछिये।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़वा सी एच सी की बिल्डिंग बनाने का मामला था, जिसका 06 अक्टूबर, 2023 को कार्यादेश दिया और 9 महीने गुजरने के बाद आज तक वहां कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इसको अन्तिम नोटिस दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि 9 महीने में तो बिल्डिंग बन जानी चाहिए थी, 9 महीने में क्या काम हुआ? क्यों नहीं हुआ? कौन-सी एजेंसी कार्य एग्जीक्यूट कर रही थी? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई और संवेदक के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? इसका जवाब दें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बस्सी, सी एच सी, बडवा, इसकी 5 करोड़ 36 लाख की सैंक्शन वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गई थी। यह स्टेट हैड से फंड दिया गया है। इसका वर्क आर्डर 06.10.2023 को जारी हो गया था और काम शुरू नहीं हुआ था। दिनांक 04.07.2024 को, एक कम्पनी है, शर्मा कंस्ट्रक्शन को फाइनल नोटिस दे चुके हैं। अब हमें रिएक्शन टाइम तो चाहिये कि उस पर आगे क्या कार्यवाही करें। अब लास्ट फाइनल नोटिस दे दिया है, उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या संवेदक को फाइनल नोटिस देने में 9 महीने लगते हैं? कितनी बार नोटिस दिये जाते हैं? कितने-कितने अन्तराल में नोटिस दिये जाते हैं? आप यह बतायें।

श्री अध्यक्ष: यह तो दोनों तरफ है। जो बताना है, आप बताइये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 9 महीने पहले तो हमारी सरकार ही नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी। अभी दो महीने आचार संहिता भी थी। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 6 महीने से तो आपकी सरकार थी।

श्री अध्यक्ष: यह क्या है। I will name you. यह प्रश्न काल है। हर प्रश्न पर खड़े हो जाते हो। केवल विपक्ष के नेता को अधिकार है, किसी और को नहीं है, माइंड इट। आपके दो प्रश्न हो गये हैं।

प्रश्न संख्या 24

श्री अर्जुन लाल जीनगर। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री प्रताप लाल भील।

पशुपालकों को देय आर्थिक सहायता

25. श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा पशुपालकों के पालतू मवेशियों द्वारा जहरीली घास अथवा चारा खाने से मृत्यु होने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जाती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त को सहायता राशि देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): जी नहीं। पशुपालकों को उनके पशुओं की जहरीली घास अथवा पदार्थ खा जाने से आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: अब पूरक प्रश्न।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार पशुपालकों को जहरीली घास एवं अन्य पदार्थ खा जाने से, मृत्यु होने पर बीमा सहायता देने का विचार रखती है क्या?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय जी ने पशु बीमा करवाये जाने की कल बजट घोषणा की है जिसमें प्रथमत: दुधारू पशुओं जैसे- पांच-पांच लाख गाय, भैंस के अतिरिक्त पांच-पांच लाख भेड़, बकरी एवं एक लाख ऊंटों सहित कुल 21 लाख पशुओं का बीमा किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इस योजना में बीमित पशुओं की मृत्यु होने पर क्लेम की राशि

(श्री जोराराम कुमावत)
का भुगतान पशुपालकों को देय होगा। इससे प्रदेश में लम्पी एवं अन्य समस्त संक्रामक रोग, प्रकोप, प्राकृतिक आपदा, सांप एवं अन्य जहरीली जीव, जन्तु-काटने, जहरीली घास-पदार्थ खाने, सड़क दुर्घटना एवं तालाब में डूबने से पशु की मृत्यु पर पशुपालकों को बीमा क्लेम स्वरूप मुआवजा दिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): धन्यवाद, सर।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सर, मेरा एक सुझाव है। इसी में है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा। आप पुराने हैं, प्रश्न काल में अनुमति नहीं है।

महिला उत्पीड़न के दर्ज प्रकरण

26. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माह जनवरी, 2024 से माह जून, 2024 तक महिला उत्पीड़न के कितने प्रकरण दर्ज हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा महिला अपराध की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक महिला उत्पीड़न के 20,767 प्रकरण दर्ज हुए हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्टअ पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा महिला अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष महिला अपराध अनुसंधान इकाई का गठन समस्त जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वर्ष 2019 से किया गया है। महिला सुरक्षा हेतु एक टोल फ्री नम्बर 1090 महिला गरिमा हैल्पलाइन के नाम से राज्य के समस्त जिलों में संचालित किया जा रहा है। निरन्तर गश्त निगरानी एवं जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं। शहरों के मुख्य स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा निगरानी जारी है। महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा हेतु दिनांक 26.03.2021 से स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करने के आशय से

(श्री गजेन्द्र सिंह)

राजस्थान पुलिस द्वारा 'सुरक्षा सखी' नाम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो समस्त जिलों में संचालित है। राज्य के 1,024 पुलिस थानों में से 1,020 पुलिस थानों में महिला हैल्प डेस्क संचालित है। महिला हैल्प डेस्क पर महिला अधिकारी की नियुक्ति कर महिला अपराध से सम्बन्धित शिकायतों की संवेदनशीलता से सुनवाई कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से समय-समय पर परिपत्र/दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(विवरण एवं प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से माननीय मंत्री महोदय ने अपना जवाब पढ़ा और यह लिस्ट मेरे पास आयी है, मैंने पूछा कि राजस्थान में जनवरी से अब तक कितने प्रकरण महिला अत्याचारों के दर्ज हुए तो उसमें सबसे टॉप अलवर में 881 आया है। सैकंड नम्बर पर आया है भरतपुर, जहां से माननीय मुख्य मंत्री महोदय हैं। जितनी भी योजनाएं माननीय मंत्री महोदय ने बतायी, वो सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार के द्वारा चलायी गयीं। पिछली बार भाजपा के आप सब लोगों ने विरोध में इस तरह से पेपर छपवाये और विरोध किया, जितना हो सकता है उतना विरोध किया, जबकि जितनी योजनाएं मंत्री महोदय ने बताईं, वो सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस ने चलायी हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मैं प्रश्न पर ही आ रही हूं। यह इस तरह से पोस्टर आप सबने छपवाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछिये। इसको रख दीजिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): इस तरीके के राजस्थान में ...(व्यवधान) सुन लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष: यह सदन की गरिमा नहीं है। प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष जी, जब तक भूमिका नहीं बनेगी तो सवाल क्या पूछूंगी?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न में भूमिका नहीं होती। वह भाषण में करना।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आज हमारी बालिकाएं भी, बच्चे भी आये हैं, सबको पता होना चाहिये...

श्री अध्यक्ष: आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): कि जनवरी से जब से सरकार बनी है तब से 20 हजार से ऊपर प्रकरण महिला अत्याचारों के प्रकरण दर्ज हो गये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है, वह पूछें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मेरा प्रश्न यह है कि जितने प्रकरण दर्ज हैं, इसमें भाजपा के आप सभी लोगों ने यह कहा कि अब नहीं सहेगा राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये। मैं बैठा दूंगा। अगला प्रश्न पुकार लूंगा। प्रश्न पूछें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अब क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है? माननीय मंत्री महोदय, बतायें कि क्या राजस्थान सहने के लिए मजबूर है?

श्री अध्यक्ष: इधर सम्बोधित करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): और मैं पूछना चाहती हूं कि डिम्पल मीणा का प्रकरण जो कि पुलिस तीन बार प्रेस नोट जारी कर चुकी है, उसको तोड़-मरोड़ कर किस लेवल पर ले जाया जा चुका है कि उसके परिजन और सामाजिक संगठन धरना दिये हुए बैठे हैं। माननीय मंत्री महोदय, बतायें कि वो सिर्फ सी बी आई की जांच मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या आप उस प्रकरण की सी बी आई की जांच करायेंगे, ताकि सच्चाई का पता लग पाये कि परिजनों ने किया है, किसी और ने किया?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। हो गया। प्रश्न पूछ लिया, अब बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सब बातों के जवाब में एक ही चीज बोलूंगा। माननीय विधायक ने बोला कि एकदम इतना क्राइम महिला उत्पीड़न का बढ़ गया है। मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहूंगा कि 2022 में 22,074 मामले रजिस्टर हुए थे, 2023 में 21,087 और ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यही पूछा है। उत्तर सुनिये। मंत्री जी का उत्तर सुनना पड़ेगा। माननीय हरिमोहन जी। माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जवाब सुनिये। अभी बी जे पी, कांग्रेस का पता लग जायेगा आपको। अभी कह रहे थे बी जे पी, कांग्रेस का। अब सुनिये जवाब।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न का उत्तर दीजिये। आप बैठिये। उत्तर सुनिये पहले।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक फिगर्स नहीं देंगे न, आपने पूछा है, आपका प्रश्न है, यू हैव क्वेश्चन कि पिछले 6 महीने में और मैं जो बता रहा हूं 2022 के और 2023 का बता रहा हूं। हरिमोहन जी पता नहीं क्यों कूद रहे हैं बीच में।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दीजिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लेट मी आन्सर। मुझे जवाब देने दो। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ...(व्यवधान) याद करो वह मर्दों का प्रदेश, शर्मसार हुआ था राजस्थान यहां पर।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री को बोलने दीजिये। आपके मंत्री सक्षम हैं। बोलिये। पहले वो उत्तर दे दें। हरिमोहन जी को भी बिठाओ आप। केवल इधर का नहीं है, इधर भी बैठो तो मैं नहीं उठने दूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 से 2023 जनसंख्या तो बढ़ी है और 2023 से 2024 जनसंख्या और बढ़ी है, लेकिन ये जो केसेज हैं 2022 से 2024 तक 6 प्रतिशत कम हुए हैं, 6 प्रतिशत कम हुए हैं हमारे केसेज महिला उत्पीड़न के और हमारी सरकार आते ही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे मत बोलिये। आपके विपक्ष के नेता बैठे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायक महोदया जब पूछ रही थीं हमारे से प्रश्न, तो बीच में से बोल रहे थे शेम, तो 6 प्रतिशत कम हुआ है आप से, आपके ऊपर शेम।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: नो, प्रश्न काल में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): स्पीकर साहब, जो माननीय मंत्री महोदय का कृत्य है अंगुली दिखाना, इसकी इजाजत सदन में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप लोग शेम बोल सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। माननीय सदस्य, मैं अगला प्रश्न पुकार लूंगा। बैठिये आप। आप अनुभवी सदस्य हैं। अगला प्रश्न। हो गया आपका? श्री ललित मीना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष: ये हल्ला मचायेंगे तो अगला प्रश्न पुकारूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, कोई हल्ला नहीं मचायेगा।

श्री अध्यक्ष: खड़े रहोगे तो मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, सिम्पल-सी बात है महिला अत्याचार का जो मामला है वह बहुत गम्भीर है। आप तो चाहते हो कि अगला प्रश्न आ जाये और इसका पीछा छूट जाये। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है खण्ड 'ब' में, आपने जो परिशिष्ट लगाये हैं न, पहला है 10.08.2023, दूसरा है 09.05.2022, तीसरा है 12.05.2014, चौथा है 20.08.2009, उससे आगे है 20.12.2012, उसके बाद में है 26.03.2021, उसके बाद में है 22 जून, 2006 और उसके बाद ये सारे परिशिष्ट आपने साथ लगा कर दिये हैं। जो आपने, नयी सरकार ने डाइरेक्शन दिये हैं, इनमें एक भी डाइरेक्शन मौजूदा सरकार के हों तो आप बता दो एक भी डाइरेक्शन। दूसरा मेरा सवाल है, आपने कहा है कि 20,767 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इसमें दलित महिलाओं के कितने हैं, नाबालिग के कितने हैं और कितनों में चालान पेन्डिंग है? तीसरा, इसमें दलित महिलाओं को सरकार कोई पैकेज देती है तो कितना पैकेज अभी पेन्डिंग है, कितनी महिलाओं को? यह मैं पूछ रहा हूं। एक प्रश्न और पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न में नहीं पूछा है। प्रश्न का पार्ट नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं आया इसमें और आप जो आंकड़े दे रहे हैं न, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आपने अप्रैल, 2024 में जो बताया है न 2,861 मामले दर्ज हुए हैं और मई के अन्दर 4,088 दर्ज

(श्री टीकाराम जूली)

हुए हैं जो कि एक महीने में ही 43 प्रतिशत के आस-पास वृद्धि है। आप 6 प्रतिशत कम बता रहे हो, यह कहां से बता रहे हो? ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, कुछ कहेंगे?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हकीकत जो है, सदन को गुमराह नहीं करें। सही चीज बतायें।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिक इश्यू यह है कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने क्या किया। मैं बता रहा हूं कि हमारे 7,400 ऐसे स्थान हमने चिह्नित किये हैं, जहां पर लेडीज का मूवमेन्ट ज्यादा होता है। शॉपिंग माल्स हैं, आपके पार्क्स हैं, आपके सिनेमा हाउसेज हैं, ये जितनी भी जगह हैं, शॉपिंग एरियाज के अन्दर, हमने 20,615 नये सी.सी.टी.वी. कैमराज डी.ओ.आई.टी. से आर्डर कर दिये हैं। पहले केवल 11,511 ही कैमरा थे। हम बीस हजार अतिरिक्त लगा रहे हैं और दो सौ महिला स्क्वॉड को मोटर साइकिल, वायरलैस, कैमराज उनकी जैकेट पर लगाकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका हो गया। आप बैठिये। नो। अगला प्रश्न। श्री ललित मीना।

किशनगंज के फूल डोल लोकोत्सव हेतु सहायता

27. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बून्दी की तीज व कोटा के दशहरा को पर्यटन विभाग के कैलेण्डर में शामिल किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बारां जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित होने वाले फूल डोल लोकोत्सव को पर्यटन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लोकोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहयोग देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित मीना)

(3) क्या सरकार सीताबाड़ी में आयोजित होने वाले सहरिया लघुकुम्भ मेले को पर्यटन विभाग के कैलेण्डर में सम्मिलित कर प्रतिवर्ष बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, जवाब दें। (व्यवधान) आप भाषण करती हैं, प्रश्न नहीं पूछती हैं। माननीय मंत्री महोदय, बोलिए।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) (पर्यटन मंत्री के स्थान पर): (1) पर्यटन विभाग के वार्षिक मेले-उत्सव कैलेण्डर में बून्दी की कजली तीज व कोटा का दशहरा मेला सम्मिलित है।

बारां जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित होने वाले फूल डोल लोकोत्सव को पर्यटन से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है।

विभाग में मेलों को पर्यटन से जोड़ने से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर स्थानीय जिला प्रशासन की रिपोर्ट तथा श्रद्धालुओं/मेलार्थियों/पर्यटकों की संख्या इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(2) उक्त लोकोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है।

विभाग में प्राप्त प्रस्तावों को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया जाता है।

(3) बारां जिले में स्थित सीताबाड़ी में आयोजित होने वाले सहरिया लघुकुम्भ मेले को पर्यटन विभाग के वार्षिक कैलेण्डर में सम्मिलित करने तथा बजट आबंटन संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है।

विभाग में मेलों को पर्यटन कैलेण्डर में सम्मिलित करने व इनके लिए बजट आबंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर स्थानीय/जिला प्रशासन की रिपोर्ट, श्रद्धालुओं/मेलार्थियों/पर्यटकों की संख्या व उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं, मेलों के आयोजन स्थल की लोकप्रियता, सांस्कृतिक महत्व, पर्यटकों की आवाजाही, पर्यटन विकास की संभावनाओं इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) वेल से पीछे।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज का फूल डोल लोकोत्सव पिछले 126 वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से केवल यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसको पर्यटन में शामिल करने का विचार रखते हैं? ऐसा विचार नहीं है तो कहीं न कहीं इसको सरकार से बजट दिलवाने का प्रावधान कराएं। चूंकि किशनगंज में फूल डोल की यह 126 साल पुरानी परम्परा है तो बूंदी की तीज व दशहरा के मेले की तर्ज पर इसको भी बजट देने का प्रावधान करने के लिये मंत्री जी आश्वस्त करें।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इस पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, फिर भी जिला पर्यटक विकास समिति के माध्यम से प्रस्ताव मंगवाकर एवं पर्यटन की दृष्टि से परीक्षण करवाकर उसमें युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा और फिर उस पर निर्णय लेकर कार्यवाही की जायेगी।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: सब अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मंत्री महोदय, केलवाड़ा में सीताबाड़ी में जहां आदिवासी कुंभ भरता है, फूल डोल एवं सीताबाड़ी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, इन दोनों को आप बजट दिलवाने का श्रम करें, ताकि मेले का आयोजन किया जा सके। विभाग से इसके प्रस्ताव मंगवाकर इसको बजट आबंटन करने का आप आश्वासन दें।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): पर्यटक विभाग द्वारा वर्ष पर्यन्त राज्य की लोक संस्कृति व कला के प्रोत्साहन हेतु मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है और हमारी सरकार भी इसके लिये प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा प्रस्ताव मंगवाकर इस पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह रावत।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपके दो हो गये। श्री शंकरसिंह रावत।

ब्यावर में मेडिकल कालेज खोलने की कार्ययोजना

28. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ब्यावर में मेडिकल कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नवीन जिला ब्यावर में मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है, तथापि भविष्य में नीतिगत निर्णय होने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर मेडिकल कालेज खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ब्यावर में मेडिकल कालेज खोलना अति आवश्यक है। ब्यावर जिला बना है और ब्यावर में चार तरफ का स्टेट हाईवे रोड का चौराहा है तथा उस जगह पर चार जिलों के मरीज आज भी किसी न किसी अस्पताल में मिलेंगे, इससे वहां पर स्टाफ की कमी रहती है। मेरा आपसे आग्रह है कि ब्यावर में मेडिकल कालेज खोलने के लिये माननीय मंत्री महोदय से आदेश करवाने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बेसिक नियम है कि एक जिले में एक मेडिकल कालेज होना चाहिये। हमारे 33 जिले हैं, सर्वप्रथम हमारे 6 डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर मेडिकल कालेज खुले। उसके बाद फेज 2 में 7 मेडिकल कालेज खुले। यह 7 और 6, कुल 13 फंक्शनल हैं। 20 स्वीकृत हुए 15 और बने और 5 की डी पी आर तैयार हो रही है। ये पांच हैं, बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनूं और सवाईमाधोपुर में इस वर्ष कम्प्लीट हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो 17 नये जिले बने हैं, उनमें हम आगे बढ़ रहे हैं और इनको भी ले रहे हैं। ब्यावर, अजमेर से 55 किलोमीटर, भीलवाड़ा से 110 और पाली से 125 किलोमीटर है। जब सब जिलों में बनेंगे तो ब्यावर में भी बनेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री भागचन्द टांकड़ा।

पंचायती राज संस्थाओं को रूपान्तरित भूमि के पट्टे जारी करने के अधिकार

29. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं को शहरी निकाय की भांति धारा 90 (ए) के तहत रूपान्तरित भूमि (खातेदारी, आबादी या अन्य) के पट्टे जारी करने का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90(ए) कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग से संबंधित है। जबकि राज्य में ग्राम पंचायतों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत स्वयं के स्वामित्व की आबादी भूमि के ही पट्टे जारी किये जाने का अधिकार प्राप्त है। यदि धारा-90(ए) के तहत कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरित किया जाता है तथा उक्त रूपान्तरित आबादी भूमि राजस्व रिकार्ड में संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवा दी जाती है, तो ऐसी भूमि का पट्टा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान प्रावधानों के तहत दिया जा सकता है। इसलिए शहरी निकायों की भांति ऐसा प्रावधान किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी सीटों पर जाइए। प्रश्न काल के बाद मैं आपको अनुमति दूंगा। (व्यवधान) यहां भाषण नहीं होगा।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताएं कि जब शहरी निकाय एवं ग्राम पंचायत के एक समान कानून हैं और एक समान संविधान है, तो फिर यह भिन्नता क्यों? आप यह भी बताएं कि ग्राम पंचायत में वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार स्वयं की खातेदारी में रह रहे हैं, किस्म परिवर्तन कराकर पक्के निर्माण बना रखे हैं, ग्राम पंचायत की आबादी में रह रहे हैं, उनको पट्टा जारी करने हेतु सरकार के नियमों में संशोधन कराने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि दुबारा बोलें।

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय मंत्री महोदय, जब शहरी निकाय और ग्राम पंचायत का एक समान कानून है, एक संविधान है, तो फिर भिन्नता क्यों? यह भी बताएं कि ग्राम पंचायतों में वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार उनकी स्वयं की खातेदारी में किस्म परिवर्तन कराकर पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं, ग्राम पंचायत की आबादी में सैकड़ों वर्षों से लोग रह रहे हैं,

(श्री भागचन्द टांकड़ा)

उनको पट्टे जारी करने हेतु सरकार नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है क्या?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज में यह प्रावधान है कि कोई किसी के खेत में वह मकान बनाता है तो 500 वर्ग गज तक का बना लेता है। उसको पट्टा लेने के लिये ग्राम पंचायत में सरेंडर करना पड़ता है, फिर ग्राम पंचायत उसका पट्टा बना देती है। पट्टे दिये जा रहे हैं, पट्टे देने में कोई व्यवधान नहीं है, न कोई रोक है।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय मंत्री महोदय, सरकार जिन गांवों की आबादी कटी हुई है, वहां नगरपालिका की तर्ज पर नियमों में संशोधन करके आबादी में पट्टे देने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, कुछ कहना है?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आबादी से सटी हुई है। पंचायती राज का काम इतना ही है कि आबादी में जो जमीन होती है, उसी के पट्टे देती है। परंतु जिन खेतों में मकान बनाये हुए हैं, नियम है कि मकान बना सकते हैं, लेकिन पट्टा लेने के लिये उस जमीन को सरकार को समर्पित करना पड़ेगा, फिर सरकार उसको आबादी में कन्वर्ट करेगी और फिर हम पट्टा दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. शैलेश सिंह।

डीग-कुम्हेर की गोशाला में चारे-पानी की व्यवस्था

30. डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के पशु प्रजनन केन्द्र, कुम्हेर में बनी हुई गोशाला में गोवंश हेतु चारेपानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): जी नहीं। वर्तमान में राजकीय पशु प्रजनन केन्द्र, कुम्हेर में गोशाला संचालित नहीं है, इसलिए राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 संशोधित 2021 के अंतर्गत सहायता राशि देय नहीं है।

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(डॉ. शैलेश सिंह)

माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि रियासत काल से कुम्हेर में गोशाला संचालित थी। सन् 1961 में राज्य सरकार के अधीन आयी और पशुपालन विभाग के नियन्त्रण में दे दी गयी। उसके बाद से 2021 में जो अधिनियम जारी हुआ, उसमें गोशालाओं को अनुदान देने का प्रावधान खतम कर दिया गया, लेकिन डीग-कुम्हेर में इस कुम्हेर की जो गोशाला है, उसके पास 886 बीघा जमीन उपलब्ध है, जिसमें से नगरपालिका क्षेत्र में 3.71 हैक्टेयर जमीन आती है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए। मंत्री जी से क्या चाहते है?

डॉ. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि गोशाला के लिए अनुदान देकर इस जमीन को, जो नगरपालिका क्षेत्र में आ रही है, उसको गोशाला के लिए आबंटित कर दें और नगरपालिका को उसमें नोडल एजेंसी बना दें, जिससे उनका अनुदान गोशाला में आता रहे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल में मांग नहीं होती।

श्री जोराराम कुमावत (गोपालन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान में वहां गोशाला संचालित नहीं है, पशुपालन विभाग के अधीन है। यदि माननीय सदस्य वहां गोशाला खोलना चाहते हैं तो वहां एक संस्था बनाकर नियमानुसार आवेदन करें तो हम उसमें मदद करेंगे।

गुंदोलाव व हमीर सागर तालाब (किशनगढ़) को स्वच्छ रखने की कार्ययोजना

31. श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर की विभिन्न झीलों व मछली पालन वाले तालाबों की स्वच्छता हेतु सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित है? सरकार द्वारा उक्त तालाबों में जल-कुंभी के निवारण हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा नगर परिषद् क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित गुंदोलाव झील (तालाब) की स्वच्छता तथा मृत मछलियों से बीमारियों के खतरे के संबंध में क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गुंदोलाव तालाब व हमीर सागर तालाब में

(श्री विकास चौधरी)

प्रदूषित पानी को स्वच्छ रखने के प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि

32. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन 13,000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका का 6,500 रुपये व आशा सहयोगिनी (कार्यकर्ता) का 6,000 रुपये मानदेय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (डॉ. मंजू बाघमार): बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को शत प्रतिशत राज्य निधि मद से दिये जा रहे मानदेय की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से की गई है। वर्तमान में दिए जा रहे मानदेय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसी प्रकार आशा सहयोगिनियों को देय मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि उपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 4,508/- रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है।

वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चरणबद्ध रूप में वृद्धि समय-समय पर की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रख गया)

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): उत्तर प्राप्त हो गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अपने घोषणा-पत्र/नीतिगत दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक वेतन 13 हजार रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका का 6,500 व आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता का 6 हजार रुपये करेंगे तो सरकार अपने घोषणा-पत्र के अनुसार यह मानदेय कब तक तय कर देगी?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे घोषणा-पत्र के अनुसार हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। समय-समय पर, अभी भी हमने 01 अप्रैल, 2024 को 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाया था और क्रमिक रूप से चरणबद्ध तरीके से इनका मानदेय बढ़ाया गया है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या यह सही है कि वर्ष 2023 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका व आशा सहयोगिनी को मिलने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। यदि हां, तो आपकी सरकार द्वारा मानदेय की वार्षिक वृद्धि में 5 प्रतिशत की कमी किस आधार पर की गयी?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने घोषणा-पत्र में बताया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनियों और सहायिकाओं की चरणबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि की जायेगी। अभी सात महीने ही हुए हैं और 01 अप्रैल, 2024 से हमने इसको 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है और आगे भी क्रमिक रूप से प्रति वर्ष इसको बढ़ाया जायेगा।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि 5 प्रतिशत की कमी, 2023 में 15 प्रतिशत बढ़ाया था, 5 प्रतिशत की कमी क्यों कर दी?

श्री अध्यक्ष: आश्वस्त कर दिया कि चरणबद्ध बढ़ायेंगे। डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ में फसल बीमा के बकाया का भुगतान

33. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में फसल बीमा योजना अन्तर्गत फसल बीमा क्लेम बकाया है? यदि हां, तो कितने किसानों का, कितना-कितना और कब से? उक्त क्लेम के बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (कृषि मंत्री के स्थान पर): जी हां। फसल बीमा योजनांतर्गत विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में निम्न प्रकार बीमा क्लेम बकाया हैं-

(श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई)

मौसम	**पालिसी धारक कृषक (संख्या में)**	**बीमा क्लेम (राशि रु में)**
खरीफ 2022	60	42,996
रबी 2022-23	245	1,20,492
खरीफ 2023	272	7,579
योग	577	1,71,067

उक्त बीमा क्लेम नेफ्ट बाउन्स एवं खाता सत्यापित न होने के कारण लंबित हैं, जिसके लिये भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों एवं जिलों को निर्दिष्ट किया गया है। बकाया बीमा क्लेम शीघ्र ही बीमा कंपनियों के माध्यम से वितरित कराये जायेंगे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 के लिये तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 के लिये बीमा क्लेम संकलन पोर्टल के माध्यम से गणनाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बीमा क्लेम नेफ्ट बाउन्स और खाता सत्यापित न होने के कारण लंबित है, जिसके भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिये कि वैकल्पिक खाता चुन लिया जाये और उसमें क्लेम दे दिया जाये। फिर भी किसानों को दो साल से अभी तक क्लेम नहीं मिला है तो क्या इसमें किसान दोषी है या फिर अधिकारी दोषी हैं? इस शीघ्र का मतलब क्या कोई टाइम बाउंड है कि जिनको अभी तक क्लेम नहीं मिला, एक क्षेत्र में ही 577 लोग दर-दर भटक रहे हैं तो कोई ऐसा टाइम बाउंड है कि इतने टाइम में दे दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत बताना चाहूंगा कि यह जो 577 की संख्या है, इसमें पिछले तीन वर्षों का क्लेम मात्र 1,71,067 रुपये का है, जिसके लिए बीमा कंपनियों को निर्देशित किया चुका है। पोर्टल के माध्यम से बताया गया है कि जिस हिसाब से क्लेम दिया जाता है और सरकार के द्वारा बीमा कम्पनियों को निर्देशित कर दिया गया, क्योंकि जिनके खाते नहीं मिलते हैं या

(श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई)

जिनके खातों से पैसा वापस आ जाता है, उन्हीं को वापस वहां पर कैम्प लगाकर देने की प्रक्रिया है और यह प्रक्रियाधीन है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इतना-सा है कि सरकार कब तक दिला देगी? कोई टाइम?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): बहुत ही जल्द।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

34. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो प्रदेश में वर्तमान में कितने जिला चिकित्सालयों में उक्त केन्द्र स्थित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा में उक्त केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं। प्रश्न काल में नहीं बोलते। नियमों के तहत आपको अनुमति मिल जायेगी। बैठिये। आपको नहीं पुकारा है, आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बैठिये, आपको अनुमति नहीं है। आप छह बार के विधायक हैं। आप नियमों को मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप बैठिये, अंकित नहीं हो रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी नहीं। प्रदेश में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्तमान में राज्य में कुल 42 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थित हैं, जिनमें से 24 जिला चिकित्सालय, 16 चिकित्सा महाविद्यालय एवं 2 उप जिला चिकित्सालय में ये सेन्टर स्थित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा अधिक प्रसव भार वाली चिकित्सा संस्थानों पर, जहां Maternity Bed Occupancy Rate 70 प्रतिशत से अधिक होने पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अतिरिक्त 50/100 बेड के एम सी एच विंग निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति पर विचार किया जाता है।

वर्तमान में जिला चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा का प्रसव भार अनुसार Maternity Bed Occupancy Rate 48.44 प्रतिशत है, जो कि Maternity Bed Occupancy Rate 70 प्रतिशत से कम होने के कारण जिला चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ये यह जानना चाहता हूं कि आपने जो लिस्ट दी है और उसके अलावा भी जो जिला चिकित्सालय में मातृ शिशु केन्द्र खोल रखे हैं, क्या उनमें आक्यूपेंसी उतनी है या कहीं कम भी है, जहां भी खोले गये हैं? नंबर वन।

साथ ही, मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और हम जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिशु केन्द्र नहीं खोल रहे हैं। सरकार इसके बारे में क्या विचार करती है? हम स्कूल खुलवाने जाएं तो आप कहते हैं कि बच्चों की संख्या इतनी होनी चाहिए। हम अगर सड़क बनवाने के लिए जाएं तो दो हजार की आबादी होनी चाहिए। हम हास्पिटल खोलने के लिए जाएं तो इतनी आबादी होनी चाहिए। हम जनसंख्या कम कर रहे हैं तो आप शिशु केन्द्र नहीं खोल रहे हैं। मंत्री महोदय, जहां जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, वहां शिशु केन्द्र खोलने का विचार है या नहीं है?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो नोर्म्स हैं, मैंने नोर्म्स के अनुसार बोला है। आप फरमा रहे हैं कि कई हास्पिटल हैं, जहां 70 प्रतिशत से कम है,

(श्री गजेन्द्र सिंह)

उसकी पूरी जांच की जायेगी और आपके यहां डी एच, निम्बाहेड़ा में है, वहां पर दो करोड़ रुपये का रिपेयर और मेंटेनेस का काम भी हो रहा है और 31 करोड़ के पी आई पी के थ्रू 100 नये विंग का प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। आप बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो एक ही चीज पूछना चाह रहा हूं कि कितने ऐसे प्रकरण हैं जो आपके 70 प्रतिशत के नियम पूरे कर रहे हैं, उसके बाद भी वहां शिशु चिकित्सालय नहीं बने हैं और कितने ऐसे हैं जो नियम से कम में भी बनाये गये हैं? उनकी संख्या आप बताएं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न निम्बाहेड़ा का ही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): प्रदेश का है, साहब।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न प्रश्नकर्ता पूछ चुके हैं। मैंने उनको समझाया कि 70 परसेंट से कम कई हास्पिटल में हैं। अब ये कब-कब बने हैं, आपकी सरकार में भी हो सकते हैं, किसका कार्यकाल था, हमें मालूम नहीं है। इसकी जांच करके पूरी डिटेल्स लाकर माननीय नेता, प्रतिपक्ष को भी दे दूंगा और माननीय प्रश्नकर्ता को भी दे दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कह रहा हूं कि नियमों से कम में पहले बने हैं तो निम्बाहेड़ा को भी बना दीजिए।

श्री अध्यक्ष: निम्बाहेड़ा पर विचार करना आप। श्री संदीप शर्मा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मंत्री महोदय, एक बार आश्वासन तो दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कह दिया, आपके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे।

कोटा के विद्यालयों के भवनों व कक्षा-कक्षों का निर्माण

35. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा में विगत तीन वर्षों में कितने विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक से सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में अनेक विद्यालयों को संसाधनों के अभाव में क्रमोन्नत कर देने से विद्यार्थियों को अध्ययन में

(श्री संदीप शर्मा)

समस्या हो रही है? यदि हां, तो उक्त जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जहां एक कक्ष में एक से अधिक कक्षाएं तथा खुले में कक्षाएं लगाई जा रही हैं? विद्यालयों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों के भवनों व कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों के कितने कक्षा-कक्षों के प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा सरकार द्वारा अब तक किन-किन विद्यालयों में कितने कक्षा-कक्षों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विगत 03 वर्षों में कोटा जिले के 83 राजकीय माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर एवं 15 राजकीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।

(2) जी हां। जिला कोटा में 35 राजकीय विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें एक कक्षा-कक्ष में एक से अधिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका नामवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

कोटा जिले में किसी भी क्रमोन्नत राजकीय विद्यालय में खुले में कक्षाएं नहीं लगाई जा रही हैं।

(3) राजकीय विद्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष ऑनलाइन भरे जाने वाले यू-डाइस के आधार पर विद्यालयवार कक्षा-कक्षों की आवश्यकता, उपलब्धता व कमी (गैप्स) के आधार पर समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव प्रतिवर्ष समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रेषित किये जाते हैं।

गत 03 वर्षों में कोटा जिले के क्रमोन्नत 98 विद्यालयों में से 26 विद्यालयों में 62 कक्ष निर्माण एवं 01 नवीन भवन (सीनियर सैकण्डरी स्कूल) कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। चलिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तीन वर्ष में सरकार ने हजारों विद्यालयों को

(श्री संदीप शर्मा)

क्रमोन्नत किया, परन्तु उनमें संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए। न फर्नीचर, न शिक्षक, न अन्य संसाधन और बिना कक्षा-कक्ष के, बिना शिक्षकों के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिस तरीके से विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया, ये प्रस्ताव किससे लिये गये? मेरे कोटा जिले के अन्दर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया? किसके कहने से क्रमोन्नत किया गया? कृपया मंत्री जी बताएं?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): वही पूछ रहा हूं, कृपया मंत्री जी बताएं। बिंदु संख्या 02, अधिकारियों ने जो आपको बिंदु संख्या (2) में सूचना उपलब्ध कराई है, उसमें उन्होंने 35 राजकीय विद्यालय ऐसे बताये हैं, जिनमें कक्षा-कक्षों में एक से अधिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जबकि इनकी संख्या और अधिक है। माननीय मंत्री महोदय, चूंकि आप बेहद संवेदनशील हैं और शिक्षा के प्रति आप लगातार नवाचार कर रहे हैं। एक मेरे पास ये तथ्य है कि नयागांव में ही खुले में कक्षा चल रही है। इसको देखिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: ये भूल जाएंगे। आप उत्तर सुन लीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): शिक्षा मंत्री महोदय माफी नहीं मांगेंगे, सदन से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम इनका जवाब नहीं सुनेंगे। (व्यवधान) आप इनसे माफी मंगवाइए।

श्री अध्यक्ष: आप लोग बैठिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में शिक्षा का जो स्तर था ...(व्यवधान) निश्चित रूप से बहुत दयनीय स्थिति शिक्षा की थी। (व्यवधान) मंत्री महोदय मेरा जवाब देना चाह रहे हैं, परन्तु नहीं आने दे रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आदिवासी समाज के बारे में ...(व्यवधान) इस प्रकार की बात करना ...(व्यवधान) और वह इस सदन में हैं। आप इनसे माफी नहीं मंगवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर नारे)

श्री अध्यक्ष: आप को जो पूछना है, पूछिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) इन्होंने शिक्षा की दयनीय स्थिति की है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का बंटाधार पहले वाली कांग्रेस सरकार ने किया है। (व्यवधान) तीन साल में 26 विद्यालयों में 62 कमरे दिए और हमने ...(व्यवधान) तीन महीने में 21 विद्यालयों में 52 कमरे दिए हैं। इन्होंने पांच साल में 13 करोड़ 66 रुपये दिए हैं पांच साल में, ...(व्यवधान) हमने इन 6 महीने में 12 करोड़ 41 लाख रुपये दिए हैं और निरंतर चरणबद्ध तरीके से भवन भी बनाएंगे और हम आने वाले समय में सारे पदों को भरेंगे तथा फर्नीचर की व्यवस्था भी करेंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न है। इसमें जो सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं ...(व्यवधान) बिंदु संख्या 3 में कोटा में।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा।

जहाजपुर के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत पद

36. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र कार्यरत कार्मिकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सालयों के भवन, चारदीवारी व उपचार थियेटर, सैटअप उपलब्ध नहीं है तथा अधिकतर चिकित्सालयों के बने हुए भवन, चारदीवारी अन्य सैटअप क्षतिग्रस्त व पुरानी अवस्था में हैं? यदि हां, तो पशु चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीचन्द मीणा)

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने व प्रतिनियुक्ति निरस्त करने तथा भवन, चारदीवारी निर्माण, पशु उपचार सैटअप, थियेटरों का निर्माण व पशु चिकित्सालयों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर का कोई भी कार्मिक अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पशु चिकित्सालयों में आपरेशन थियेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा जिला स्तरीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भीलवाड़ा में उपलब्ध है।

इस विधान सभा क्षेत्र के समस्त पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के लिये आवश्यक सैटअप जैसे ट्रेविस, चिकित्सा/कृत्रिम गर्भाधान आदि के उपकरण उपलब्ध हैं।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पशु चिकित्सालयों के भवन, चारदीवारी का पशु चिकित्सालयवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर का कोई भी कार्मिक अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

पशु चिकित्सा संस्थाओं के नवीन भवन निर्माण विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाये जाते हैं।

राजकीय भवन युक्त विभागीय संस्थाओं के जर्जर भवनों की मरम्मत एवं चारदीवारी निर्माण, इलाज हेतु आउटडोर शैड व थियेटर निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय पिछले 5 वर्ष में मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। कितने पशु चिकित्सा अधिकारी के पदस्थापन किये और कितने एल एस ए के पदस्थापन किये? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2021 में प्रदेश में आवश्यक अस्थाई आधार पर 300 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिनमें जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी पशु चिकित्सा अधिकारी को नियुक्ति नहीं दी गयी। वर्ष 2022 में प्रदेश में आवश्यक अस्थाई आधार पर 200 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिनमें जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी पशु चिकित्सा अधिकारी को नियुक्ति नहीं दी गयी। वर्ष 2020-21 में कुल 2,149 पशुधन सहायकों का पदस्थापन किया गया...

श्री अध्यक्ष: उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए केवल।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): उनमें से केवल दो को ही जहाजपुर में नियुक्ति दी गयी। इसी तरह वर्ष 2021-22 में पशुधन सहायकों के कुल विज्ञापित 1,436 पदों के विरुद्ध ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह तो आ गया। यह तो पढ़ लिया आपने।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपके दोनों हो गये। आप बोलिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो पद रिक्त हैं, वहां पशु मित्र लगे हुए हैं क्या आप उनका मानदेय निर्धारित करके संविदा में उनको शामिल करना चाहते हैं? जिससे जो रिक्त पदों की संख्या है, उससे आपको छुटकारा मिल सके।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष महोदय को बताना चाहूंगा कि अभी हमारे डाक्टरों की 900 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्दी उनको भी लगाएंगे। जो पशु मित्र हैं, उसमें भी विचार करेंगे और आने वाले समय में सरकार अच्छा निर्णय करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल।

पीपल्दा के उम्मेदपुरा से श्योपुरा नहर तक सड़क का निर्माण

37. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में विगत पांच वर्षों में कृषि उपज मण्डी की आय से सड़कों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम उम्मेदपुरा से श्योपुरा नहर तक डेढ़ किलोमीटर तक सड़क बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) (कृषि विपणन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। विगत 5 वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति की आय की राशि से कोटा जिले में कुल 25 सडकों के कार्य स्वीकृत किये गये। इनमें से 15 सडकों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 10 सड़कों का कार्य प्रगतिरत है। सड़कों के निर्माण का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि उपज मण्डी समिति, इटावा से सम्पर्क सड़क ग्राम उम्मेदपुरा से श्योपुरा नहर तक की सड़क बनाने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विभाग के अधीनस्थ कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा अपने क्षेत्र में विभागीय सड़क नीति दिनांक 31.12.2014 एवं दिनांक 18.03.2020 के प्रावधानानुसार मण्डी समितियों से सम्पर्क सड़क (मिसिंग लिंक) निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी समिति की बचत के अनुसार गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछना है?

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल चुका है। खण्ड (2) में मेरे प्रश्न का जो जवाब आया है, विभाग द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, यह सरासर गलत है। इस विषय में मैंने पूर्व में माननीय कृषि मंत्री जी, जयपुर और मंडी सचिव, इटावा को दिनांक 12.02.2024 को पत्र लिखा। मेरे पत्र पर मंडी सचिव, इटावा द्वारा दिनांक

(श्री चेतन पटेल कोलाना)

24.02.2024 को अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कोटा को स्टेटमेंट बनाकर प्रस्ताव जयपुर भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र के बाद की कार्यवाही कृषि विपणन बोर्ड की है। मेरा आपसे इतना-सा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, आजादी के बाद से इस गांव में अभी तक रोड नहीं बन पाया है और इस रोड पर बहुत सारे किसानों की कृषि भी है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इस पर विचार रखते हैं? क्या इस रोड को बनाना चाहते हैं?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पीपल्दा से आने वाले माननीय विधायक, आपका यह प्रस्ताव 2023-24 में आया था, तब बजट नहीं था। (व्यवधान)

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): मेरे पास कापी है, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, सुनिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं बता रहा हूं। 2024-25 में आपके द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया गया। यह कर्मवीर मुख्य मंत्री भजन लाल जी की सरकार है, आप प्रस्ताव भिजवाइये, हम करके देंगे। प्रस्ताव भिजवाइये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। (व्यवधान) आसन पांव पर है। श्रीमान जी, वहीं बैठो। वहीं बैठो। मैंने इतनी बार सिखा दिया।

(शेष तारांकित तथा समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से पूर्व राज्यपाल स्व. श्रीमती कमला बेनीवाल की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

(1) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

(2) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश के राशन विक्रेताओं का बकाया कमीशन एवं प्रतिमाह मानदेय दिलाये जाने के संबंध में।

(3) श्री हंसराज पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा में डेयरी संचालन में हो रही अनियमितताओं की जांच करवाकर समुचित कार्यवाही करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर ज़िले के उपनिवेशन क्षेत्र में भू-सर्वे से वंचित ग्रामों का सर्वे करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्ष 2021 में बाढ़ से हुए बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आबंटन करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, छोटी सादड़ी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(7) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध शैक्षिक संस्थानों में छात्रसंघ चुनाव प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा से गुजरने वाले मेगा हाई-वे पर रणसीगांव, झाक, खारिया-मीठापुर एवं बिलाड़ा का बाईपास बनाये जाने के संबंध में।

(9) श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में महानरेगा योजनान्तर्गत बीएफटी, बेयरफुट टेक्निशियन को संविदा नियम-2022 में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

(10) श्री ललित मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में जल- जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल की सुचारु व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विभिन्न नव-निर्मित 33 के.वी. जी.एस.एस. का संचालन शीघ्र प्रारम्भ कराने एवं स्वीकृत 132 के.वी. जी.एस.एस. निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत कोटड़ी, राजसमन्द में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चरागाह भूमि पर अवैध रूप से अपशिष्ट निस्तारण करने से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में।

(13) श्री उदयलाल डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की जयसमंद झील से जुड़ी नदी में RSMML. झामरकोटड़ा माइन्स द्वारा केमिकल पदार्थ डालने पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

(14) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, भरतपुर के कुलपति द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के संबंध में।

(15) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से नागौर ज़िले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का भुगतान करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 11/07/2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 52 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई, जो निम्नानुसार हैं:-

(1) श्री प्रताप लाल भील, गोगुन्दा स्थित नेशनल हाईवे संख्या-27 पर आये दिन हो रही दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री अमृतलाल मीणा, सराड़ा में 132 केवी जीएसएस का कार्य धीमी गति से होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री जेठानन्द व्यास, विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में बीकानेर इलैक्ट्रिकल सप्लाई लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा आमजन को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री हरिमोहन शर्मा, उदयपुर के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक तंगी के कारण शिशुओं को बेचकर घर खर्च चलाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

पर्ची पर बोलने की अनुमति होगी। श्री गोविन्द प्रसाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मनोहर थाना में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहर थाना झालावाड़ जिले का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लाक है। यह मध्यप्रदेश सीमा से लगता है

श्री अध्यक्ष: वैल में से कोई नहीं आएगा। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): मैं पिछले काफी समय से मांग कर रहा हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहर थाना को 30 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का किया जाये तथा अकलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बेड से बढाकर 100 बेड का किया जाये। मनोहर थाना में ओ पी डी 400 प्रतिदिन है तथा अकलेरा में 900 प्रतिदिन है। मनोहर थाना में लगभग 150 गांव से ग्रामीण आते है, लगभग आबादी 1,05,000 का विस्तार हो चुका है, जबकि अकलेरा में 1,30,000 के लगभग आबादी है। नजदीक में कोई बड़ा सरकारी हास्पिटल नहीं है। सबसे ज्यादा आउटडोर रोगी आते हैं। पूर्ण उपचार उपलब्ध नही होने से मरीजों को अन्यत्र स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत कठिनाइयां आती हैं। मजदूर वर्ग के लोग आए दिन चोटिल हो जाते हैं, जिससे लगभग 100 कि.मी. की दूरी पर झालावाड़ रेफर करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहर थाना में कोई बड़ी सुविधा नही है। अस्पताल का भवन पर्याप्त है, परन्तु चिकित्सकों के आवास नहीं हैं व पद भी रिक्त चल रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि अविलम्ब अमलीजामा पहनाया जाये। उसकी शत-प्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित करवायें, ताकि गरीब मजदूर वर्ग व आमजन को समय पर उपचार के साथ-साथ धन के अपव्यय से भी राहत मिल सके। विशेष ध्यान देकर क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

राशन विक्रेताओं के बकाया कमीशन एवं मानदेय की प्रति माह उपलब्धता

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राजस्थान राज्य के अधिकृत राशन विक्रेता का बकाया कमीशन, प्रतिमाह मानदेय एवं दुकान किराया दिलाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान राज्य के अधिकृत राशन विक्रेताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो इस प्रकार हैं:-

1. पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार की योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त से फूड पैकेट्स वितरण प्रारम्भ किया था जिसका अगस्त से नवम्बर 23 तक का कमीशन बकाया है। आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत आफलाइन वितरित किये गये गेहूं का कमीशन बकाया है।

2. राशन विक्रेता व सहायक (तोलक) को वर्तमान में कोई मानदेय नहीं दिया जाता है और विक्रेता को दुकान का किराया भी नहीं दिया जाता है। 3-4 वर्ष पूर्व राशन विक्रेताओं से आधार सीडिंग का कार्य करवाया गया था जिसका पेमेंट भी अभी तक बकाया चल रहा है।

3. सरकार द्वारा पोस मशीन के 10 रुपये व मेंटिनेंस के 5.21 रुपये काटे जा रहे हैं। वर्तमान में जो पोस मशीनें विक्रेता को दी जा रही हैं, उनके पेटे पुरानी मशीन एजेन्सी वाले ले रहे है, जबकि पुरानी मशीन का पेमेन्ट विक्रेताओं द्वारा पूर्व में किया जा चुका है।

4. राज्य सरकार ने जुलाई माह से अशक्त व वृद्ध उपभोक्ताओं के लिए 10 कि.ग्रा. का बैग होम डिलीवरी करने की योजना बनायी है, परन्तु राशन विक्रेताओं में कई विक्रेता अशक्त एवं वृद्ध हैं।

श्रीमान् से आग्रह है राशन विक्रेताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विक्रेताओं का बकाया चल रहा कमीशन दिलाने के साथ ही राशन विक्रेता व सहायक (तोलक) को मासिक मानदेय भी दिया जाये। विक्रेताओं की ली जा रही पुरानी पोस मशीन की आधी राशि विक्रेताओं को दी जाये एवं अशक्त व वृद्ध राशन विक्रेताओं के स्थान पर उनका सहयोग करने वाले आश्रित को नियुक्त किया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज पटेल। 295 पढ़िये। पढ़िये ना, आपने जो लिखकर दिया है, 295 में उसको पढ़ना है।

श्री हंसराज पटेल (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बजट में जो हमारे कोटपूतली का नाम आया, कोटपूतली के लिए सबसे बड़े ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें जो लिखा है वह ही आपको पढ़ना है। जो आपने इसमें लिखकर दिया है आपको वही पढ़ना है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप किसी और से पढ़वा दो।

महवा में डेयरी संचालन में अनियमितताओं पर कार्रवाई

श्री हंसराज पटेल (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत, खौंचपुरी के गांवों में संचालित सरस डेयरी में डेयरी अधिकारी/सरस डेयरी इंचार्ज, महवा द्वारा नियम विरुद्ध डेयरी समिति, BMC, दुग्ध कलेक्शन सेंटर के आबंटन में अनियमितताएं की गईं तथा उनमें उक्त अधिकारियों की मिलीभगत से इनका संचालन भी निर्धारित स्थान के बजाय अन्य स्थानों पर हो रहा है एवं अपने चहेते लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को एक से अधिक डेयरी/संकलन केन्द्र/समितियां आबंटित कर रखी हैं जिनमें कुछ केन्द्र या समितियों के तो सचिव भी उस गांव के नहीं हैं जहां सेंटर संचालित हैं। इससे महवा के आस-पास के कई गांवों में कई जगहों पर मिलावटी और नकली दूध का संकलन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो कि आमजन के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है।

अतः नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण में निम्न गुणवत्ता और नकली दूध की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर जांच कराएं तथा महवा डेयरी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह। आप थोड़ा माइक पास ले लें।

जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र में भू-सर्वे से वंचित ग्रामों का सर्वे

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में आने के बावजूद विभिन्न राजस्व ग्रामों का ग्राम सर्वे नहीं होने से किसानों को सामान्य आबंटन की समस्या के निदान हेतु वंचित गांवों का सर्वे करने हेतु निवेदन है।

महोदय, जैसलमेर जिले में उपनिवेशन विभाग के पास सात तहसीलें

(श्री छोटूसिंह)

हैं जिनमें लगभग 200 गांव उन तहसीलों में आते हैं। कई गांवों को राजस्व विभाग से उपनिवेशन विभाग में स्थानांतरित हुए कई वर्ष हो गये, परन्तु उनका ग्राम सर्वे नहीं हो पाने के कारण ऐसे गांव में नहर व खाले बनने के बावजूद आबंटन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पा रही है। इससे न केवल सैकड़ों भूमिहीन पात्र किसान सामान्य आबंटन से वंचित हैं, बल्कि नहर व खालों पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद आज तक उस पर खेती नहीं होने से हजारों टन फसल उत्पादन से भी वंचित होना पड़ रहा है तथा विशेष आबंटन के जरिए होने वाली आय से भी सरकार वंचित हो रही है।

मैंने विगत सरकारों में भी कई बार यह मुद्दा उठाया था, परन्तु आज तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बातचीत चैम्बर में जाकर करना। आप चैम्बर में जाकर मंत्रीजी से मिलें। माननीय सदस्य अभी 295 का पढ़ रहे हैं। मैं आपको ही कह रहा हूं, आप अपनी सीट पर पधारें। (व्यवधान) माननीय हरिसिंहजी, मंत्रीजी से बाद में चैम्बर में मिलें। (व्यवधान)

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर):...प्रथम सत्र में मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या 2608 पूछने पर अधिकारियों ने औपचारिकता निभाने में बहुत अधिक जल्दबाजी करते हुए दो-दो पटवारियों की टीम गठित कर उसे जैसलमेर भेज दिया, जबकि इससे पहले इंस्पेक्टर जांच कर चुके हैं। फिर यह औपचारिकता क्यों? जब इंसपैक्टर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके तो पटवारी कैसे निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे? मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जिले के उपनिवेशन विभाग में वंचित गांवों लूणार, गुंजनगढ़, उकरालापार, दबडी, लाम्बापार सहित अन्य वंचित गांवों के ग्राम सर्वे हेतु केन्द्र सरकार की DILRMPG योजना के तहत उपनिवेशन तहसील जैसलमेर को मॉडल तहसील घोषित कर रीसैटलमेंट करवाया जाए, ताकि वंचित गांवों का ग्राम सर्वे पूरा हो सके और स्थानीय निवासियों को भूमि आबंटन का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप खड़े मत रहिये सदन में।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी ट्रेनिंग करवाइये।

श्री अध्यक्ष: सभी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सभी को दूंगा। सभी को

(श्री अध्यक्ष)

देंगे। आपको भी देनी पड़ेगी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, सामने से नहीं जाते हैं। आप बैठिये। श्री चेतन पटेल कोलाना।

पीपल्दा में बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास आवंटन

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में विशेष प्रधानमंत्री आवास दिलवाने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में वर्ष 2021 में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण कई परिवार बेघर हो गए थे। राज्य सरकार द्वारा कई घरों के नष्ट होने से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान किया गया व कई परिवार मुआवजे से वंचित भी रह गए जो आज तक वंचित हैं और इनकी पत्रावली विभाग के पास विचाराधीन है।

इसी क्रम में पूर्व में कोटा के माननीय सांसद की ओर से समाचार पत्रों में हाड़ौती के 10 हजार बाढ़ पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने हेतु समाचार प्रकाशित हुए। इन मकानों में कोटा जिले को 6,106 प्रधानमंत्री आवास मिलने थे जो आज तक नहीं मिले हैं।

राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि पूर्व में माननीय सांसद, कोटा द्वारा स्वीकृत करवाये गये प्रधानमंत्री आवास में से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में बाढ़ के कारण बेघर हुए व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का श्रम कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा यह निवेदन है कि थोड़ा आप माइक लम्बा करवा दो। आवाज सही नहीं आती है। माइक थोड़ा लम्बा करवा दीजिए, लम्बाई के हिसाब से करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विचार करेंगे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ऐसा है कि इनको बैठे-बैठे बोलने की इजाजत दे दो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पढ़िये।

छोटी सादड़ी (निम्बाहेड़ा) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सादड़ी को उप जिला चिकित्सालय (100 बेडेड) में क्रमोन्न्त करने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्बाहेडा विधान सभा क्षेत्र की छोटी सादड़ी तहसील जनजाति उप योजना क्षेत्र (TSP) के अन्तर्गत आती है। छोटी सादड़ी उप खण्ड मुख्यालय होने व जनजाति बहुल क्षेत्र होने के कारण यहां बेहतर एवं उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि:-

1. वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 4 चिकित्सा अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें सर्जन, एनेस्थीसिया, शिशु रोग, हड्डी रोग के पद रिक्त हैं।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रतिदिन का ओ पी डी भार 400-450 मरीज का है।

3. ट्राइबल एरिया होने से लगभग 100-120 प्रसव प्रतिमाह होते हैं जिनमें कुछ जटिल प्रसव की स्थिति में मरीजों को सर्जन एवं एनेस्थीसिया चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद होने से अन्यत्र उच्च चिकित्सा संस्थान को रैफर करना पड़ता है।

4. नेशनल हाईवे शहरी क्षेत्र के पास से गुजरने के कारण 24X7 आपातकालीन चिकित्सकीय सेवाएं सुचारु रूप से संचालित हैं, लेकिन गम्भीर मरीजों को हड्डी रोग व अन्य चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद होने से अन्यत्र उच्च चिकित्सा संस्थान को रैफर करना पड़ता है।

5. प्रति बुधवार को निःशुल्क गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की जाती है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टेटिक सेन्टर होने के कारण नसबन्दी कैम्प का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें आस-पास के 30 किलोमीटर के मरीजों को कैम्प के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी सादड़ी को उप जिला चिकित्सालय (100 बेडेड) में क्रमोन्न्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्राथमिकता प्रदान कर उक्त केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने का कष्ट करें, ताकि आमजन को बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं मिल सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध शैक्षिक संस्थानों में छात्र संघ चुनाव

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्र संघ चुनावों के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विगत सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 'छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं' छात्र संघ चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूर्णतः औचित्यहीन है।

मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराया जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितान्त आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीतिक नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। आज राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ राज्य स्तर के अधिकतम नेतृत्वकर्ता छात्र संघ राजनीति से ही निकले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं इसी छात्र संघ राजनीति से आते हैं। मेरा संबंध भी छात्र राजनीति से रहा है और साथ ही साथ इस सदन में बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के मंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। छात्र संघ चुनाव में युवा राजनीतिक मूल्यों को सीखता है। युवा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है, जहां पहली बार

(श्री रविन्द्र सिंह भाटी)

जन सेवा की भावना अंगड़ाई लेती है। छात्र संघ चुनाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आधार स्तम्भ है, जिस पर आगामी राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तय होगी। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य हैं।

मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाने की कृपा करें। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की नीति निर्माण में और राष्ट्र की लोक कल्याणकारी अवधारणा को साकार करने में सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर बाईपास का निर्माण

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्व के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है कि बिलाड़ा, खारिया मीठापुर, झाक, रणसीगांव, गांव व कस्बे गोटन-सोजत मेगा हाईवे पर स्थित हैं। इन गांवों व कस्बों के आबादी क्षेत्र में से मेगा हाईवे पर दैनिक भारी वाहनों का आवागमन रहता है।

मेगा हाईवे का राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा पूर्व में वर्ष 2010 में निर्माण हुआ, लेकिन उक्त गांव व कस्बे के लिए प्रस्तावित बाईपास न बनाकर आबादी क्षेत्र से ही भारी वाहन गुजरते हैं। बिलाड़ा कस्बे का दो भागों में विभाजन कर गुजर रहे इस मार्ग पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी तक कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा चोटिल हो चुके हैं।

इस हाईवे पर प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जिसके कारण आमजन को आबादी क्षेत्र में सड़क पार करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार भीड़-भाड़ के कारण हाईवे पर वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती हैं और कई घंटों तक जाम लग जाता है।

बिलाड़ा कस्बे की आबादी करीब 50 हजार के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में तीज-त्योहार, सामाजिक शोभा यात्राएं, रैली, प्रदर्शन एवं मेलों के दौरान इस हाईवे को बंद कर अन्यत्र मार्ग से डाइवर्ट किया जाता है। मेगा हाईवे के निर्माण के समय भी बिलाड़ा के कस्बेवासियों ने, रणसीगांव, झाक एवं खारिया मीठापुर के ग्रामवासियों ने आबादी क्षेत्र से सड़क निर्माण का विरोध किया था।

(श्री अर्जुन लाल)

इसके बावजूद भी हाईवे को शहर के बीच से निकाल दिया गया था। खारिया मीठापुर के बीच 7 कि.मी. सड़क का निर्माण भी आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा नहीं करवाया एवं चारों स्थानों पर बाईपास का निर्माण भी नहीं करवाया। इसके बावजूद इस मेगा हाईवे पर तीन टोल लगाकर वर्ष 2010 से टोल वसूली की जा रही है।

अत: राज्य सरकार से निवेदन है कि इस मेगा हाईवे पर रणसीगांव, झाक, खारिया, मीठापुर, बिलाड़ा का बाईपास बनाकर लोगों को बढ़ती दुर्घटनाओं से राहत दिलायी जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवरलाल।

बी.एफ.टी. (बेयरफुट टेक्निशियन) का संविदा नियम-2022 में सम्मिलन

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि वर्ष 2013-2018 तक भाजपा सरकार द्वारा महानरेगा योजना के अन्तर्गत बी एफ टी बेयरफुट टेक्निशियन को ग्राम पंचायत स्तर पर लगाया गया था। बी एफ टी बेयरफुट टेक्निशियन द्वारा महानरेगा योजना अंतर्गत कार्यों का माप, तकमीना, सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा कार्यों की गुणवत्ता आदि कार्य जे टी ए की तरह संपादित किये जा रहे हैं।

उक्त बी एफ टी बेयरफुट टेक्निशियन को राजस्थान में माह में सिर्फ 14 दिन का रोजगार ही दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार बी एफ टी को मासिक संविदा पर नियोजित किया जाना है।

पड़ोसी राज्य हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ही बी एफ टी बेयरफुट टेक्निशियन को मासिक रोजगार देकर संविदा सेवा नियम, 2022 में शामिल किया गया है।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध व गुजारिश करता हूं कि उक्त बी एफ टी बेयरफुट टेक्निशियन जो लगातार 8 साल से सेवा दे रहे हैं, उनको संविदा नियम, 2022 में शामिल करते हुए पूरे माह का रोजगार उपलब्ध करायें।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीना।

किशनगंज में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल की सुचारु व्यवस्था

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। कई जगह जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियां बना दी गई हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनमें पानी नहीं आया है जिससे लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कई जगह जैसे-जलवाडा, गरडा, मामुनी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकियों की पाइप लाइन जमीन से बाहर ही छोड़ दी है, जिससे उनके टूटने का खतरा बना रहता है और वहां पर पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद के कुछ गांवों जैसे-बांसथूनी, फल्दी, कुण्डी, ख्यावदा, अकोडिया, रामगढ़, छीनोद, शोभागपुरा, उम्मेदपुरा, मायथा, कागला बम्बोरी, दीगोदपार, बरूनी व सुवास में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी की टंकी बनने पर लोगों को पानी की समस्या से राहत प्रदान होगी। पंचायत समिति, रामगढ़, पींजना में पानी की टंकी का निर्माण होने पर भी पानी लोगों के मध्य नहीं पहुंच पा रहा है। कई जगह जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो बोर करवाये गये थे, वे भी सूख चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है जिसमें लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि वे खुद पेयजल की व्यवस्था कर सकें। गर्मी में पानी के टैंकर द्वारा भी लोगों को पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया था। अध्यक्ष महोदय, आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग हमारी सरकार से पेयजल की उम्मीद लगाये हुए हैं। अतः पी एच ई डी मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

रामगढ़ के नवनिर्मित 33 के.वी. जी.एस.एस. का शीघ्र प्रारम्भ एवं अन्य स्वीकृत 132 के.वी. जी.एस.एस. का शीघ्र निर्माण

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत

(श्री जुबेर खान)

मैं आपके और इस सदन के माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में विद्युत विभाग द्वारा नवनिर्मित 33 KV GSS का कार्य पिपरौली, सैंथली, नगला बंजीरका एवं रघुनाथगढ़ में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा काफी लम्बे समय के बाद कार्य पूर्ण किया गया है, लेकिन फिर भी इन GSS को चालू नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां के किसानों एवं आमजन की बिजली संबंधी समस्या को ध्यान में रखते हुए इन चारों GSS को तुरंत प्रभाव से चालू करवाया जाए, ताकि इलाके में बिजली की समस्या का कुछ समाधान सम्भव हो सके।

साथ ही, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा मुबारिकपुर में स्वीकृतशुदा 132 KV GSS का कार्य शीघ्र चालू करवाया जाये, क्योंकि यह इलाका पहाड़ियों के बीच में है इसलिए वोल्टेज बहुत कम आते हैं। यहां पर इस GSS की बहुत आवश्यकता है। बिजली संबंधी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार से आग्रह है कि इस GSS के कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। इधर ध्यान देना चाहिए माननीय सदस्यों को, बातचीत नहीं।

कोटड़ी ग्राम पंचायत (राजसमन्द) में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चरागाह भूमि पर अपशिष्ट निस्तारण

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत राज्य सरकार का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

राजसमन्द जिले की ग्राम पंचायत कोटड़ी की चरागाह भूमि पर वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। यह कंपनी चरागाह भूमि का उपयोग टेलिंग डैम से जिंक और लेड के अनुपयोगी एवं प्रदूषण फैलाने वाले अपशिष्ट डालने के लिए कर रही है। तेज हवा एवं पानी के बहाव के साथ इस अपशिष्ट के कारण क्षेत्र के महत्वपूर्ण जल स्रोत फूटरिया तालाब, रामसागर एवं मुख्य तालाब कोटड़ी और आसपास

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

के कुएं गंभीर प्रदूषण से दूषित हो गए हैं। कंपनी रात्रि के समय टेलिंग डैम से प्रदूषण एवं रसायनयुक्त जल आसपास की सरकारी एवं चरागाह भूमि में छोड़ रही है जिसके कारण क्षेत्र में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पशुधन में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो गई है। रसायनयुक्त पानी पीने से ब्रेन हेमरेज, लिवर, हार्ट अटैक एवं कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं।

हिंदुस्तान जिंक की खनन एवं प्रसंस्करण इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को लेड व जिंक के कारण श्वसन संबंधी एवं अन्य गंभीर रोग हो जाते हैं। इस कारण कंपनी इन श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य करती है। ऐसे कर्मचारियों को भूमिगत खनन के स्थान पर अन्य कार्यों पर लगाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी इन कर्मचारियों के उपचार के लिए कंपनी को पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।

टेलिंग डैम की ऊंचाई सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके बढ़ा दी गई है। इस कारण एसिड व रसायनयुक्त पानी भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहा है। नया दरीबा एवं सुनारिया खेड़ा क्षेत्र में एस एल एफ वेस्ट एवं टेलिंग डैम की प्रदूषित मिट्टी और पानी के कारण 1000 बीघा से अधिक की भूमि बंजर हो गयी है।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान करने एवं चरागाह भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिये आग्रह कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री उदयलाल डांगी।

जयसमन्द झील की नदी में झामरकोटड़ा माइन्स द्वारा केमिकल पदार्थ डाला जाना

श्री उदयलाल डांगी (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सादर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुराबड़ क्षेत्र में जयसमंद झील में जाने वाली नदी में RSMML झामरकोटड़ा माइन्स द्वारा केमिकल पदार्थ छोड़े जा रहे हैं जिससे नदी क्षेत्र की जमीन बंजर हो रही है व हैण्डपम्प व कुओं का पानी प्रदूषित हो चुका है। यहां पर पशुओं की अकाल मृत्यु हो रही है तथा मानव जीवन भी खतरे में है। इससे स्थानीय निवासियों में असंतोष व आक्रोश व्याप्त है।

(श्री उदयलाल डांगी)

अतः मैं मांग करता हूं कि उक्त RSMML झामरकोटड़ा माइन्स के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही कर स्थानीय निवासियों को शीघ्र राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री बहादुर सिंह कोली।

भरतपुर के महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, भरतपुर के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा के द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं धांधलेबाजी कर विश्वविद्यालय के राजकोष का दुरुपयोग करने, अपने परिचितों को नियम विरुद्ध अवैधानिक रूप से विश्वविद्यालय में संविदा पर नियुक्ति दी जा रही है। विश्वविद्यालय के सत्र 2023-24 में एस.एफ.एस. नीति, एस.एफ.एस. आधारित समस्त कोर्सेज/पाठ्यक्रम में अध्यनरत विद्यार्थियों की संख्या विषय/संकायवार, शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ मय पदनाम कुल संख्या विषय/संकायवार समस्त विद्यार्थियों से ली जाने वाली कुल कितनी फीस प्राप्त हुई, उसकी ऑडिट करवाये जाने की आवश्यकता है। कुलपति द्वारा महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में संविदा पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर डॉ. नेहा गोपाल, सुश्री वैष्णवी शाह, डॉ. लवनीश कुमार एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रवि तोमर की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में विश्वविद्यालय को प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के द्वारा जारी एकेडमिक बुलेटिन 2023-2024 के पृष्ठ संख्या-86 पर वर्णित/उल्लेखित ADJUNCT FACULTY की सूची में शामिल समस्त शिक्षकों की ADJUNCT FACULTY के रूप में नियुक्ति यू जी सी के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं की गई है।

अतः मेरा प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा की जा रही अनियमितताओं की अविलम्ब जांच करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

नागौर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का भुगतान

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये नागौर जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का भुगतान करने के क्रम में निवेदन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नागौर जिले के डेगाना, मेड़ता, जायल, नागौर, खींवसर, परबतसर, डीडवाना, मकराना, लाडनूं एवं नावां के 1,68,191 किसानों द्वारा वर्ष 2023-24 में खरीफ की फसलों का बीमा कराया गया है तथा 58,537 किसानों द्वारा रबी की फसलों का बीमा कराया गया है, लेकिन अभी तक किसानों को खरीफ की फसलों का बीमा क्लेम भी नहीं मिला है। नागौर जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा किसानों की फसलों का बीमा किया गया। राज्य के 33 जिलों में से 23 जिलों में इसी बीमा कम्पनी द्वारा बीमा किया गया है।

महोदय, जिले के किसान बार-बार बीमा कम्पनी के चक्कर लगाने को मजबूर हैं तथा बार-बार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए सरकार इस पर विशेष ध्यान दे तथा योजना की मॉनिटरिंग के लिए अपने निष्पक्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दे। नियमों का सरलीकरण करे तथा बीमा कम्पनी को बाध्य करे कि वह किसानों की बीमा क्लेम राशि का भुगतान निश्चित समयावधि में करे। अनावश्यक देरी होने पर बीमा कम्पनी पर पेनल्टी आरोपित करने के प्रावधान किये जाने चाहिए तथा ज्यादा देरी होने पर किसानों को ब्याज सहित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

महोदय, बार-बार भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए मेरा राज्य सरकार एवं कृषि मंत्री जी को सुझाव है कि राजस्थान में हमें स्वयं की सरकारी बीमा कम्पनी बनानी चाहिए तभी भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी और राज्य सरकार भी मजबूत एवं अच्छे तरीके से कार्य कर सकेगी एवं प्रदेश के किसानों को भी बीमा क्लेम की राशि का उचित भुगतान समय पर हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पर्चियां। श्री प्रताप लाल भील।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

गोगून्दा स्थित नेशनल हाईवे संख्या 27 पर आये दिन घटित दुर्घटनाएं

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 गुजरता है और इस नेशनल हाईवे के पास पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र को काटकर इस नेशनल हाईवे का निर्माण करवाया गया था। कई जगह उतार-चढ़ाव भी हैं, विकट मोड़ भी हैं और इस कारण से इस हाईवे पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं में कई लोगों की जानें भी गयी हैं और जान-माल का नुकसान भी होता है। मेरा निवेदन रहेगा कि इस हाईवे का नये सिरे से सर्वे करवाकर इसका निर्माण करवाया जाये। इसके साथ में 100 किलोमीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई ट्रोमा सेंटर भी नहीं है। कभी दुर्घटना हो जाती है तो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी को पार करते हुए जो भी एक्सीडेंट होता है तो उससे रास्ते में ही घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके लिये मेरा निवेदन रहेगा कि इस क्षेत्र में ट्रोमा सेंटर का निर्माण भी करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कोई जवाब देंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, यह बहुत ही गंभीर विषय है। आज जितनी चांस डेथ की आटोमोबाइल में है, उतना बीमारी से कम रहती है। माननीय सदस्य ने बताया है कि इनका जो क्षेत्र है वह एक तो पहाड़ी एरिया है, उसमें मोड़ बहुत ज्यादा हैं ढलान बहुत ज्यादा हैं और जो हैवी ट्रैफिक नेशनल हाईवे पर चलता है, उससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अभी पिछले छह महीने में करीबन 63 दुर्घटनाएं हुईं। मृतकों की संख्या 50 है और 37 लोग घायल हुए हैं। इसके अन्दर गृह विभाग आगे कार्यवाही कर रहा है और निर्देश दे रहे हैं कि रम्बल ब्रेकर्स और साइन बोर्ड हैं डार्क स्पाट के अन्दर और जो इंटरसेप्टर की गाड़ियां हैं, जितने भी उपाय हैं, इनमें सेफ्टी मेजर्स का प्रावधान किया है और NHAI को भी लैटर लिखा है कि आप इस रोड को ठीक करने की कार्यवाही करें। हमें आशा है कि शीघ्र कार्यवाही होगी और आपके यहां जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनकी संख्या कम होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा। आपका हो गया। इस पर चर्चा नहीं होती।

सराड़ा में 132 के.वी. जी.एस.एस. का शिथिल कार्य

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा में 132 के.वी. जी.एस.एस. 2017 में स्वीकृत हुआ, परन्तु पिछले 5 साल में उस सरकार ने कोई काम नहीं किया। न बड़ी लाइन खींची और शुरुआत में बाउण्ड्रीवाल के अन्दर यार्ड का काम भी शुरू नहीं किया। साथ ही 132 के.वी. जी.एस.एस. का जो ट्रांसफार्मर लगना था वह भी नहीं लगा, जिसकी वजह से काफी समस्या उस क्षेत्र में लाइट की बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि 400 के.वी.जी.एस.एस. 2012-13 में स्वीकृत हुआ। धारीवाल साहब, 12 वर्ष हो गए, लेकिन उदयपुर संभाग में, उदयपुर में 400 के.वी. का जो जी.एस.एस. लगना था, वह शुरू नहीं होने की वजह से, आपने शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के किसानों को ...(व्यवधान) बिजली की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बिजली मंत्रीजी भी विराजमान हैं, मैं चाहूंगा कि इस 132 के.वी.जी.एस.एस. को पूरी तरह से शुरू किया जाए और 400 के.वी.जी.एस.एस. जो उदयपुर में स्वीकृत है, उसको भी शुरू किया जाए। जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: श्री जेठानन्द व्यास। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं क्या? (व्यवधान) आप बैठिए, दो मिनट। (व्यवधान) जो जवाब देना चाहे उसको अनुमति है। मंत्री की इच्छा पर है, जवाब देना चाहें तो दे देंगे।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो 132 के.वी.जी.एस.एस. के बारे में पर्ची के माध्यम से उठाया है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अंतर्गत 132 के.वी. जी एस एस सराड़ा हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.08.2019 को जारी की गई थी तथा इसकी संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 31.08.2020 को जारी की गई। इसके टर्नकी माध्यम से निर्माण हेतु कार्यादेश दिनांक 17.05.2021 को जारी किया गया। धीमी गति से कार्य करने के कारण फर्म का कार्यादेश दिनांक 26.12.2022 को निरस्त कर दिया गया।

(श्री हीरालाल नागर)

वर्तमान में उक्त जी एस एस का शेष कार्य विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। जी.एस.एस. के सिविल कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 08.05.2023 को जारी कर मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य इलेक्ट्रिक कार्य हेतु दिनांक 03.03.2023 था जिसे 2024 तक करने का लक्ष्य किया गया है। उक्त जी.एस.एस. मार्च, 2025 तक स्थापित किया जाना लक्षित है। कार्य की वर्तमान स्थिति यह है कि लाइन का कार्य, स्टब सेटिंग, 29 में से 29 स्टब सेटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। सब स्टेशन कार्य, सिविल कार्य, कंट्रोल रूम का कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। 102 फाउण्डेशन में से 68 का कार्य पूर्ण हो चुका है। 20 फाउण्डेशन पर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य हो चुका है। ब्लास्टिंग की आवश्यकता है। ब्लास्टिंग की आवश्यकता होने पर अभी कार्य भी थोड़ा अपेक्षा से धीमी गति से चल रहा है। इस कारण उपकरण स्थापना में विलम्ब हो रहा है, लेकिन जो लक्ष्य 2025 का इसको चालू करने का दिया गया है, उस तक चालू कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 400 के.वी. उदयपुर का भी, जो स्वीकृत है, उसके बारे में भी प्रश्न उठाया है, उसको भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जेठानन्द व्यास।

बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा आमजन को कारित परेशानी

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि बीकानेर में मेरी जीत कांग्रेस को पच नहीं रही है। उसका कारण यह है कि वर्तमान में जो BKESL कम्पनी है ..(व्यवधान) बोलने दो पहले मुझे, फिर आप बोलना।

श्री अध्यक्ष: आप बोलें। आप सदस्य नये हैं, बोलने दो।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, BKESL जो कम्पनी है उसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं, कांग्रेस की पूर्व सरकार के जो मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार व उनके समर्थक वहां पर लगे हुए हैं।

(श्री जेठानन्द व्यास)

(व्यवधान) बी जे पी का राज आने के बाद वो लगातार मुझे, यानी पूरी जनता को डिस्टर्ब इसलिए कर रहे हैं कि जनता जेठानन्द का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे कि कांग्रेस के राज में लाइट नहीं जाती थी अब लगातार जा रही है, यह उनका पूरा प्रयास है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो पूरे राजस्थान में ही जा रही है। (व्यवधान)

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपका पूरा बोल रहा हूं, चिंता मत करो। (व्यवधान) आपके नेताजी ने, ठेके ले रखे उनके रिश्तेदारों ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हरिमोहनजी, बोलने दो इनको, वो आपको नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): ठेके ले रखे हैं इनके रिश्तेदारों ने BKESL कम्पनी में। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): गलत ले रखे हैं तो आप कार्यवाही करवाओ।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मैं बता रहा हूं, आप सुनिए अच्छे तरीके से। आप सुनने की हिम्मत रखिए।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए, आप जारी रखिए। आप बोलते रहो। (व्यवधान)

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): लगातार यह अव्यवस्था वो करने करने जा रहे हैं। एम ओ यू में हो रखा है कि जब एक घण्टा से ऊपर लाइट जाती है तो कम्पनी को जनरेटर के माध्यम से रोशनी देनी चाहिए, लेकिन BKESL कम्पनी अभी नहीं दे पा रही है। दस-दस घण्टे लाइट शहर में चली जाती है। फॉल्ट के नाम से मेरे पास इसमें कई ऐसे मैसेज आए हैं जिनके क्षेत्र में फॉल्ट नहीं होने के बावजूद भी वहां पर लाइट नहीं रहती है। (व्यवधान) आप पहले सुनिए, बीच में मत बोलिए।

श्री अध्यक्ष: आप इनको जवाब मत दो, आप इधर सम्बोधित करके बोलें।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि जो विजिलेंस की टीम जा रही है, जिस घर में केवल दो व्यक्ति रहते हैं, उनका सवेरे छह बजे मीटर उखाड़ कर ले जाते हैं। उसमें भी उनके आदमी शामिल हैं। फिर कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है। उसमें एक किलोवाट का कनेक्शन है और विजिलेंस में दो किलोवाट के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यह लगातार हो रहा है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि विजिलेंस जब होती है तो वहां सरकारी एक आदमी साथ होना चाहिए, तब यह सही होगा। लगातार हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह है कि कम्पनी को आप निर्देशित करें कि वो राजनीति नहीं करे और राजनीतिक लोग उसमें शामिल हैं उनको या तो हटाएं या उनको समझाएं कि वो आम जनता के साथ राजनीति नहीं करें। आप BKESL कम्पनी को यह बताएं। एम ओ यू पर अगर वो सही नहीं चल रही है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, लाइट आ नहीं रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह बहुत पुरानी बीमारी है। (व्यवधान) आप बोलिए, .. (व्यवधान) यह बहुत पुरानी बीमारी है। (व्यवधान) आप फिर खड़े हो गए? अबकी बार बिना अनुमति के खड़े हुए तब बाहर भेजूंगा। (व्यवधान) मतलब मेरे को हल्के में ले रहे हो? माननीय मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य ने बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड की फ्रेंचाइजी कम्पनी है, इसको पी पी पी मोड पर दिनांक 16 मई, 2017 से बीकानेर का फ्रेंचाइजी कार्य दिया हुआ है। आपने जो समस्या उठाई है कि वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से कर्मचारी लगे हुए हैं, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं और वहां पर जो लाइटों में व्यवधान आ रहा है, निश्चित रूप से इस कम्पनी को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है कि अपने कार्य में सुधार करे, दिनांक 11.07.2024 को नोटिस दिया गया। अगर फिर भी इसमें सुधार होने की संभावना नहीं हो और इसमें इस तरह से राजनीतिक दबाव से काम हो रहा है और कम्पनी ठीक से काम

(श्री हीरालाल नागर)

नहीं कर रही है, आपने जो प्रश्न उठाया है कि एक घण्टे बाद वहां पर जनरेटर की व्यवस्था से लाइट दी जानी चाहिए, निश्चित रूप से जो कमियां कम्पनी की हैं, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि एक कमेटी बनाकर उन सबकी जांच कराई जाएगी।

कम्पनी को अभी तक 2017 से निरन्तर जिस तरह का वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहिये था, जो सुविधाएं डवलप करनी चाहिये थीं, वे नहीं की हुई हैं तो कम्पनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। चारों जगह एक कम्पनी काम कर रही है। वह अजमेर में भी कर रही है, कोटा में भी कर रही है, भरतपुर में कर रही है, बीकानेर में कर रही है। चारों जगह उस कम्पनी की जांच करवाकर उसकी जो भी अनियमितताएं होंगी, उन पर रोक लगाएंगे और निश्चित रूप से जो भी कमी है, उसे दुरुस्त कराएंगे। कांग्रेस के राज में तो ये नहीं करा पाये। धारीवाल जी ने कहा था कि हम आएंगे तो पचास दिन में इस KEDL को कोटा से भगा देंगे, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, यह समस्या अजमेर में भी है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर का भी कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: अजमेर में भी टाटा पावर की बहुत अनियमितताएं हैं उसकी जरा जांच करवाइये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि आपने अजमेर का भी नाम ले लिया। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान में दिक्कत है। आप तो पूरे राजस्थान की ही जांच करा दें, कहां लाइन किस वजह से नहीं मिल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दें।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): पूरे राजस्थान में आपके कारनामों की जांच करा देंगे, आप प्रस्ताव दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक तंगी के चलते शिशुओं का व्यापार

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो समस्या पैदा हुई है और जो हालात पैदा हुए हैं मैं पूरे सदन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाये। हालात ये हैं कि बच्चों की खरीद-फरोख्त हो रही है और दिल्ली के दलाल आदिवासी क्षेत्रों में 20 हजार में खरीदकर 8 लाख में बेच रहे हैं। गर्भ में ही बच्चे का सौदा। लड़का हुआ तो 40 हजार और लड़की हुई तो कम। ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में बाहर से दलाल आकर पी एच सी और सी एच सी में जाकर ...(व्यवधान) आप सुन लीजिये, इसे राजनीतिक मोड़ क्यों देना चाहते हैं? (व्यवधान) जो हालात पैदा हुए हैं, वे शर्मनाक हैं। यहां तक कि घर खर्च को चलाने के लिए 6 दिन के बेटे को 7 हजार रुपये में बेचा गया। यहां तक भी है कि इन 8-9 महीनों में जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उसमें करीब 20 बच्चों को दलालों के द्वारा बेचा गया है। (व्यवधान) वहां का कलक्टर, वहां का एस पी, वहां का बी डी ओ, वहां के अधिकारी, वहां के जन-प्रतिनिधि क्या कर रहे थे, जब वहां ऐसे हालात हुए? यह पुलिस चुप क्यों थी? यह मानव तस्करी की यूनिट चुप क्यों थी? वहां काम करने वाले चुप क्यों थे? वहां पर जो प्रतिनिधि थे, जो पंचायत समिति में विकास अधिकारी बैठा था, जो आंगनबाड़ी केन्द्र में काम कर रहे थे, वे लोग चुप क्यों थे? (व्यवधान)

मैं भास्कर की इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम तक यह जानकारी पहुंचायी। एक बहुत ज्यादा शर्म की बात और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पांचों गांव जहां बच्चों की बिक्री ज्यादा हुई, ये माननीय मंत्री महोदय के विधान सभा क्षेत्र के हैं। (व्यवधान) यह और भी ज्यादा शर्म की बात है। जब समाचार मिल गये, कानूनी रूप से अपराध है, यहां तक कि मर्जी से भी हो तो कोई बच्चा तक अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसके लिए कानूनी प्रावधान है। उन कानूनी प्रावधानों को छोड़कर, उनसे अलग हटकर, चुपचाप दलाल उन बच्चे-बच्चियों को खरीदकर बेचने जा रहे थे। सरकार ने इस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया। अख़बार में होने के बाद भी माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान नहीं गया, अख़बार में छपने के बाद भी माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान नहीं गया।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने आदेश दिये, वे पूछ रहे हैं सरकार से कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने सीधा एक अख़बार के माध्यम से कॉग्निजेंस लेकर डी जी को लिखा कि इस बात का पता लगाइये। क्या सरकार के गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्य मंत्री जी का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद यह कर्तव्य नहीं था कि उन अधिकारियों को बुलाकर पूछें कि हमारे राज में यह क्या हो रहा है? इन नौ महीनों के अन्तराल में इस प्रकार की स्थितियां क्यों बनीं? यह विचारणीय प्रश्न आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। बेकारी आज इतनी है कि उन गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार के अभाव में अपने बच्चे-बच्चियों को बेचकर वे अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके और हमारे लिये क्या होगी?

इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में लिया जाना चाहिये। यह राजनीतिक समस्या नहीं है, लेकिन जो नौ महीने से राज चला रहे हैं, उन्हें नहीं दिख रहा है कि हमारे हालात क्या हैं? हमारा एस पी क्या कर रहा है? हमारे यहां दलाल क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं, हमारे यहां किस प्रकार की सौदागरी हो रही है और बच्चे-बच्चियों को बेचकर रोजाना गुजारा किया जा रहा है, क्या यह सरकार को नहीं दिखा? अख़बार में आने के बाद मानवाधिकार आयोग को तो दिखा, लेकिन आपको नहीं दिखा, मुख्य मंत्री जी को नहीं दिखा, मंत्री जी को नहीं दिखा। नहीं तो सीधा कॉग्निजेंस लेकर कहना चाहिये था कि हम इसकी जांच करवाएंगे। सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों धारण किये हुए हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको 2 मिनट दिये थे, 7 मिनट हो गये। विराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): साहब, आप सुनिये। आप अध्यक्ष हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, मैं सुन रहा हूं। बैठिये। अब अंकित नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सीनियर एम एल ए साहब ने जो बात उजागर की है कि आदिवासी क्षेत्र में गरीब माता-पिता अपने बच्चों को बेच रहे हैं, बहुत

(श्री गजेन्द्र सिंह)

दु:खद घटना है कि अब मां-बाप ही बच्चों को बेचने लग जाएं तो फिर पीछे क्या रह गया?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: उत्तर सुनिये। मैं उत्तर दिलवा रहा हूं, फिर भी बोल रहे हैं। आप बैठिये, अन्यथा उत्तर नहीं आयेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पलासिया और बाघपुरा पुलिस स्टेशन में 7 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 6 प्रकरण 2023 में दर्ज हुए और एक प्रकरण 2024 में दर्ज हुआ। इन सभी प्रकरणों की मेरे पास डिटेल्स हैं। 6 प्रकरण 2023 में दर्ज हुए और 2024 में खाली एक हुआ है। हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहे जो भी हो, इसमें काउंसलिंग की जरूरत है, एन जी ओ की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा समाज की जरूरत है। समाज के लोग मिलकर काम करेंगे, तभी ऐसे हादसे खतम होंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। मंत्री जी वहीं से आते हैं। मंत्री जी का भी बयान आया था, ज्यादा बच्चे पैदा करो। क्या इसलिए करवा रहे थे पैदा? इनके पिछले समय में भी आप वहां से विधायक थे। आज मंत्री हैं और ऐसी हालत हो गयी है। आप इसे पिछली सरकार या इस सरकार का कहकर नहीं बच सकते। आप तो दलालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, क्या एक्शन लेंगे और इस पर पिछले 7 दिनों में क्या एक्शन लिया? वह बताइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होती।

घोषणा

माननीय मंत्री, हरियाणा सरकार, श्री संजय सिंह द्वारा दीर्घा से सदन की कार्यवाही का अवलोकन

मुझे सदन को सूचित करना है कि आज हमारे बीच में श्री संजय सिंह, माननीय मंत्री, वन व पर्यावरण विभाग, हरियाणा अपने निजी सचिव के साथ हमारे मध्य सदन की कार्यवाही देख रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान के भी संजय जी हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, राजस्थान के भी संजय जी हैं।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही दो बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

आउटपुट बजट (वर्ष 2022-23) एवं आउटकम बजट (वर्ष 2023-24)

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। आउटपुट एवं आउटकम बजट। डॉ. मंजू बाघमार।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट बजट वर्ष 2022-23 एवं आउटकम बजट वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखती हूं।

अधिसूचना

वित्त (कर) विभाग

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। डॉ. मंजू बाघमार।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (कर) विभाग की 49 अधिसूचनाएं एवं वित्त (जीएण्डटी) विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-33, दिनांक 16.08.2023, जिसके द्वारा कुछ शर्तों के अधीन ईसीओज के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के लिए आरजीएसटी अधिनियम की धारा 24(9) के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एफडी/कर/2024-63, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 86 एवं

(डॉ. मंजू बाघमार)

87 के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एफडी/कर/2024-64, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (भाग-प्रथम) में संशोधन के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 69 के अन्तर्गत संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एफडी/कर/2024-65, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा भूमि कर के लम्बित मामलों के संबंध में एमनेस्टी योजना के संबंध में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 18 और 22 के तहत छूट प्रदान की गई है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एफडी/कर/2024-66, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के पट्टा अभिलेखों/पट्टों पर स्टाम्प शुल्क की दरों का सरलीकरण किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एफडी/कर/2024-67, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 एवं धारा 9-ए के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में रियायत तथा उस पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एफडी/कर/2024-68, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क और अन्य विविध शुल्क की दरों में सरलीकरण किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.2(28)एफडी/कर/2016-69, दिनांक 12.02.2024, जिसके द्वारा जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान क्षेत्र और खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना विशेष विनिधान क्षेत्र के लिए परियोजना भूमि के हस्तांतरण के संबंध में रीको द्वारा राजस्थान इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)एफडी/कर/2023-70, दिनांक 20.02.2024,

(डॉ. मंजू बाघमार)

जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अन्तर्गत उप रजिस्ट्रारों की नियुक्तियां दी गई हैं;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.2(4)एफडी/कर/2019-71, दिनांक 01.03.2024, जिसके द्वारा राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निष्पादित हस्तांतरण/लीज डीड या निजी व्यक्ति/संस्था द्वारा शहीद के आश्रितों के पक्ष में आवासीय फ्लैट/मकान के लिए निष्पादित उपहार डीड पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.12(7)एफडी/कर/2024-72 दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा निरसित अधिनियमों के लिए एमनेस्टी स्कीम, 2024 जारी की गई है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)एफडी/कर/2018-72, दिनांक 05.03.2024, जिसके द्वारा हुडको द्वारा आरडब्लूएसएससी के पक्ष में निष्पादित 3090.73 करोड़ रुपये के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-73, दिनांक 07.03.2024, जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 158 ए की उप धारा (2) के तहत सहमति के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझा करने की प्रणाली के रूप में "फ्रेक्शनलैस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफार्म" को अधिसूचित किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.12(3)एफडी/कर/2024-74, दिनांक 14.03.2024, जिसके द्वारा पेट्रोल और डीजल की वैट दर में कमी के लिए वैट अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-75, दिनांक 15.04.2024, जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 के तहत अधिसूचना संख्या एफ.12(1)एफडी/कर/2024-71 दिनांक 09.01.2024 के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा 01.04.2024 से 15.05.2024 तक बढ़ाई गयी है;

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)एफडी/कर/2009-73, दिनांक 26.06.2024, जिसके द्वारा आरआरवीपीएनएल/आरआरवीयूएनएल/डिस्कॉम द्वारा

(डॉ. मंजू बाघमार)

आबंटित या खरीदी गई भूमि पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

(17) अधिसूचना संख्याः प.4(2)वित्त/कर/2024-74, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत प्रतिफल के भाग के रूप में प्रभारित माल और सेवा कर की रकम पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है;

(18) अधिसूचना संख्याः प.4(2)वित्त/कर/2024-75, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत दो या अधिक कंपनियों के मध्य आमेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के आदेश से संबंधित हस्तांतरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से रियायत प्रदान की गई है;

(19) अधिसूचना संख्याः प.4(2)वित्त/कर/2024-76, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत कृषिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए विद्युत संयोजन उपलब्ध करवाये जाने के लिए निष्पादित करार पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट तथा अन्य प्रयोजनों के लिए निष्पादित विद्युत कनेक्शन के करार पर स्टाम्प डयूटी में रियायत प्रदान की गई है;

(20) अधिसूचना संख्याः प.4(2)वित्त/कर/2024-77, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित मध्यवर्ती दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(21) अधिसूचना संख्याः प.4(2)वित्त/कर/2024-78, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा प्राप्त करने के अधिकार के हस्तान्तरण विलेख पर स्टाम्प डयूटी में रियायत प्रदान की गई है;

(22) अधिसूचना संख्याः प.4(2)वित्त/कर/2024-79, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में

(डॉ. मंजू बाघमार)

पचास लाख रुपये तक के फ्लैट्स की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(23) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-80, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत चार तलों से अधिक बहुमंजिला भवनों की इकाई के 3 वर्ष की अवधि में निष्पादित पश्चातवर्ती हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(24) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-81, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 की उप-धारा (2) के तहत शहीद के आश्रितों के पक्ष में राज्य सरकार, नगरीय स्थानीय निकायों या अन्य सरकारी निकायों द्वारा फ्लैट या भवन के संबंध में निष्पादित हस्तान्तरण पत्र या लीज डीड या प्राइवेट व्यक्ति या संगठन द्वारा निष्पादित दान पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान की गई है;

(25) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-82, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9-क के तहत दस्तावेज के निष्पादन के दिनांक से कलेक्टर (मुद्रांक) के निर्णय से एक माह पश्चात की अवधि तक स्टाम्प शुल्क की रकम पर प्रभार्य ब्याज की छूट प्रदान की गई है;

(26) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-83, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 86 तथा 87 के तहत राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 57 में संशोधन किया गया है;

(27) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-84, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत एक ही ऋण के संबंध में निष्पादित दो या अधिक ऋण दस्तावेज में से मुख्य दस्तावेज को छोड़कर शेष लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है;

(28) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-85, दिनांक 10.07.2024,

(डॉ. मंजू बाघमार)

जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9-क के तहत बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है;

(29) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-86, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड) के अधीन करार या किसी करार के ज्ञापन और अनुच्छेद 44 के खण्ड (च) के अधीन मुख्तारनामे पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(30) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-87, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 की उप-धारा (1) एवं (2) एवं धारा 79 के तहत पंजीयन शुल्क व अन्य विविध शुल्कों के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/2024-68 दिनांक 08.02.2024 में संशोधन किया गया है;

(31) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-88, दिनांक 10.07.2024 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत 31 मार्च, 2004 से पूर्व निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(32) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-89, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के खण्ड (x) के तहत विभिन्न वृत्तों में नियुक्त समस्त उप-महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के प्रयोजनों के लिए कलक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है;

(33) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-90, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2 (82) वित्त/कर/2010-97, दिनांक 30.11.2010 को विखंडित किया गया है;

(34) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-91, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 69 की उप-

(डॉ. मंजू बाघमार)

धारा (2) के तहत राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 के खण्ड-1 के नियम 181 में संशोधन किया गया है;

(35) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-92, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 की उप-धारा (2) के तहत परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित व्यवस्थापन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस में रियायत प्रदान की गई है;

(36) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-93, दिनांक 10.07.2024 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 की उप-धारा (2) के तहत विभिन्न ऋण दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(37) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-94, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 की उप-धारा (2) के तहत परिवार के सदस्यों के मध्य उनके संयुक्त स्वामित्व की गैर-कृषिक सम्पत्तियों के विनिमय के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस में रियायत प्रदान की गई है;

(38) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2024-95, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 की उप-धारा (2) के तहत भूमि के स्वामी के पक्ष में जारी अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(39) अधिसूचना संख्या: प.12(26)वित्त/कर/2024-78, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा आबद्ध ऊर्जा संयंत्र द्वारा सहायक ऊर्जा उपभोग पर विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(40) अधिसूचना संख्या: प.12(26)वित्त/कर/2024-79, दिनांक 10.07.2024,

(डॉ. मंजू बाघमार)

जिसके द्वारा आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों द्वारा सहायक ऊर्जा उपभोग पर संदेय विद्युत शुल्क की रिबेट और ब्याज तथा शास्ति का अधित्यजन किया गया है;

(41) अधिसूचना संख्या: प.12(26)वित्त/कर/2024-80, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा फ्लाइंग ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन या एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन को एवियेशन टरबाइन फ्यूल के विक्रय पर दो प्रतिशत से अधिक के कर पर छूट प्रदान की गई है;

(42) अधिसूचना संख्या: प.12(26)वित्त/कर/2024-81, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा निरसित अधिनियमों से संबंधित एमनेस्टी स्कीम, 2024 दिनांक 08.02.2024 में संशोधन किया गया है;

(43) अधिसूचना संख्या: प.12(26)वित्त/कर/2024-82, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 एवं 54 के उप-नियम (1) का विद्यमान स्पष्टीकरण को हटाया गया है;

(44) अधिसूचना संख्या: प.12(26)वित्त/कर/2024-83, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर के विक्रय पर 20 प्रतिशत से अधिक संदेय कर से छूट प्रदान की गई है;

(45) अधिसूचना संख्या: प.6(179)/परि/कर/मु./2024/1, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप धारा (1)(ख) के अंतर्गत राज्य के परिवहन एवं गैर-परिवहन यानों पर देय एकबारीय कर का आरोपण युक्तिसंगत बनाया गया है;

(46) अधिसूचना संख्या: प.6(179)/परि/कर/मु./2024/2, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप धारा (1)(क)(ग) के अंतर्गत राज्य के यात्री यानों एवं अन्य राज्यों के अस्थाई/प्रतिहस्ताक्षरित परमिटों पर संचालित यात्री यानों पर देय मोटर वाहन कर का आरोपण युक्तिसंगत बनाया गया है;

(डॉ. मंजू बाघमार)

(47) अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2024/3, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप धारा (1)(क)(ग)(गग) के अंतर्गत राज्य के माल यानों एवं अन्य राज्यों के अस्थाई/प्रतिहस्ताक्षरित परमिटों पर संचालित माल यानों पर देय मोटर वाहन कर का आरोपण युक्तिसंगत बनाया गया है;

(48) अधिसूचना संख्या: प.6(179)/परि/कर/मु./2024/4, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 32 को प्रतिस्थापित किया गया है: एवं

(49) अधिसूचना संख्या: प.6(179)/परि/कर/मु./2024/5, दिनांक 10.07.2024, जिसके द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 200 की उपधारा (1) के अंतर्गत खान विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना की सूचना के आधार पर अतिभरण के प्रकरणों पर प्रशमन राशि में कमी की गई है।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017, दिनांक 28.02.2024, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8) एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017, दिनांक 20.06.2024, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8) एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017, दिनांक 03.07.2024, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8) एफडी/जीएफएण्डएआर/2011, दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रेमचन्द बैरवा।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(डॉ. प्रेम चन्द बैरवा)

अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.(6)(179)परि/कर/मु./2024-25/1, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत पुरानी बकाया एवं नष्ट हो चुके वाहनों हेतु शास्ति एवं ब्याज में छूट प्रदान की गई है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.(6)(179)परि/कर/मु./2024-25/2, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 200 की उप धारा (1) के अन्तर्गत खान विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना की सूचना के आधार पर अतिभरण के प्रकरणों पर प्रशमन राशि में छूट प्रदान की गई है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.(6)(179)परि/कर/मु./2024-25/3, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 211-क की उप धारा (2) के अन्तर्गत चालन अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र को स्मार्ट कार्ड के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिकली जारी किये जाने के संबंध में; एवं

(4) अधिसूचना संख्या: प.(6)(179)परि/कर/मु./2024-25/4, दिनांक 08.02.2024, जिसके द्वारा मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा में क्रियाशील यान की समाप्ति पर पुरानी बकाया हेतु बकाया कर पर शास्ति एवं ब्याज में छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय मंत्री। वे हैं नहीं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा-44 के अन्तर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 सदन की मेज रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमन्त मीणा।

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.1(7)राज-6/2024/01 दिनांक 07.3.2024, जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3(जी) के तहत राज्य सरकार द्वारा कतिपय अधिकारियों को ई.आर.सी.पी. परियोजना हेतु जिला कलक्टर की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं;

(2) अधिसूचना संख्या: प.6(14)राज-4/81पार्ट/07 दिनांक 18.06.2024, जिसके द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को भंग किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.1(04)राज-6/2024/08, दिनांक 24.06.2024, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम-9 में संशोधन किया गया है; एवं

(4) अधिसूचना संख्या: प.1(19)राज-6/2024/09 दिनांक 24.06.2024, जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3(जी) के तहत राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त, नाचणा को मुख्य नहर पीथेवाला पॉइंट 141 हेतु जिला कलक्टर की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (वर्ष 2023)

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2006 की धारा-44 के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2023 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्थान वित्त निगम के लेखे) (वर्ष 2022-23)

(1) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाड़ी के लेखा प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

(2) राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 66 (a) एवं 66(b) के अन्तर्गत भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी के लेखा प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2022-23)

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2022-23; एवं

साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

(4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2022-23)

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा।

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन। श्री जोगेश्वर गर्ग।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 4)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2024 को मध्याह्न पश्चात् 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2024 से मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2024 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई 2024 शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2024	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 13 जुलाई 2024 रविवार, दिनांक 14 जुलाई 2024	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 15 जुलाई 2024	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2024	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2024	बैठक नहीं होगी।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2024 शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2024 शनिवार, दिनांक 20 जुलाई 2024	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
रविवार, दिनांक 21 जुलाई 2024	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 22 जुलाई 2024 मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई 2024	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव करिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

घोषणा

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का आबंटन।

मुझे सदन को सूचित करना है कि परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं, विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

क्र.सं.	पार्टी/दल का नाम	आबंटित समय
1.	भारतीय जनता पार्टी	09 घण्टे 26 मिनट
2.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	05 घण्टे 25 मिनट
3	भारत आदिवासी पार्टी	15 मिनट

(श्री अध्यक्ष)

क्र.सं.	**पार्टी/दल का नाम**	**आबंटित समय**
4.	बहुजन समाज पार्टी	10 मिनट
5.	राष्ट्रीय लोकदल पार्टी	05 मिनट
6.	निर्दलीय	39 मिनट
	कुल आबंटित समय	**16 घण्टे**

सामान्य वाद-विवाद में राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ करने हेतु सूची में जो नाम आये हैं, सबसे पहले दीप्ति किरण माहेश्वरी शुरू करें।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर

सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

"कल हम सभी ने देखा 'सबका साथ-सबका विकास' वाला बजट,
हमारे राजस्थान के एक बेहतरीन भविष्य का अहसास वाला बजट।
एक ऐसा बजट, जो उन्नति के तमाम आधार लिखेगा,
एक बजट, जिसमें हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ दिखेगा।
एक बजट, जिसमें बांध, नहर और नल तक के वादे हैं,
एक बजट, जिसमें जन-समस्याओं के समाधान के इरादे हैं।
एक बजट, जिसमें बिजली, सोलर और जी एस एस के निर्माण समाये हैं,
जिसमें सड़क, पुल और एक्सप्रेस हाईवे के नये मार्ग बताये हैं।
सिर्फ सड़कें ही नहीं, पूरे यातायात पर हमारा ध्यान है,
मैट्रो और इतनी बसों की घोषणा, उसी का परिणाम है।
यह बजट बेहतर बनायेगा प्रदेश के हरेक बच्चे की शिक्षा,
यह बजट बेहतर बनायेगा, हरेक क्षेत्र की चिकित्सा।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

यह सरकार सुनिश्चित करेगी, सारे बेहतरीन उपाय,
देखना अब निखरेंगे ग्रामीण और शहरी निकाय।
उद्योगों ने भी सुनी होगी कल कुछ बेहतर की आहट,
जब टेक्सटाइल से मार्बल तक पहुंच रही थी राहत।
बजट में वोकल फोर लोकल को निखारने की बात थी,
बजट में धरोहरों और संस्कृतियों को संवारने की बात थी।
बजट में किसान एवं कृषि के उत्थान की बात थी,
बजट में पर्यावरण के एक महा-अभियान की बात थी।
कुलगुरु की पदवी में गुरु और शिष्य की बात थी,
बजट में खेलों में एक उज्ज्वल भविष्य की बात थी।
सिर्फ एक बजट नहीं पेश कर रही थी हमारी सरकार,
कल हम तो बना रहे थे, एक स्वर्णिम प्रदेश का आधार।
तो यकीन मानिये, जल्दी ही बेहतरीन परिणाम देखेंगे,
अगले पांच साल में हम सभी एक श्रेष्ठतम राजस्थान देखेंगे।
जी हां, कल का बजट बिलकुल एक श्रेष्ठतम राजस्थान की आधारशिला की तरह था,
जिसमें प्रत्येक शब्द इसकी नींव को मजबूत कर रहा था।
हमारे दस संकल्प हमारे दस मजबूत पिलर की तरह लग रहे थे,
जिन पर राजस्थान का निर्माण होगा।
एक ऐसा राजस्थान जिसमें किसान, महिला व युवा,
प्रत्येक वर्ग के लिए एक बेहतरीन जीवन होगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना यह उद्बोधन कुछ पंक्तियों के साथ इसलिये शुरू किया, क्योंकि इतना अच्छा बजट जिसके अन्दर कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहा। हर वर्ग के लिए सोचा गया। हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ इन्क्लूड किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता ने पिछले विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो जंगल राज था उससे मुक्ति पाकर भारतीय

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

जनता पार्टी को सरकार चलाने का जनादेश दिया। भारतीय जनता पार्टी यह विश्वास दिलाती है कि आने वाले पांच वर्षों में, जिस तरीके से पिछले पांच वर्षों में कुशासन हमारे इस प्रदेश में रहा उससे मुक्त करायेगी और विकसित राजस्थान की तरफ राजस्थान को बढ़ायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में भी भारतीय राजनीति में एक इतिहास रचा है। इस इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष जिसमें हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आदेश दिया है। एक युवा विधायक होने के नाते इस सदन में दूसरी बार जनता के प्यार की वजह से मैं आज यहां पर खड़ी होकर एक बात जरूर पूछना चाहूंगी हमारे विपक्ष में बैठे हुए ...(व्यवधान) मैं तो आदरणीय ही बोलूंगी पर हमारे विपक्ष में बैठे हुए साथीगण जिन्होंने बड़ी-बड़ी बातें कहीं संविधान को लेकर, बड़े-बड़े प्रश्न उठाये, संविधान को जिस तरीके से भ्रमित करने का, असत्य फैलाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी आते ही संविधान को बदल देगी। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी थी कि कांग्रेस की पार्टी थी जिन्होंने आपातकाल लगा कर संविधान का, सबसे पहले अगर संविधान को किसी ने कुचलने का काम किया है तो इनकी पार्टी ने किया है। आज ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं संविधान को सुरक्षा देने की, लेकिन यह वही पार्टी है जिसने संविधान को कदम-कदम पर सिर्फ कुचलने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी की विकास भरी सोच का नतीजा है कि पिछले दस वर्षों में भारत ने एक नया आयाम क्रियेट किया है। हम सब युवा पहले जब राजस्थान या जब भारत की बात आती थी तो जिस तरीके से विदेश के लोग हमारी तरफ नजरें उठा कर देखते थे, आज वो लोग हमारे को सम्मान की नजरों से देखते हैं और यह सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री मोदी जी के आयामों की वजह से हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बात कहना चाहूंगी कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि मैं जन-कल्याण को एक मजबूरी के रूप में नहीं बल्कि देश को सशक्त बनाने के माध्यम के रूप में देखता हूं और मोदी जी की गारन्टी पर पूरे देश को भरोसा था। इस वजह से तीसरी बार पूरे देश की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार भी सुशासन और जन-कल्याण की अवधारणा पर विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। हमारी उप मुख्य मंत्री महोदया एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने भी अपने बजट वक्तव्य में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, सस्टेनेबल डवलपमेंट, नीति निर्धारण की पहल और आमजन को राहत देने वाला बजट ही उनका लक्ष्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहूंगी कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से आखिरी बजट पेश किया गया था और इतनी सारी रेवड़ियां बांटने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया था, जनता ने उसी बात से समझ लिया था कि विकास से कोसों दूर है कांग्रेस की यह सरकार और अगर इस बजट को हम अच्छे से देखें तो हमें इसमें क्लियर पता चलता है कि सस्टेनेबल डवलपमेंट, स्किल डवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट, इस राज्य को किस तरीके से प्रगति पर पहुंचाया जाय, उसकी बात अगर किसी ने की है तो इस बजट में की है और वह हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले एक वर्ष में राजस्थान देखने जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन में जिस तरीके के काम हुए हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक सपना देखा कि हर घर में नल होना चाहिये, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जल जीवन मिशन के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया है, काम पूरा नहीं होने दिया है। पिछले पांच वर्षों का अगर डेटा निकाला जाये तो कांगेस की सरकार में बहुत सारी जगह जल जीवन मिशन के जो कार्य होने चाहिये थे, जिस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिये था वह एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी जगह इस तरह के केसेज आपको मिलेंगे। मैं मेरे राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहां पर तीन पंचायतें हैं कोटी, काबरा, खरबानिया, जिनमें सत्रह करोड़ रुपये की लागत से जल जीवन मिशन के द्वारा पानी पहुंचना चाहिये था, लेकिन आज दो साल बाद टेन्डर होने के बाद भी काम चालू नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मंत्री महोदय को, हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय को कि

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द चालू करवाने के आदेश भी दे दिये हैं और काम चालू होने के वर्क आर्डर भी अगले पन्द्रह दिन में जारी हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन में बहुत जगह इस तरीके के काम हुए कि बिना सोच डवलप किये पाइप लाइन बिछ गई। पिछले पांच वर्षों से जिस तरीके से पाइप लाइन का काम किया गया, मैं जानती हूं, मानती हूं इस बात को बहुत अच्छे से कि जनता ने तो सच्चाई देख ली थी और इसलिये अब उन्हें भरोसा है कि काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में करके दिखायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में जो बिन्दु लिखे थे, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहूंगी कि उस घोषणा पत्र के करीबन 45 बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है जिसमें आचार संहिता का भी समय देखा। जैसे ही सरकार बनी उसके दो महीने बाद आचार संहिता लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी करीबन 45 बिन्दुओं पर काम हो गये हैं। इनमें से अगर प्रमुखता से हम बात करें तो साढ़े चार सौ रुपये में एल पी जी सिलेन्डर निर्धन परिवारों की महिलाओं को उपलब्ध कराने का काम हमारी भजन लाल जी की सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को सम्मान निधि देने का काम, दो हजार रुपये बढ़ाने का काम, अब किसानों के खाते में सीधे आठ हजार रुपये की जो राशि दी गई है वह भजन लाल जी की सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 10,106 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर फसल ऋण को ब्याज मुक्त किया है। यह हमारी भजन लाल जी की सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, इतने कम समय में और यह कम समय में इसलिये बोल रही हूं क्योंकि 06 महीने के अन्दर करीबन तीन महीने तो आचार संहिता लगी रही, तीन लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में लायी गईं। यह कार्य हमारी सरकार ने करके दिखाया है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में महिला आरक्षण को तीस प्रतिशत से बढ़ा कर पचास प्रतिशत करने का काम हमारी भजन लाल जी की सरकार ने करके दिखाया है। सामाजिक सुरक्षा मासिक पेन्शन को बढ़ा कर एक हजार एक सौ पचास रुपये देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वह भारतीय

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों के मानदेय में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी अगर किसी ने की है तो हमारी इस सरकार ने की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने करीबन 53 हजार करोड़ की विभिन्न पेयजल योजनाओं की घोषणा की थी जिनमें से एक भी काम अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। यह काम कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है। करीबन 2,547 करोड़ रुपये के 759 कार्य आज तक धरातल पर नहीं आये। यह असत्य घोषणा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह पुरानी सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी असत्य घोषणाएं, थोथी घोषणाएं, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस सरकार करती आयी है, लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को आगे रखते हुए, प्राथमिकता देते हुए डवलपमेंट की बात करती है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने युवाओं को स्किल डवलपमेंट देने की बात कही। पिछली सरकार ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे हम। पिछली सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की तो बात की ही थी, उसके साथ-साथ हमें यह पेपर दिया था जिसके अन्दर करीबन 1 लाख 95 हजार 329 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट प्रपोज किये थे। इस प्रदेश के युवाओं ने सोचा कि अब हमें इन इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा रोजगार मिलेगा। पढ़े-लिखे युवाओं ने सोचा कि अब हमें राजस्थान से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने प्रदेश में अपने परिवारों के बीच में रह कर हम काम कर सकेंगे, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगी कि इन इन्वेस्टमेंट्स की घोषणा में से सिर्फ और सिर्फ 15 प्रतिशत एम.ओ.यूज. का इन्वेस्टमेंट्स आया है, वरना किसी भी इन्वेस्टमेंट की कोई बात यहां पर नहीं हुई है। इस तरीके के काम किये हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बात की स्किल डवलपमेंट की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वहां पर मार्बल इंडस्ट्री एक प्रमुख उद्योग है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमको मार्बल मंडी दी, जिसकी वजह से हमारे यहां उद्योग बढ़ेगा।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

मैं एक बात और कहूंगी कि जो आपने कालेजज की बात की है पॉलिटेक्निक कालेज, आई.टी.आई. कालेज, इन कालेजेज की वजह से मेरे यहां का युवा, इस प्रदेश का युवा अच्छी पढ़ाई कर के मार्बल इंडस्ट्रीज में, जहां पर आये दिन अलग-अलग जगहों पर लोगों की जरूरत होती है, वहां पर ये लोग आ सकेंगे और काम कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का युवा सम्मान की रोटी चाहता है। आज का युवा यह नहीं चाहता कि घर बैठे हमें कोई भत्ता मिले या हमें कोई बोले कि कोई बात नहीं आप काम मत करो, आपको हम घर पर ही देंगे। आज का युवा सम्मान से पढ़-लिख कर इस देश को आगे बढ़ाने की सोच से, हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की सोच से काम करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट की बात की। उन्होंने यह कहा कि इन युवाओं को हम अलग-अलग तरह की स्किल्स में अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे, जिसकी वजह से युवाओं को बेरोजगारी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और उनके लिये अलग-अलग नये आयाम खुलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और इस सदन में लाना चाहूंगी कि विकसित राजस्थान के जो 10 संकल्प हमने लिये हैं, उनमें पहला संकल्प है, जिसमें प्रदेश की 29,225 अरब रुपये की अर्थव्यवस्था की हमने बात कही है। इस बात के लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बजट के प्रारम्भ में ही अमृत काल में विकसित राजस्थान बनाने के लिये सरकार को और इस प्रदेश को इतनी अच्छी सोच दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पूरे सदन के सामने लाना चाहूंगी। जब हम ऋण की बात करते हैं जब हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं, वर्ष 1950-51 से वर्ष 2017-18 तक, अर्थात पिछले 67 वर्षों में राज्य सरकार के अगर कुल ऋण और अन्य दायित्व देखें तो वह करीबन 2,81,182 करोड़ रुपये था, जबकि गत कांग्रेस सरकार ने इन 67 वर्षों में लिये गये ऋण से भी अधिक ऋण लेकर केवल 5 वर्षों में ही इस ऋण का भार 2,89,463 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है। इस तरह से कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में ही राज्य को ऋण के भार में डुबो दिया। (व्यवधान) मेरे पास फैक्ट्स हैं। आई

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

कैन प्रोवाइड एट आन सदन। रोहित जी, सब चीजें आयेंगी। आप जब बोलते हैं तो मैं आपको टोकती नहीं हूं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि हम बजट पर चर्चा करें और आप अपने पाइंट्स अपने समय पर रखें।

(समय: 14.22 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इस तरीके के जो ऋण लिये गये हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश को कर्ज में डुबोने का काम पिछली सरकार ने किया है। वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट अनुमानों के अनुसार कुल ऋण एवं दायित्व 6,40,688 करोड़ 27 लाख रुपये होना अनुमानित है, जो जी.एस.डी.पी. का 35.97 प्रतिशत है। माननीय सभापति महोदय, गत कांग्रेस सरकार की अडॉप्ट फिस्कल पालिसी मेजर्स के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया था तथा राज्य को लगभग डैट ट्रेप की स्थिति में ला दिया था। हमारे पूर्व नेता, प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ जी ने भी यहां पर बोला था कि किस तरीके से आर.बी.आई. ने इस बात की आलोचना करते हुए सरकार को पत्र लिखा है कि आप इस तरीके से प्रदेश पर भार नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सरकार ने एक हॉलेस्टिक डवलपमेंट का विचार रखते हुए आज जो जी.एस.डी.पी. की वृद्धि की है, दिसम्बर, 2023 में जी.एस.डी.पी. की जो ग्रोथ रेट 11.58 परसेंट थी, जिसको बढ़ाकर तीन-चार महीनों में, मार्च, 2024 तक 12.56 कर दिया है। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने कम समय में इस ग्रोथ रेट में वृद्धि की है। इस बात के लिये आपका बहुत-बहुत आभार है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बात बिजली को लेकर हुई। इस बिजली के लिये भी मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लाना चाहूंगी। जब 2014-15 में हमारी वसुन्धरा जी की सरकार थी, तब हमने प्रोफिट में डिस्काम्स को छोड़ा था। पिछले पांच वर्षों में जिस तरीके से लोन नहीं लिया, इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप नहीं होने दिया, बिजली में कुछ भी नये आधार नहीं लाने दिये, उसके कारण से 2020-21 में डिस्कॉम पुन: घाटे की स्थिति में आ गया और टोटल एक्युमुलेटेड लॉस दिसम्बर, 2023 में 1,01,215 करोड़ रुपये था, जबकि 2018-19 में डिस्कॉम को करीबन 20,607 करोड़ रुपये राशि के साथ प्रोफिट में छोड़ा गया था। माननीय सभापति महोदय, इस तरीके का मिस मैनेजमेंट करते हुए जिस तरीके का भार डिस्कॉम को लेकर, हमारी विद्युत को

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

लेकर यह कांग्रेस सरकार छोड़ कर गई है। मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने कम समय में पीएस.यूज. से एम.ओ.यू. कर के नये आदेश जारी किये हैं, जिससे डिस्कॉम की आर्थिक स्थिति सुधर सके। हमारी सरकार राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। इसमें करीबन सवा दो लाख करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. किये जा चुके हैं। इन संशोधनों से प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये के नये निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। सौर ऊर्जा परियोजना के लिये भूमि आबंटन डी.एल.सी. दर के 7.5 प्रतिशत पर किया जा सकेगा। अब दो हैक्टेयर भूमि पर एक मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा का भी उत्पादन हो सकेगा। हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी की जो सोच है 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना', जिसमें 40 प्रतिशत सब्सिडी डोमेस्टिक यूजेज के लिये मिलेगी, मैं उसके लिये भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बिजली के मामले में लोगों को स्वावलम्बी बनाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें अलग-अलग विभागों में हुईं, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पालिसी की जो बात हमारे मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी मंत्री दिया जी ने रखी है, उन्होंने जो बात इस बजट में पेश की कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट पालिसी होगी, उनका जो एक KEY पाइंट है, जहां से वह अर्न कर सकते हैं, उसको हम प्रमोट करेंगे। जैसे कि मेरे राजसमन्द में टेराकोटा, बाड़मेर में ब्लॉक प्रिंटिंग, कोटा-डोरा की साड़ी के लिये जालौर, ऐसे अलग-अलग क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने की बात की है, मैं उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि अब राजस्थान में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पालिसी के माध्यम से उद्योग में नये आवाम स्थापित हो सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से युवा अटल केन्द्र, जो युवा इनोवेशन सेंटर्स रखे गये हैं, उसके लिये भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि करीबन 100 करोड़ रुपये के फंड्स आफ फंड से आईस्टार्ट फंड में 10 करोड़ रुपये की फंडिंग की जो सुविधा उपलब्ध कराई है, मैं उसके लिये भी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने यह सोचा कि युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और उसको जो इनिशियल मदद चाहिये, वह हमारी सरकार उसको प्रोवाइड करेगी।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में एक और बहुत बड़ी घोषणा जिसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, वह यह है कि जिस तरीके से टी.एस.पी. फंड को बढ़ा कर 1,500 कर दिया गया है, उसके लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगी। किस तरह से सामुदायिक पट्टों के द्वारा कम्युनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी, एग्रो फोरेस्ट्री, चरागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाये जायेंगे इससे टी.एस.पी. को आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सरकार ने किया है, उसके लिये भी मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि ये स्ट्रीट वेंडर्स पूरे दिन काम करके कहीं न कहीं यह सोचते हैं कि हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के द्वारा जिस तरीके से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में, कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स को आप लोगों ने सहायता दी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

बहुत सारी बातें महिला अपराधों के लिए भी की गयीं। हमने भी पिछली सरकार में इस मुद्दे को बहुत बार उठाया। पूरे देश में राजस्थान की महिलाएं असुरक्षित थीं, यह बहुत बार अलग-अलग पेपर्स, अलग-अलग के माध्यम से आया था। राजस्थान में जिस तरीके से अपराध फैला हुआ था, वह सबने देखा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने फंड्स देकर पुलिस के अन्दर 5 हजार 5 सौ नये पद दिये, जिससे कि स्टेट की सुरक्षा और बेहतर हो सकेगी। यह अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, हम काम करते हैं और काम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अपराधों की बात, साइबर क्राइम की बात, पेपर लीक, चोरी की बात इस सदन में बहुत बार उठी, लेकिन उसमें कोई भी काम नहीं किया गया। मैं मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना पदभार संभालते ही करीबन 100 से ज्यादा लोगों को पेपर लीक प्रकरण में जेल के अन्दर पहुंचाया। साइबर में जो धोखाधड़ी हो रही है, उसमें भी उन्होंने सुचारु रहकर बहुत सारे काम किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें, सब अलग-अलग कहते हैं कि हमने यह काम किया, लेकिन यह जो बजट पेश किया गया है, यह वाकई में हर-वे में हॉलिस्टिक बजट है, हर तरीके से सब जनों को सुविधा देने का

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

बजट है। मैं यह बात आपके माध्यम से वापस से इस सदन में कोट करना चाहूंगी कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी से शासन-सुशासन के सम्बन्ध में कहा था- 'हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है, हम सेवा का माइंडसेट लेकर आये हैं, हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है, हमने तुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण को अपना आधार बनाया है।' माननीय सभापति महोदय, इसके रहते जिस तरीके से रोड सेफ्टी की बात इस बजट में कही गयी है, जिस तरीके से रोड सेफ्टी के लिए अलग-अलग आयाम लिख गये हैं, उसका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात इस सदन के पटल पर रखना चाहूंगी कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक बड़ा अभियान, एक बड़ा मिशन 'हरियालो राजस्थान' के माध्यम से लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय करने का काम कराने की घोषणा की है, उसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे प्रधान मंत्री जी की सोच कि 'एक पेड़ अपनी मां के नाम' उस सोच को आगे बढ़ाते हुए, उस सोच से प्रेरणा लेते हुए यह काम राजस्थान में होगा और मेरे क्षेत्र में तो इस काम से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि माइनिंग एरिया होने की वजह से हमारे यहां पर हरियाली की जो कमी है, उसमें यह 'हरियालो राजस्थान' मदद करेगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में गिलूण्ड को तहसील बनाने का काम किया है, जिससे हमको उस एरिया में विकास के नये कार्य भी मिल पायेंगे। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि खारी फीडर की एक बड़ी डिमांड जो राजसमन्द ने देखी है, यहां के किसानों ने देखी है, उसके लिए आप लोगों ने डेढ़ सौ करोड़ रुपये की जो सहायता की है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, सड़क में, हम सब जानते हैं कि जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट नहीं होगा, किसी भी प्रदेश को सही रूप में डवलप नहीं किया जा सका है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो सोच, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने पूरे देश में रखी थी, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, हमारे प्रधान मंत्री जी की सोच को भी आगे बढ़ाते हुए जिस

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

तरीके से सड़क में और परिवहन में एक बड़े बजट की घोषणा की गयी है, उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में करीबन 6 सौ अरब रुपयों की लागत से 53 हजार किलोमीटर लम्बाई के सड़क नेटवर्क बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की जो घोषणा की गयी है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार देना चाहूंगी। 9 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रादेशिक राजमार्गों, सड़कों के साथ ही बाईपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज आदि के कार्य करवाने की जो घोषणा की गयी है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, बोलने को तो बहुत कुछ है क्योंकि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ मिला है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दिया गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में अपनी बात को समाप्त करते हुए एक ही बात कहूंगी कि

"पिछली सरकार ने प्रदेश को दिये थे बहुत सारे मर्ज,
अपराध, अत्याचार और राज्य पर बहुत सारा कर्ज।
प्रदेश में पूरे पांच साल तक चला सिर्फ अपराधी दौर,
पनप रहा था भू-माफिया, भ्रष्ट तंत्र और पेपर चोर।
अब जनता बेफिक्र रहे, बीत गया वो अपराधी दौर,
अब पकड़े जा रहे हैं, पेपरबाज, हुए सरेण्डर साइबर चोर।
क्योंकि अब उन सभी मर्ज का इलाज तय है,
राजस्थान के नव-निर्माण का आगाज तय है।
अब राजस्थान का सदा सतत आगे बढ़ना तय है,
हमारे राजस्थान का विकास के आयाम गढ़ना तय है।"

जय जय राजस्थान। जय जय श्री राम।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को आम बजट पढ़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं

(श्री रोहित बौहरा)

कि 21 साल बाद किसी वित्त मंत्री ने इस सदन में बजट पढ़ा। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली भी समझता हूं कि मेरी पार्टी से आज पहले बोलने का मौका दिया, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आयी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह बजट लाने की इतनी जल्दी क्या थी? हम वेट क्यों नहीं कर सकते थे कि सेंट्रल बजट आये, उसके बाद हम अपना बजट लेकर आयें। आपको पता है कि पिछली बार एक तारीख को सेंटर का बजट आया था तो हमने 10 फरवरी को बजट पेश किया था। आज यदि वे जे जे एम जैसी स्कीम ला दें और वे स्टेट को कहें कि 45 हजार करोड़ रुपये आपको जे जे एम जैसी या कोई हाईवे की स्कीम में लेकर आना है तो आप कहां से देंगे? आप किधर से अकाउंट फोर करेंगे? यह आपने सोचा है? इतनी क्या जल्दी है? यह बजट लाने की इतनी क्या जल्दी थी? आपको वेट करना चाहिए था। राजस्थान में कोई गुजरात या हरियाणा का हाल थोड़े ही होने वाला है जो इतनी जल्दी थी? कोई हटाये थोड़े ही जा रहे थे, जो इतनी जल्दी थी आपको यह समझना चाहिए कि पहले देश का बजट आये, फिर राज्य का बजट आये। नहीं तो आपकी आधी चीजें अकाउंट फोर ही होंगी।

बजट आम आदमी की इच्छाओं और अपेक्षाओं का दर्पण होता है। सरकार की नीति, रीति की झलक उसमें दिखायी देती है, लेकिन मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की कोई रीति-नीति नहीं है, कोई इच्छाशक्ति नहीं है और राजस्थान के विकास के लिए वे कुछ नहीं करना चाहते हैं। यह बजट दिशाहीन है। आम आदमी को इस बजट के बाद गहरी निराशा हुई है। इस बजट में न तो किसानों का दुख-दर्द समझा गया, न गरीब, मजदूर, आदिवासी, बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को समझा गया। हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहा है। संकल्प-पत्र में आप यह कहते हैं कि हमने 45 बिन्दुओं पर अपनी घोषणाएं पूरी कर दीं। 45 विषयों पर, मैं संकल्प पत्र की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) या तो आप बोल लें, मैं बैठ जाता हूं। यह परसेंट नहीं है 45 लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह पढ़ लें और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने 45 परसेंट। क्या सही है? या तो मुख्य मंत्री जी सही हैं या यह बजट सही है। क्या सही है? '45 बिन्दु' सही हैं या '45 परसेंट' सही है? यह डिसाइड करना आपका काम है। आप डिसाइड करके इसका जवाब दे दीजियेगा। जब आप उत्तर दें तो मुझे इसका जवाब दे दीजियेगा।

(श्री रोहित बौहरा)

जब अपन स्टेट बजट की बात करते हैं। स्टेट बजट को अपन जब भी देखेंगे, उसको सेंट्रल बजट से देखना पड़ेगा, क्योंकि 46 परसेंट की रेवेन्यू जो आती है, वह जी एस टी के थ्रू आती है और जी एस टी को कौन कंट्रोल करता है? जी एस टी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका उसमें कोई लेना-देना नहीं है। जब से जी एस टी आयी है। (व्यवधान) मंत्री जी, आप चुप रहो, आपको मंत्री बनवा देंगे, आप चिन्ता मत करो। आप चुप रहो और सुनो। आपका थोड़ा फायदा ही होगा। इसलिए कह रहा हूं, आप समझेंगे, तब समझ में आयेगा न। आज आपको यह समझना होगा कि जी एस टी में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। न तो हम रेट चेंज कर सकते हैं, न हम कोई अमेंडमेंट ला सकते हैं, हम जी एस टी में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी स्टेट की सॉवरनिटी खतम हो गयी है, जी एस टी आने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज यदि हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पिछली बार जो बजट दिए थे, आप सबको पता है, देश किन मुश्किलों के दौर से इस वक्त गुजर रहा है। 2014 में हमारी सरकार गयी, तब हम 55 लाख करोड़ का लोन छोड़कर गये थे इस कंट्री के ऊपर और 31 मार्च, 2024 को जब नया फिगर आपकी सरकार ने दिया तो आपने कर्ज का बोझ 1 लाख 68 हजार करोड़ कर दिया। मतलब दस साल में आपने 112 करोड़ का लोन लिया। मेरे से पुरानी वक्ता कह रही थीं कि 1 लाख 12 हजार करोड़, 112, जो दस साल में किया और हम लोगों ने 70 साल में 55 लाख करोड़ किया। क्या किया उस पैसे का? आपको पता है सभापति महोदय, क्या होता है? हर साल आपकी सेन्ट्रल गवर्नमेंट 17 लाख से 18 लाख करोड़ का कर्ज ले रही है, कोरोना के बाद। प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है। बाजार से पैसा ही नहीं मिलता, क्योंकि सब बांड्स इश्यू हो जाते हैं। बांड्स में इतना अच्छा रिटर्न है कि लोग-बाग बाजार से पैसा ही नहीं उठा पा रहे। नये उद्योग नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी है।

अब आप देखिए, हमारे पास एन डी ए की सरकार जब थी, तब ये सब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज हंगर इंडेक्स ले लीजिए। 125 देश हैं, उसमें हमारा स्थान क्या है हंगर इंडेक्स में? 111वां। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी नीचे हैं। क्या हमारी स्थिति है? एक जमाने में हमारा देश कहलाता था 'सोने की चिड़िया' ये 'सोने की चिड़िया' का हाल

(श्री रोहित बौहरा)

आपने ऐसा कर दिया कि आपको पता ही नहीं पड़ा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आज भुखमरी की सिचुएशन लाकर रख दी आपने। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि एन डी ए सरकार जब दस साल रूल कर रही है तो आपकी बेरोजगारी दर 8.9 परसेंट है।

श्री सभापति: शांति रखिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, जब दीप्ति जी बोलीं, हम कोई नहीं बोले। अगर ऐसा होगा तो फिर हम एक को भी नहीं बोलने देंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको ये पता होना चाहिए अन-एम्प्लायमेंट की दर, इन दस सालों में, जब हम कम्पेयर करते हैं एन डी ए और यू पी ए की सरकारों को, आपकी दर, दर की बात कर रहा हूं, वह 4 परसेंट बढ़ गयी है, 4 परसेंट। हरियाणा ऐसा राज्य है, जहां पर करीब-करीब 30 परसेंट अन-एम्प्लायमेंट है, जहां पर इनकी सरकार है। 30 परसेंट और भारत में यदि सबसे हाईएस्ट अन-एम्प्लायमेंट यदि कहीं है तो वह हरियाणा के अन्दर है।

आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि एक परसेंट लोग, इस भारत में एक परसेंट लोग 80 परसेंट वेल्थ अपने पास रखते हैं। एक परसेंट लोग 70 परसेंट वेल्थ का जनरेशन कर रहे हैं, सिर्फ एक परसेंट लोग। ज्यादा नहीं कर रहे। जो 70 करोड़ की जनता है, उनकी आमदनी के अन्दर एक परसेंट से इजाफा होता है। 70 करोड़ लोगों का इजाफा सिर्फ एक परसेंट होता है। ये हाल है इनका। बड़ी-बड़ी बातें, मोदी की गारंटी, इसकी गारंटी, बड़ी-बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप ये देखिए, इन्फ्लेशन को भी आप बीट नहीं कर पा रहे हैं। आपका इन्फ्लेशन है साढ़े छह परसेंट और आपकी तादाद क्या है? 70 करोड़ जनता क्या कमा रही है? एक परसेंट ज्यादा कमा रही है। वह इन्फ्लेशन से भी कम कमा रही है। इसका मतलब, जो अमीर हैं वे अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं, वे गरीब होते जा रहे हैं। यह हाल है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। सिर्फ हमें नारे लगाने हैं। नारे लगाने से कुछ नहीं होता। इसलिए वह 6 महीने में बता दिया कि 44 परसेंट सीट किसी ने जीती तो राजस्थान में यू पी ए की सरकार, एन डी ए ब्लाक ने जीती। ये इसी का नतीजा है।

(श्री रोहित बौहरा)

आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि जितने स्टार्ट-अप्स हैं, जो भी डाले गये हैं, 30 हजार लोगों ने इन स्टार्ट-अप्स में नौकरी खो दी है, एक साल के अन्दर। 25 हजार लोगों ने टी सी एस, इन्फोसिस और जितनी कंपनियां हैं, उनमें 25 हजार नौकरियां गयी हैं लास्ट सिक्स मंथ्स के अन्दर। कहां जाएगा ये देश? हम क्या बेरोजगारों का देश बनाना चाहते हैं? 3 हजार कंपनियों ने एक साल के अन्दर अपने आफिसेज बंद कर दिये और विदेशों में वापस चली गयीं। नाम चाहते हैं तो मैं नाम भी दे सकता हूं। हैंकल चली गयी, हार्ले डेविडसन चली गयी, फोर्ड मोटर कंपनी ने अपना प्रोडक्शन यहां बंद कर दिया। क्या करना चाहते हैं? स्वरोजगार ऐसे ही बढ़ेगा? बिलकुल ऐसे ही बढ़ेगा।

इसी तरह से आपने अनाउंस किया था दस साल पहले कि हम 2022 तक हर आदमी को जिसको भी मकान चाहिए, हम हर आदमी को मकान दे देंगे 2022 तक। क्या हुआ? दे दिए? आपको वापस दो करोड़ हाउसेज बनाने का एलान करना पड़ा लास्ट ईयर अपने बजट के अन्दर। क्यों किया? बन गये थे मकान। वह तो बन गये थे मकान। दो करोड़ लोगों को आपको वापस देना पड़ा, क्योंकि वे मकानों से वंचित थे।

इसी तरह से आपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट दस साल पहले अनाउंस किये। दस साल पहले आपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट अनाउंस किये। क्या हुआ? The Smart City projects have not taken any shape till so far! अभी तक सिर्फ 93 परसेंट उनमें काम हुआ है। अभी-भी 7 परसेंट में काम बचा हुआ है और केन्द्र सरकार ने एक साल उनकी मियाद और बढ़ा दी है। अब आप ये सोच लीजिए, जो दस साल से प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए, उनकी कोस्टिंग कितनी बढ़ गयी होगी? वह कोस्टिंग का भार किसके ऊपर आया होगा? या तो काम कम हुआ होगा या सरकार ने अपनी डी पी आर को चैंज किया। ये सब आपके सोचने की बात है और आप इस पर खुद सोच सकते हैं।

आज हमारे स्टेट बजट की बात मैं शुरू करता हूं, क्योंकि आपके समझ में नहीं आयेगी इसलिए आप हंसिए। जो मुझे कहना था, वह मैंने कह दिया। आपने पहली बार, कोरोना के टाइम पर भी 70 हजार करोड़ का हमने डेफिसिट नहीं किया था। जब हमारी आन रेवेन्यू आलमोस्ट 30 परसेंट हो गयी थी। आज की डेट में हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। टार्गेट जितने हों, उतनी नहीं बढ़ी, परंतु फिर भी 5 से 7 परसेंट हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। 70 हजार करोड़ का पहली

(श्री रोहित बौहरा)

बार किसी ने बजट दिया है, जो डेफिसिट में बजट है। यदि आप इसको पांच साल लें तो ये हो जाएगा साढ़े तीन लाख करोड़ और इन्फ्लेशन और काउंट कर लेना तो ये आपका लोस होगा 3 लाख 75 हजार करोड़। कभी सोचा था 3 लाख 75 हजार करोड़ का मतलब क्या है? राजस्थान के हर आदमी को अपनी जेब से 50 हजार रुपये देने पड़ेंगे इन पांच सालों में। यह हाल आपने किया है पहले बजट के अन्दर।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आप क्या हाल छोड़ कर गये थे?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको वह भी बता देता हूं। मंत्री जी, बैठिए, I am even coming to that point. आप भी पहले उस कैबिनेट के पार्ट थे, वह भी मैं बोल रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए। I am covering each and every point. जब हम छोड़कर गये थे 2014 में सरकार, 2013-14 एक ही बात है। 2013 में जब हम छोड़कर गये थे तो 1 लाख 29 हजार करोड़ का हम लोन छोड़कर गये। ठीक है। आज जब छोड़कर गये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उस पर 90 हजार करोड़ बिजली का और जोड़ लीजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): उस पर नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उदय योजना में हमने 62 करोड़ लिये हैं ... (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, ये बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनका बोलने का नम्बर आए तब ये जवाब दे देंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति जी, या तो आप इधर से आंखें मूंद कर लो। आपको कुछ बोलना ही नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, बोलना है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): फिर अगले भी बोलना शुरू हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे?

श्री सभापति: आप तो बोलिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): उदय योजना में हमने 1 लाख 10 हजार करोड़ की गारंटीज दी हैं, are you aware of it? This is 7.8 per cent of GDP and separate from this budget. You are talking about other liabilities and even you are not aware. आप बजट पढ़ो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप भी उधर नहीं, यहां बताओ।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): वह बोल रहे हैं तो मैं उनका जवाब दे रहा हूं। 2018-19 में जब हमें सरकार मिली, ये 3 लाख 9 हजार 385 करोड़ का लोन छोड़कर गए थे। मतलब इन्होंने पांच साल में 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये तो लोन लिया था, 62 हजार करोड़ इन्होंने उदय योजना में लिए थे, जिसकी इन्होंने गारंटीज दीं, मतलब 1.80 और 62 मिलाकर 2.42 लाख करोड़ हो गए। हमने इन पांच साल में यदि इन्फ्लेशन काउंट करते हैं तो क्या कर दिया? 2 लाख 70 हजार करोड़ ले लिया। अब आप क्या करके जाओगे वह मैंने आपको बता दिया, 3 लाख 75 हजार करोड़ करके जाओगे। बोलने से कुछ नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो रखे हुए हैं। यह बहुत अच्छा किया, एक तरफ तो आपके पास पैसा नहीं है, सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, डेफिसिट में 70 हजार करोड़ लेंगे। आपने अभी क्या किया? कैप्टिव पॉवर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो 60 पैसे प्रति यूनिट आती थी, वह आपने खतम कर दी। सभापति महोदय, ऐसा खेल हुआ, अगर आप उस लाइन को पढ़ो, यदि मेरी आउटस्टैंडिंग है तो उसमें केवल 10 हजार जमा कराओ और आउटस्टैंडिंग क्लियर। कितना बड़ा खेला किया है इस सरकार ने? किसी को पता नहीं है। कितना बड़ा खेला हुआ है? किसी को पता नहीं है। पूरी आउट स्टेंडिंग दस परसेंट में, कौनसी एमनेस्टी स्कीम थी? Did you announce that Amnesty Scheme? एमनेस्टी स्कीम अनाउंस नहीं हुई और उससे पहले दस परसेंट में आपने सब तो यह हाल किया है। तो यह खेला हो रहा है राजस्थान में बैठे-बैठे। बड़ी-बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है।

साहब, एक बहुत अच्छी छूट दी। क्या कहा कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स कराओगे रजिस्ट्रेशन में तो आपको हम छूट देंगे। यानी लोन डॉक्यूमेंट के अलावा हम छूट देंगे। मुझे भी लगा कि यह बहुत बड़ी छूट होगी, अपने को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। पता लगा कि लोन डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो 0.25 परसेंट की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। सभी बैंक लेंगे, उस पर आपने कोई चेंज नहीं किया। उसके अलावा जो पेपर लगते हैं, 100 रुपये का तो गारंटर का पेपर लगता है और 100 रुपये का जो आदमी लोन लेता है उसका पेपर लगता है, मतलब एक आदमी के लिए 200 रुपये की छूट हो गई। यदि मैं एक करोड़ का लोन लूंगा तो 200 रुपये उसमें क्या मायने रखते हैं? 'ऊंट के मुंह में जीरा' कहने में भी हमें शर्म आनी चाहिए। अपन क्या बात कर रहे हैं, किसको छलावा दे रहे हैं? यह ड्रेसिंग की है, कहते

(श्री रोहित बौहरा)

हैं न विण्डो ड्रेसिंग। ऐसी ड्रेसिंग की है, बहुत शानदार ड्रेसिंग की है। आपने पेट्रोल-डीजल पर वैट 2 परसेंट किया, क्यों कम किया? क्योंकि आपको लगता था कि हमें प्राइस इक्वेलाइजेशन करना है। गंगानगर में एक रेट है, भरतपुर में एक रेट है, जयपुर में एक रेट है। आज भी भरतपुर और गंगानगर में करीब -करीब 1 रुपये 90 पैसे का डिफरेंस है। यह आपके अफसर आपको सिखा रहे हैं, आपका वैट कम करना दिखा रहे हैं कि यह वैट कम हुआ। यू पी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से आपकी रेट अभी भी ज्यादा है। आज भी ज्यादा है। यह मोदी जी की गांरटी थी, आप पढ़ लेना। आपने क्या किया? न ही प्राइस इक्वेलाइजेशन हुआ, न आपकी प्राइस दूसरे राज्यों से कम हुई, तो क्या फायदा हुआ? वाह, क्या जबरदस्त किया है।

एक बहुत अच्छा काम किया जिसकी मैं भी तारीफ करता हूं। ज्वाइंट फैमिली की आपने एक्सचेंज डीड करवाई, वह बहुत अच्छा काम है, उसमें ज्वाइंट फैमिली के सब झगड़े खतम होते हैं। आपने 6 परसेंट से 2 परसेंट कम किया, उसके लिए मैं भी मेज़ थपथपाता हूं कि बहुत अच्छा काम किया। जो अच्छा काम है उसके लिए मैं आपकी बुराई नहीं करता, बट जो अच्छा काम नहीं है, वह तो आपको सुनना पड़ेगा।

अब आप आइये, स्टेट की आन टैक्स रेवेन्यू पर। जी एस टी सबसे बड़ा कम्पोनेंट है, उसको ले लेते हैं। जी एस टी में जब भी हमने बजट में जो भी फिगर दिए हैं, आज तक वे फिगर कभी पूरे नहीं किए। कभी भी पूरे नहीं किये फोर लास्ट टेन ईयर्स आपने जो भी जी एस टी के फिगर दिए या पहले वैट था, आपने जो भी बजट किया, आज तक कभी पूरे नहीं किये। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं 2020-21, we were down 15 per cent. In the year 2022-23, we were down 9 per cent and, in the year 2023-24, we were down minus (-) 2 per cent. इस साल आपने ग्रोथ क्या ले ली, नॉमिनल मैं रियल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं। रियल और नॉमिनल टर्म्स में डिफरेंस होता है। नॉमिनल टर्म्स आपने इन्क्रीज लिया है 16 परसेंट का, जो कि नेशनल एवरेज भी नहीं है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने, बजट भाषण में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, there will be an increase of 10.5 per cent. They have taken an average of 10.5 per cent, but we are saying it '16 per cent.' एक तो यह फिगर आपका गलत होना ही होना है।

(श्री रोहित बौहरा)

इसी तरह एक्साइज का। आपकी दुकानें तो उठी ही नहीं। जुलाई तक नहीं उठीं, आपने पुरानी दुकानों को ही चलाया, उनसे ली। लोग-बाग़ मेन सीजन में पैसा कमाकर, दुकान बंद करके चले गए। अब आपको डिस्काउंट में करना था, जो आपने 17 हजार 100 करोड़ किया है उसमें आपको मुश्किल से 15 हजार करोड़ की रेवेन्यू भी नहीं आएगी, तो आपके लोसेज और बढ़ते जाएंगे। आपने वैट पहले दो परसेंट कम कर दिया। सी एन जी और पी एन जी में अभी आपने वैट कम कर दिया। टर्बाइन फ्यूल में तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे तब आप करोगे, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी आपकी रेवेन्यू कम होगी।

व्हीकल्स की रेवेन्यू इसलिए कम होगी कि आज पूरे देश में आल डीलर्स, यह बड़ा आर्टिकल था इकॉनामिक टाइम्स में, all car dealers throughout India are carrying vehicles worth Rs. 44,000 crore. हमें पहले एकदम गाड़ियां नहीं मिलती थीं, गाड़ियों का वेट करना पड़ता था, गाड़ियां फ्री अवेलेबल हैं, डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं, गाड़ियों की बिक्री होना कम हो गई तो टैक्सेज ऑन व्हीकल है वह भी कम मिलेगा।

फिर आता है, taxes on duties of electricity. वह खेला तो आपने कर ही दिया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर तो खेल हो ही गया, कैप्टिव पावर प्लान्ट्स का, जो मैग्जिमम ड्यूटी आती थी वह तो इन्होंने खेल कर ही लिया। खेला हो गया। मेरा सिर्फ यह कहना है कि आपने जो फिगर्स दिए हैं, आन टैक्स रेवेन्यू के फिगर्स आपने दिए हैं, मैंने एक-एक को आपके सामने पढ़कर बता दिया कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। फिर क्या होगा? रिवाइज बजट आएगा, आप फिर रिवाइज बजट में सेटिंग करोगे कि रिवाइज बजट में यह-यह कम हो गया, यह-यह ज्यादा हो गया और इतना खर्चा कम हो गया।

हमारा पिछली बार का कैपिटल आउट-ले 38 हजार करोड़ का था। दिसम्बर में जब हम गए तब तक हम 32-33 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुके थे। तीन महीने जब इनके थे तो इनका वह फिगर 34 हजार करोड़ पर रुक गया। पी डब्ल्यू डी, जल जीवन मिशन, जितने ठेकेदार हैं 6-6 महीने से पैसा नहीं पा रहे हैं। ट्रेजरी बंद पड़ी हैं। इसी तरीके से आपने नगरपालिकाओं में पुराने एम.एल.एज. को रोड्स ठीक कराने के लिए पैसा दिया था, उनमें पिछले साल का सिर्फ 45 परसेंट तक पैसा आया है। नाबार्ड ने आपको पैसा

(श्री रोहित बौहरा)

रिलीज नहीं किया। वह पैसा क्यों नहीं रिलीज हुआ रूडसिको का? वह तो नाबार्ड का लोन था, वह पैसा तो रिलीज होना था। आपकी सरकार ने वेज एंड मीन्स में से अपने को निकालने के लिए वह पैसा आपने अपने आप यूज कर लिया। इधर अपन बात कर रहे हैं घोषणा कर दो 44 हजार करोड़ की। घोषणा तो हो जाएगी, चुकाओगे कहां से? लेंगे कहां से? आपकी एफ आर बी एम लिमिट में आप लेंगे कहां से? साढ़े तीन परसेंट आपकी एफ आर बी एम लिमिट है। आप उसको क्रोस कर रहे हो, आपको कौन पैसे देने वाला है?

साहब, एक बहुत जबरदस्त बात है। यह लोन खड़ा है वह तो खड़ा ही है। सरकार ने पिछले सालों में...(व्यवधान) मैडम आप बोलते हो तो मैं नहीं बोलता न, आप सुनो। आपको अपना टाइम मिलेगा, आप कंट्राडिक्ट करो न।

(समय: 15.00 बजे)

No one stops you. एक लाख दस हजार करोड़ की आपने गारंटीज कैसे दे दीं? Who's responsible? जिस दिन आपकी गारंटीज रिटर्न होना शुरू हो गईं तो 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपया और घुस जायेगा तो आप कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? क्योंकि वह तो हाल होने वाला ही है न। जब आपने रेवेन्यू पर, एक पैसे की रेवेन्यू नहीं बढ़ाई है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सर, मुझे टाइम लगेगा।

श्री सभापति: 30 मिनट की आपके दल की व्यवस्था है, आप पांच मिनट में समाप्त करें। आप पांच मिनट में कन्क्लूड करें। आपके दल ने यहां पर लिख रखा है, आपके प्रतिपक्ष के नेता ने।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मेरे को टाइम लगेगा, आप बात कर लें।

इश्यू यह है कि आपने यह सब कर लिया। इसी तरह से आपने 9 हजार करोड़ रुपये की रोड्स सैंक्शन की है कि रोड्स बनेंगी, आर.यू.बी. बनेंगे, आर.ओ.बी. बनाएंगे तो यह बहुत अच्छी बात है। उसकी विंडो ड्रेसिंग क्या करी? हजार करोड़ रुपये जो आपको मिलने थे सी.आर.एफ. में, वे रोड्स भी उसमें आपने डाल दीं और 953 करोड़ रुपये की जो पी.एम.जी.एस.वाई. की रोड्स हैं, वे भी इसमें चली गईं तो बजट कितना बड़ा हो गया? 9 हजार करोड़ रुपये की रोड्स दे रहे हैं और दिया कितना? 7 हजार करोड़। सेंटर का पैसा

(श्री रोहित बौहरा)

और गुड़ अपन खा रहे हैं। पैसा किसी का है और गुड़ अपन खा रहे हैं, यह आपका बजट का पार्ट नहीं बनता है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि विंडो ड्रेसिंग मत करिये बजट में। This is not a part of the budget. टेबल कर दिया न तो दिक्कत आ जायेगी। This is not a part of this budget. Are you spending money? No. You are not spending money. This is a grant-in-aid from the Central Government!

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आप भी यही करते थे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमने नहीं किया है। सी.आर.एफ. की एक रोड नहीं डाली हमने कभी भी। मंत्रीजी, नहीं डाली। आप चैक कर लें। (व्यवधान)

एक मैं यह भी चाहता हूं कि जब भी इसका जवाब आये, हमारी वित्त मंत्रीजी जब भी जवाब दें तो यह जो गारंटीज के ऊपर है, उस पर एक डिस्कशन होना चाहिए और आफलाइन बजटिंग, जितने आपके यह कारपोरेशंस हैं, जिनमें आपने यह लोन उठाया है जो कि इस बजट का पार्ट नहीं है, वह भी टेबल पर आना चाहिए। हमें यह पता तो पड़े कि हम कहां पर स्टैण्ड कर रहे हैं, हमारी दशा क्या है। पता पड़ा कि आफलाइन बजटिंग में हमने चालीस-पचास हजार करोड़ रुपये लेकर रख रखा है। आर.एस.आर.डी.सी. ने लोन ले रखा है, ई.आर.सी.पी. कारपोरेशन ने लोन ले रखा है, आपके इतने सारे कार्पोरेशंस हैं, उनमें आपने नई-नई कम्पनीज बनाकर लीवरेजिंग कर रखी है। कभी कहां पर लैंड दे रखी है, कहां पर बिल्डिंग दे रखी है, आपने कहां-कहां यह दे रखा है, वह हमें पता तो पड़े कि क्या हो रहा है। जैसे आपकी सरकार ने एफ.सी.आई. में लोन ले रखा था और एक बार में चुकाया उन्होंने, तो यह सब हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस सरकार में यह क्या हो रहा है, वह हमें पता पड़े, क्योंकि छह महीने में ही आप लोगों को यह लग रहा है कि क्या बजट दे दिया, क्या यह दे दिया तो उसकी आधी चीजें तो ये हैं।

अब जो इस सरकार ने धोखा किया किसानों के साथ, जो को-आपरेटिव में हम लोगों ने लास्ट ईयर 778 करोड़ रुपया दिया था, जो अच्छे लोनीज थे, को-आपरेटिव सोसाइटी को उनके इंटरेस्ट के लिए वह अपने 778 करोड़ रुपये से लाकर रख दिया 480 करोड़ रुपये। इसी तरह से लास्ट ईयर

(श्री रोहित बौहरा)

हमने 480 करोड़ रुपये दिये थे, को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो दूसरी वाली है, वहां पर इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए हमने 480 करोड़ रुपया दिया था, इस बार आपने 324 करोड़ रुपये दे दिये, तो मतलब वहां पर भी खतम। इसी तरह से रूरल डवलपमेंट में स्टेट फाइनेंस कमीशन ने पिछली बार पांच हजार करोड़ रुपया दिया था। मंत्री महोदय, यह आपके लिए है। पांच हजार करोड़ रुपया स्टेट फाइनेंस कमीशन ने लास्ट ईयर सैंक्शन किया था एस.एफ.सी. का, इस बार आपने वह घटा दिया, चार हजार करोड़ रुपया कर दिया तो एक हजार करोड़ रुपया सीधा स्लैश कर दिया। अब गांवों में जो आपको डवलपमेंट के लिए पैसा मिलेगा, प्रधानों और सरपंचों को, वह एक हजार करोड़ रुपया कम मिलेगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आपके टाइम में तो तीन-तीन, चार-चार किस्तें ही नहीं आयी थीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): किस्तें तो अभी भी नहीं आई हैं। आपकी कौनसी किस्तें आ गईं?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): चार-चार किस्तें तो आपके टाइम में आई ही नहीं थीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपकी कौनसी किस्तें आ गईं? आपकी एस.एफ.सी. और अन्य में कौनसी किस्तें आ गईं? (व्यवधान)

अरबन नरेगा, जो कि हमने चालू किया था, हमने अरबन नरेगा चालू किया, 650 करोड़ रुपये का हमारा प्रावधान था, आपने वह कट करके 300 करोड़ रुपया कर दिया तो 350 करोड़ रुपया आपने वहां पर खतम कर दिया। सबसे बड़ा काम यह किया, यह तो थोड़े ही है कि 25 सांसद हम आपको देते, तब हमारा काम आप लोग ढंग से करते। आपने स्वस्थ भारत मिशन जो कि हमारे प्रधान मंत्रीजी का सबसे बड़ा पैट प्रोजेक्ट है, उसमें हमने 1,324 करोड़ रुपये दिये थे शहरों के लिए, इस बार वह आ गया 608 करोड़ मतलब, slashed by more than 50 per cent. और इसी तरह से ग्रामीण में, जब हमने दिया था 1,146 करोड़ रुपया और आपने क्या दिया? एक हजार। यह तो प्रधान मंत्रीजी का पैट प्रोजेक्ट है। जीवारामजी, मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो प्रधान मंत्रीजी कहते हैं। यह उनका पैट प्रोजेक्ट है, तो ये अब क्या करें?

इसी तरह से आपने दिव्यांगों के साथ खेल खेल दिया। बड़ी बातें कीं

(श्री रोहित बौहरा)

दिव्यांगों के साथ। हमने अपने समय में पहले साल में चार हजार, फिर अगले साल में पांच हजार स्कूटी बांटी थीं, पर आपने क्या किया? (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): दो हजार स्कूटी आपने दी है तो मतलब उनके साथ भी आपने अन्याय किया।

बोलने के लिए तो बहुत है, पर पांच मिनट आप दे दो। पांच मिनट, फिर मैं बंद कर दूंगा।

मेडिकल कालेजज की बात हो रही है तो आपके पांच मेडिकल कालेजज रिजेक्ट कर दिये। इन्हीं की सरकार है सेंटर में, डबल इंजन की सरकार है न, तो उसी ने रिजेक्ट कर दिये। उसने क्यों रिजेक्ट किये? यह क्या करते थे, जैसे धौलपुर मेडिकल कालेज खुला तो पचास डाक्टर्स का ट्रांसफर आन पेपर धौलपुर हो जाता था, चालू हुआ और वह वापस ट्रांसफर होकर जयपुर आ जाते थे। इसी तरह से इन्होंने यह कहा कि यह कर दो। जब तक डाक्टर्स की भर्ती नहीं होगी, तब तक यह नहीं होगा। आज आपके राजमेस में डाक्टर्स ही नहीं आ रहे हैं, वे यह कहते हैं कि 30 परसेंट सैलरी हम उनसे क्यों कम लें जो आर.पी.एस.सी. से सलेक्टेड हैं? उसमें आप क्या करते हो? वह ज्वॉइन नहीं करता तो आप वेटिंग लिस्ट नहीं रखते हो। वह ज्वॉइन नहीं करता तो आप उसको कह देते हो कि तू जा तो क्या, क्यों? वे बच्चे जो पढ़ने के लिए मेडिकल कालेजज में गये हुए हैं, जिनके मां-बाप ने पैसा खर्च किया है, उनकी क्या गलती है? उनकी कोई गलती थोड़े ही है। वहां पर टीचर्स नहीं हैं। पता पड़ा कि आपने वहां पर मेडिकल कालेजज तो खोल दिये, छह महीने में बड़ी वाहवाही तो ले ली, सेंट्रल सरकार ने ये कर दिये, पर एक मेडिकल कालेज में, एक या दो के अलावा छोड़कर, जितने भी नये मेडिकल कालेज खुले हैं, हरीशजी, किसी में भी कैथ लैब नहीं है। डाक्टर साहब, आप तो समझती हैं, You are a doctor. कैथ लैब नहीं होने से आदमी को कितनी परेशानी होती है? उसको रश करके जयपुर जाना पड़ेगा। कोई संभाग हैडक्वार्टर पर कैथ लैब नहीं है। आप यह जो छोटे-छोटे पी.एच.सीज. वगैरह खोल रहे हो तो उससे फायदा क्या हो रहा है? कम से कम एक जगह, डिस्ट्रिक्ट में जहां पर पचास किलोमीटर या सौ किलोमीटर, जहां पर भी, वह दूर है डिस्ट्रिक्ट

(श्री रोहित बौहरा)

सेंटर, वहां पर कम से कम कैथ लैब खोलिये। कैथ लैब तो एक ऐसी चीज है and which is a must for any Medical College. अदरवाइज, स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ेंगे क्या? मेरा इतना-सा ही कहना है कि यह जो आपने बजट पेश किया है, यह बिलकुल दिशाहीन, बिलकुल विंडो ड्रेसिंग वाला कि जो विंडो ड्रेसिंग आप कर सकते थे, बड़े-बड़े अंग्रेजी के शब्द आप जो लिख सकते थे और सबमें आपने यह क्या कहा कि यूथ पालिसी बनेगी, स्पोर्ट्स पालिसी बनेगी, लैंड पालिसी बनेगी। सबकी पालिसी बनाने में ही आप तीन साल लगा दोगे तो पता पड़ा कि पालिसीज ही बनती गईं और रिजल्ट जीरो, जो कि एक्सपेक्टेड है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): विजन 2047 का है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): विजन 2047 का है, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि विजन 2047 जीरो हो जायेगा आने वाले समय में यदि इसी तरह से गाड़ी चलती रही तो। जो चीज आपको करनी है वह धरातल पर करनी है। कोई भी चीज आपको धरातल पर करनी है। सिर्फ पालिसीज बना-बनाकर वह ही काम होने वाला है। आप तो इतना-सा करवा दो कि जो हमारे यहां के काम, पिछली सरकार के काम थे, जो टेंडर हो गये, काम चालू हो गये, छह महीने से उनके पेमेंट नहीं हुए हैं, उनके पेमेंट करवा दो, जिससे वे रोड्स धरातल पर आ जाएं। आपने कुछ भी नहीं कर रखा है। लाइट की ऐसी हालत खराब है कि रात को ग्यारह बजे लाइट जाती है और सुबह चार बजे लाइट आती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, बस खतम कर रहा हूं। ग्यारह बजे लाइट जाती है और सुबह चार बजे लाइट आती है तो किसान कैसे सोए?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): रात को थोड़ी ठंड हो जाती है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जीवारामजी, आपके यहां पर ठंडी हो जाती है, हमारे यहां पर तो पत्थर है, वह ठंडी नहीं होती। हमारा इलाका तो पत्थर वाला है, आप इस बात को समझें।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है कि यह जो बजट है, यह सिर्फ विंडो ड्रेसिंग का बजट है, इससे इस राजस्थान

(श्री रोहित बोहरा)

में न तो कोई विकास होगा, न और कुछ होगा। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री कुलदीप।

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, इस बजट चर्चा में आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कवि के द्वारा रचित कविता के माध्यम से अपनी बात को प्रारम्भ करुंगा। कवि ने कहा है,

'उनको गुमान है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है,
यह जो बाग़ है इसको उन्होंने बहुत कुछ दिया है,
सूखी हैं शाख़ें, टूटे पत्ते दे रहे बानगी भी,
झूलों के नाम पर उन्होंने गुलेलों से सौदा किया है'।

आगे उन्होंने कहा है,

'हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है।
जिधर भी निकलेंगे, रास्ता हो जायेगा,
वे खुद ही मान जायेंगे बुलंदी आसमानों की,
परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की।'

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी के सानिध्य में हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री के द्वारा राजस्थान की विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया गया है। उस संकल्प के साथ में, जो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 में विकसित भारत बने, उसी का प्रयास करने के लिए, अपना यह पहला कदम, पहले बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने रखा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने भी कि आज के सारे अखबारों में, पूरे राजस्थान में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। और तो और, पूरे देश में राजस्थान के इस बजट को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में यह हमारी सरकार का पहला बजट जो प्रस्तुत हुआ है इतिहास कायम करने वाला बजट है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं।

कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा कुछ विषय ऐसे निकाले जा रहे हैं जो

(श्री कुलदीप)

शब्दों के जाल में फंसाकर, विस्तृत रूप से वह सदन में चर्चा कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं पहले शुरुआत में कांग्रेस की सरकार की बात करूं या हमारी सरकार की बात करूं। कांग्रेस की जो सरकार थी, उस समय के बहुत सारे विषय भी मेरे पास हैं, वे भी बताना चाहता हूं।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने भी कहा कि इस बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया। मैं किसान का बेटा हूं। इस देश में 80 फीसदी किसान और मजदूर के बेटे हैं। जिस किसान के घर में हमने जन्म लिया, हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है कि किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिला की जितनी चर्चा हम सदन में बैठकर कर सकते हैं, उतनी करनी चाहिए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान की विधान सभा में किसान सम्मान निधि के नाम से मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की। उसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि किसान के नाम पर राजनीति हुई। आपकी पांच साल सरकार थी, आपके भी मुख्य मंत्री किसान के बेटे थे। उनके पास किसान को देने के लिए कुछ था या नहीं था? यह तो आपको विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान को 23 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। यह हमारे राजस्थान की सरकार का विजन है। किसान की हमने चिंता की, मजदूर की हमने चिंता की। साथ-साथ पानी तो चला गया राजस्थान में, उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के कारण से जो आज संकट देखना पड़ रहा है, चाहे वह बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, उनका जिक्र मैं करूंगा। राजस्थान में 31 मार्च, 2024 तक जो हमारे किसानों के कृषि कनेक्शन थे, जिनकी पेंडेंसी लगातार आपके कारण से चल रही थी, उसको हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया। हमारे बजट में हमने घोषणा की है, यह पेंडेंसी राजस्थान की खत्म होगी।

सभापति महोदय, पानी का मैं जिक्र कर रहा था। ई आर सी पी का बड़ा मामला था। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 2017 में हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ई आर सी पी का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया। उसकी डी पी आर भी हमने तैयार की। पांच साल कांग्रेस का शासन

(श्री कुलदीप)

रहा। कांग्रेस के शासन में पांच साल में केवल राजनीति का खेल खेला गया। जब भी कोई विषय आता था तो कहा गया कि नरेन्द्र मोदी जी राजस्थान को ई आर सी पी से जोड़ना नहीं चाहते। आपने पांच साल में तो कुछ किया ही नहीं। जिस किसान के बेटे होने की आप बात करते हो, मैं समझता हूं कि इस विधान सभा में लगभग 90 क्या 100 परसेंट किसान के बेटे और बेटियां ही हैं। किसी न किसी रूप से जुड़े हुए ही हैं किसान से जुड़े हुए हैं। पांच साल में आपने कुछ नहीं किया। मैं मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भजन लाल शर्मा जी के राजस्थान का मुख्य मंत्री बनने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन लाल यादव जी के साथ में मिलकर, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री के साथ मिलकर इसी योजना का प्रारूप तैयार करके, ई आर सी पी को लाने का राजस्थान में काम किया।

पिछली बार जब सेशन चल रहा था, उस समय हमारे कांग्रेस के मित्रों के द्वारा इस प्रकार की बात की गयी कि ई आर सी पी में है क्या? आपने तो उसका अध्ययन किया ही नहीं था। पांच साल तक आप राजनीति ही करते रहे। इतनी बड़ी योजना, 50 हजार करोड़ की योजना राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी लेकर आये हैं, मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि देश और दुनिया में सबसे बड़ा कोई संकट आयेगा तो पीने के पानी का आयेगा। इस संकट को समाप्त करने की किसी ने पहल की है तो उनका नाम भजन लाल शर्मा है। एक बार जोर से स्वागत करके उनका आभार व्यक्त करिये। मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं कि पानी तो आपको भी चाहिए। सारे काम तो आपके परिवारों को भी करने हैं। ई आर सी पी के नाम पर आप लोग इस प्रकार की चर्चा राजस्थान में हर चुनाव में करते रहे।

अभी जिक्र किया गया जे जे एम योजना का कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने जे जे एम योजना पर बहुत सारा काम किया, किसानों के नाम पर बहुत सारा काम किया। मैं आपकी सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं। जिस किसान की बात हमारे मित्र अभी कर रहे थे कि किसान की चिंता हमारी सरकार ने नहीं की। कांग्रेस की सरकार ने कितनी चिंता की, उसका एक नमूना मैं निवेदन करना चाहता हूं। जैविक खेती हेतु 50 हजार कृषकों को प्रति कृषक 5 हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा आपकी सरकार ने की थी, जिसमें एक रुपये का भी काम इन्होंने पांच साल में नहीं किया।

(श्री कुलदीप)

हमारी जयपुर कैपिटल और जिस जोधपुर जिले से माननीय अशोक गहलोत जी आते हैं, मुख्य मंत्री थे, 100 करोड़ रुपये की लागत से आर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना की घोषणा इसी सदन में की गयी थी। उसकी नींव भी नहीं रखी गयी। एक रुपये का काम आपकी सरकार ने नहीं किया। यह नमूना है आपकी सरकार का। हमारी सरकार में और आपकी सरकार में यह फर्क है। हमारी सरकार विजन के साथ काम करती है। प्रदेश के बारे में मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र हैं, उन्होंने किसान की चिंता की। अगर आप इस प्रकार का प्रयास करते तो आपको हक होता किसान की बात करने का।

मैं कहना चाहता हूं कि पंजीकृत साढ़े तीन हजार गौशालाओं में पेयजल हेतु, गाय माता बोलती थोड़े ही है, पशु कभी बोलता नहीं है, लेकिन जीव तो उनमें भी है। आत्मा उनके पास भी है। गौशालाओं में पेयजल हेतु आवश्यकतानुसार थ्री फेज ट्यूबवैल की स्थापना करने की बात आपकी सरकार ने की थी, इस पर एक ट्यूबवैल आपकी सरकार पूरा नहीं कर पायी। यह आपकी सरकार में और हमारी सरकार में फर्क है।

अनेक जगहों पर जिला दुग्ध संघ बनाये जाने की घोषणा, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की भी बात आपकी सरकार ने बजट घोषणा में की थी। वह काम भी पूरा नहीं किया। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बड़ी-बड़ी घोषणाएं, अभी कहा जा रहा था कि आपकी सरकार में इसमें बजट रखा है, इस विभाग में इतना बजट रखा है, आपकी सरकार के बजट से उसकी तुलना की है।

सभापति महोदय, इनकी जो बजट घोषणा थी, उसमें तो काम हुए ही नहीं। एक रुपये का काम इनकी सरकार ने नहीं करवाया। डवलपमेंट की बात चल रही थी, कौशल नियोजन में, उद्यमिता विभाग में लगभग 100 करोड़ की लागत से अनेक जगहों पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आई टी आई, सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकास करना था पर इन्होंने एक रुपये का काम भी नहीं किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 25 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर स्थित, जिस दिव्यांग की बात हमारे एक मित्र ने सदन में रखी, मैं उन दिव्यांग साथियों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। दिव्यांग

(श्री कुलदीप)

विश्वविद्यालय में सेंटर आफ एक्सीलेंस फोर असिस्टिव टैक्नोलॉजी की स्थापना होनी थी, उसमें आपकी कांग्रेस की सरकार ने काम प्रारम्भ नहीं किया था। यह आपके पांच साल का कार्यकाल रहा है। लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से संभाग मुख्यालयों पर 100 से अधिक एवं जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिये वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाने थे, उसका काम भी आपकी सरकार ने एक रुपये का भी प्रारम्भ नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमने किसानों को दिन में बिजली देने की बात कही। पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में कांग्रेस का शासन रहा 2018 से 2023 के बीच में, उस समय राजस्थान में बिजली उत्पादन कितना होता था? यह शायद कांग्रेस के किसी मित्र ने सदन में रखा नहीं। अच्छा होता, एक बार आपके किसी सदस्य के द्वारा या नेता, प्रतिपक्ष सदन को बता दें कि पांच साल में आपकी सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर कितना काम किया। हमारा प्रोडक्शन कितना होता था और राजस्थान में बिजली कितनी कंज्यूम होती थी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की जनता से हमारी सरकार ने वादा किया है, हमारी पार्टी ने वादा किया है। हमने चुनावी घोषणा पत्र में जो-जो वादे किये थे, उसमें बहुत सारे वादे हमने इस छह माह के अंतराल में किये हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, हमारी पार्टी ने राजस्थान की जनता के साथ जितने वादे किये हैं, सभी वायदों को हम पूरा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमने कहा कि किसान को दिन में बिजली मिलनी चाहिये। हमारे विपक्ष की ओर से दो-तीन सदस्यों द्वारा किसी न किसी रूप में बातें आयीं कि किसान को बिजली नहीं मिल रही। यह बात सही है कि किसान को बिजली मिलनी चाहिये और कटौती भी हो रही है। उसके कारण क्या हैं, जरा कांग्रेस पार्टी के लोग भी अपने विचारों के माध्यम से बता दें। अगर पिछले पांच साल में आप बिजली प्रोडक्शन का काम ठीक तरह से कर लेते तो शायद आज राजस्थान में इस प्रकार की स्थितियां पैदा नहीं होतीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी ने अभी एक बहुत बड़ा MOU किया। 2 लाख 25 हजार करोड़ का MOU किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह जमीन पर MOU आयेगा तो इतना बड़ा उत्पादन हमारे

(श्री कुलदीप)

राजस्थान में होने वाला है कि राजस्थान में बिजली का संकट तो समाप्त हो ही जायेगा, अन्य प्रांतों को राजस्थान बिजली देने का काम भी करेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारी राजस्थान की सरकार लेकर आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूं और मेरे मन में भाव कहीं इस प्रकार के आते हैं। मैंने हमेशा मेरे माता-पिता को खेत में काम करते हुए देखा है और साथ-साथ मैं भी उनके काम में हाथ बंटाया करता था। ट्रैक्टर चलाना, खेत में हल जोतना, धूप में बैठकर अपनी खेती-किसानी को देखते रहना, मैं हमेशा बचपन से उनके साथ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पीने का पानी चला गया, सिंचाई का पानी है नहीं, लेकिन जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिये हमारी सरकार ने एक अच्छा प्रयास प्रारम्भ किया है। जब जैविक खेती पर हम पूरा ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का किसान ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री कुलदीप (विराटनगर): मेरे को समय दिया है। थोड़ा-सा इसमें समय लगना है।

श्री सभापति: आपका समय तय कर रखा है।

श्री कुलदीप (विराटनगर): प्लीज, मैं निवेदन करूंगा। महोदय, मैं पानी का जिक्र लेकर आ रहा था। ERCP की जो योजना थी, उसमें प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विराटनगर क्षेत्र में तीन बांधों, जवानपुरा धाबाई, बुचारा एवं छितोली को जोड़ने का काम किया है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने किसान के बेटे की चिंता की। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है, किसानों का क्षेत्र है, उनकी ओर से आपको अनेकानेक धन्यवाद। साथ ही जो अस्पताल है उनका क्रमोन्नयन किया है।

मेरी दो बड़ी मांगें हैं। मैं उस विराटनगर से आता हूं माननीय सभापति महोदय, जहां पर महाभारत काल का विराटनगर है और जहां पर अशोक सम्राट ने 300 दिन तक रहकर वहां पर अपने को अध्यात्म रूप से जोड़ने का काम किया था। ऐसी विराटनगर की धरती से मैं निकलकर आया हूं। वहां की जनता-जनार्दन को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधान सभा में चुनकर भेजा है।

(श्री कुलदीप)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो ऐसे बड़े विषय, सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय, मेरे जो दो आग्रह हैं, उनको स्वीकार करेंगे। निश्चित रूप से मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मेरे विराटनगर में टूरिज्म के हिसाब से बहुत सारे पर्यटक आते हैं और मेरा विराटनगर पर्यटन स्थल घोषित होगा, ऐसी मुझे सरकार से पूरी आशा है। ग्रामीण इलाका होने के कारण से आवागमन के साधन बहुत कम हैं। सड़कों का काम भी कांग्रेस के शासन में हुआ, लेकिन बहुत कम संख्या में हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरी एक सड़क, जो गांव से निकलकर आती है और सीधी अलवर-जयपुर को जोड़ती है, उस हाईवे से यह टच करेगी। मैं एक MDR की मांग भी सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मैंने मुख्य मंत्री महोदय को भी आग्रह किया है। मैं समझता हूं कि मेरी ये दोनों मांगें हैं, सरकार इन पर विचार करके इन्हें पूरा करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पहले भी इनकी कांग्रेस की सरकार ने आयुष्मान भारत को, चिरंजीवी योजना के माध्यम से उसका नामकरण किया था, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत हमारे जो कैंसर के रोगी होते थे, उनको प्रोपर इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर एक क्रिटिकल रोग है, अब उससे निजात मिलेगी, उसमें एक सहयोग मिलेगा। ईश्वर का लेख होता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब गांव या ढाणी से कोई व्यक्ति निकलकर आता है कैंसर की बीमारी को लेकर आता है तो उसको प्रोपर इलाज मिल नहीं पाता। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बीमारी को योजना में जोड़ने का काम किया है। बहुत सारी योजनाएं नई भी बन रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों का जाल राजस्थान में बिछाने का पूरा प्रयत्न किया है। मेरा पड़ोसी इलाका कोटपूतली लगता है। तीन-तीन नेशनल हाईवे गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, बीकानेर से हमारे राजस्थान से मुख्य मंत्रीजी ने जोड़ने का काम किया है। मैं मेरी जनता की ओर से हमारे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के जो आस-पास के लोग हैं, उनकी तरफ से राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा जाल आपने यहां बिछाने का काम किया है।

श्री सभापति: अब विराजें।

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ा समय और दीजिये। मेरे दो-तीन विषय छूट गये हैं।

मैं बात कर रहा था जे.जे.एम. की बात, आपकी तरफ से उठाया गया। जे.जे.एम. योजना के बारे में मैं थोड़ा-सा जिक्र करना चाहता हूं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री महोदय ने हर घर तक पानी पहुंचाने का एक संकल्प लिया था। कांग्रेस का पांच साल शासन रहा। लगभग 30 हजार करोड़ रुपये राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भारत सरकार की ओर से दिये गये। उसमें कुछ हिस्सा राशि आपकी थी और कुछ हिस्सा राशि हमारी भी थी। पांच साल में पिछली कांग्रेस सरकार ने जे.जे.एम. को लेकर जो काम किया, अगर पांच साल में आपकी सरकार में भी जांचें हुई थीं, आपके बहुत सारे ठेकेदार जेल में भी गये थे, उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई हैं। जेजे.एम. का काम अगर किसी कारण से लेट हुआ है, देरी से उसका काम चल रहा है, तो उसकी देन भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ही है, वरना हर घर में आज नल का पानी आ जाता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जे.जे.एम. में किया क्या? टंकियों का निर्माण करवा दिया, पाइप लाइन बिछायी नहीं। कहीं पर आपकी पाइप लाइनें लीकेज हो गयीं, कहीं टंकियां लीकेज हो गयीं। मैं नमूना बताना चाहता हूं। आज राजस्थान में जे.जे.एम. में जांच चल रही है। अगर यह जांच बहुत जल्दी आ जायेगी तो मैं इतना कह देता हूं कि राजस्थान के बहुत सारे नेता, जिन्होंने जे.जे.एम. का खेल राजस्थान में किया था, वे जेल में जायेंगे। ऐसी स्थितियां जे.जे.एम. में आपकी सरकार ने करने का प्रयास किया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाह रहा था, एक साथी ने कहा कि हमारी सरकार का विजन था। कांग्रेस पार्टी का राज पिछले पांच साल रहा। मैं ऐसे काम बताना चाहता हूं और इस सदन के माध्यम से सिर्फ राजस्थान की जनता को आईना दिखाना चाहता हूं कि आपने बजट में कौन-कौनसी घोषणाएं की थीं, जिनमें एक रुपये का भी काम आप लोगों ने नहीं किया। पर्यटन विभाग में 125 करोड़ की लागत से माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर तथा उदयपुर सहित पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनाने की घोषणा आपकी सरकार ने की थी। उसमें एक रुपये का काम भी कांग्रेस सरकार ने नहीं करवाया। 150 करोड़ रुपये से खासाकोठी का पुनरुद्धार करते हुए स्टार होटल कम स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में, जो

(श्री कुलदीप)

हमारी जयपुर की बहुत अच्छी प्रोपर्टी है, सबके काम आती थी, उस प्रोपर्टी के लिये आपने 150 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, उसमें एक रुपये का काम आपकी सरकार ने नहीं करवाया।

80 करोड़ रुपये से पुष्कर घाट देवी-देवताओं के लिये, तो आपकी सरकार ने काम क्या किया, यह मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जो लोग हमेशा देवी-देवताओं के खिलाफ रहते हैं, उनसे आशा भी क्या की जा सकती है? देवी-देवताओं के लिये, मंदिरों के लिये कोई ऐसा निर्माण करवाते। कांग्रेस सरकार ने पिछले पांच सालों में बजट में घोषणा तो की कि 80 करोड़ रुपये पुष्कर घाट के लिये रखकर काम करेंगे, लेकिन एक रुपये का काम भी पुष्कर के लिये नहीं किया। पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन की जो आपने घोषणा की, उस काम को भी आपकी सरकार ने पूरा नहीं किया। बेणेश्वर धाम के मन्दिर के विकास के लिये 100 करोड़ रुपये से विकास कार्य प्रारम्भ करने की बात भी कांग्रेस सरकार के बजट में कही गयी थी, जिसका काम आपकी सरकार ने नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं 30 करोड़ रुपये की लागत से खाटूश्याम जी, सीकर में डेडिकैटेड कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा कांग्रेस सरकार ने इसी सदन में की थी पर एक रुपये का काम इनकी सरकार ने करवाया नहीं। अब कांग्रेस के मित्र कौनसे विजन की बात करते हैं? हमारा विजन स्पष्ट रूप से है कि हमने राजस्थान की जनता के साथ मिलकर एक संकल्प लिया था कि गरीब को गणेश मानकर हम काम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी ने कहा था, जब तक सरकारी योजनाओं का लाभ उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब तक हमारे प्रदेश और देश का विकास सम्भव नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी के उन शब्दों को आगे बढाते हुए हमारी सरकार, भजन लालजी की सरकार काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कांफ्रेंस और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इनकी सरकार ने 100-100 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशंस व एक्जीबिशंस सेंटर्स के लिए घोषणा की थी, उनका काम भी कांग्रेस की सरकार ने पांच साल में एक रुपये का नहीं किया। फिर हमारे मित्र हमको आईना दिखाना चाहते हैं। जो सरकार छह महीने में आई है और छह महीने में अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, अपना काम करना

(श्री कुलदीप)

प्रारम्भ किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय को कि जब हम राजस्थान में पक्ष में होते हैं तो हमारी बातें करते हैं और विपक्ष में होते हैं तो विरोध की बातें करते हैं। मैं हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि पांच साल का राज आपने राजस्थान में किया है, कितनी नौकरियां हमारे बेरोजगार साथियों को दीं? हमारी सरकार का एक विजन है, हमारे मुख्य मंत्रीजी का विजन है कि राजस्थान में मेरा जो नौजवान है, पढ़ा-लिखा नौजवान है वह सड़कों पर न घूमे, बेरोजगार न रहे, उसके लिए चार लाख लोगों को हमने चार साल में रोजगार देने का फैसला किया है, हमारी सरकार ने फैसला किया है। उसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद नहीं बनता है क्या? इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या-क्या हुआ, यह मैं समझता हूं कि यह कहने की आवश्यकता भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, महिला बाल विकास, इसमें मातृ शक्ति हमारी आधी आबादी के बराबर की है। उसके लिए, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए आपकी कांग्रेस की सरकार ने प्रियदर्शिनी डे केयर योजना प्रारम्भ की थी। उसकी लागत कितनी बताई आपकी सरकार ने? 50 करोड़ रुपये, लेकिन 50 करोड़ रुपये में से एक रुपये का काम नहीं किया। यानी सुई का काम भी कांग्रेस की सरकार ने पांच साल में नहीं किया। ऐसा विजन था कांग्रेस की सरकार का, और हमारी सरकार पर आए दिन इस प्रकार के आक्षेप लगाते रहते हैं कि यह शब्दों का मात्र जाल है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं शिक्षा की बात कर रहा था, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के माध्यम से एन टी एस ई की तर्ज पर दसवीं कक्षा में दस हजार मेधावी विद्यार्थियों को नेशनल राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कालरशिप की बात आपने की थी पर एक रुपया भी इस स्कालरशिप में आपकी सरकार ने नहीं दिया। यह नमूना है कांग्रेस की पांच साल की सरकार का, जो आपने विजन की बात कही थी। यह आपके ही सारे के सारे डाक्यूमेंट हैं, यह मैं अपने घर से, बाहर से नहीं लेकर आया। आपके ही डाक्यूमेंट हैं, जो आपने पांच साल में काम किया, जो टेबल पर आप पेपर लेकर आते हैं, वे सारे डाक्यूमेंट लेकर आया हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इतने सारे बजट की बात हम करते हैं कि इतना बजट हम लेकर

(श्री कुलदीप)

आ गए। 250 करोड़ रुपये की लागत से आई टी सी परियोजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई, जिसमें इन्होंने कहा था कि चार हजार उच्च माध्यमिक विद्‌यालयों में हम कम्प्यूटर लैब लगाएंगे, इन्होंने एक रुपये काम भी अपनी सरकार में नहीं किया।

हमारे माननीय एक सदस्य महोदय भी कह रहे थे, उनके शब्दों का भी मैं ध्यान कर रहा हूं। आयुर्वेदिक विभाग में योग और नैचुरोपैथी एकीकृत महाविद्‌यालय, जयपुर में सेंटर आफ एक्सीलेंस एण्ड पंचकर्म की स्थापना की भी आपकी सरकार ने बजट में घोषणा की थी। उसमें भी एक रुपये का काम नहीं हुआ। ये वे काम हैं, जिनमें पांच साल में आपने बजट में घोषणा के बाद एक रुपये का काम नहीं किया।

कैथ लैब की बात अभी हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे थे कि कैथ लैब बननी चाहिए और कैथ लैब बनने से हमारे सभी प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। इनकी सरकार ने जयपुर और बाकी प्रदेश में कैथ लैब स्थापना करने की घोषणा की थी, उसमें भी इनकी सरकार ने एक रुपये का काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ और जिक्र भी करना चाहता हूं। राजस्थान के बेरोजगारों की बात ये लोग करते हैं कि राजस्थान में रोजगार नहीं मिला। बहुत सारे विषय हैं, जहां पर हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सकता था, जिसमें जयपुर, उदयपुर में नवीन एयर कार्गो परिसर के निर्माण की आपकी कांग्रेस सरकार ने बजट में की थी, एक रुपये का काम नहीं किया। बीकानेर में इन्लैंड कंटेनर डिपो से जोधपुर में एक अतिरिक्त इन्लैंड ड्राईपोर्ट के निर्माण की बात आपकी कांग्रेस की सरकार ने की थी, उसमें एक रुपये काम नहीं किया। लगभग 50 जगहों पर औद्‌योगिक क्षेत्रों का निर्माण करना, भिवाड़ी-जोधपुर मल्टी स्टेट इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स की घोषणा आपकी सरकार ने की थी, 100 करोड़ रुपये की लागत से भिवाड़ी में ड्रैनेज कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा आपकी सरकार ने की थी। सभापति महोदय, बहुत सारे विषय हैं, इनके पांच साल के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने जो वायदे किये, कर्जा माफी की बात तो इनकी हर गांव में, ढाणी में देखने और सुनने को मिल जाएगी। इनकी पार्टी के नेता ने कहा था, एक से दस तक गिनेंगे और राजस्थान प्रदेश के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन पांच साल में एक भी किसान का कर्जा इनकी सरकार ने माफ नहीं किया। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने आत्महत्या की, उसके लिए जिम्मेदार है तो आपकी पार्टी है, और आप किसान और मजदूर की आप बात करते हैं।

(श्री कुलदीप)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का समग्र विकास हो, उसके लिए हमारी सोच है और उस संकल्प के साथ हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लालजी शर्मा ने कार्य भी प्रारम्भ किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान का बहुत सारा काम, चाहे मैं किसान की बात करूं, चाहे बिजली उत्पादन की बात करूं, चाहे मैं जैविक खेती की बात करूं, बहुत सारे ऐसे विषय निकलकर आने वाले हैं, जिन पर हमारी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता के सामने वायदे किये थे उन एक-एक घोषणा को हम पूरा करने वाले हैं।

मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और हमारे वित्त मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए आपने इतना बड़ा बजट जो राजस्थान के इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ है कि ऐसा बजट राजस्थान में आने वाले समय में बहुत कम देखने को मिलेगा। सरकारें जब जाती हैं, सरकारें जब जाने लग गई होती हैं, उस समय उस दल की सरकार एक चुनावी बजट पेश करती है जिसमें बहुत सारे वायदे किये जाते हैं लेकिन हमारी सरकार के चर्चे हो रहे हैं कि हमारे सरकार ने पहले बजट में ऐसी ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं जिनको राजस्थान की जनता याद करेगी।

माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. ऋतु बनावत।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। सर्वप्रथम यह जो बजट आया है, उस पर मुख्य मंत्रीजी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी,

"शंखनाद मंगल बेला का, हम नव सोपान चढ़ रहे हैं,
संकल्प सृजन का मन में लेकर, नित निरंतर बढ़ रहे हैं,
कल्याणकारी बजट सुखद है, हर्षाया जन मानस बोल रहा है,
आदरणीय भजन लालजी, नित-नित नूतन प्रतिमान गढ़ रहे हैं।"

सर्वप्रथम, यह जो बजट आया है उसमें किसी भी वर्ग को चाहे युवा हो, महिला हो, वृद्धजन हो, आदिवासी समुदाय हो, पत्रकार हो, खिलाड़ी हो, किसान हो और यहां तक कि छोटे बच्चों का ध्यान भी इस बजट में किया गया है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से बहुत आभार

(डा. ऋतु बनावत)

व्यक्त करती हूं, धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने इस बजट के माध्यम से इस पूरे प्रदेश को उन्नति की सौगात दी है।

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि पहले कई दशकों से जो बजट आता था, उसमें भरतपुर जिला गौण नजर आता था, लेकिन इस बार बजट में भरतपुर जिला हमें सुनाई दिया। हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के विधान सभा क्षेत्रों के नाम हमें सुनाई दिए, इसके लिए उनका बहुत-बहुत साधुवाद बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा तोहफा ई आर सी पी का हमारे पूर्वी राजस्थान को दिया है। ई आर सी पी के माध्यम से 13 जिलों की पेयजल और सिंचाई की जो समस्या है उसके समाधान का प्रयास एक कदम बढ़कर मुख्य मंत्रीजी ने किया। यह भी कहना चाहूंगी कि वे इस पूर्वी राजस्थान के दर्द से पूर्णत: वाकिफ हैं, क्योंकि वे वहीं के रहने वाले हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि ई आर सी पी के माध्यम से बयाना विधान सभा क्षेत्र में डूंगरी कैनाल से बंध बारेठा में जो पानी आएगा और वहां से सुजानगंगा पहुंचेगा, उस फेज के लिए जो वर्क आर्डर दिए हैं, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र का वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, उसका कारण केवल और केवल यह है कि गम्भीरी नदी का जो प्रवाह होता था, वह पहले 12 मास होता था, लेकिन अब वहां पर पानी बहना बन्द हो गया है। पांचना बांध से पानी छोड़ा ही नहीं जाता। मैं आपको वहां के किसानों की स्थिति बताना चाहती हूं। पांच-छह साल पहले जब पांचना बांध से थोड़ा-सा पानी ओवरफ्लो होने के कारण छोड़ा गया था तो किसानों ने झूमकर उस आने वाले पानी का स्वागत किया। चाहे उनकी फसलें खराब हो गईं, लेकिन कारण यह था कि वहां पर वाटर लेवल ग्रो करे।

मैं यह कहना चाहूंगी कि ई आर सी पी के माध्यम से जो योजना बनायी जा रही है, उसमें गम्भीरी नदी में पानी छोड़ा जाना अत्यन्त आवश्यक है। किसानों की स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि ई आर सी पी में खानवा बांध को जोड़ा जाये और रूपवास ढहर के क्षेत्र में पानी आये। रूपवास क्षेत्र के सभी गांवों का वाटर लेवल कम होने के कारण बोकोली, सिंघावली, पाउड्री, चेकोरा, मेरथा, मिल्समा, इब्राहिमपुर, घाटोली, जटमासी, विनउवा, पुरामालोनी, चकसामरी आदि में सूखा मिटाये जाने का

(डा. ऋतु बनावत)

काम इस सरकार को ई आर सी पी के माध्यम से करना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं यह कहना चाहूंगी कि खानवा बांध को इस ई आर सी पी में जोड़ लिया जाये, क्योंकि रूपवास क्षेत्र में कोई भी ऐसा बड़ा बांध नहीं है, जिससे कि ई आर सी पी का फायदा रूपवास क्षेत्र की जनता को हो पाये। मेरा कहना यह है कि गम्भीरी नदी में पानी पांचना से छोड़ा जाये और गम्भीरी नदी का जो पानी है, वह यू पी बोर्डर तक पहुंचे, उसकी व्यवस्था ई आर सी पी के माध्यम से कर हमें अनुग्रहित करें।

साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बिजली की ट्रिपिंग की समस्या बहुत है। अभी मुख्य मंत्री जी ने हमें 220 के वी का जी एस एस स्वीकृत किया है, उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह भी कहना चाहूंगी कि 33 के वी के जी एस एस जो हैं, थानाडांग, मेरथा, मिल्समा, रिछोली, विनउआ आदि में कनेक्ट किये जाने शेष हैं। उन्हें भी जल्दी से जल्दी कराया जाये, ताकि हमारे यहां पर जो बिजली की समस्या है, उससे निजात मिल सके।

जिन जी एस एस के काम हमारे यहां चल रहे हैं, उनको प्रगति में लाने का प्रयास करें। "दिन में बिजली" का संकल्प हमारे भजन लाल जी की सरकार ने कहा है। अगर समय पर कार्य कम्प्लीट हो जाएंगे तो हमें दिन में बिजली मिलने लगेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिन में बिजली नहीं मिलने के कारण रात में जब बिजली मिलती है तो सिंचाई के कारण कई बार किसानों की मृत्यु तक हुई है। मैं यह कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी ऐसी समस्याओं का समाधान हो। आपने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री सभापति: विराजें।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): थोड़ी-सी बात और कह लेने दीजिये। साथ ही, रोड्स के लिए बहुत अच्छा पैसा दिया है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि रुदावल-बंसी पहाड़पुर, बयाना-थानाडांग शाहपुर, पहाड़पुर-सिंघनिया और रूपवास -जटमासी, ये रोड हमारी बहुत ज्यादा खराब हैं। पर्यटन का बहुत अच्छा बजट दिया कुमारी जी ने पेश किया। पर्यटन के लिए विशेष नीति बनायी। मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र पर्यटन में अपार सम्भावनाएं रखता है। बयाना फोर्ट, बंद बारेठा और कृष्णकालीन उषा मन्दिर यहां पर हैं, उनके लिए भी काम किया जाना चाहिये। पर्यटन बजट में से हमें कुछ हिस्सा इसके लिए भी मिलना चाहिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): पूर्वी राजस्थान में कोई भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है। उसके लिए भी काम किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री सभापति: विराजें आप।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): धन्यवाद।

श्री सभापति: डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मैंने अपना समय तो डाक्टर साहब को दे दिया था। मैं तो सरकार को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का कोटिकोटि धन्यवाद देते हैं। अभी उधर के एक सदस्य बोल रहे थे, बहुत ही चिन्तित हो रहे थे।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): कैबिनेट को भी धन्यवाद दीजिये। बजट कैबिनेट से आया है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां, कैबिनेट को भी धन्यवाद दे रहा हूं। विपक्ष को भी धन्यवाद दे रहा हूं। आप बहुत चिन्तित हो रहे थे। अभी तो छह महीने हुए हैं सरकार बने हुए। पहला बजट है। बजट पेश करने वाले चिन्तित हैं नहीं, पड़ोसी चिन्तित हो रहे हैं। सुबह घूमते हुए मुझे हरिमोहन शर्मा जी मिल गये। मैंने उनसे पूछा, कैसा बजट है। उनका पहला रिएक्शन यह था कि, साहब, मुझे तो हर बजट में गहलोत जी के समय से आज तक वही चीज मिल रही है। हर बार उसी चीज की घोषणा होती है। मैंने उनसे कहा, कोई पूरी नहीं करता क्या आपकी? अबकी बार आपकी मांग पूरी हो जायेगी। फिर अभी भाटी जी मिले मुझे। मैंने पूछा, कैसा बजट है। वे बोले, ऐसा बजट मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जितना मेरे क्षेत्र में दिया है, इतना दिया, जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): कौन-से भाटी जी?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): भीम राज भाटी। वे बोले, ऐसा बजट है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी और मैं फ्लोर पर माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मैं भी धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं। मैंने भी नहीं सोचा था, मेरे क्षेत्र में इतना काम मिल जायेगा। मैं आज हर हालत में, चाहे दो मिनट और बोलना पड़े, सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को, उनके विजन को, वित्त मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं और इसमें कोई

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

शक-ओ-शुबहा नहीं है कि राजस्थान के विकास में कोई कमी रह जाये। पहला मुख्य मंत्री है। आपके समय जब कांग्रेस सरकार थी, जिले घोषित हुए, हालांकि, जिन्होंने जिले घोषित कराये, उनमें 99 परसेंट धराशायी हुए क्योंकि बिना सोचे-समझे जब काम होते हैं, जहां बजट नहीं है, उस टाइम एक हमारे साथी बौहरा जी, आप फाइनेंस के हैं, वैसे फाइनेंस वालों को मैं देखता भी हूं।

माफ करना टीकाराम जी, आप छोटे हैं मुझसे, मैं राजनीति में दो औलाद लेकर आया। एक मेरा बेटा जो शिकागो बूथ स्कूल से है, जो फाइनेंस में वर्ल्ड का नम्बर वन है। दूसरा बेटा जो हार्वर्ड से मैनेजमेंट कर रहा था, वह आया। मैंने सोचा, मेरी विरासत इसी को दे दूं। आज एक राज की बात खोल रहा हूं, मैंने टीकाराम जूली जी को गोद लिया। मैंने इनका टैलेंट देखा तो मैंने यह कहा था कि एक दिन आप बहुत बड़ी पोजिशन पर जाएंगे। आज वह पोजिशन आ गयी।

श्री सभापति: तभी तो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं ये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आने वाले समय में, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इस प्रदेश का मुख्य मंत्री बनना तय है इनका।

श्री सभापति: ये ताली भी उत्साह से नहीं बजा रहे, साहब। प्रतिपक्ष के नेता एक ही हैं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और एक मेरा बेटा था, उसको मैंने टिकट दिलाया तो वह तो, बौहरा जी, फाइनेंस में ही लगा रहा और हार गया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं भी पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा हूं, मैं दूसरी बार विधायक बनकर आया हूं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, आप फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे हैं, पर बूथ स्कूल से नहीं हैं आप, जो वर्ल्ड में नम्बर एक है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको एक चीज बता देता हूं, आपका बेटा जहां से कर रहा है न, मेरा बेटा भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके आया है वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से जो एटलांटा, जार्जिया में है। Doesn't make a difference. आपमें पढ़ने की क्षमता होनी चाहिये। आप यह मत सिखाएं। आपमें पढ़ने की क्षमता होनी चाहिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपन तो अपनी बात करें, बेटों की बात बाद में करेंगे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं तो स्थिति बता रहा हूं, यह तो गहलोत जी की गलती है कि आप जैसे टैलेंट को वे कैसे भूल गये थे, खामख्वाह विपक्ष में बैठना पड़ा। जब इतने जिले बन रहे थे, तब आपको चिन्ता जाहिर नहीं हुई कि इनके अन्दर 400 करोड़, 500 करोड़ कहां से आएंगे। क्या होगा इन जिलों का? नगरपालिकाओं में कोई भर्ती नहीं की, कैसे चलेंगी ये, कैसे पंचायतें चलेंगी? कहां हैं मॉडल स्कूल इंग्लिश के महात्मा गांधी के? जब आपकी अपनी सोच का समय था, अपना घर बचाने का समय था, तब तो आपकी चिन्ता जाग्रत नहीं हुई और हमारी सरकार को छह महीने हुए तो मोदी जी के बजट की भी चिन्ता कर ली आपने और राजस्थान के बजट की भी चिन्ता कर ली।

मैं मुख्य मंत्री जी से निश्चित रूप से कहूंगा कि जरूरत पड़ने पर आपको हायर कर लेंगे वे। ले-देकर बात यह है, लम्बी-चौड़ी बहस नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस बजट की विपक्ष भी बड़ाई कर रहा हो, जिसने हर जिले को, हर विधान सभा क्षेत्र को छुआ हो, जिसके अन्दर हर सदस्य सन्तुष्ट हो, उससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता। मुख्य मंत्री जी में टैलेंट है, तब ही तो मुख्य मंत्री बन गये। अच्छे-अच्छे रह गये न।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): गलती से बन गये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गलती किसकी है? कौन कह रहा है गलती से? बनाया हमने, थारो गलती से के लेणो-देणो? इसलिए बढ़िया सरकार चलेगी। इतना बढ़िया बजट मिला है। माननीय भजन लाल जी की सरकार, उनके कैबिनेट मिनिस्टर, आपकी तरह, माफ करना, माफी चाहता हूं, जिसने जो मांगा, जो घोटाला किया, वह दिया। यह सरकार घोटाला नहीं करेगी। जनता की कसौटी पर खरा उतरेगी और जनता का भविष्य उज्ज्वल है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रतन देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, बजट पर चर्चा पर हमारे सभी माननीय सदस्य, हमारे वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे। अभी तक पांच सदस्य बोले हैं। हमारे तो एक ही माननीय सदस्य बोले हैं। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि बजट सुन रहा हूं या राज्यपाल अभिभाषण सुन रहा हूं। सभापति महोदय, ये जो बोल रहे थे।

श्री सभापति: आप बजट पर सुना दें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): जी, सर। आपका संरक्षण लेते हुए उसी पर बोलूंगा। इनको बोल नहीं सकता, ये भी हमारे वरिष्ठ संरक्षक हैं।

सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि जब बजट पर चर्चा हो या राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा हो तो हम लोग सदन में राजनैतिक तौर पर पक्ष-विपक्ष, हां-ना में बंटकर अपनी बात कहते हैं। हमारे एक ही माननीय सदस्य पिछले दो घंटे में अभी तक बोले हैं। उन्होंने एक बात पर तारीफ भी की और खुद ने मेज भी थपथपाई। हम सब लोग इस सदन में आये हैं, क्योंकि बजट पूरे स्टेट का बना है। स्टेट के विकास के लिए, गांव, गरीब, शहर से लेकर, इस राजस्थान को, पूरे देश में प्रथम नम्बर पर लाने के लिए बजट बनाया जाता है।

श्री सभापति: इन्होंने मन से बजाई थी क्या ताली? यह तो पूछ लें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मेरे पड़ोस की कांस्टीट्यूएंसी के साथी माननीय सदस्य संघर्ष कर ही रहे हैं तो उनको तो दोनों तरफ थपथपानी है। सर, एक बहुत पुराना मुजफ्फर वारसी का शेर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दो-तीन माननीय सदस्य यहां बोले और जो बजट में पढ़ा गया, उससे ताल्लुक रखता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं।

"औरों के खयालात की लेते हैं तलाशी,
औरों के खयालात की लेते हैं तलाशी
और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता।"

सर, बताइये। आप हमको कह रहे हो, आप तो मान लो कि हमने तो कुछ नहीं किया, इसलिए हम यहां आकर ना पक्ष में बैठ गये, मगर आपको किसने कहा है करने के लिए? आज जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, बहुत लम्बे अर्से बाद, हमने बहुत लम्बे अर्से तक इस हाउस में देखा है, काफी सीनियर सदस्य यहां हैं, हम भी पहले हाउस में सदस्य रहे हैं, हमने देखा है कि राज्य के मुख्य मंत्री, सदन के नेता वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते थे। बहुत लम्बे अर्से के बाद कैबिनेट से एक मंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। हमको लगा कि बजट अच्छे से पेश होगा, पर आपने तो जैसे चुनाव में अभी जाने वाले हो और आपका पांच साल का पीरियड खतम हो गया है, यह पब्लिक परसेप्शन बनाते हुए आपने बजट पेश किया है। सिर्फ वाहवाही लेनी है, आंकड़ों में जाना है, शायद कल ही चुनाव हों, आपने इस प्रकार का बजट पेश किया है।

(श्री रतन देवासी)

देखिये, आप भी हमारे साथी हैं। सभापति जी, मेरा समय चला जायेगा। मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं। इनका समय आ जायेगा, ये बोलेंगे।

श्री सभापति: शान्त रहें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अच्छे श्रोता बनें तो अच्छे वक्ता भी बनेंगे। आप जो बोल रहे हो, आपका वह नोट हो रहा है। आपके लीडर के पास शाम को बात चली जायेगी कि इन-इन लोगों ने सरकार का पक्ष रखा है, बोला है तो उस नोटिंग से पॉलिटिकल करियर डवलप नहीं हो पाता है। लेजिस्लेचर के लिए, जब डवलप होगा, तब आप भी उस बात को सही बात के रूप में बोलेंगे और आपके लोग उस बात को देखेंगे, तब जाकर लेजिस्लेचर डवलप होगा।

सभापति जी, मैं सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। कुछ चार-पांच विभाग हैं, उनमें क्या कमियां रह गईं, आपने कागजों में कैसे लिया और अभी जब माननीय मंत्री जी वापस जवाब देंगे, जब एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा और जब डिमांड्स आयेंगी, तब उन चीजों को ठीक करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यदि उसको करेंगे तो राज्य के हित में होगा, हमारे भी हित में होगा, सबके हित में होगा।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बजट की स्पीच, आपने 8 फरवरी को जब वित्तीय अनुमान पेश किया, आपने पहली स्पीच अध्यक्ष महोदय के नाम से सम्बोधित करके, आपके दो नम्बर, चार नम्बर, पांच नम्बर, जो भी पैरा बने, आपने पिछली सरकार की आलोचना में ही निकाल दिये। फिर रोडमैप कहां से आयेगा? आपने कल बजट पेश किया।

माननीय सभापति महोदय, बजट पेश कर रहे हैं, उसके बाद में आपने जो दूसरा पैरा पढ़ा, वह पिछली सरकार की आलोचना से आपने तैयार कर दिया तो फिर आपका रोडमैप कहां से बन पायेगा? यह नहीं होना चाहिए था। हो सकता है, सरकारों ने गलतियां भी रखी होंगी, कमियां भी रही होंगी और सबसे बड़ी बात है, मैं नहीं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी उन सब प्री-बजट मीटिंग में अगर इन्वोल्व होते और माइन्यूटली उन मीटिंगों को देखते। विभिन्न सेक्टर्स के लोगों को बुलाया जाता था, हर बजट के पहले, उसमें कमी आई है। उन तमाम लोगों को नहीं बुलाया गया है। एक परसेप्शन बन ही नहीं

(श्री रतन देवासी)

पाया कि बजट की प्री-मीटिंग हो रही है। आपने केवल दो मीटिंगें करवा दीं और उसके बाद ले लिया। अगर फाइनेंस मिनिस्टर उसको माइन्यूटली देखते तो अच्छा बजट दे पाते। उसमें कमियां कैसे रह गईं? आपको लिखवाकर पढ़वाया गया और आपसे क्या लिखवाया कि 53 परसेंट, आचार संहिता लगने के बावजूद, तो क्या आचार संहिता लगने के बाद में पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस पर चुनाव का काम नहीं कर रहा था? बजट इम्प्लीमेंटेशन में लगा हुआ था? 53 परसेंट से ज्यादा हमने बजट घोषणा पूरी कर दी और संकल्प पत्र के 45 बिन्दु भी हमने कम्प्लीट कर दिये। मैं मान लेता हूं, चलो गलत नहीं लिखा, मैं मान लेता हूं, जब आपने सारी चीजें सदन के पटल पर रखीं, पी डब्ल्यू डी, पानी की, तो आप ये 45 आपके संकल्प पत्र के और 53 परसेंट जो बजट घोषणाएं आपने पूरी की हैं, उसको भी सदन के पटल पर रख देते। अभी भी मौका है, जब मंत्री जी जवाब देंगे, एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इन्होंने जो कहा है, उसको सदन के पटल पर रखें। हम भी पढ़ सकें कि 53 परसेंट कौन-सी बजट घोषणाएं इन्होंने पूरी की हैं। यह मेरा विशेष निवेदन रहेगा।

सभापति महोदय, चार विभागों के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने पेयजल में जल जीवन मिशन की बात की। माननीय सदस्य भी बोल रहे थे। यह सही बात है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि जल जीवन मिशन में जिस स्तर पर काम होना चाहिए था, उस स्तर पर नहीं हुआ है। मैं खुद कह रहा हूं कि वह काम इतना डिफेक्टिव हो गया है कि पी एच ई डी की लाइन खतम हो गई। यह गर्मी गई है, उसमें लोगों ने भगवान के भरोसे पानी पीया है। आपने कंटिंजेंसी प्लान भी, आचार संहिता हट गई, लोक सभा का वोट पड़ गया, उसके बाद में आपने कागजों में वह कंटिंजेंसी प्लान निकाला, लोगों को टाइम पर ट्यूबवैल, हैंडपम्प भी नहीं मिला और उसकी वजह से डिफेक्ट हुआ, यह मैं भी मानता हूं। मगर आपने जब 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है कि हम पेयजल में खर्च करेंगे, जल जीवन मिशन में 25 लाख परिवारों को हम लोग वहां पानी उपलबध करवायेंगे तो यह भी कह देते कि जो गलतियां आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि हमने गलती की है, मगर उसको आप कैसे ठीक करोगे। वे जो लाइनें नहीं पहुंची हैं वे जो चार सौ, पांच सौ, हजार करोड़ के ठेकों का काम चल रहा है, उनमें

(श्री रतन देवासी)

बराबर लाइनें घरों तक नहीं गई हैं, उसको आप कैसे ठीक करोगे? ठेकेदार के बिल कैसे पेमेंट हो जायेंगे?

सभापति जी, आपको यह भी कहना चाहिए था और मेरा निवेदन है कि इसको वापस उनकी स्पीच में लाया जाये कि हम इस तरीके से इसको टाइम बाउंड कर देंगे, ताकि करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है और लोग बिना पानी के अभी तक बैठे हुए हैं तो वह सिस्टम हमारा कैसे ठीक होगा। वह चीज आपके इस बजट में आनी चाहिए बनिस्बत कि 15 हजार करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे।

दूसरा, ये माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, भले किसी भी पक्ष के हों। हम लोग ग्रीन कॉरिडोर बना दें। आप 60 हजार करोड़ रुपये रोड पर खर्च कर दो। आप डी पी आर बना दो, 400-400 किलोमीटर का एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए, वे फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं, मान लिया, मगर गांव में जब कोई चुना हुआ विधायक या सदस्य जायेगा तो उसका सदस्य सबसे पहले यह पूछता है कि हमारे यहां सड़क नहीं है। हमारी मिसिंग लिंक सड़क का आप क्या करोगे? वह जो मिसिंग लिंक सड़क की देन थी, जिसको हमने 10 करोड़ रुपये किया था और 10 करोड़ रुपये माननीय सदस्यों को मिसिंग लिंक के लिए आबंटित हुए थे, जिसके लिए लोग उत्साहित रहते थे कि यह मिसिंग लिंक, जिसके लिए हमारी जवाबदेही लोगों में तय होती है। आपने पांच करोड़ आचार संहिता के पहले कैसे लिये, कैसे दिये, उस बात को छोड़ो, समय कम है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।

सभापति महोदय, मैं पांच मिनट लूंगा। आपका संरक्षण चाहता हूं। राज्यपाल अभिभाषण में भी आपने घंटी बजा दी थी। मैं आपको सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: आपका 10 मिनट का समय लिखा हुआ है।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): फाइनेंस मिनिस्टर जी से मेरा निवेदन है कि इस मिसिंग लिंक को, ये तमाम सदस्य जो हाउस में बैठे हैं, उन सबके लिए, आप दस नहीं, हमने दस किया था, आप पन्द्रह करोड़ करो, जैसे एम एल ए फंड आपका एक से पांच करोड़ हमारी सरकार ने किया था। यह मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा।

(समय: 16.00 बजे)

(श्री रतन देवासी)

सभापति महोदय, दो बातें आपकी परमिशन से कह रहा हूं। आपने उद्योग में अम्बेडकर जी का स्लोगन देकर बात तो कह दी और नीचे आपने लिख दिया प्रधान मंत्री जी का वोकल फोर लोकल। अब आपने बड़े उद्योगों की तो बात कर दी। सीमावर्ती जिले में, बाड़मेर हो, जालौर हो, सिरोही हो, पाली हो, जिसके सारे लोग राजस्थान से बाहर रह रहे हैं, माननीय सदस्य कई यहां से आते हैं। आज वो लोग दक्षिण से, मुम्बई से अपनी जगह छोड़ कर सब गुजरात आ गये हैं, बीस से तीस प्रतिशत ग्रोथ अहमदाबाद में हो रही है। हमारे बोर्डर पर छोटे उद्योगों की बात करो। वो बर्तन का उद्योग लगा सके, वो हार्डवेयर का उद्योग लगा सके जो वह आलरेडी लगा रहा है, उसकी कोस्टिंग रीको में आप कम कर दो, उसके प्लाट की कोस्टिंग कम कर दो, छोटी यूनिट्स आप काटो, ताकि राजस्थान के लोग जो बाहर गये थे वो यहां वापस बसना चाह रहे हैं और उद्योग डालना चाहते हैं तो उनकी बात उसमें आनी चाहिये।

अन्त में, दो बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं पशुपालन के बारे में। बहुत जरूरी है।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति जी, पशुपालन की बात करें। अपन ऊंट की बात करते हैं, कोई कर नहीं रहा है, मैं कर लेता हूं ऊंट की। सभापति जी, ऊंट की बात की, आपने दस से बीस हजार रुपये बढ़ा दिये। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने नवजात ऊँट को, जो शिशु होता है उसको बड़ा करने के लिए दस से बीस हजार रुपये कर दिये। आपने राज्य पशु घोषित किया है वह भी स्वागत योग्य है मगर आप उस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करोगे तो वह बीस हजार रुपये लेकर उसको बड़ा करेगा और जब बड़ा होकर उससे कमाने का उसको मौका आता है तो उसका अध्ययन करो कि वह आज क्यों नहीं हो रहा है, ऊंट कम क्यों हो रहे हैं इसके बारे में आप अध्ययन कीजिये। पशुपालन में गायों के लिए अलग से सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने डायरेक्ट्रेट बनाया था। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि जो घुमक्कड़ लोग हैं, जो पलायन करते हैं गायों को लेकर, आप उनके अनुदान की बात करो, आप उनको भी अनुदान दो, ताकि वह बरसात में, गर्मी में, सर्दी में घूमता है तो उस अनुदान से उसका भी पेट पाल सके और उन गायों को पाल सके, यह निवेदन है।

(श्री रतन देवासी)

अन्त में, आखिरी बात माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने टूरिज्म की सबकी अच्छी बात की होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने दो चीजें कहीं। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने भी लिखा था, आपने दी। आशा करता हूं कि और भी कुछ घोषणाएं जवाब के समय होंगी विधान सभा क्षेत्रों के लिए, मगर पूरे स्टेट का, पूरे राजस्थान का एकमात्र पर्यटन स्थल है माउन्ट आबू और आपका भी वहां से लगाव है, माननीय वित्त मंत्री जी का। वहां के लोग आपको भी स्थानीय मानते हैं विभिन्न कारणों से। मन्दिरों की भी अभी बात कर रहे थे माननीय सदस्य। आपने जीर्णोद्धार का किया तो मेरा निवेदन है कि सबसे बड़ा शक्तिपीठ अपने स्टेट का एकमात्र वहां है, आपने उसके जीर्णोद्धार की बात क्यों नहीं की? आपने जो पैसे अलग-अलग दिये तो रामदेवरा जी की बात आपने क्यों नहीं की? अलग-अलग जगह की और बातें माननीय सदस्यों ने, कइयों ने उनकी भी की तो उनके भी नाम उसमें आने चाहिये और जो धार्मिक नगरी है, भगवान शिव का एकमात्र पूरे मुल्क के अन्दर, विश्व के अन्दर एक ही मन्दिर है जहां उनके अंगूठे की पूजा होती है और जो सदियों-सदियों, वर्षों पुराना मन्दिर है, आपने उसके जीर्णोद्धार का नाम नहीं लिया।

पिछली सरकार ने बीस करोड़ रुपये वहां पोलो ग्राउंड के लिए दिये, ताकि उसका विकास हो सके। राष्ट्रीय 20-20 के मैच हो सकें और राष्ट्रीय स्तर के फुटबाल के मैच हो सके। वह पूरी डी पी आर बन गई, आपकी सरकार आने के बाद वह काम शुरू नहीं हो पाया। इसलिये अन्त में, मैं आपको इतना ही निवेदन कर रहा हूं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि अभी मौके हैं ठीक करने के, बनिस्बत हम इसमें पड़ें कि अच्छा बजट दिया और वाहवाही लूटें, जो रह गई हैं उन त्रुटियों को ठीक करें, कागजों में दिये हुए बजट को खतम करें। यही मैं आपसे निवेदन करते हुए आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र पाल मीना।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): सम्माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने परिवर्तित बजट 2024-25 पर मुझे बोलने का मौका दिया। राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय सम्माननीय भजन लाल जी को और इस विजन के साथ बजट पेश किया, इसके लिए मैं

(श्री महेन्द्र पाल मीना)

हमारी वित्त मंत्री सम्माननीय दिया कुमारी जी को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने अमृत काल खंड के इस महोत्सव में जो मिशन के रूप में काम किया, यह अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा।

हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी की विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरा करने के लिए राजस्थान को दिशा देने वाला शानदार, दमदार और जानदार बजट पेश किया। इस बजट के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बजट में विकसित राजस्थान की तस्वीर पेश की गई। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों, बुजुर्गों, सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया और युवाओं के लिए विशेष तौर से पांच वर्ष में चार लाख नौकरियों की घोषणा की गई, यह अपने-आप में युवाओं के लिए बहुत सुनहरा और भविष्य को सुधारने वाला कार्यक्रम है। सरकार ने बीस हजार नियुक्ति पत्र बांट कर इसकी शुरुआत की।

माननीय सभापति महोदय, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा के साथ सम्भाग मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कालेज खोलने की घोषणा करके प्रदेश को खेलों में अग्रणी बनाने का काम किया है। प्रदेश में सरकार बनते ही 21 जिलों में पेयजल की पूर्ति के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ केन्द्र सरकार को साथ में लेकर राजस्थान के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम किया है। यह योजना प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करेगी।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने पिछले पांच सालों में इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को अटकाने का और भटकाने का काम किया है, यह पूरा प्रदेश, पूरा राजस्थान इनको देख चुका है। मैं धन्यवाद देता हूं इस सदन के माध्यम से कि हमारे किसान के बेटे हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को गम्भीरता से लेते हुए जो भगीरथी प्रयास किया, वह अपने आप में दूरदर्शी और किसानों के लिए और राजस्थान की जनता के लिए बहुत भगीरथी काम सिद्ध होगा।

सभापति महोदय, मैं जयपुर जिले के जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जहां पर रामगढ़ बांध राजस्थान की राजधानी जयपुर को कई

(श्री महेन्द्र पाल मीना)

सालों तक पानी पिलाया करता था, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने हमारे रामगढ़ बांध की तरफ और ई आर सी पी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री को जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सभी जनता की तरफ से बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जमवारामगढ़ बांध की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक काम किया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि रामगढ़ बांध जयपुर को सालों तक पानी पिलाया करता था और जयपुर की लाइफलाइन रहा है।

सभापति महोदय, बीसलपुर बांध से जिस प्रकार से पानी जयपुर को पिलाया जा रहा है, वह बरसात के ऊपर आश्रित है। रामगढ़ बांध में ई आर सी पी के द्वारा जो पानी आयेगा जो एक प्रकार से राजस्थान की राजधानी जयपुर के विकल्प के रूप में काम आयेगा। यह एक दूरदर्शी काम हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने किया है। योजना में जयपुर जिले के सबसे बड़े बांध में पानी लाने के लिए ईसरदा बांध से हमें 4,100 करोड़ रुपये का बजट दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। जमवारामगढ़ बांध से सिंचाई और पेयजल के लिए अतिरिक्त स्रोत हमें मिलेंगे।

सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने हमें जमवारामगढ़ कृषि महाविद्यालय दिया, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। बिजली के संकट को दूर करने के लिए 132 के.वी. जी एस एस हमें दिया, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जिससे बिजली का संकट दूर होगा और ग्राम पंचायतों में किसानों और उपभोक्ताओं को समस्या से निजात मिलेगी।

सभापति महोदय, जमवारामगढ़ में जयपुर जिले के आस-पास जो फूलों की खेती होती है उसमें बहुतायत में गुलाब के फूल जमवारामगढ़ में पैदा होते हैं। उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने वहां पर एक फूल मण्डी दी है, जिसके लिए मैं सदन के माध्यम से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही, हमारे जमवारामगढ़ में जयपुर के नजदीक होते हुए भी नगरपालिका नहीं थी, लेकिन आपने दूरदर्शी सोच रखते हुए जमवारामगढ़ को नगरपालिका दी, इसके लिए भी मैं सदन के माध्यम से हमारे मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट इस प्रकार का दिया

(श्री महेन्द्र पाल मीना)

है कि जैसे चुनाव में जाने वाले हैं। इनको ऐसा ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यह कागजों में घोषणा करते हैं और जब इनके कागजों का कोई अता-पता नहीं होता है, तब इनको इधर सामने बैठना पड़ता है।

सभापति महोदय, जमवारामगढ़ बांध के लिये भी पूर्व की सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। जब हमने सदन के माध्यम से मालूम किया तो उसके बजट की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री किसान के बेटे हैं, उनकी सोच है कि जो घोषणाएं हम करते हैं, उसका शिलान्यास भी हम करें और उसका उद्घाटन भी हम करें। यह सोच इस राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जायेगी। इसके लिये भी मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्री जी ने छह महीनों में हमारे बजट की 50 प्रतिशत से ज्यादा घोषणाओं को पूरा किया, यह अपने आप में मील का पत्थर साबित होता है। और तो और हमारे जन-जन की भावनाओं से जुड़े हुए मंदिरों के लिये उन्होंने विशेष बजट रखा। खासतौर से खाटूश्यामजी के लिये 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट रख कर हमारे हजारों-लाखों श्रद्धालुओं को तोहफा दिया। इसके लिये मैं उनको इस सदन के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का एक सपना है 'लोकल फोर वोकल।' इस क्षेत्र में भी हमारी वित्त मंत्री महोदया द्वारा एक जिला एक उत्पाद की घोषणा करके प्रदेश का मान बढ़ाया है। सभापति महोदय, जमवारामगढ़ राजधानी के निकट होते हुए भी पिछली सरकार ने जिस प्रकार की उदासीनता रखी और आज इस बजट में जो सौगात दी गई है, इसके लिये पूरे जमवारामगढ़ के लोग बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, हमारे जमवारामगढ़ में आंधी हमारी एक तहसील है, वहां से दौसा-मनोहरपुर का एक हाईवे गुजरता है। आपने कई बार अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि वहां से खाटूश्यामजी के यात्री गुजरते हैं और ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिसमें वहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा और हर महीने में एक-दो मौत जरूर होती है। मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

(श्री महेन्द्र पाल मीना)

कि उस दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर आंधी तहसील में हमें एक ट्रोमा अस्पताल देने की कृपा करें, ताकि हम समय पर एक्सीडेंट होने वालों का इलाज करा सकें। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। भारत माता की जय।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गणेशराज बंसल।

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 के सामान्य वाद-विवाद पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी व उनकी पूरी कैबिनेट एवं उप मुख्य मंत्री माननीय दिया कुमारी जी द्वारा जो वित्त विभाग की तरफ से बजट पेश किया गया है, यह बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सभी वर्गों के हितों को साध कर उनके द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया है और सभी वर्गों को साधने का भरसक प्रयास किया गया है। हम हां पक्ष और ना पक्ष दोनों के बीच की एक कड़ी हैं। मैं पहली बार चुन कर आया हूं और मैंने यह देखा है कि जनता हमें यहां अपने हितों की रक्षा के लिये चुनकर भेजती है, लेकिन यहां पर हमारे माननीय सदस्य वाद-विवाद में ज्यादा समय व्यतीत करके जनता के हितों पर मंथन नहीं करते। एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस सरकार आज ना पक्ष की तरफ बैठी है तो उनमें कोई कमियां रही होंगी। हां पक्ष को भी चाहिये कि हम भी जनता के हितों का ध्यान रखें, ताकि अगली बार चुनाव में हमें ना पक्ष की तरफ न बैठना पड़े।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर ध्यान नहीं दिया गया है। आज के समय दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र में लोग सड़कों के अभाव में जी रहे हैं। आज के समय गांवों में थ्री फेज की लाइट नहीं है। गांवों में लंबे-लंबे कट लग रहे हैं, उन्हें थ्री फेज की बिजली नहीं मिल रही है, मात्र 6 घंटे की बिजली गांवों में मिल रही है। इस भीषण गर्मी में दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को बहुत ही दुखी क्षणों में अपना समय व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अच्छी बिजली नहीं मिल पा रही है और उनके बच्चे इस भीषण गर्मी में प्रताड़ित हो रहे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं हैं,

(श्री गणेशराज बंसल)

यहां तक कि बिजली के इंसुलेटर तक हमारे विभाग के पास नहीं हैं। गांवों की ढाणियों में विद्युत कनेक्शन देने की जो बात है, वह भी बिजली के सामान के अभाव में कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के साधन भी बहुत कम हो रहे हैं। राजस्थान रोडवेज का बेड़ा भी कम हो रहा है और उनका स्टाफ भी बहुत कम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के लिये शहर में जाते हैं, उन्हें समय पर साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण वे अपनी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। राज्य सरकार को परिवहन के साधनों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

जलदाय विभाग के पास भी स्टाफ दिनों-दिन कम होता जा रहा है। एन.जी.ओ. के माध्यम से स्टाफ लेकर उनके द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी डिग्गियां भी बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। मैंने देखा है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की डिग्गियों में कुत्ते तक नहाते रहते हैं और जनता को बहुत ही दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जबकि एक आम आदमी का हक है कि उसे स्वच्छ पानी मिले। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये, क्योंकि जब भी कोई जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग सड़कों की मांग करते हैं, स्वच्छ पेयजल की मांग करते हैं और थ्री फेज बिजली की मांग करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए। आपका समय पूरा हो गया।

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): आपने समय दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अतुल भंसाली।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय,

'ॐ असतो मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय।'

हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। मंगलाचरण की इस प्रार्थना का

(श्री अतुल भंसाली)

तात्पर्य हमारी डबल इंजन सरकार के प्रथम बजट से झलकता है। पूर्ववर्ती सरकार के नकली दावों से विपरीत हमारे ठोस वित्तीय प्रबंधन की 100 परसेंट गारंटी वाला हमारा यह बजट है और भजन लाल सरकार का भी प्रथम बजट है।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन चुनावी लाभ के लिये जिस तरह से वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार, आनन-फानन की योजनाओं के अंधकार से स्वतंत्रता की प्राप्ति के 100 वर्ष पूर्णता के 2047 के 25 वर्षों के विजन को लेकर ठोस वित्तीय प्रबंधन युक्त प्रदेश के सुनहरे भविष्य वाली हमारी सरकार के प्रथम बजट का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि हमारी सरकार और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इतना शानदार बजट इस सदन में प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय, नकल, बजरी, घातक मादक पदार्थ के माफियाओं के अपराधों के सामने नत-मस्तक कांग्रेस सरकार से अपने भविष्य को अंधकारमय देख रहे युवाओं के सुनहरे भविष्य को समर्पित है हमारी राष्ट्रवादी भाजपा सरकार का प्रथम बजट।

बजट उसके पांच साल के कार्यकाल का विजन डाक्यूमेंट होता है। डबल इंजन की सरकार का प्रदेश के विकास को समर्पित डबल शक्ति से युक्त बजट युवा शक्ति को समर्पित बजट है, जो प्रदेश के प्रत्येक जिले, प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए ठोस योजना और गारंटी एवं वित्तीय प्रबंधन वाला बजट है। इस बजट पर किसान, व्यापारी, शहरी, ग्रामीण और सभी राजस्थानवासी एक लंबी आशा के रूप में एक उम्मीद से देख रहे हैं, उसको पूर्ण करने में यह सरकार जरूर सफल होगी।

मैं अभी पूर्व में साथी विधायकगण की बात को सुन रहा था। मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं, पर राजनीति में नया नहीं हूं। मैं पिछले 40 वर्षों से राजनीति से जुड़ा हुआ हूं और इस राजनीति के अन्दर जब भी चुनाव हुए, जब भी बात होती थी, मैं एक ही नारा सुनता था, पानी-बिजली दे न सके, वह सरकार निकम्मी है। मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया कि यह नारा इतने लम्बे समय तक क्यों चला। सरकारें कई पक्षों की आयीं और गयीं, पर यह नारा आज तक अजर-अमर है। यह आज तक अजर-अमर था, क्योंकि पहली बार राजस्थान की चुनी हुई सरकार ने अपने पहले साल के विजन के रूप में राजस्थान में पानी की समस्या कैसे दूर हो, इस बारे में ध्यान दिया और बिजली की समस्या कैसे दूर हो, इस बारे में ध्यान दिया।

(श्री अतुल भंसाली)

जो हमारे साथी विधायकगण इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह सरकार लंबे वादे कर रही है, सुनहरे सपने दिखा रही है, उसकी वजह यह है कि उनका पालन-पोषण और उनका वैचारिक पालन-पोषण उस जगह हुआ, जहां पर तत्कालीन लाभ लेकर चुनकर आ सकते हैं और राजनीति कर सकते हैं। उसी तरह का उनको अभी तक ज्ञानवर्धन हुआ है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लंबे विजन डाक्यूमेंट बनाने का क्या फायदा होता है, लंबे विजन का क्या फायदा होता है। उनको अगर देखना हो तो पिछले साल के, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की 2014 से 2024 की जो सरकार है, एक लंबे विजन के साथ आदरणीय मोदी जी ने 2014 में 2030 का विजन रखा है और 2023 में 2047 का विजन रखकर आजादी के अमृतकाल में भारत को क्या-क्या अचीव करना है, उसके बारे में चर्चा की है।

इस बजट के अन्दर जो घोषणाएं हुईं, मेरे पूर्ववर्ती सदस्यों ने उस बारे में बताया है कि जल के अन्दर जल जीवन मिशन में क्या घोटाले हुए। हमने इस बजट में क्या एलोकेशन किया, कैसे हम काम करेंगे। सड़क के लिए हम क्या काम करेंगे, आर.ओ.बी., ग्रीन-वे, एक्सप्रेस हाईवे के लिए हम क्या काम करेंगे और उस बारे में सभी योजनाएं आप सबके सामने रखीं, उनको मैं विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा, पर मैं यह जरूर बताऊंगा कि उनका बार-बार एक कथन था कि कुछ योजनाओं को उन्होंने पांच साल के अन्दर पूरा करने की बात की, किसी को दो साल में पूरा करने की बात की। यह बात हमारी सरकार ने, हमारे बजट में इसलिए कही क्योंकि उनकी कुछ योजनाएं धरी की धरी रह गयीं। आदरणीय कुलदीप जी ने उस बारे में विस्तृत चर्चा की कि पिछली सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की थीं, उन घोषणाओं का शुभारंभ भी नहीं हुआ और वे धरी की धरी रह गयीं। योजना उसी को कहते हैं कि जिसको बनाकर दो-तीन-चार साल उस पर काम किया जाए, क्योंकि एक साल में उस काम को पूरा नहीं कर सकते। कमिटमेंट होना चाहिए कि हम इस बजट में यह दे रहे हैं, अगले साल यह एलोकेट करेंगे। थर्ड ईयर यह एलोकेट करेंगे, उसको कमिटमेंट कहते हैं क्योंकि इन्होंने कभी योजना बनाकर काम नहीं किया। इसका सब्जेक्ट ही इनको मालूम नहीं है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं।

उद्योग के क्षेत्र में हमारी भाजपा सरकार का यह बजट है। इस विधान सभा के अन्दर सदस्यों के द्वारा पिछले टाइम से जो मांग इस सदन

(श्री अतुल भंसाली)

में चल रही है, इतना जल्दी उसका निराकरण हो जायेगा, इस बारे में कभी नहीं सोचा था। कुछ दिन पहले रीको के वार्षिक प्रतिवेदन के ऊपर विचार हुआ था। उस विचार में कई लोगों ने इंडस्ट्री के लिए अपने सुझाव दिये थे। मैं बहुत हर्ष के साथ कहता हूं और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उस पार्टी का रिप्रजेंटेशन यहां पर कर रहा हूं, जिस पार्टी की सरकार ने रीको के अन्दर और इंडस्ट्री के अन्दर उस दिन जो मांगें मांगी थीं, वे सात-आठ दिन बाद इस बजट के अन्दर उन मांगों को मानकर मूर्त रूप दिया गया है। इतनी संवेदनशील बातों को माना। जैसे कि जोधपुर में एम्स के बाद रीको का एरिया है। उसके अन्दर सारी इंडस्ट्री चलती है, प्रदूषण होता है, डाक्टरों ने कह दिया। उस दिन सदन में यह बात रखी और कल उसकी नीति की घोषणा कर दी गयी।

जिस तरह से हमारे कांग्रेस के साथी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, तब उन्होंने राज्य सरकार की बात न करके केन्द्र सरकार के बजट और उसके ऊपर चर्चा चालू कर दी, तो मैं उनको भी एक जवाब देना चाहता हूं। उनका कहना था कि 45 हजार करोड़ केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए नहीं दिया होता तो क्या होता? दूसरा, रोहित जी ने सवाल उठाया कि केन्द्र से पहले राज्य का बजट क्यों लाये? इसकी आपको इतनी जल्दी क्या थी और केन्द्र की योजना के बजट के अन्दर आपको क्या-क्या मिलता है, किस मद में कितने रुपये मिलते हैं, उस मद के हिसाब से राज्य का बजट बनता तो शायद आप जो बजट बनाये, वह पूरा होता। पर हम लोग, हमारी भजन लाल सरकार यह बजट पहले इसलिए लेकर आयी कि उन्होंने जनता से जो वादे किये थे और जनता ने उनको भरोसा देकर इस प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया, सदन का नेता बनाया, उनके अन्दर इतना आत्मविश्वास था कि हम जो बजट के अन्दर वादे करते हैं, यह भाजपा सरकार, नरेन्द्र मोदी और भजन लाल की गारंटी है। यह गारंटी कभी फेल नहीं होगी और इस गारंटी के दम पर ही उन्होंने इस बजट की रचना की है।

उन्होंने जी.एस.टी. की बात की, जी.एस.टी. से हमको कितना पैसा मिलेगा। हमेशा कम हो रहा है, पर उनकी सूचना के लिए बता दूं, 2016 में जी.एस.टी. चालू हुई थी। 2018 के अन्दर 82 हजार करोड़ का एवरेज मंथली कलेक्शन था, जो 2024 में 01 लाख 68 हजार करोड़ रुपये पर-मंथ कलेक्शन केन्द्र सरकार का होना चालू हो गया है। उसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और यह

(श्री अतुल भंसाली)

वृद्धि आगे कायम रहेगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान की जी.डी.पी. 2014 में, जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार आयी थी, उस समय से बढ़कर अब लगभग दोगुनी जी.डी.पी. हो गयी है। आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी जी.डी.पी. ग्रोथ भारत के अन्दर हो रही है। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन इन्फ्लेशन का उठाया था। 2014 के अन्दर जब केन्द्र में भाजपा सरकार आयी थी तो इन्फ्लेशन 8 परसेंट था और 2024 में इन्फ्लेशन 4 परसेंट है। उनको यह भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वे बार-बार कह रहे थे कि इन्फ्लेशन उस समय से भी बढ़ गया, ग्रोथ घट गयी। उनके सारे दावे सिर्फ जुमले हैं। वैसे ही जुमले हैं, जैसे कांग्रेस की सरकार के पिछले जुमले थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो माननीय अशोक गहलोत जी का गृह क्षेत्र है। मैं आपको तीन-चार नमूने बताकर बात खतम करूंगा। मुझे बोलना कुछ और था पर चूंकि यहां बात सुनकर उसका जवाब देना ज्यादा जरूरी था। जो मुख्य मंत्री पिछली सरकार में थे, उनको खुद यह कहना पड़ा कि जोधपुर में आकर एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर की व्यवस्था कराओ, आठ किलोमीटर दूर पाल रोड में मेरी सभा है। अफसरों को इतना कह दिया, उसके बाद भी इतने गड्ढ़े हैं कि मैं रोड से नहीं जा सकता। यह एक पहला उदाहरण है।

दूसरा उदाहरण, उन्होंने जोधपुर के अन्दर आर.यू.आई.डी.पी. से करीबन 300 करोड़ रुपये का बजट दिया। तीन विधान सभा क्षेत्र लगते हैं, सूरसागर, जोधपुर शहर और सरदारपुरा। तीनों में बराबर पैसे बांटे। जब काम चालू हुआ चूंकि उनका मन सरदारपुरा में ज्यादा लगा रहता है, जोधपुर शहर की 68 में से 33 किलोमीटर रोड और सूरसागर की 58 में से 14 किलोमीटर सीवर लाइन पूरी की पूरी सरदारपुरा में घोटाले से शिफ्ट कर दी और वहां भी सीवर लाइन नहीं बनी। यह उनकी मंशा है। वे जो बजट की बात करते हैं, बजट के एक भी वादे को पूरे करने में वे अक्षम रहे और इस सरकार ने पूरे मनोबल से उसको पूरा करने के लिए इस बजट का निर्माण किया और हमारे भजन लाल जी के नेतृत्व वाली पूरी कैबिनेट ने उस बजट को अप्रूव कर सदन में रखा, सुश्री दिया कुमारी जी ने उस बजट को पेश किया। पूरे सोच-विचार करके समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति को भी, भले ही वह युवा हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब जगह, उन्होंने सब लोगों का ध्यान रखकर,

(श्री अतुल भंसाली)

सबका समावेशी विकास करने के लिए यह बजट रखा है और मैं समझता हूं कि इस बजट से विकसित राजस्थान के साथ-साथ विकसित भारत का नरेन्द्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, वह पूरा होगा।

मैं एक बात जरूर इस सदन के माध्यम से वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमने कुलपति को तो कुलगुरु बना दिया, पर पिछली सरकारों ने ऐसे जो रिटायर कुलगुरु और प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी पेंशन की सुध नहीं ली। मैंने बार-बार इस बारे में लिखा भी है और आगे भी मैं इसकी मांग करूंगा कि ऐसे सभी ज्ञानियों की और जो हमारे गुरु रहे हैं, उनके पेंशन की जो भी राशि है, वह सरकार खुद वहन करके नियमित रूप से उनको पेंशन मिल सके, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री समरजीत सिंह।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, आज बजट 2024-25 पर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए आपने जो समय दिया, उसके लिए आभारी हूं। कल ही राज्य का बजट पेश हुआ। सरकार की हिम्मत की दाद दूंगा कि सेन्ट्रल बजट से पहले आपने राज्य बजट पेश किया। शायद आपकी डबल इंजन की ताकत का दिखावा करना चाहते होंगे। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की जनता को इससे फायदा मिले।

मैं पहले भी दस साल रहकर गया, पन्द्रह साल बाहर रहा हूं और फिर आया हूं विधान सभा में। जो मेरा अनुभव है कि हम जब भी बैठते हैं या चर्चा करते हैं तो हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में लगे रहते हैं, जबकि इस प्रजातंत्र में होना ये चाहिए कि हम यहां बैठकर राजस्थान के बारे में राजस्थान का जो आप लोगों ने बजट पेश किया है, उसके बारे में पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करें और एक-दूसरे से चर्चा भी। अभी जोधपुर से आने वाले विधायक कह रहे थे कि पिछली सरकार ने बजट पर मंथन नहीं किया होगा, चर्चा नहीं की होगी। हम भूल जाते हैं कि बजट तैयार करने वाले अधिकारी तो वही के वही हैं जो हमारे समय थे और आपके समय भी वही के वही हैं। हम लोग इस चीज से बाहर नहीं निकलते। हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और असली मजा तो जो लेने वाले हैं, वे ही ले लेते हैं।

(श्री समरजीत सिंह)

मेरा निवेदन है आपसे कि प्रजातंत्र में खूबसूरती तभी होगी जब हम एक-दूसरे को चैक एंड बैलेंस करें और अपनी बात कहें और सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। आपको मौका दिया है जनता ने, अवसर दिया है अगले पांच साल के लिए। हमें सोचना पड़ेगा कि राजस्थान में पांच-पांच साल से सरकारें क्यों बदलती रही हैं। कमियां रही होंगी तभी हम भी यहां आए, तो क्या आप हमें वह बता-बता कर, आप भी वही कमियां वापस रिपीट करना चाहते हैं तो सोचना चाहिए आपको। नहीं करेंगे, ये तो सबको लगता है, परंतु पिछले 20-25 साल का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए यही चल रहा है। फिर समय चला जाता है और बातें रह जाती हैं। रोहित जी ने भी बहुत बजट की बात की। मैं इकोनौमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, पॉलिटिकल साइंस का हूं तो मैं ज्यादातर मेरे क्षेत्र की और जनता की बात ही करना चाहूंगा।

मैं यहां पर वित्त मंत्री जी ने जो कोट किया था, अमरीकन एक्स प्रेसीडेंट रूजवेल्ट को कि, “The country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a reasonably good place for all of us to live in.” हम सबके लिए रहने के लिए अच्छा वातावरण बने, अच्छी जगह बने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। वह सरकार का दायित्व है। रहने के लिए, सुविधाओं के लिए क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में क्या किया है आप लोगों ने, क्या आपने प्रस्ताव रखे, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। पिछली सरकार ने जिले बनाए 19 जिले बनाए। एक पॉजिटिव सोच के साथ बनाए कि जितना एडमिनिस्ट्रेटिवली कम एरिया होगा, लोगों को ज्यादा फायदा होगा। वह अलग बात है कि अब सरकार आने के बाद में आपने रिव्यू कमेटी बनायी है, उसके लिए मंथन करने की बात की है। इस बजट में तो उस बारे में कोई चर्चा नहीं की।

मेरा निवेदन है कि आपने एक अच्छी बात भी की है 'वन स्टेट-वन इलेक्शन'। इसका मतलब मैं जो समझा हूं वह यह है कि नगरपालिका, पंचायती राज के चुनाव एक साथ होने चाहिए। होने भी चाहिए, समय खराब होता है आचार संहिता में परन्तु इसको कैसे करेंगे? अभी जिले के बारे में आपने सोचा नहीं, जिले के बारे में आपने बात नहीं की। डिलिमिटेशन भी पंचायती राज का आपने जिले बना दिए, उसके हिसाब से भी करना पड़ेगा। नगरपालिकाओं के भी करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आप मिल-बैठ कर कमेटी

(श्री समरजीत सिंह)

बनाकर अच्छे विचार से करें, ताकि आने वाले समय में राजस्थान को इसका फायदा मिले। अलग-अलग जगह गांवों में समस्याएं हैं। एस डी ओ हैडक्वार्टर अलग है, पंचायत समिति अलग है और तहसील अलग है। लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मेरे भीनमाल के अन्दर एक गांव है, 7 किलोमीटर पर पंचायत है और उसको 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जसवंतपुरा। इस तरह की जो अनियमितताएं हैं या जो अलग-अलग बन चुके हैं, इनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और इस बारे में सोचे। यह मेरा आपसे निवेदन है।

जैसा कि मैंने कहा मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी और सड़क। बिजली और पानी तो एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। आप कितने भी दावे कर लें पिछले 6 महीने के, बिजली के हालात राजस्थान में सबसे खराब रहे। हमारे पास गांव से बच्चों के फोन आते हैं कि हमने गुनाह कर लिया कि हमारे शाम को बिजली नहीं मिले, पढ़ने के समय नहीं मिले। गृहिणियों को उनके काम-काज के लिए बिजली नहीं मिले। अभी जीवाराम जी बैठे कह रहे थे, पसीना तो पोंछ रहे थे इस ए.सी. में बैठकर, परंतु बिजली पूरी आ रही है। हमें तो दो मिनट बिजली नहीं आती तो हम परेशान हो जाते हैं, तो गांव में जो बिना बिजली के पूरी रात निकालते हैं, उनकी हालत क्या होगी? आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। खाली अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा।

मेरा अनुरोध है कि एग्रीकल्चर कनेक्शन, हो सकता है कि हमारी सरकार ने 2016 से 2022 तक के सारे कनेक्शन और डिमांड भरा कर रख लिए। अब हालात ये हैं कि डिमांड बरत गये, लोगों ने अपने ट्यूबवैल खुदवा दिए, परन्तु सामान नहीं मिल रहा है। लोग भटक रहे हैं। इस बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैसों के नीचे आ गये लोग, गरीब किसान किस तरह से एक ट्यूबवैल खुदवाता है, यह आपको सोचना पड़ेगा। लोन लेता है, उधार लेकर आता है, परंतु उसको सामान नहीं मिल रहा है। इस बारे में भी सरकार हाउस को एड्रेस करे और समाधान करे।

सोलर की बात की गयी। हर गांव में दो मेगावट के सोलर प्लांट लगाने की बात है, अच्छा आइडिया है। अगर इसको आप क्रियान्वित करते हैं तो लोगों को फायदा ही होगा और बिजली की जो भारी समस्या है, इससे हमें निजात मिलेगी। बिजली से जुड़ा हुआ पानी है। जब बिजली ही नहीं आ रही है तो लोगों को पीने का पानी कहां से मिलेगा? हमारे यहां नर्मदा स्कीम बनी। 15 साल हो गये, 2013 में स्कीम पास हुई। सरकारें आयीं-गयीं, अभी तक

(श्री समरजीत सिंह)

पानी पीने को नहीं मिला। आपकी सरकार भी आकर गयी, हमारी भी आकर गयी और अभी तक लोग तरस रहे हैं। इसको भी गंभीरता से लेकर फंड अलाट करके सरकार को चाहिए कि उस पर कार्य करे।

कृषि के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इर्रिगेशन वैल, ये हमारे गुड़ामालानी से आए हुए मंत्री जी बैठे हैं, शायद इन्होंने मेहनत करके खुद का एरिया गुड़ामालानी में डी.पी.आर. बनाने का काम तो स्वीकृत कराया है, परन्तु सांचौर का एरिया जो लगता हुआ है, जीवाराम जी का और हमारा, उस एरिया में भी सर्वे करना चाहिए ताकि जो बीच में वंचित रह गये, जमाई है हमारे, जमाई है सांचौर के, ले गये तो सांचौर का भी पूरा ध्यान रखकर सरकार से बैठकर इस चीज को कराएं, ताकि लोगों को फायदा मिले। सबसे बड़ी योजना, माही योजना के लिए कई सालों से संघर्ष चल रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माही का पानी पूरे गुजरात में खम्भात की खाड़ी तक हमारा पानी उपयोग हो रहा है, फसलें लहलहा रही हैं और हम लोग प्यासे बैठे हैं।

पिछली सरकार ने डी.पी.आर. में पैसा स्वीकृत किया था। मैं अनुरोध करता हूं आपके मार्फत सरकार से, किया था, जो भी किया हो, कम से कम उसको हाउस में लिया तो सही।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आपको भी ध्यान है, क्या किया था।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): एम.एल.ए. साहब, उसको लिया तो सही कम से कम।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि इस योजना को भी टॉप प्रायोरिटी पर लें। इसी तरह से मेरे यहां पर एक बांडी-सिणधरा बांध बना। 2003-2004 में बना और इतने साल हो गये आज तक उससे इर्रिगेशन नहीं हुआ। कैनालें टूट गयीं। लोगों को पानी नहीं मिला है। बांध भरा पड़ा रहता है, वहां मछली पालन हो रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से कि उससे जो डाउनस्ट्रीम के गांवों में जहां पर खेत सूख गये हैं, वहां पर कार्य किया जाए। इस पर कैनाल के लिए स्कीम बनाई जाए। एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

पी.डब्ल्यू.डी., वो कहते हैं मारवाड़ी में मामा रो ब्याव, मां पुरसगार,

(श्री समरजीत सिंह)

तो वित्त मंत्री जी ने खुद के पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा पैसा दिया। अच्छी बात है। पूरे राजस्थान में प्रस्तावित जो स्कीम्स हैं, वे पूरी हों और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे कार्य हों, परन्तु इस सरकार की नाक के नीचे नेशनल हाईवे जयपुर से किशनगढ़ तक जो लोग परेशान हो रहे हैं, उप मुख्य मंत्री जी भी विराजे हैं, टोल लिया जा रहा है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है। लोग चार-चार, पांच-पांच घंटे परेशान हो रहे हैं। सरकार आपकी है, ऊपर बात करिए। कम से कम इस चीज का समाधान किया जाए। (व्यवधान) ब्रिज बन रहे हैं, सही बात है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): तो पैसा किस का ले रहे हैं? उसके लिए भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्या? यह आप लोगों को सोचना पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): एजुकेशन के बारे में भी निवेदन कर देता हूं। आप लोगों ने कालेज एजुकेशन के लिए बात की। यूजी. से पी.जी. करने की बात की। इसमें भी बिना राजनीति किये, जहां वास्तव में डिमांड है, पुरानी डिमांड है वहां पी.जी. कालेज खोली जाए। सेठ लोगों ने मेरे भीनमाल में 1960 में बनाया वह अभी भी खाली यू जी कालेज है, उसको पी.जी. कालेज किया जाए। सरकार ने स्कूल क्रमोन्नत की बात की। हमारी सरकार ने तो सभी उच्च माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया था, पर आपने वहां से 100 ही की है और नई स्कूल खोलने का 50 का ही किया है। मेरा अनुरोध है कि बच्चों की संख्या देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए इन चीजों पर निर्णय किया जाए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री देवेन्द्र जोशी।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के ऊर्जावान मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा और दूरदृष्टि वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत बजट, मैं एक शब्द में कहूं तो यह बजट राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना वाला बजट है। उसका मैं तथ्य गिनाता हूं, तथ्यहीन बात नहीं कर रहा। विपक्ष से जो भी लोग बोले, या तो वे भारत सरकार की नीतियों को लेकर बोले या ऊल-जलूल बातें बोलीं

(श्री देवेन्द्र जोशी)

लेकिन इस बजट पर उन्होंने कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं की, न ही उन्होंने कोई ऐसा दावा पेश किया। मैं एक बानगी आपके सामने पेश करता हूं।

आज मैंने माननीय नेता, प्रतिपक्ष का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि यह खोखले वादों का बजट है, विजनलैस है, इस तरह की बातें आज अख़बार में छपीं। मैं इस सम्बन्ध में केवल एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं जो सरकार की एफिशिएंसी बताती है। कल बजट में घोषणा हुई जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 करोड़ के आर.ओ.बी. निर्माण की घोषणा, एम्स चौराहे पर जो घोषणा हुई, उसकी त्वरित एफिशिएंसी बताता हूं। आज उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का, डी.पी.आर. बनाने का आदेश जारी हो गया। 24 घंटे के अन्दर-अन्दर जोधपुर विकास प्राधिकरण ने उस पर काम प्रारम्भ कर दिया। मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार को और माननीया वित्त मंत्री जी को, यहां बैठे स्वायत्त शासन मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो घोषणा हुई थी उसके 24 घंटे के अन्दर-अन्दर उस पर क्रियान्वयन का काम प्रारम्भ किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस शहर से आता हूं उस शहर ने तीन-तीन मुख्य मंत्री दिए हैं। उन मुख्य मंत्रियों की चर्चा करना सामूहिक रूप से जरूरी समझता हूं और अन्त में उसका सार भी आपको बताऊंगा।

पहले मुख्य मंत्री हुए श्रद्धेय जयनारायण जी व्यास। उन्होंने सत्ता के लिए कोई समझौता नहीं किया और अपनी कुर्सी छोड़ दी। जब उनके निकटतम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी ही चिता जलाई, मैं देख-देख हंसता, तू क्यों रोता भाई। इस तरह के बयान देकर उन्होंने राजनीति में शुचिता के उच्च मापदण्ड स्थापित किये। आज भी राजस्थान का इतिहास जानता है कि स्वर्गीय श्रद्धेय श्री जयनारायण जी व्यास ने राजनीति में शुचिता का इतिहास कायम किया है, उच्च मापदण्ड कायम किये हैं, उससे आज भी राजस्थान की जनता वाकिफ है।

दूसरे मुख्य मंत्री रहे स्वर्गीय बरकतुल्लाह खान साहब। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत अल्प रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह का भाईचारा रखा, वह जोधपुर में प्यारे मियां के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने जोधपुर में सद्भाव का इतिहास कायम किया और आज भी उसी इतिहास पर हमारी जोधपुर की जनता कायम है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

(श्री देवेन्द्र जोशी)

तीसरे मुख्य मंत्री हुए माननीय अशोक जी गहलोत। पिछले पांच साल में कुर्सी बचाने के लिए क्या-क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए। उन हथकंडों में जिस तरह के भ्रष्टाचार का नाटक हुआ, जोधपुर उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा, क्योंकि उसका केन्द्र बिन्दु जोधपुर था ...(व्यवधान) मैं एक-एक का चिट्ठा खोल दूंगा, आप निश्चित रहिए। मैं पांच साल जिला अध्यक्ष था। एक-एक चिट्ठा खोलूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): पांच साल के कार्यकाल का, भ्रष्टाचार का एक-एक चिट्ठा खोलूंगा। (व्यवधान) सदन पटल पर रखूंगा।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): जोधपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ, एक-एक भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा यहां रखने वाला हूं। (व्यवधान) मैं उस समय पांच साल भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था। काले कारनामे मेरे पास दर्ज हैं, उन सभी का काला चिट्ठा सदन की मेज़ पर रखूंगा। जोधपुर में भ्रष्टाचार का नंगा नाच चला, चाहे वह जे.डी.ए. हो या कोई भी विभाग हो। माननीय विधायक अतुल जी भंसाली ने रूडिप का मामला आपके सामने रखा। रूडिप नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले हैं ...(व्यवधान) आप निश्चिंत रहिए, मैं सभी की पोल खोलूंगा। मेरे बीकानेर के साथी ने एक मंत्री की खोली है, मैं मुख्य मंत्री की खोलने वाला हूं, निश्चित रहिए। पांच साल जिला अध्यक्ष रहा हूं, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि जोधपुर में पिछले पांच साल में जितने भी काम हुए हैं, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से हो, चाहे जलदाय से हो, चाहे स्वायत्त शासन से हो, उनकी क्वालिटी ऑडिट करवाई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पैसा कहां का था, पैसा लगा कहां, वहां भी लगा कि नहीं लगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का नंगा नाच जोधपुर की जनता ने देखा है। उसी का दंश है कि पूर्व मुख्य मंत्री के अलावा कोई जीतकर नहीं आया। नगर निगम बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बना ...(व्यवधान)

आप निश्चिंत रहिए, सब बातें बताने वाला हूं। सबूत के साथ रखेंगे, आप निश्चित रहिए। कोरी कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं। सबूत के साथ सदन की मेज़ पर रखूंगा। जब सदन में बोल रहा हूं तो निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आप सभी की पोल खोलकर रखूंगा। (व्यवधान) आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? मैं आपके उतावलेपन को भी समझता हूं,

(श्री देवेन्द्र जोशी)

उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान) सब गुरु हैं। वह तो चिट्ठे सामने आएंगे तब मालूम पड़ जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में भ्रष्टाचार का जिस तरह नंगा नाच हुआ, उसकी जांच आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सभी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि एक स्पेशल टीम गठित करके, जोधपुर में पिछले पांच सालों में जो भी काम हुए हैं उनकी क्वालिटी की जांच हो, गुणवत्ता की जांच हो कि किस कार्य के लिए पैसा दिया गया, कहां खर्च हुआ। उसकी जांच होना भी आवश्यक है। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

हमारे ऊर्जावान मुख्य मंत्री, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा की घोषणाएं थीं, उन पर चर्चा करते समय कई विपक्षी सदस्य बोल रहे थे। मैं एक ही जवाब देता हूं, यह नरेन्द्र भाई मोदी के मार्गदर्शन पर चलने वाली सरकार है। भजन लाल जी के नेतृत्व में, ऊर्जावान वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के नेतृत्व में घोषणाएं हुई हैं। एक बात साफ कर देता हूं कि पूरे देश ने मोदी जी कि जिस एक बात पर विश्वास किया, वह है हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। आप निश्चिंत रहिए। हो सकता है आपको कोई भड़ास हो। मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं, इस बात का सम्मान करना सीखिए। तीसरी बार बने हैं तो किसी जादू की छड़ी से नहीं बने, अपने कार्य के आधार पर बने हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार कार्य करके दिखाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है।

साथियों, पिछले लम्बे समय से मैं एक चीज देख रहा था, पिछले पांच सालों में बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई लेकिन उन घोषणाओं में आखिर हुआ क्या? किसी को अटका दिया गया, किसी को लटका दिया गया और जनता को भटका दिया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): इन तीन मूल वाक्यों पर पिछली कांग्रेस की सरकार चली लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार काम करके दिखाएगी और काम करने का एक उदाहरण, 24 घंटे में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वह मैंने आपके सामने रखा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गणेश घोगरा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, बजट जो पेश किया है, इसमें आदिवासी, युवा, गरीब, पिछड़े वर्ग के लिए बिलकुल शून्य के बराबर यह बजट पेश किया है। यह बजट काफी निराशाजनक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, लेकिन यह बजट खाली यहां पर ए.सी. रूम में बैठकर बनाया जाता है। धरातल पर क्या हो रहा है, धरातल में क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या मांगें हैं, उसको लेकर आज तक कोई बजट बनाया नहीं है। वहां से आज हमारे मंत्रीजी आ रहे हैं, जनजाति मंत्रीजी, झाडोल-कोटड़ा में ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि एक मां को अपने कलेजे के टुकड़े को दलाल के माध्यम से बेचने का समय आ गया? ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गयी? वहां पर मंत्रीजी के बिलकुल पांच किलोमीटर एरिया की बात मैं कर रहा हूं, इनके विधान सभा क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं। साठ हजार रुपये में बच्चे का सौदा हो रहा है, कहीं पर चालीस हजार रुपये में बच्चे का सौदा हो रहा है। कोई भी मां अपने बच्चे को बेचती नहीं है, लेकिन वह मां मजबूरी में, अपने दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके खाने के लिए, भरण-पोषण के लिए, मजबूरी में, उनको खाना नहीं मिल रहा है दो टाइम, इसलिए उन बच्चों का दलाल के माध्यम से सौदा हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। मंत्रीजी के खुद के एरिया में बच्चे बेचे जा रहे हैं तो मंत्रीजी क्या कर रहे हैं?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपको कुछ पता ही नहीं है। यह सारे कारनामे आपके समय में हुए हैं। आपके समय में ही हुए हैं, आप उनको पढ़ो। (व्यवधान)

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, आज भी आदिवासियों को उनका हक-अधिकार नहीं मिला है। खाली कागजों में ही उनको हक-अधिकार मिला है, वास्तविक रूप से धरातल पर जो हक-अधिकार मिलना चाहिए, वह हक-अधिकार आज तक उन आदिवासियों को नहीं मिला है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपको रिएक्शन देना है? आप इस पर चर्चा करवा लो। (व्यवधान)

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी तो दो साल कोरोना था, ढाई साल हमने शासन किया, लेकिन किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया, कोई भूख से नहीं मरा। वह हमारी पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब हम हमारे क्षेत्र की बात करते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बालिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): हमारे हक-अधिकार की बात करते हैं तो हमको यहां रोका जाता है। जब इनके सदस्य बोलते हैं तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं और आप भी फिर हमको ही बिठाते हो बार-बार। उनको नहीं बिठाओगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के हैं। हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है?

श्री सभापति: बोलिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): हमारे साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए। हमको भी बोलने का मौका दो, हम भी हमारे क्षेत्र की मांग रखने यहां पर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की विशेष ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें। आप बोलते जाएं।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र की, युवाओं की विशेषकर यह मांग है कि सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि आज जो भी आरक्षण मिला है, हमको उसका फायदा नहीं मिला है। अगर विज्ञप्ति, कोई भर्ती निकलती है, भले ही कोई पुलिस की निकले, पटवारी की निकले, सचिव की निकले तो उसमें अगर हमारा एस.टी. का लड़का जनरल मैरिट टॉप करता है, फिर भी उसकी मैरिट एस.टी. कोटे में बनायी जाती है, तो फिर यह आरक्षण किसको मिल रहा है? यह हमारा ज्वलंत मुद्दा है। इस बारे में कई बार आंदोलन भी हुए, कई बार हमने ज्ञापन भी दिये हैं पर आज तक हमारी यह मांग पूरी नहीं हुई है।

उसके बाद प्रशासनिक सेवा में एस.टी. को राज्य का 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, बारह-साढ़े बारह प्रतिशत, तो हमारे टी.एस.पी. एरिया को देखते हुए, हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, हमारे रीति-रिवाज को देखते हुए हमको पृथक् से, टी.एस.पी. एरिया को

(श्री गणेश घोगरा)

प्रशासनिक सेवा में 6 प्रतिशत आरक्षण अलग मिलना चाहिए। इसका बजट में कोई हवाला नहीं दिया है, यह हमारी वर्षों से मांग है। हमारी वहां पर जमीन नहीं है। एक बीघा जमीन, दो बीघा जमीन पर लोग निवासरत हैं और उनको भी भू-माफियाओं द्वारा हटाया जाता है। हमारी यह विशेष मांग है। उसके अलावा छोटी-मोटी मांग तो होती रहेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि हमारी ये दो मांग विशेष मांगें हैं, जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होंगी तो हमको वास्तव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज देश को आजाद हुए 76-77 साल हो गये। आज कई पंचायतों में पंच भी हमारे एस.टी. का बनता है, एस.टी. का सरपंच बनता है, लेकिन नाममात्र का है। उस सरपंच को कोई दूसरा ही चलाता है। सरपंच बकरी लेकर उसको चराने जा रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, तो यह कब तक चलता रहेगा? वास्तव में लाभ न हमको राजनीतिक रूप से मिला है और न ही सरकारी नौकरियों में हमको आरक्षण मिला है। आज तक हमारे टी.एस.पी. एरिया के लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। मैं यह चाहता हूं कि यह मांग हमारी जल्दी से जल्दी पूरी की जाये।

माननीय सभापति महोदय, बजट में रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग-धंधे नहीं हैं, सब अहमदाबाद पलायन करते हैं। हमारे वहां पर उद्योग-धंधे लगाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे नाथद्वारा, राजसमन्द में जो माइन्स हैं, जावर माइन्स में जो माइन्स हैं, मार्बल की जो खदानें हैं, वे किसकी हैं? वे सब पूंजीपतियों की हैं, तो उनमें क्षेत्र के स्थानीय लोग लगने चाहिए पर उनको नहीं लगाया जा रहा है। हमारे वहां पर सीसा, जस्ता, सिल्वर आदि निकाला जा रहा है और बाहर के मजदूरों को लाकर काम करवाया जा रहा है। टेक्निकल अधिकारी हैं, वे भी बाहर से आकर यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी तो हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए। मंत्रीजी, वह मजदूरी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रही है, यह आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप जनजाति मंत्री हैं। हमारे क्षेत्र की समस्या आपको उठानी चाहिए और मांग पूरी करवानी चाहिए। बाहर के लोग आकर यहां पर मजदूरी कर रहे हैं और हमारे लोग दूसरी जगह पर पलायन कर रहे हैं।

(श्री गणेश घोगरा)

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि टीएस.पी. एरिया में कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं इसलिए खाली नरेगा के माध्यम से ही हमारे लोग काम पर जाते हैं। नरेगा में टी.एस.पी. एरिया में हमारी सरकार ने 125 दिन मजदूरी के दिये थे, लेकिन आपकी सरकार के बनते ही उसको आपने 100 दिन कर दिये, 25 दिन घटा दिये। आपको दिन और बढ़ाने चाहिए थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सभापति महोदय, समय बढ़ाना हो तो देख लो आप। समय बढ़ाना हो तो देख लो, समय समाप्त हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समय पहले से ही छह बजे तक का निर्धारित है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, महंगाई के बारे में इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। इस महंगाई के दौर में जो नरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं उनकी दिहाड़ी एवं मजदूरी प्रतिदिन कम से कम चार सौ रुपये होनी चाहिए और जो कुशल कारीगर हैं उनकी सात सौ रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पानी और बिजली यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। पानी से बिजली बनती है और बिजली ही पानी को सप्लाई करती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा समय नहीं हुआ है अभी।

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। दस मिनट का समय था आपका। आपका समय समाप्त होने वाला है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, जब हमारी सरकार थी तो 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अभी छह महीने से सरकार बदल गयी तो घरों में बिजली तो नहीं आ रही है, लेकिन बिलों में बिजली आनी चालू हो गयी है। बिल पकड़ते हैं तो बिलों में करंट जरूर आ रहा है, लेकिन घरों में लाइट नहीं आ रही है। ग्यारह बजे लाइट चली जाती है और सुबह पांच बजे लाइट आती है, तो गांव के लोग इंसान नहीं हैं क्या? शहर में लाइट आ रही है लेकिन गांवों में लाइट बिलकुल नहीं दी जा रही है, कटौती कर रहे हैं, चार-चार दिन तक गांवों में लाइट नहीं आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, पानी की बात कर रहे हैं, जे.जे.एम. की बात कर रहे हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, विकसित भारत बना

(श्री गणेश घोघरा)

दिया, तो पानी की समस्या शहर में भी है और गांवों में भी है। अगर कोई जन-प्रतिनिधि जनता की मांग उठाता है पानी-बिजली को लेकर तो आपकी सरकार के माध्यम से हमारे ऊपर असत्य मुकदमा करवाया जाता है। हमारे नेताओं पर असत्य मुकदमे करवाये जाते हैं, लेकिन सरकार पानी, बिजली, शिक्षा जनता को नहीं दे सकती और आप अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं इसलिए नेताओं पर असत्य मुकदमे करवाना चाहते हैं, लेकिन हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। पूरे राजस्थान की बात है।

(समय: 17.00 बजे)

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सभी स्कूलें जर्जर अवस्था में हैं। कहीं कमरों की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी टपक रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने की वजह से कई स्कूलों में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं पानी भर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगायें ताकि बच्चों का समय खराब नहीं करें।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी। अब आप विराजें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 15 लाख कहां गये आपके? मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 लाख खाते में डालूंगा। वह दिये क्या? 15 लाख आये क्या आपके खाते में?

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। केसाराम जी, आप बोलिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा के इस पवित्र सदन में 2024-25 का परिवर्तित आय-व्ययक माननीय दिया कुमारी जी, उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री के द्वारा रखा गया। उनके हम बहुत आभारी हैं।

बजट किसी भी सरकार का विजन होता है। 5 साल में क्या काम होंगे, उसका यह दर्पण है जिसमें विपक्ष भी मुंह देख सकता है। प्रदेश की सरकार को जनता ने जिस विश्वास और स्नेह से चुनकर भेजा, उसी भावना से

(श्री केसाराम चौधरी)

प्रदेश के आम गरीब, किसान, युवा, सभी वर्गों की भावना का सम्मान करते हुए जनकल्याणकारी, विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित कर दी है।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी जिन्हें ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार आमजन का विश्वास एवं साथ प्राप्त हुआ है, उनके मार्गदर्शन में माननीय मुख्य मंत्री जी श्री भजन लाल जी की सरकार ने कार्यभार संभालते ही जनता से किये वादों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया हैं। जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सरकार बनते ही चुनाव में किये गये वादों को अल्प समय में 53 परसेंट से अधिक बजट घोषणाओं को तथा 45 बिन्दुओं पर कार्य पूरी तरह से कर चुकी है। किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपये जो केन्द्र सरकार के द्वारा दिये जाते थे, उसमें 2 हजार रुपये बढ़ाकर के 8 हजार रुपये किये।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, यहां मीटिंग मत करो। अपने-अपने स्थान पर विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपके विधान सभा क्षेत्र में जाकर देख लेना। किसानों के खातों में जमा हो चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो 1,000 रुपये मिलते थे, 1,150 रुपये देकर के हर गरीब के खाते में 150 रुपये बढ़ा दिये, वह भी आपके सामने है।

राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाने के लिए शुरू में ही प्रत्येक विधायक को 5-5 करोड़ रुपये दिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उन 5-5 करोड़ रुपयों से जो मिसिंग लिंक सड़कें बन रही हैं, उनसे आवागमन में सुविधा बढ़ रही है। आपने जो सड़कें दीं, उन सड़कों का यह हाल है कि उन ठेकेदारों को आज दिन तक पैसे नहीं मिले। आपके जमाने में स्वीकृतियां तो कर दीं, लेकिन आज भी वह सड़कें बन नहीं पायी हैं। कुछ ठेकेदार तो छोड़कर भाग गये। किसी की यह दशा हुई कि जेब में धेला नहीं। हाथी खरीदने निकले थे, लेकिन आप तो उन गरीबों का पैसा भी नहीं दे पाये, इसलिए वे सड़कें भी अधूरी पड़ी हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हमें तो देना ही है। तभी तो बन रही हैं। अभी 5 करोड़ रुपये के टेंडर निकालने शुरू कर दिये हैं। बैठ जाओ। जो आप बातें करते थे, आपकी बातों को मैं सुन रहा था। इस तरह से अगर इंटरप्ट करोगे तो एक बार भी नहीं बोलने दूंगा, समझ लेना। क्या बात करते हो? नहीं बोलने दूंगा। बैठ जाइये आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप बैठ जाइये पहले। बीच में इंटरप्ट नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गैस का सिलेंडर कभी देखा भी था? आज हमारे गरीब के घर में गैस का सिलेंडर नि:शुल्क दिया है। कभी देखा भी है आपने? बातें करते हो। आपके जमाने में 8-8 हजार रुपये की रिश्वत लेकर के गैस के सिलेंडर देते थे। कल्याण हो नरेन्द्र भाई मोदी का, जिन्होंने हर गरीब के घर में गैस पहुंचा दी। जो सिलेंडर ब्लैक से मिलता था, वह गरीब के घर में पहुंचता है।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) विराजें। बोलने दीजिये न।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: विराजें, आप क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? आप क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): किस बात की बात करते हैं।

श्री सभापति: आप विषय पर बात करें, माननीय सदस्य। आप विराजें, माननीय सदस्य विराजें ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अगर मेरे बीच में बोलने की चेष्टा करेंगे तो मैं अब की बार इनको बोलने भी नहीं दूंगा। ऐसी क्या बात है। हम कभी इंटरप्ट नहीं करते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप सुबह से ही इनको टोक रहे थे जब तो बुरा नहीं लगा और अब आपको इन लोगों ने टोक दिया तो बुरा लगा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैंने कभी बोला क्या? आपने कभी देखा है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैठे-बैठे मत बोलो। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। दोनों ही पक्षों को मौका मिल रहा है। हमारा सदस्य कोई बात कह रहा है और आपको जवाब देना है तो उसके बाद जो आपका सदस्य बोले, वह उसका जवाब दे दे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यह जो मंडली बीच में बना रखी है न, आप जब टोको तब तो बुरा लगता नहीं ... (व्यवधान) सभापति जी, इसलिए दोनों ही तरफ, इनको भी डायरेक्शन दे दो।

श्री सभापति: विराजें, विराजें। केसाराम जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति जी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, विपक्ष के नेता मंडली किसको कह रहे हैं? कौनसी मंडली है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): भजन मंडली, भजन मंडली, भजन लाल जी के सारे, आपके सदन के नेता भजन लाल जी हैं, उनके आप सारे सदस्य हो तो उन्हीं की मंडली हुई। भजन मंडली हुई।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): भजन मंडली कैसे कह रहे हैं?

श्री सभापति: अब तो ये सभी भजन कर रहे हैं न। आप विराजो। अब भजन के बिना तो काम ही नहीं चल रहा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): चुनाव के पहले भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार आयेगी तो डीजल के ऊपर वैट घटायेंगे। दो परसेंट वैट घटाकर के जनता को राहत प्रदान की।

श्री गोरधन (धोद): विपक्ष के नेता ने जो भजन मंडली कहा है उसे अपलोपित किया जाये।

श्री सभापति: देखिये माननीय सदस्य, भजन अपनी संस्कृति का गौरवशाली नाम है। अगर अपनी भजन मंडली है तो हां हैं। आपकी भजन मंडली है, उसमें क्या हो गया?

श्री गोरधन (धोद): मुख्य मंत्री भजन लाल जी की भजन मंडली नहीं हो सकती, उसको निकालो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): भजन लाल जी सदन के नेता हैं और अपन सब लोग उनके सदस्य हैं। वो चाहे वैसे कह लो। मतलब तो वही है।

श्री सभापति: बोलो, बोलो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, ये मेरा समय जाया कर रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं को सम्मान देने के लिए सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापकों में 50 परसेंट का आरक्षण किया है। यह होता है विजन कि महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाना है।

राजस्थान में गैंगस्टर बनकर के गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा था, उसके लिए गैंगस्टर फोर्स का गठन किया। जो गुंडागर्दी और आतंकवाद फैला रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह एंटी गैंगस्टर है। मुख्य मंत्री जी भी गैंगस्टर फोर्स बता रहे हैं। आप भी गैंगस्टर बता रहे हो। यह एंटी गैंगस्टर फोर्स है। यह आप समझ लो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैंने यही बोला है, एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया है।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): पढ़कर बोल रहे हैं।

श्री सभापति: शांत रहें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप ठीक से सुनते नहीं। इनके मशीन लगाओ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि ठीक है हंसी मजाक, लेकिन आप बैठे-बैठे इस तरह से कमेंट करो तो ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन जवाब मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको कोई बात कहनी है तो जरूर कहिये। परमिशन लीजिए और अपनी बात जरूर कहिये। लेकिन बैठे-बैठे कमेंट नहीं। अपन किस हाउस में बैठे हैं?

श्री सभापति: सदन में बार-बार इस तरीके से कोई भी व्यवहार करें, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बैठे-बैठे बोल रहे हो। थोड़ी-सी संसदीय परम्पराएं सीखो तो सही।

श्री सभापति: इनको भी और आपको भी, दोनों को सुनना चाहिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में पीने के पानी की जो समस्या थी, आपने कितने साल तक राज किया मगर पानी की समस्या को नहीं मिटा सके। ERCP का, पूरे राजस्थान

(श्री केसाराम चौधरी)

के लिये, 12 जिलों को पीने का पानी देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने आते ही कर दी। समझौता किया।

माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक के मामले में राजस्थान का विद्यार्थी मायूस हो गया था। 18-19 बार पेपर लीक हुए। माननीय सभापति महोदय, गरीब घर का बच्चा पढ़ने जाता तो मां-बाप देखते थे कि मेरा बेटा अब की बार परीक्षा देकर नौकरी में लग जायेगा। उसको उधार पैसे लेकर परीक्षा देने भेजते और वह वापस घर आता तब तक तो पेपर लीक। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने पेपर लीक के लिये एस.आई.टी. का गठन किया और 100 से ज्यादा लोग जेल में भेजे गये। अब कुछ बड़े लोगों का भी नंबर आने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में जिस तरह से इस कांग्रेस सरकार ने गुड़-गोबर करके उस योजना को खतम कर दिया, आज की तारीख में आप गांवों में जाइये तो चलने के लिये रास्ता नहीं, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी थी, ठेकेदार भाग गये, पाइप बेचकर पैसे खा गये। ई.डी. का छापा पडा तो आज ठेकेदार भागते नजर आ रहे हैं।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य। श्री राम सहाय वर्मा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैंने अभी तो शुरू किया है। मेरा तो टाइम ही इन्होंने ले लिया। माननीय सभापति महोदय, मुझे कुछ बातें मेरे लिये तो कहने दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। बहुत अच्छा बोले।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पांच मिनट में मेरी बात खतम कर रहा हूं। बहुत इंटरप्ट किया है।

श्री सभापति: समय पूरा हो गया। सात बजे खतम करना है। वक्ता बहुत हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरे क्षेत्र की बात तो रख दूं। माननीय सभापति महोदय, रानीवाड़ा, फालना शहर और 50 गांवों के पेयजल हेतु 18 करोड़ 90 लाख रुपये की स्वीकृति के लिये मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मारवाड़ जंक्शन में पॉलिटेक्निक कालेज दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। खिवाड़ा में पीएच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया, उसके लिये क्षेत्र की जनता की तरफ से

(श्री केसाराम चौधरी)

बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मगरा क्षेत्र डांग और मेवात क्षेत्र के लिये 50-50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिये आभार व्यक्त करता हूं। बरखाना-पाली में श्रीराम क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का भी आभार व्यक्त करता हूं। न्यू मारवाड़ जंक्शन और न्यू जवाली को डामर सड़क से जोड़ने के लिये जो पैसा दिया, इस बजट में प्रावधान किया, उसके लिये भी आभार व्यक्त करता हूं। सोजत की मेहंदी विश्व में प्रसिद्ध है, अत: 'लोकल फोर वोकल' स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिये जो मोदीजी का विजन है, सोच है, उसके अनुसार मेहंदी उद्योग सोजत का सबसे प्रसिद्ध उद्योग है, उसके लिए वहां पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मांग करता हूं। यही निवेदन करते हुये आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री राम सहाय वर्मा।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मै माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब तथा वित्त मंत्री का कार्य देख रहीं हमारी आदरणीया दिया कुमारी जी का हृदय से आभार, जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की लंबे समय से चलती आ रही मांगों को पूरा करते हुए निवाई को उप जिला अस्पताल, निवाई में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा पीपलू उप खण्ड कस्बे को नगरपालिका तथा कृषि मंडी की सौगातें दीं और डोडवाडी से बोरदा सड़क का मय काजवे के निर्माण के लिये 25 करोड़ की सौगात दी। 'विकसित राजस्थान 2047' की अवधारणा पर 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य को लेकर बनाया गया यह बजट समाज के हर उस तबके के लिए मील का पत्थर साबित होगा जिसने विगत सरकार की कागजी घोषणाओं से त्रस्त होकर हमें सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" की सोच रखने वाले हमारे देश में तीसरी बार माननीय प्रधान मंत्री जी की सरकार बनना इस बात को परिलक्षित करता है कि हमारे देशवासियों को लोक लुभावन वायदों से नहीं

(श्री राम सहाय वर्मा)

वरन् बुनियादी सुविधाओं के साथ सुशासन, गरिमामयी जीवन, धरोहर संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, सतत एवं सुनियोजित विकास से सरोकार है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा उप मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इस बजट में सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों, मेरे पेंशनर्स साथियों, किसानों, लघु उद्यमियों तथा बड़े उद्योगपतियों एवं युवा वर्ग, सभी को महत्व देकर आपने बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर जी की संकल्पनाओं को साकार करने का प्रयास किया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के 'लोकल फोर वोकल' के लिए की गई पहल के क्रम में सम्पूर्ण राजस्थान के सभी जिलों के लिए स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने की मंशा से 'एक जिला एक उत्पाद' पालिसी की घोषणा कर आपने सभी प्रदेशवासियों का मान बढ़ाया है।

राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होने से राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नये अवसर प्रदान होंगे जिससे विगत 5 वर्षों में फैली बेरोजगारी पर कुछ अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है।

माननीय सभापति महोदय, विगत 5 वर्षों में जिस संस्कृत शिक्षा को हाशिए पर रखा गया, उस संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालयों के भवन निर्माण तथा अन्य कार्यों की घोषणा कर आपने देववाणी संस्कृत शिक्षा का मान बढ़ाया, उसके लिए सरकार का हृदय से आभार है।

विगत वर्षों में देवस्थान विभाग के नाम पर केवल कागजी कार्यवाही होती रही, आपने खाटूश्यामजी के मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया, उसके लिए आपका हार्दिक आभार।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में यह जानकर हर्ष हुआ कि हिन्दू त्योहार यथा- होली, दीपावली, शिवरात्रि, रामनवमी को प्रदेश के लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज-सज्जा पर 13 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा, जिससे हमारे त्योहारों को और अधिक भव्यता से मनाया जा सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मंदिर व धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को बजट में जोड़ा है।

(श्री राम सहाय वर्मा)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की मुख्य मांगों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नटवाड़ा में स्थित प्राचीन बद्रीनाथ जी का मंदिर के विकास कार्यों को भी बजट में जोड़ने की कृपा करें। निवाई में केन्द्रीय बस स्टैण्ड, राहोली को उप तहसील तथा उप तहसील दत्तवास को तहसील में क्रमोन्नत करने, निवाई के रक्तांचल पर्वत के पीछे स्थित भूमि को सेन्ट्रल पार्क के रूप में विकसित करने, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलू में शय्या क्षमता 30 से बढाकर 100 करवाने, राहोली व पीपलू में राजकीय महाविद्यालय खोलने और राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करवाने का मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

निवाई विधान सभा क्षेत्र में राजीविका के 4 CLF (Cluster Level Federation) को सरकार की ओर से कार्यशाला की स्वीकृति प्रदान की जावे, ताकि SHG की महिलाएं समूह में सम्बन्धित गतिविधियां कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी तथा उप मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर बजट में जुड़वाने की कृपा करावें।

माननीय सभापति महोदय, 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' के ध्येय को लेकर बनाये गये बजट के लिए निवाई विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष में बैठे मेरे साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार राष्ट्रवाद की 'इदं राष्ट्राय, इदं न मम' की भावना से सोचना प्रारम्भ करो, आपको इस बजट के असली मायने समझ आ जायेंगे। वन्दे मातरम्।

'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। आपणो अग्रणी राजस्थान।'

माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार इस विधान सभा में चुनकर आया हूं और जो विपक्ष में बैठे हैं उनमें भी कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो मेरी तरह पहली बार आये हैं तो कम से कम आचरण इस तरह का हो कि जो कोई बात को कह रहा है उसको सुनें, उस पर विचार करें और हम लोगों को सीखने का मौका प्रदान करें, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मैंने पिछले कई दिनों में यह देखा है कि के विपक्ष में बैठे लोग या तो नारे लगाने में माहिर हैं या फिर विधान सभा को घेरने में माहिर हैं। इधर से डोटासरा जी एक कंधा यूं

(श्री राम सहाय वर्मा)

करते हैं तो सदस्य उठकर आगे आ जाते हैं या हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली कहते हैं तो सदस्य उठकर आ जाते हैं, लेकिन किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या सीखेंगे? मैं हूं चाहे विपक्ष वाले हों, हम लोग क्या सीखेंगे? इसलिये मेरा विपक्ष के सदस्यों से निवेदन है कि किसी से भी बात सीखें और अच्छी बात करें। राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने में हम लोग सहयोग कर रहे हैं और आप भी उसमें सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री सभापति: डॉ. शिखा मील बराला।

डा. शिखा मील बराला (चौमूं): सदन को नमस्कार। माननीय सभापति महोदय का आभार कि परिवर्तित बजट 2024-25 के बारे में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं तथ्यों पर बात करूंगी, कुछ सुझाव दूंगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, मांगें भी होंगी और सराहना भी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि मौजूदा सरकार काफी सौभाग्यशाली है, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के साथ ही उन्हें विरासत में मिली है पिछली कांग्रेस सरकार की बहुत सारी जन-कल्याणकारी योजनाएं। बजट की शुरुआत माननीय उप मुख्य मंत्री साहिबा ने निदा फाजली की कुछ पंक्तियों से की थी और मैं भी उन्हीं की पंक्तियों में इस बजट को बयां करूंगी।

"कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़ज़ा

ख़ुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो।

यही है ज़िंदगी (यहां माने बजट) कुछ ख़्वाब चंद उम्मीदें

इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो।"

माननीय सभापति महोदय, बातें हैं जल संकट की तो बिन्दु क्रमांक 5 में जे.जे.एम. का उल्लेख है क्योंकि मैं राजधानी से सटे चौमूं विधान सभा क्षेत्र से आती हूं जो कि एक डार्क जोन भी है, वहां हम बहुत ही गम्भीर जल संकट फेस कर रहे हैं। जे.जे.एम. अंतर्गत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है पर कहीं भी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह योजना 31 मार्च, 2024 को ही पूर्ण हो चुकी है और तारीख के बाद केन्द्र सरकार की ओर से फर्दर वर्क आर्डर पर रोक लगी हुई है।

(डॉ. शिखा मील बराला)

माननीय सभापति महोदय, गति की बात की जाती है पर केन्द्र में बी.जे.पी. सरकार होने के बावजूद भी हमारी राज्य सरकार को कोई एक्सटेंशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी जगह ट्यूबवैल और ओ.एच.एस.आर. के लिए लैंड एलोकेट नहीं हुई है। बात करें अमृत-2 योजना और बीसलपुर योजना की, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र को इससे वंचित रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि हम बहुत ही गम्भीर जल संकट से गुजर रहे हैं तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे लिए भी कोई ऐसी योजना प्रस्तावित की जाए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जल शक्ति योजना जैसी उच्च एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रपोजल्स को सीरियसली इम्प्लीमेंट करने की दिशा में विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा की बात करें तो हर्ज कि आगामी 10 वर्ष या 2047 के मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखें पर क्या सरकार के पास जवाब है कि जिस पीड़ा से, पिछले चार महीने जनता अघोषित बिजली कटौती से गुजरी है, सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनके पास भी जरूर रात-दिन फोन आते होंगे। घर में दो महीने का छोटा बच्चा है, चार घण्टे से बिजली कटौती हो रही है। 85 साल के बुजुर्ग हैं, जिन्हें कोई आपरेशन हुआ है, बीमार है, खाना बनाने का समय है, बिजली चली गई है। खाना खाने का समय है, दीया-बाती का समय है, बिजली चली गई है। यह जो बिजली संकट है, यह जो पीड़ा है, इसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा और क्या सरकार के पास कोई इमीजिएट सोल्यूशंस हैं या अगले एक साल में भी इसके निराकरण के लिए कोई विजन सरकार रखती है? एक तरफ दो लाख से ज्यादा डोमेस्टिक कनेक्शन देने की बात कही गई, डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को कनेक्शन देने की बात कही गई पर दूसरी तरफ हर सब-स्टेशन चार ब्लाक्स में सप्लाई कर रहा है। कहीं भी यह नहीं बताया गया कि दो सब-स्टेशन पर ब्लाक का स्टेटस आने में क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? उसका क्या विजन है? सौर ऊर्जा के लिए कुसुम योजना पर काफी जोर दिया गया। वर्क आर्डर्स भी उसके पास हुए हैं पर एग्जिस्टिंग सब्स्टेशंस को अपग्रेड करने के लिए जो अनुमानित लागत पांच हजार से दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त है, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी कुसुम योजना के बारे में अगर बात करें तो सच्चाई यह है कि कुसुम-सी योजना में किसान भाग नहीं ले रहे हैं।

(डॉ. शिखा मील बराला)

बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कोई कम्पनी टेंडर लेने तक को नहीं आ रही है। जो बड़ी कम्पनियां आ रही हैं वे बिना लैंड के आ रही हैं। बहुत सारी जगह जमीन तक आबंटित नहीं की गई है। भले ही लैटर आफ इंटेंट जारी हो गए हैं पर धरातल पर कोई काम वहां पर नहीं दिखता है।

माननीय सभापति महोदय, बात सड़कों की करें तो विधान सभावार पांच करोड़ बजट की बात आई, जिसका लैटर फरवरी में निकाला गया। प्रतिपक्ष में बैठे बहुत सारे विधायक साथी भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि किस तरह पक्षपातपूर्ण तरीके से उस बजट को एलोकेट किया गया। तीन करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट का लैटर आया, आज तक उसके प्रपोजल्स जिला परिषद् में अटके पड़े है और वहां उन पर कार्यवाही करने के लिए सरकार के ऊपर से कोई आर्डर्स नहीं पहुंचे हैं। फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और माननीय उप मुख्य मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि चौमूं को उन्होंने सात करोड़ की पांच मुख्य सड़कें प्रस्तावित लिस्ट में डाली हैं। इसके साथ ही एक मांग भी रखना चाहूंगी कि हमें सख्त जरूरत है लोहरवाडा से टांकरड़ा मेगा हाईवे के कंस्ट्रक्शन की और एक आर.ओ.बी. कंस्ट्रक्शन की, जिसे अनदेखा किया जा रहा है। इसके अभाव में या तो दुर्घटनाएं हो रही है या ट्रैफिक जाम की सिचुएशंस बन रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह डिस्कशन है इसलिए मैं सराहना भी करूंगी कि पब्लिक प्लेसेज में महिलाओं कें लिए जो बायो-पिंक टॉयलेट्स का प्रस्ताव लाया गया है और एविएशन सेक्टर की घोषणाएं, प्रथमदृष्टया काफी प्रोमिसिंग दिख रही हैं। राजकीय अनुदानित और खेल छात्रावासों में मैस अलाउंस को बढ़ाया गया है, यह भी काफी सराहनीय है। श्रद्धा की बात पर आएं तो खाटूश्यामजी मन्दिर को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का एक बड़ा बजट प्रस्तावित है, पर मुझे बहुत ही निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि शेखावाटी के सालासरजी मन्दिर और मेरे चौमूं क्षेत्र में सामोद बालाजी महाराज का मन्दिर जो एक पर्यटन स्थली भी है उनका नाम कहीं भी किसी लिस्ट में प्रस्तावित नहीं है। इन्हें वंचित रखा गया है कोई भी बजट से, तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस पर भी विचार किया जाए और हमारे नाम भी कुछ बजट, हमारे बालाजी महाराज के मन्दिर के नाम अलॉट किया जाए।

(डॉ. शिखा मील बराला)

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु क्रमांक 59, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत ही सहजता से लिखा गया है कि गुरुशिष्य की परम्परा को पुन: स्थापित करने के लिए और उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 'कुलगुरु' की पदवी दी जाएगी। कितनी सहजता से शिक्षा का स्तर सुधार दिया, क्योंकि यह बजट ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज है तो मैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स को काम्प्लीमेंट करूंगी उनके सेंस आफ ह्यूमर के लिए।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करूं तो बीईंग ए डाक्टर मुझे लगता है कि एक हैंडसम अमाउंट आफ बजट इस क्षेत्र को दिया गया है जो एक सकारात्मक संकेत है पर कहीं न कहीं अनियोजित तरीके से दिया गया है। कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है पर कहीं भी कोई कमेंट नहीं है कि प्रति परिवार पांच लाख या पच्चीस लाख का कवर दिया जाएगा। मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कैंसर के लिए आई.पी.डी. और डे केयर पैकेजेज का प्रावधान दिया गया है पर मैं आपको बताऊं कि ये पैकेजेज पहले से एग्जिस्ट करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

डॉ. शिखा मील बराला (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट सेक्टर के एम्पैनलमेंट में रिलेक्सेशन का एक अच्छा कदम उठाया गया है। पैकेज रेट्स रैशनलाइज करने का विचार रखा गया है। मेरी राय है कि प्राइवेट सेक्टर को ऐसी रेट्स दी जाएं कि वो सरवाइवेबल हों और प्राइवेट सेक्टर खुद इंटरेस्टेड रहें।

मा-वाउचर योजना में गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच हेतु प्रस्ताव रखा गया है पर उसमें प्राइवेट सेक्टर शामिल होगा या नहीं, उसमें बड़ी जांचें शामिल होंगी या नहीं इसका इसमें कहीं भी प्रस्ताव नहीं रखा गया है। बहुत निराशा हुई यह जानकर कि महिला प्रसव पैकेज को प्राइवेट सेक्टर से नहीं जोड़ा गया है। महिला के लिए चाइल्ड बर्थ जीवन के सबसे सुखद पलों में से एक होता है, तो मेरी सरकार से मांग है कि इसे जरूर कंसीडर किया जाए और डिलीवरी पैकैजेज को इसमें शामिल किया जाए।

पीडियाट्रिक पैकेज को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है तो मेरी मांग है कि टीकाकरण को भी उसमें शामिल किया जाए।

(डॉ. शिखा मील बराला)

माननीय सभापति महोदय, कृषि-सिंचाई की बात करें, पशुपालकों के उद्धार की बात की जाती है पर दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है।

पशु बीमा की बात की जाती है जो कांग्रेस सरकार के समय से चल रहा है, दुधारू गाय और भैंस के 5-5 लाख रुपये देने के अलावा भेड़ और बकरी का कवर भी 5-5 लाख का है और ऊंट का 01 लाख का। यह राशि किस तरह से आबंटित की गयी है, यह थोड़ा समझ से बाहर है। मुख्यमंत्री दुग्ध सम्बल योजना में जयपुर जिले में ही कम से कम 2.2 लाख किसानों के बकाया 112 करोड़ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह योजना आगे चालू रखने की मंशा है कि नहीं, इस पर भी कोई कमेंट नहीं किया गया। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सर, दो मिनट और प्लीज। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री सभापति: बैठें प्लीज। समय हो गया।

डॉ. शिखा मील बराला (चौमूं): ई.आर.सी.पी., पी.के.सी. की अगर बात करें तो इस परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने की चर्चा की गयी है।

श्री सभापति: 7 बजे समाप्त करना है।

डा. शिखा मील बराला (चौमूं): सर, मेरी रिक्वैस्ट है, दो मिनट। वर्क आर्डर जारी किये गये हैं, पर सच्चाई यह है कि इसका एम.ओ.यू. ही हुआ है, जबकि अभी तक मेमोरेंडम आफ एग्रीमेंट होना बाकी है। सरकार क्या बता सकती है कि दिल्ली, हरियाणा, एम.पी. का कोई कम्बाइंड डी.पी. आर अभी तक तैयार हुआ है या नहीं? जब जमीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ तो नहर किस तरह से आयेगी? इस तरीके से प्रतीत होता है कि यह एक बहुत ही सुपरफिशियल बजट है जो सिर्फ एक कास्मेटिक एक्सरसाइज है। चूंकि केन्द्र सरकार के पहले यह बजट पेश किया गया है तो हमें अभी तक यह भी नहीं पता कि राज्य को और कितना कर्जभार वहन करना पड़ेगा।

पर्ची सरकार पर ब्यूरोक्रेसी काफी हावी है। संकल्प पत्र से सरकार भटक चुकी है। उस संकल्प पत्र की याद दिलाते हुए मैं बशीर बद्र साहब के कुछ शब्दों से अपनी बात समाप्त करूंगी-

"तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर,
तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर,
तूने वादा किया था, याद तो कर।।"

जय हिन्द। जय भारत। जय संविधान।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गुरवीर सिंह। अपनी बात 8 मिनट में पूरी करें। समय कम है।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय, उन्हें 15 मिनट और हमें 8 मिनट?

श्री सभापति: अभी 8 मिनट कर दिया। संक्षिप्त में बोलें।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी का, हमारी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी का, जिन्होंने बहुत ही काम्प्रिहैंसिव बजट पेश किया है। सदन के तमाम सदस्य, चाहे वे कांग्रेस के हों, बी.जे.पी. के हों अथवा निर्दलीय हों, यह सबके लिए खुशी की बात है कि यह बजट हर शहर और हर कस्बे का है।

मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई कि विपक्ष के नेता ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर डाला, बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बजट की तारीफ करते हुए बताया कि उनके विधान सभा क्षेत्रों में क्या मिला। इससे यह साबित होता है कि यह "सबका साथ, सबका विकास" वाला बजट है, "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" का बजट है। इससे पहले भी हमने बजट देखे हैं। हम जिस इलाके से आते हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। पंजाबी में एक कहावत है, "घर दा व्याह, ते दादी-पोती गावणवालियां", मतलब घर की शादी और दादी-पोती गाने वाली। ये सारा सामान जोधपुर में ले जाते थे। वह चन्द हाथों में रहता था। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रहता था। आज इस बजट ने राजस्थान के कोने-कोने को टच किया है। हर जिले, हर विधान सभा क्षेत्र के लिए इन्होंने काम किया है। हर वर्ग को इस बजट में कुछ न कुछ मिला है।

"One district, one product", यह जरूरी नहीं है कि सारा बजट, सारा फोकस मैट्रो सिटीज पर रखा जाये। आज हमारे राजस्थान में पोटेंशियल है, चाहे गंगानगर, बाड़मेर हो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो, अलवर, भरतपुर हो, सबकी जरूरतें अलग-अलग हैं। "One district, one product" के माध्यम से, चाहे हमारे गंगानगर की बात करूं तो हम देश का सबसे बेहतर किन्नू उत्पादन करने में एक नम्बर पर हैं। हमारे यहां हॉर्टिकल्चर का हब है। हमें भी मौका मिलेगा, हमें अवसर मिलेगा हमारे प्रोडक्ट्स को देश-दुनिया में लेकर

(श्री गुरवीर सिंह)

जाने का। आज जो सरसों है, मैंने पहले भी इस सदन में रखा है, पूरे देश में 58 परसेंट हम एडिबल आयल इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमें इसका फायदा लेना चाहिये कि जो पूरे देश की 47 परसेंट पैदावार राजस्थान में हो रही है, इन प्रोडक्ट्स को हम और आगे लेकर आएं। इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहैंसिव पालिसी बने जिससे राजस्थान के किसान को इसका फायदा हो।

"Vocal for Local" पर जो प्रधान मंत्री जी ने बल दिया है, निश्चित रूप से हमारी राजस्थान की सरकार इसके लिए कदम उठायेगी। हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एम एस एम ई पॉलिसीज के लिए "मेक इन इंडिया" का जो हमारे प्रधान मंत्री जी का विजन है, राजस्थान की सरकार ने जो 50 क्लस्टर्स बनाने का काम किया है, मैं कहता हूं कि यह वेलकम स्टेप है। छोटे शहरों, कस्बों को आगे आने के लिए, नौजवान युवाओं को आगे आने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं कृषि की बात करूं तो 50 हजार करोड़ रुपये आज तक किसी भी सरकार ने कृषि के लिए सिंचाई विभाग को नहीं दिये।

जहां मुख्य मंत्री जी ने ई आर सी पी और यमुना प्रोजेक्ट पर काम किया, उस पर सदन में बहुत सदस्य बोले। ऐसी आज तक कोई सरकार नहीं हुई, जिसने 90 दिन के अन्दर इतनी बड़ी अचीवमेंट राजस्थान को लाकर दी। इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आई जी एन पी नहर, जो सतलुज के पानी को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर होते हुए पीने का और सिंचाई के लिए लाये, इसके लिए जहां पहले डबल इंजन की सरकार 2013-14 में शुरू होकर जब मोदी जी प्रधान मंत्री थे और वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री थीं, 2,400 करोड़ रुपये फर्स्ट फेज में आये।

(समय: 17.36 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

आज सैकंड फेज के लिए 1,430 करोड़ रुपये मिले हैं। जैसलमेर तक बैठे किसान को इसका फायदा होगा। हर खेत, हर ढाणी तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आज स्काडा सिस्टम की जो जरूरत है, वह नहरी क्षेत्र से जुड़ा किसान जानता है। 2,300 करोड़ रुपया आई जी एन पी पर स्काडा सिस्टम लगने के लिए भी उसके संचालन में हमें, उसकी गुणवत्ता पर काम करने के लिए हमें मौका मिलेगा, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं।

(श्री गुरवीर सिंह)

फिरोजपुर फीडर, जो लम्बे अरसे से मांग थी, आज गंगानगर के अखबारों में कांग्रेस के नेताओं के बयान छपे हैं, गंगानगर के सांसद और जिलाध्यक्ष ने कहा है, "यह हमारी घोषणा थी'', बिलकुल यह 2022 में आपकी घोषणा थी, 2023 में आपकी घोषणा थी, पर आप उस पर समाधि लगाकर बैठ गये। 200 करोड़ की घोषणा करके दो पैसे आप नहीं लगा सके। आज मुख्य मंत्री जी ने इस पर काम किया है। आज डबल इंजन की सरकार का यह फायदा मिला है कि पी एफ आर हमारी दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय तक पहुंच गयी है, बी बी एम बी से पास हो गयी है, सेंट्रल कमेटी से पास हो गयी है। आज डी पी आर पंजाब सरकार के पास पड़ी है और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारी डबल इंजन सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि जिस दिन पंजाब डी पी आर तैयार करके केन्द्र में भेजेगा, 15 दिनों में उसके बजट पर सैंक्शन आयेगी। फिरोजपुर फीडर के लिए 200 करोड़ मिलना गंगानगर के किसान की जीवनदायिनी नहर के लिए बहुत बड़ा कदम है। हम इसकी सराहना करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछली बार की जो आपकी सरकार थी, आपके सिंचाई मंत्री 05 साल तक सोये रहे। गंगानगर में धरना लगा, आपका मंत्री पहली बार पंजाब गया, पानी तो आपको एक बून्द भी मिला नहीं, पर आप वहां राजस्थान कैनाल के हिस्से की जो जमीन है, उसका सौदा करके आ गये। आज पंजाब मालवा नहर बनाने जा रहा है। मैं इस बात की सरकार और सदन से मांग करता हूं कि जो पिछली सरकार ने गलती की, वह दोहरायी न जाये, राजस्थान की एक इंच जमीन हम किसी को नहीं देंगे। वह हमारी सरकार की जमीन है और हमारे पास रहनी चाहिये।

इसी के साथ कृषि बजट में 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स का मैं स्वागत करता हूं। छोटे-छोटे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। हर एक को-आपरेटिव सोसाइटी 10 लाख तक के काम्पोनेंट्स खरीद सकेगी। ग्रीन हाउस, पाली हाउस, मल्चिंग, फार्म पॉन्ड्स, ड्रिप्स, स्प्रिंकलर, ये सारी हमारे किसानों की जरूरतें हैं। बूंद-बूंद पानी से खेती कैसे हो सकती है, यह राजस्थान ने दुनिया को दिखाया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जिले में यूनिट लैब होना अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। 500 नये एफ पी ओ आना, को-आपरेटिव सोसाइटी के फेल्योर के बाद जो हमारे प्रधान मंत्री जी की योजना है, 500 नये

(श्री गुरवीर सिंह)

एफ पी ओ को सैंक्शन देना, यह किसानों के लिए वरदान है। बोनस मिलना, किसान की सम्मान निधि में बढ़ोतरी होना, ये अपने आप में बहुत बड़े कदम हैं।

आज जो युवा नीति है, एक तरफ कांग्रेस की नाथी के बाड़े की नीति थी, जहां 19 बार पेपर लीक हुए और एक हमारी नीति है, आज हमारी नीति में युवाओं को 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। पहले साल में एक लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ-साथ डेढ़ लाख युवाओं को स्किल डवलपमेंट के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) साहब, मेरा पांच मिनट टाइम पड़ा है।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट नहीं हैं। आपके पास आधा मिनट है। मुझे साढ़े 6 तक खतम करना है।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): स्टार्टअप्स की बात हो, अटल एंटरप्रिन्योर प्रोग्राम की बात हो, इन सबके लिए सरकार ने बहुत उच्च स्तर के काम किये हैं। जो नशा मुक्ति केन्द्र, मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं, हमारा क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर है, हमारी जमीनों में माइन्स लगते हैं, उधर से कोई अटैक होता है तो हम अपनी छाती पर सहते हैं। उधर से पैकेट गिराये जाते हैं। गत सरकार ने पुलिस के साथ मिलकर हमारे युवाओं को नशे की भेंट चढ़ाया। सरकार ने आज नशा मुक्ति केन्द्रों को पैसा दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम। आप खड़े हों। आप बोलिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): सर, मेरा टाइम पड़ा है।

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं होगा।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): 000

श्री अध्यक्ष: सबके आठ-आठ मिनट हैं। आप बैठिये, हो गया। मैंने नाम पुकार लिया है। आप शुरू करिये। अगली बार और समय देंगे। आप शुरू करें। आप बोलो।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): सर, इसका तीन जिलों को फायदा होगा, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए कैंसर हास्पिटल का। जो कैमिकलयुक्त पानी पंजाब से आ रहा था, पांच साल तक सोते रहे, केन्द्र की

(श्री गुरवीर सिंह)

सरकार ने 400 करोड़ रुपया दिया, एक पैसा कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने खर्च नहीं किया। आज कैंसर हास्पिटल गंगानगर में मिलेगा तो हमें बीकानेर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ग्रीन फील्ड कॉरिडोर हो, हवाई अड्डा हो, चाहे हमारे लिए सादुलशहर में स्टेडियम हो, मिनी सचिवालय हो, मंडी हो। पेट्रोल और डीजल के रेट कम किये, गंगानगर में यह वरदान है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करें। आठ मिनट में पूरा करना है। सबको आठ-आठ मिनट का दिया है। टाइम शोर्ट है। कल भी है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट 2024-25 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। वर्ष 2024-25 का बजट दिशाहीन, निराशाजनक और उबाऊ है। बजट में दलित, किसान, युवा, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, कर्मचारी और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। 08 फरवरी, 2024 को जो घोषणाएं की गई थीं, उन पर 06 महीने में कोई काम नहीं हुआ है। 70 हजार नौकरियों की बात 08 फरवरी को की गई थी, लेकिन एक पद पर भर्ती आज तक नहीं निकाली। यदि निकाली है तो कोई बताये। हाईटेक सिटी का क्या हुआ? 500 इलेक्ट्रिक बसों का क्या हुआ? लखपति दीदी का क्या हुआ? अटल उद्यमी योजना का क्या हुआ? कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन के बारे में सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य मंत्री दुर्घटना बीमा, जो 10 लाख रुपये का था, उसके बारे में सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। सभी को 2047 का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि हालात आज ही खराब हैं।

विद्युत विभाग, जिन्होंने 10 वर्षों में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना तैयार की है, ये बात 2031-32 की करते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2031-32 तक आपको रहने कौन देगा? पिछले 6 महीने से विद्युत आपूर्ति बाधित है। पूरे प्रदेश के अन्दर जयपुर से लोड शैडिंग के जरिये विद्युत कट लगते हैं। शहर व ग्रामीण में विद्युत कट लगते हैं। प्रभात नगर, सूरतगढ़ के अन्दर 132 के वी जी एस एस का 01 जून को उद्घाटन हुआ, लेकिन आज तक आउटपुट निकल नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय, भोपालपुरा, रतासर के अन्दर पिछली बार लोक सभा चुनाव से पहले, जब सत्र चल रहा था, तब मैंने प्रश्न लगाया था 33/11 जी एस एस का और उत्तर दिया गया था कि कार्यादेश जारी किया जा चुका है,

(श्री डूंगरराम गेदर)

कार्य प्रगति पर है, शीघ्रताशीघ्र पूर्ण किया जाना है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आज तक एक ईंट भी इन दोनों जी एस एस पर नहीं लगी है। विद्युत विभाग के पास एल टी लाइन नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, किसान को 06 घंटे आपूर्ति जो पहले मिलती थी, अब दो-दो घंटे बिजली आपूर्ति किसानों को होती है। आटा चक्की वाला आटा पीस नहीं पा रहा है, वाटर वर्क्स पानी नहीं दे पा रहा है और भारी उमस और गर्मी के कारण बुजुर्गों और बच्चों का बहुत-बुरा हाल है।

महोदय, बजट के अन्दर 05 करोड़ रुपये सड़कों के लिए देने का जिक्र किया गया। पिछली बार मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने हर एक साल के अन्दर 10 करोड़ रुपये सड़क के दिये थे। आपने उस बजट को आधा किया है और आधा करने के साथ ही, इधर सारे विधायक बैठे हैं, इनसे किसी से भी न पूछकर आप लोगों ने अपने आप, अधिकारियों ने इस बजट को देने का काम किया, जिसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। आपने तीन करोड़ रुपये अन्य आधारभूत ढांचे के दिये, सी ई ओ, जिला परिषद् के पास आपका काम आज तक नहीं पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय, भाषा अकादमी के उन्नयन के बारे में आपने बजट के अन्दर जिक्र किया है, लेकिन राजस्थानी भाषा को आप मान्यता कब देंगे? राजस्थान के स्कूलों के अन्दर राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाती है, कालेज में पढ़ाई जाती है, पीएच डी हो रही है लेकिन राजस्थानी भाषा पर राजस्थान की सरकार एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान को नहीं मानने वाले लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र इस संविधान के अन्दर किया है, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान कर लें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवम्बर, 1949 को जब संविधान सभा को संविधान भेंट किया था, उस समय कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं है तो वह बुरे से बुरा संविधान साबित हो सकता है। आज जो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष है, केन्द्र से लेकर राज्य सरकार तक वह यह कर रहा है। आपके पास आंगनबाड़ी के भवन नहीं हैं, सामुदायिक भवनों के अन्दर, स्कूल अन्य स्थानों पर चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का जिक्र भी आपने किया है, लेकिन सूरतगढ़ के अन्दर एक

(श्री डूंगरराम गेदर)

नाबालिग बच्चे को, प्रदीप शर्मा को अवैध हथियार के असत्य मुकदमे के अन्दर यहां की पुलिस ने फंसाया है और उस पर यहां के मंत्री कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं हैं। सवाई माधोपुर के खंडार के अन्दर राम किशोर प्रजापत की हत्या की गई। उसकी बेटी का अपहरण किया गया, नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया और उसकी बात पुलिस ने नहीं सुनी। उसकी हत्या कर दी। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

सूरतगढ़ के अन्दर नकली सरसों का ट्रक पकड़ा गया है। रीड़ी सोसायटी, डूंगरगढ़ से एक ट्रक सूरतगढ़ के अन्दर गया। हमारे वहां के व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने जब सरसों को हाथ में लेकर उस पर पानी डाला तो वह सारा का सारा रेत बन गया। इस तरह के हालात आज राजस्थान के अन्दर कानून व्यवस्था के हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के अन्दर भांखड़ा और गंगनहर में शेष जो खाले बनने हैं, आपने मात्र 10 करोड़ का बजट दिया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि सारे के सारे खाले लगभग 30-35 साल पुराने बने हुए हैं। यदि वे खाले नहीं बनें तो वह पानी किसानों को पूरा नहीं मिलने वाला है। गंगनहर के अन्दर 2,500 क्यूसेक पानी की जगह 1,000, कभी 1,300 क्यूसेक पानी चलता है। आई जी एन पी के अन्दर 18 हजार की जगह 11 हजार-12 हजार क्यूसेक पानी चलता है। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को एक-एक बूंद पानी के लिए तरसा दूंगा और तत्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह जी ने भी कहा था कि पाकिस्तान में एक बूंद भी पानी नहीं जायेगा, लेकिन मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान कितना पानी जा रहा है, इसका आंकड़ा आपको जारी करना चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान जा रहे पानी को रोक नहीं पा रहे हैं और इधर राजस्थान के अन्दर गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ व्यास और सतलुज नदी का पानी है, हरिके बैराज पर वहां केमिकलयुक्त पानी है, वह मिलता है जिससे पूरे गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक कैंसर फैल रहा है।

मैं फसल बीमा के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज तक फसल बीमा कम्पनी बीमा देती नहीं हैं। किसानों को बार-बार चक्कर कटवाने का काम करती है। 6 जून को सूरतगढ़ में और आसपास में जो तूफान आया था,

(श्री डूंगरराम गेदर)

उस तूफान के मुआवजे के बारे में या नुकसान के बारे में आप लोगों ने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। 2014 के अन्दर प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज पूरे देश का किसान दिल्ली जाना चाहता है। दिल्ली इसलिए जाना चाहता है, क्योंकि आपने ही कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन 10 साल बाद भी आपने लागू नहीं की। आपने कहा था कि हम एम एस पी लागू करेंगे, लेकिन आपने लागू नहीं की। इसलिए देश का किसान दिल्ली जाकर आपसे बात करना चाहता है। आपने कहा था कि किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, लेकिन आज तक दोगुनी की बात तो छोड़ो, किसानों की जेबें खाली करने का काम आपने किया है। अन्नपूर्णा किट का जिक्र आपने किया नहीं, अन्नपूर्णा रसोई का पैसा आपने घटा दिया, चिरंजीवी योजना का दायरा आप लोगों ने घटा दिया और घरेलू फ्री बिजली की बात आप लोगों ने की नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर फ्री दवाई की शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत साहब ने। फ्री जांच की शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत साहब ने। चिरंजीवी योजना को पांच लाख किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने। पांच लाख को बढ़ाकर दस लाख किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने और 10 लाख को बढ़ाकर 25 लाख किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह। अब समाप्त करें। मेरे पास बोलने वाले 10 लोगों की सूची है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): आपने उसको बढ़ाने के बजाय घटाने का काम किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र आपने किया है, लेकिन 500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत साहब ने। 500 से बढ़ाकर 750 किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने और 750 से बढ़ाकर 1,000 किसने किया? अशोक गहलोत साहब ने।

श्री अध्यक्ष: अब हो गया। बहुत अच्छा बोल रहे हो, धन्यवाद। डिमांड में और मौका आयेगा।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): 15 परसेंट बढ़ाने का काम अशोक गहलोत साहब ने किया था, लेकिन आपने नया कुछ नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अंकित नहीं हो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

श्री अजय सिंह। अब हो गया। ऐसा करोगे तो सभी रह जायेंगे। सॉरी, नो सिफारिश। आपको आठ मिनट बोलना है।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर

सामान्य वाद-विवाद

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। यह बजट लोक कल्याण को समर्पित है तथा राजस्थान के समग्र विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। युवाओं का विशेष ध्यान रखते हुए पांच साल में चार लाख नौकरियों की घोषणा की गई है और राज्य के पैंतीस लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की घोषणा की गई। बजट में की गई घोषणाओं से स्पष्ट रूप से लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा राजस्थान एक विकसित राज्य बनेगा जहां पानी एवं बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। मुख्य मंत्री जी यह विजन लेकर के चल रहे हैं कि वर्ष 2047 में राजस्थान कैसा होगा, फिर भी विपक्ष द्वारा बार-बार आलोचना की जा रही है। मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि-

'जब भी आपका हौसला आसमान तक जायेगा,
याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आयेगा।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बात चली किसान की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन कांग्रेस सरकार से पहले था तब हमने 74 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को

(श्री अजय सिंह)

दिया। अगर उसकी हम तुलना करें पिछली कांग्रेस सरकार से तो कांग्रेस ने केवल 25 हजार करोड़ रुपये की राशि से कम का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया। (व्यवधान) आपको मैं बता देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिये मत। बीच में डिस्टर्ब नहीं। बीच में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आंकड़ा बिलकुल अच्छी तरह से दे रहा हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये। आप भी बोल रहे थे, फिर जब आप बोलोगे तब वो बोलेंगे।

श्री अजय सिंह (डेगाना): वह है वर्ष 2013 से 2018 तक और आपका मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं वह है 2008 से वर्ष 2013 तक कि आपने 25 हजार करोड़ रुपये से कम का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को दिया है और भारतीय जनता पार्टी के समय यह बांटा गया 75 हजार करोड़ रुपये का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर बोल रहे हो। आपका नाम आगे से नहीं लूंगा। डोंट डिस्टर्ब एनीबडी। न इधर के न उधर के।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी किसानों की बात चल रही थी। हम लेकर के आये किसानों का दुर्घटना बीमा दस लाख रुपये तक का और दस लाख तक का पूरे देश में अगर कहीं यह बीमा हुआ किसानों का तो केवल राजस्थान में हुआ माननीय वसुन्धरा राजे जी के समय और उसको आपने बन्द कर दिया। यह चौथा स्तम्भ ऊपर बैठे हैं पत्रिका, भास्कर और छोटे-छोटे अखबारों ने बार-बार इसको निकाला, लेकिन आपने किसी तरह का कोई बीमा नहीं किया। आज किसानों का बीमा नहीं हो रहा है और अब हमारा प्रयास करेंगे। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वापस किसानों का दस लाख का दुर्घटना बीमा होना चाहिये। यह बीमा जो किया है इसकी संख्या बहुत अधिक थी लगभग पच्चीस लाख से ज्यादा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पिछले दो साल में हम देखें तो जो ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को दिया गया है वह किसान सब डिफाल्टर हो गये और डिफाल्टर का कारण यह रहा है कि किसान जमा कराना

(श्री अजय सिंह)

चाहते थे अपनी राशि उन दिनों में पर तब व्यवस्थापक हड़ताल पर चले गये तो किसी ने उनकी राशि को जमा नहीं किया। मेरे नागौर के अन्दर सौ करोड़ रुपये से ज्यादा इस तरह से डिफाल्टर में फंसे हुए हैं। हजारों किसान डिफाल्टर हो गये हैं। इस तरह अगर किसान डिफाल्टर रहेगा और वह पैसा जमा नहीं करा रहा है क्योंकि उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि किसानों की जो ब्याज और पेनल्टी बन रही है, उसको ये माफ करें।

अभी एम एस पी की बात चली थी। दो माननीय सदस्यों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप विपक्ष में थे तो आपने बार-बार यह मांग उठाई राजस्थान में कि बाजरा खरीदा जाये। मैं यह जानना चाहूंगा, नेता, प्रतिपक्ष भी बैठे हुए हैं, क्या एक दाना भी बाजरे का कांग्रेस के समय खरीदा गया है? और आंकड़े हैं मैं आपको बताना चाहूंगा समर्थन मूल्य के। देख लें कि राजस्थान में सबसे पहले अगर मूंग खरीदा जो कि राजस्थान में इतना होता है कि पूरा देश एक तरफ और राजस्थान एक तरफ और वह खरीदा गया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में खरीदा गया है। अगर समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलें किसानों से ली गई हैं, किसानों को लाभान्वित किया गया है तो वह भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस के शासन काल में एक उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति दी गई थी वर्ष 2022-23 के बजट में, परन्तु अभी तक भी वह नहीं बना है। मेरा आग्रह है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जाये, ताकि वह अब बन सके। इसी तरह मेरे डेगाना विधान सभा क्षेत्र में निम्बोला कलां गांव है जहां पर कांग्रेस के समय पी एच सी की घोषणा की गई थी, लेकिन वह अभी भी शुरू नहीं हुई है तो मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि वह भी शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करें। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चूई आंतरोली कलां, बिखरन्या कलां, चांदारूण में भी पीएचसी की स्वीकृति करने का श्रम करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि चांदारूण में यदि पी एच सी बनायी जाती है तो वह पी एच सी पूरी भामाशाहों के द्वारा बना दी जायेगी।

इसी तरह से थांवला में लगातार कालेज की मांग चल रही है और

(श्री अजय सिंह)

कांग्रेस के समय जो वहां का उप खण्ड मुख्यालय है थांवला का रियां, वहां के लिए कालेज की स्वीकृति दी गई है कांग्रेस के शासन काल में, लेकिन अभी तक वहां कालेज शुरू नहीं हो पाया है। जो भूमि का आबंटन किया गया है उसके लिए ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में विवाद है और राजस्व मण्डल द्वारा उसके लिए स्टे कर दिया गया है। यथास्थिति के आदेश हैं, इसलिये वो थांवला में अगर खोल दिया जाये तो वहां के लोग लाभान्वित होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के शासन काल में पानी की पाइप लाइन बिछाई गई थी। पूरी सड़कें तोड़ दी गई हैं और उनको ठीक नहीं कराया गया है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इन सड़कों के लिए अलग से कुछ राशि लगभग पच्चीस करोड़ रुपये दें, ताकि ये सड़कें वापस दुरुस्त करायी जा सकें। इसी तरह से डेगाना में ए डी जे कोर्ट नहीं है और अगर पूरे जिले में देखें तो हर उप खण्ड मुख्यालय पर ए डी जे कोर्ट है तो मेरी यह भी मांग है कि डेगाना के अन्दर ए डी जे कोर्ट खोला जाये। बिजली के संकट को देखते हुए पंचायत मुख्यालय पुन्दलोता और माझी में 33 के वी जी एस एस की स्वीकृति प्रदान करें। माननीय मुख्य मंत्री जी, इसी प्रकार भैरूंदा में उप तहसील है, वो पंचायत समिति मुख्यालय है, उसको तहसील में क्रमोन्नत करने का श्रम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विकास चौधरी।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट के सामान्य वाद-विवाद पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि विगत 06 माह से पर्ची सरकार पूरी तरह विफल रही। इस स्थिति में राजस्थान का जनमानस न्याय की उम्मीद से आसन की ओर बड़ी टकटकी लगाये देख रहा है। मैं भी आपके जिले का जन-प्रतिनिधि होने के नाते आपसे उम्मीद और आशा रखता हूं कि अजमेर जिले के हितों की रक्षा आप करेंगे। हम किशनगढ़, अजमेरवासियों का संरक्षण आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं सभी का करूंगा।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल जब

(श्री विकास चौधरी)

बजट हुआ, बजट के बाद जब बाहर निकले तो किशनगढ़, अजमेरवासियों के टेलीफोन आये कि अजमेर को क्या मिला। मैंने कहा अजमेर को इस राजस्थान विधान सभा का आसन मिल गया। इस अजमेर लोक सभा क्षेत्र को डिप्टी सी एम मिल गया। इस अजमेर को जल संसाधन का कैबिनेट मंत्री मिल गया। आठ में सात विधायक मिल गये। कहा जी, बजट में क्या मिला, मैंने कहा कि बजट में तो कुछ नहीं मिला, जो मिला है मैं आपके सामने रखता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के बजट 2024-25 के पृष्ठ संख्या 87 पर किसानों की आय दुगुनी करने का राग अलापा गया, किन्तु सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसी तरह का राग माननीय मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन धरातल पर किसानों की स्थिति और उनकी समृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि जब बजट बोला जा रहा था तो राजस्थान सरकार का कृषि मंत्री अनुपस्थित था। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान के लिए हो नहीं सकता। 'नहीं सहेगा राजस्थान' का नारा देने वाले सत्ता प्राप्त कर अपने संकल्प पत्र में कृषि व किसानों की उन्नति के लिए बीस हजार करोड़ के एग्री इन्फ्रा मिशन की घोषणा की थी, लेकिन इस बजट में इस दिशा में किसी प्रकार का प्रयास परिलक्षित नहीं होता। यही इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सरकार ने किसानों ...(व्यवधान)

(समय: 18.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: इन्हें बोलने दो ...(व्यवधान) आप बैठो, यह काम मेरा है। (व्यवधान) आप भी बैठो।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): इसी प्रकार सरकार ने किसानों से संकल्प पत्र में वादा किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसान परिवार से आता हूं। इस सरकार ने सरकार बनने से पूर्व अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि हम एम.एस.पी. पर किसानों के ज्वार, बाजरा, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, इत्यादि जिन्सों की खरीद करेंगे, लेकिन इस बजट में इस दिशा में कुछ नहीं दिखाई दिया।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की इन्कम के लिये जिस प्रकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन कानून पारित कर मिनिमम गारंटी इन्कम हेतु प्रयास किया, उसी तरह यह सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिये कानून पारित करे। प्रत्येक किसान को नि:शुल्क बीज और बिजली की व्यवस्था करे,

(श्री विकास चौधरी)

तभी सही मायने में किसान की लागत कम हो सकती है। डेयरी क्षेत्र में पशुपालकों को इस सरकार ने केवल 600 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जो कि पशुपालकों के लिये नाकाफी है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप जब विद्यार्थी परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लंबे समय तक आपने राजनीति की। हम छात्र राजनीति से निकलकर किसानों व युवाओं की आवाज के लिए धरातल पर संघर्ष करते हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मन्दिर में पहुंचते हैं और इस मन्दिर में जब आते हैं तो हम हमारा सिर इस मन्दिर के चरणों में झुकाते हैं। इसलिए झुकाते हैं, क्योंकि यहां हम गांव, गरीब, किसान, नौजवान की आवाज को बुलंद कर सकें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन पीड़ा तब होती है जब इस भीषण गर्मी में आमजन पानी मांगता है तो यहां इस सरकार का मंत्री कहता है कि मैं कोई बालाजी हूं क्या जो फूंक मार दूं और पानी निकल जाये। इससे बड़ी इस सरकार की दुर्गति हो नहीं सकती। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर भारत की संस्कृति और विरासत को, जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने वाले मेरे आदिवासी भाइयों के डी एन ए की जांच की मांग करता है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात इस सदन के लिये हो नहीं सकती। इसी का परिणाम है कि छह माह में सरकार का एक मंत्री चुनाव हार जाता है, अग्निवीर बन जाता है और दूसरा मंत्री अपना सम्मान नहीं मिलने के कारण इस्तीफा दे देता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रामधारी सिंह दिनकर जी की वे पंक्तियां इस सरकार पर सटीक बैठती हैं।

"दुर्योधन वह भी दे न सका,
आशीष समाज की ले न सका,
उल्टे हरि को बांधने चला,
जो था असाध्य, साधने चला।
जब नाश मनुज पर छाता है,
पहले विवेक मर जाता है।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस कथन और इन पंक्तियों को सदन शिक्षा मंत्री से जोड़ कर न देखे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर दिन भर भीषण गर्मी में खून-पसीना बहाकर अपने घर पहुंचता है तो वह चैन की नींद भी नहीं ले सकता है, क्योंकि सोने की तैयारी

(श्री विकास चौधरी)

करता है तो उससे पहले यह पर्ची सरकार गांवों में लाइट काट देती है। इसी प्रकार प्रदेश की सरकार के कुप्रबंधन के कारण बुनियादी व नियमित कार्यों के लिये आमजन को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि सरकार भजन लाल जी नहीं चला रहे हैं, सरकार नौकरशाही चला रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि आपके विधायक और मंत्री कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं, हमारा काम नहीं होता। इस स्थिति में

"उम्मीदों से देखता रहा प्रदेश का जवान और किसान,
अनर्गल बयानबाजी, पर्ची सरकार से कैसे बढ़ेगा प्रदेश का मान।
थोथी घोषणाएं, जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान, नहीं सहेगा राजस्थान,
कैसे सहेगा राजस्थान, कैसे अग्रणी बनेगा राजस्थान?"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह डबल इंजन की सरकार इस राजस्थान को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली मार्बल मण्डी के लिये जी एस टी का एक भार थोप चुकी है। वर्तमान सरकार में इंस्पेक्टर राज में आये दिन जगह-जगह चैक पोस्ट लगाकर व्यापारियों के ट्रकों को रोक कर अवैध वसूली करते हैं। प्रदेश में ईज आफ डूईंग बिजनेस का वातावरण निर्मित हो, इस बाबत सरकार का यह बजट विफल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व देने वाली मार्बल मण्डी में आये दिन ट्रैफिक जाम की दुविधा से निजात दिलाने के लिये नवीन बाईपास की मांग रखी, किन्तु इस गूंगी-बहरी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये किसी प्रकार की नीति का निर्धारण नहीं किया।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी उप मुख्य मंत्री जी बार-बार मोदी जी का नाम अलाप रही थीं। आप और हम कैसे भूल सकते हैं कि बड़ा वाला इंजन जब सत्ता में आया, उससे पहले कह रहे थे कि हम सालाना दो करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज हम देख रहे हैं कि सभी नवीन भर्तियों में एस.टी; एस.सी; ओ.बी.सी; एम.बी.सी. के आरक्षित वर्गों को कम किया जा रहा है। संविधान प्रदत्त आरक्षण के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिये विज्ञान व पर्यावरण में मात्र 31 करोड़ का प्रावधान रखा है, जो सरकार की युवाओं के प्रति नीयत को दर्शाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की 65 परसेंट आबादी 35 वर्ष से कम आयु के नौजवानों की है। प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज यही कारण है कि हताश नौजवानों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): बस, एक मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नौजवानों पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अभी आपके चार बोलने वाले हैं।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): इसी डबल इंजन की सरकार ने देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले राजस्थान प्रदेश के युवाओं पर अग्निवीर जैसी योजना थोप दी। इसलिए मैं सदन को कहना चाहूंगा कि जैसे अमरीकी राष्ट्रपति फ्रेंक्लिन ने कहा था, हम सदैव अपने युवाओं का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते, किन्तु हम हमारे युवाओं के भविष्य को तैयार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया। श्री उदयलाल भडाणा। अंकित नहीं होगा।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: दो मिनट और दे दिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: हो गया। अंकित नहीं हो रहा है, उसके बाद क्यों बोल रहे हो?

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): अध्यक्ष महोदय, आपने बजट 2024-25 के अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभार। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी द्वारा राजस्थान का जन-कल्याणकारी बजट बनाया है, उस बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा व राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मेरे भीलवाड़ा जिले में और मेरे मांडल विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने बजट में रोड दी हैं, औद्योगिक क्षेत्र दिया है, एक हरिपुरा चौराहे से लगाकर देवगढ़ के लिये फोरलेन के लिये बजट दिया है। हरिपुरा से लगाकर देवगढ़ तक हमारे मांडल विधान सभा क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां गाड़ी-घोड़ों की वजह से आये दिन एक्सीडेंट होते थे। किसी समय में वहां से रेलवे लाइन निकलती थी, उस रेलवे लाइन पर पिछली सरकार ने रोड बना दी है। वहां आये दिन नील गाय आने से बहुत सारे गांव वालों की मौत हो जाती थी। हमने इस मांग को रखा और मुख्य मंत्री जी ने उस मांग को मान लिया और अब हरिपुरा चौराहे से लगाकर देवगढ़ तक फोरलेन का निर्माण

(श्री उदयलाल भडाणा)

होगा, इससे लाखों लोगों की आवागमन की समस्या खतम होगी। वहां आज से पांच दिन पहले भी एक मौत हो गई थी।

अध्यक्ष महोदय, धुवाला से बाधू के बीच एक रोड बनाने की हमने मांग की, उसके लिये वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने 20 करोड़ रुपये की सैंक्शन दी। उसमें हमारे 30 किलोमीटर का चक्कर लगता है पर अब, इससे हजारों किसानों का भला होगा। मेवासा से लगाकर रघुनाथपुरा भोजापारा होते हुए 7 मीटर चौड़ा रोड बनाया, उसके लिये भी मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे करेडा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिये हमने सेरेमिक हब की मांग की थी। मुख्य मंत्री जी और दिया कुमारी जी ने हमारे करेडा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा देकर हमारे उद्योगों के नये आयाम स्थापित करने के लिये औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिया, उसके लिये मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हमारे भीलवाड़ा रीको में जो टैक्सटाइल पार्क की घोषणा की, उसके लिये मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार। भीलवाड़ा जिला एक वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है और भीलवाड़ा जिले में भारत का आधा कपड़ा बनता है। उस भीलवाड़ा जिले को नई ऊंचाई छूने के लिये, टेक्सटाइल व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये मुख्य मंत्री जी ने टैक्सटाइल पार्क की हमें जो सौगात दी, उसके लिये भी उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे साथी विकास जी बार-बार पर्ची सरकार-पर्ची सरकार बोल रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि पिछली मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट सरकार थी, उस रिमोट सरकार ने उसी जगह जहां हमने टैक्सटाइल पार्क की घोषणा की, उन्होंने मेमू कोच फैक्ट्री की स्थापना की, लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने यहां पर टैक्सटाइल पार्क की स्थापना की और बहुत सारे उद्योग स्थापित होंगे, जिससे हजारों-लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। भीलवाड़ा राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में कपड़े के मामले में, उद्योग के मामले में नंबर वन है। यह टैक्सटाइल पार्क देकर भीलवाड़ा को, राजस्थान को, भारत को आगे बढ़ाने का काम मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने किया है।

भीलवाड़ा के अन्दर जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे है, 193 किलोमीटर का रोड, जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक दिया, उससे भीलवाड़ा और जयपुर के बीच में लोगों को आवागमन के साधन की न कोई कमी रहेगी, न कोई

(श्री उदयलाल भडाणा)

समस्या रहेगी। मुख्य मंत्री जी ने भीलवाड़ा के लिए बहुत कुछ दिया। जो पिछली सरकार थी, उसके अन्दर केवल घपले-घोटाले करने का काम किया था। हमारी माण्डल विधान सभा क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले में ऐसा पिछली सरकार के समय में हुआ था कि वहां की जमीनों के घोटाले, यू आई टी के घोटाले, नहरों के घोटाले और वहां पर खाले, पानी की बंदियां लेकर सब घोटाले ही घोटाले। पिछली सरकार घोटाले की सरकार थी और इतने घोटाले हुए कि यह विधान सभा है तो इस विधान सभा को उठाकर सचिवालय में रख दिया, सचिवालय को उठाकर विधान सभा के अन्दर रख दिया। इतनी जमीनों की किस्में चेंज कर दीं, तरमीम चेंज कर दी। जब भी गांव में जाते हैं, लोग यह कहते हैं, भाई साहब यहां पर हमारी जमीन थी, यहां पर हमारा कब्जा हुआ करता था, लेकिन इस कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने, अधिकारियों ने मिलकर उस 100-200 साल के कब्जे को भूमिहीन किसान बताकर अपने मित्रों को बाहर से, जयपुर से, हुरड़ा गुलाबपुरा से बुलाकर जमीनें अलॉट कर दीं।

हमारे माण्डल विधान सभा क्षेत्र में करेडा एक तहसील है। उस करेडा तहसील में इतनी जमीनों का हेरफेर व घोटाला किया, उस घोटाले की 129 पेज की रिपोर्ट है। मैंने पिछली बार इसी सदन के माध्यम से मांग की थी कि मेरे माण्डल विधान सभा क्षेत्र में कितनी चरागाह, बिलानाम भूमि का अलॉटमेंट किया गया तो मुझे यहां से 129 पेज की रिपोर्ट मिली। इतनी जमीन का बंदरबांट किया। हमारे राजस्व मंत्री हेमन्त जी विराजमान हैं, मैं इनसे भी मिला था, मैंने इनसे भी आग्रह किया था, निवेदन किया था कि यह जो जमीनों का घोटाला हुआ है, मुख्य मंत्री जी से, मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं और राजस्व मंत्री जी से भी मांग करता हूं कि घोटाला उजागर करें। एक कमेटी बनायें और पूरे राजस्थान में जमीनों का घोटाला हुआ, उस घोटाले की जांच करें, क्योंकि जो पिछली सरकार में थे, उन लोगों ने जमीन अपनी खुद की संस्था के नाम करा ली, अपने बेटे के नाम पर करवा ली। इतना घपला किया, जो बड़ी का खेड़ा गांव था, वहां के लोग उनके पास गये। भाई साहब, यह हमारी चरागाह भूमि है, हमारे गांव की भूमि है, उनको लगा कि यह कीमती जमीन है तो उन्होंने अपनी खुद की संस्था के नाम पर करवा ली। परसों ही उनका फोन आया कि भाई साहब, हमारा कुछ हो नहीं रहा, हमारी बात रखना। मैंने राजस्व मंत्री जी से भी निवेदन किया था और मुख्य मंत्री जी से भी सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जो

(श्री उदयलाल भडाणा)

जमीनों की बंदरबांट की, उसके लिए एक कमेटी बनायें और जो जमीनें दीं, उनको निरस्त करें, क्योंकि लोगों को भूमिहीन किसान बताकर, जो बहुत सारे अधिकारी हैं, उनकी भी मैं शिकायत करूंगा। उन अधिकारियों ने अपने खुद के नाम जमीनें कर लीं, पांच-पांच सौ बीघा जमीन, हजार-हजार बीघा जमीन अलॉट कर ली। एस डी एम का काम होता है, वहां का काम करना। कब्जा किसी और का, जमीन किसी और की, और अलॉमेंट किसी और को कर दिया।

हमारे भीलवाड़ा शहर के अन्दर यू आई टी है। उस यू आई टी में मेरे माण्डल विधान सभा क्षेत्र के पैरिफेरी के 56 गांव आते हैं, उन सारी जमीनों की बंदरबांट कर दी। वहां पर जो हलेड़ के अन्दर एक हाईवे निकाला, अभी तक उस हाईवे का कोई अता-पता नहीं, निर्माण का पता नहीं। अभी उस जगह पर फसल खड़ी हुई है। भीलवाड़ा शहर की कालोनियों में, इलाकों में मुआवजा ले लिया गया और भीलवाड़ा में जो जमीनों का खेल हुआ है, उस खेल के लिए मैं पुन: राजस्व मंत्री जी से भी, क्योंकि ये विराजमान हैं, सुन रहे हैं, मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जो घपले हुए हैं घोटाले हुए हैं, पूरे राजस्थान में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उनकी जांच करें। अभी पांच-छह दिन पहले अखबार में आया था कि भीलवाड़ा यू आई टी में 3,126 फाइलें गायब हो गयीं और एक हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। एक हजार करोड़ रुपये का घोटाला डी एल सी रेट पर हुआ था। अगर उसकी मार्केट वैल्यू गिनी जाये तो 10 हजार करोड़ रुपये की थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूसाराम गोदारा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): जो तत्कालीन अधिकारी सीटों पर थे, उनकी जांच की जाए, उनको सज़ा दी जाये, उनको जेलों के अन्दर डाला जाये। जो शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, उन सब लोगों ने जो घोटाले, घपले किये हैं, उन सब लोगों को डाला जाये।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। पूसाराम गोदारा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): 000

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो संशोधित बजट पेश किया गया है

(श्री पूसाराम गोदारा)

यह निश्चित तौर से ऐसा बजट पेश किया गया है, जिसमें आंकड़ों के जाल में फंसाया गया है और इसमें धरती पर क्या वास्तविकता होनी चाहिए, वह ग्रास रूट पर नहीं हो रहा है और न ही इसमें इस प्रकार का कोई विजन दिया गया है। बजट दिशाहीन है, यह भी बात मैं आपको कहना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं और सबसे पहले बिजली की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। निश्चित तौर से आज प्रदेश में, हमारे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ और चूरू जिले में हालात इतने विकट हैं कि रात एवं दिन को शहरों में 8-8 घंटे कटौती होती है और ग्रामीण क्षेत्र में 10-12 घंटे कटौती होती है। बरसात होने के बावजूद आज मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ और पूरे जिले में हालात खराब हैं। वहां 400 के वी का जी एस एस है, उसके ओवरलोड होने से ऐसी हालत जिले की बना रखी है। इस बजट में 400 के वी जी एस एस, इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए, 132 के वी जी एस एस जो कि रतनगढ़ तहसील में मात्र एक है, वहां 75 परसेंट क्षेत्र जो कि सिंचाई क्षेत्र है, वहां हमेशा संकट बना रहता है। चार-पांच घंटे से ज्यादा किसान को बिजली नहीं मिलती है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां माननीय विद्युत मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैंने यह बात इनको मीटिंगों में भी बतायी और 132 के वी जी एस एस की मांग भी की। मैंने यह बताया कि कम से कम हमारी कांग्रेस सरकार के टाइम में स्वीकृत 100 एमवीए ट्रांसफार्मर, 50 एमवीए ट्रांसफार्मर और 25 एमवीए ट्रांसफार्मर जो सैंक्शंड हैं, उनको लगाया जाए, ताकि हमारे किसान, गांव और गरीब को बिजली मिल सके, क्योंकि विकास का जो मुख्य आधार है, वह इस समय बिजली है।

इसके अलावा आज 2 लाख 8 हजार घरेलू कनेक्शनों की बात की गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में कहीं भी ढाणियों का कनेक्शन करने के लिए कोई भी रेगुलर व्यवस्था, रेगुलर योजना और इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है, जबकि पूरे प्रदेश के लोग जो लाखों की संख्या में ढाणियों में रहते हैं, वे सरकार की तरफ देख रहे थे कि ढाणियों के कनेक्शन के लिए कोई न कोई योजना शुरू की जायेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ढाणियों के रेगुलर कनेक्शन को चालू किया जाना चाहिए। इसके अलावा गांव और शहर के आबादी क्षेत्र में बसे हुए जो लोग हैं आज उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और कालोनियों में 75 रुपये प्रति गज की दर से पैसा वसूल करने के बाद

(श्री पूसाराम गोदारा)

उनसे लाखों रुपये लेकर बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इससे लोग बर्बाद हो रहे हैं और अपनी जमीन बेचने पर भी उन्होंने कनेक्शन नहीं मिल रहा है। यह किस प्रकार की नीति है? इससे भी छूट प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2024 तक किसानों को कनेक्शन देने की जो व्यवस्था की गयी है, जो बात बतायी गयी है, मैं कहना चाहता हूं कि 31 मार्च, 2023 तक के किसानों के डिमांड नोटिस जमा किये हुए एक-डेढ़ साल हो गये, लेकिन उनको अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। राजस्थान में प्रत्येक ब्लाक में 17-18 की योजना में ही अभी घूम रहे हैं। ट्रांसफार्मर जलने के बाद किसान को 72 घंटे में ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए, लेकिन आज किसान को 20-25 दिन बाद ट्रांसफार्मर मिलता है। यह बताइये कि उसकी खेती किस प्रकार होगी?

अपन सब किसान की बात करते हैं, लेकिन धरती पर उसको दर्द है। जिस कारण से उसको नुकसान हो रहा है, उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। आज किसान सरकार की तरफ देख रहा है। निश्चित तौर से अलग से कृषि बजट पेश किया गया है, जिसमें किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके अलावा किसान को सहकारिता का जो लोन दिया जाता है, यह बात सही है कि आपने नये किसान जो कि सहकारिता से जुड़े हैं, 736 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन वह 'ऊंट के मुंह में जीरा' है। आज एक किसान जो सहकारी समिति का सदस्य बना है, उसको मात्र 05 हजार रुपये का लोन सहकारिता विभाग दे रहा है तो उसके आने-जाने में पैसा खर्च हो जाता है और उससे बीज तक नहीं आता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में ट्रांसफार्मर की जो मांग की गयी है, स्वीकृत है, उसकी समय-सीमा तय की जाये।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने कृषि यार्ड की मांग की है। लेकिन बजट में मात्र एक जगह को छोड़कर किसी तरह का नया कृषि यार्ड बनाने की घोषणा नहीं की गयी। मेरी कृषि मंडी किराये के मकान में चलती है। वहां जमीन उपलब्ध है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि रतनगढ़ में किसानों के लिए कृषि यार्ड स्वीकृत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि आज ड्रेनेज और सीवरेज की जो स्कीम्स चल रही हैं, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, मेरा तहसील राजलदेसर बहुत बड़ा कस्बा है। वहां 25 पाइंटों पर पानी इकट्ठा होता है और करोड़ों रुपये उसको निकालने में खर्च होते हैं। मैंने मांग की थी कि

(श्री पूसाराम गोदारा)

वहां ड्रेनेज स्कीम लागू की जाए और स्वीकृत की जाए, लेकिन बजट में (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी पर्टिकुलर घोषणा नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ड्रेनेज योजना राजलदेसर में लागू की जाए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं में निश्चित तौर पर हमारी पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से शुरू की गयी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) परंतु हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त था, लेकिन इस आरोग्य योजना में किसी भी प्रकार से नहीं बताया गया है कि कितने लाख तक का इलाज फ्री किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री लादु लाल जी। विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हालात और परिस्थितियों को देखते हुए किसानों का कर्जा माफ हमारी सरकार ने किया। आपकी जो केन्द्रीय बैंक हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी होने के बावजूद एक पैसा भी सरकार ने माफ नहीं किया। बात बहुत गम्भीर है। किसानों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया। विराजिए।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजनलाल जी व दिया कुमारी जी का धन्यवाद करता हूं कि सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में सरकार द्वारा जन हित कार्यों का बजट 2024-25 में घोषणा की गयी है। शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत गंगापुर में 04 करोड़ 45 लाख रुपये और हमीरगढ़ में 03 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ब्लाक सहाड़ा, रायपुर और सुआना के 264 ग्राम एवं 231 मजरों के समस्त घरों को 'हर घर जल' से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु कुल 277 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

बनास नदी, बाड़ौत-देवली के बीच पुलिया निर्माण, सहाड़ा हेतु 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। भीलवाड़ा-देवगढ़ वाया पांसल, पीथांस बागोर, बोराणा जगदीश भगवान सड़क चौड़ाईकरण 8 किलोमीटर सहाड़ा हेतु

(श्री लादु लाल पितलिया)

08 करोड़ रुपये स्वीकृत। नाथडियास जो मेरा ही गांव है, उसमें 33 के वी जी एस एस स्वीकृत किया गया है। गंगापुर में सहायक अभियंता खनिज विभाग कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गयी है। हमीरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया। हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग की शुरुआत की जायेगी। माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को फीडर नहर के माध्यम से जयसमंद बांध में लाकर भीलवाड़ा बांधों को भरने के सम्बन्धित कार्य के लिए 7 हजार 100 करोड़ रुपये दिए हैं। 20 हैंडपंप और 10 ट्यूबवैल दिए हैं। 5 करोड़ रुपये की लागत से रोड बनाने की घोषणा की और सभी ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे पशु चिकित्सा उप-केन्द्र निर्माण की घोषणा की है। इसी प्रकार कई और कार्य भी स्वीकृत किये गये हैं, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य को अग्रणी राज्य की श्रेणी में ले जाने हेतु सार्थक प्रयास पहले बजट में साकार होता दिख रहा है, जो एक जन-कल्याणकारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की निम्न जन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नगरपालिका गंगापुर को उच्च श्रेणी में क्रमोन्नत करवाना है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के लरकी रायपुर फीडर एवं नहर, लाम्बा सहाड़ा चन्द्रभागा फीडर, काबरड़ा बांध, देवरिया बांध, रायपिरास बांध, लाखोड़ा तालाब इत्यादि तालाबों एवं नहरों का जीर्णोद्धार हेतु 300 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत करवाना है।

बनास नदी से फूंकिया बांध, सहाड़ा में आंव नहर द्वारा पानी भरना। यह बांध 50 सालों से खाली है। इस बांध को बनास नदी से नहर हेतु राशि स्वीकृत कराने के लिए इस बजट में शामिल करवाना है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर, भीलवाड़ा कार्यालय खोलना है।

कोशीथल, जिला भीलवाड़ा में उप-तहसील खोलनी है। मुकुन्दा, भीलवाड़ा में उप-तहसील खोलनी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर, जिला भीलवाड़ा को उप-जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाना है। उप-स्वास्थ्य केन्द्र, नेगदियाखेड़ा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाना है। उप-स्वास्थ्य केन्द्र, चीरखेड़ा

(श्री लादु लाल पितलिया)

को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाना है। कारोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाना है।

हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा में सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय खोलना है। मुकुन्दा, दरीबा, गुंदली, शिवरत्ती, बाड़ौत, माजावास, मंडी, भोजापुरा, सांगवा में 33 के वी जी एस एस स्वीकृत कराना है।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग स्तर का कार्यालय गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में खोलना है।

गंगापुर व रायपुर में राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय खोलना है।

अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग स्तर का कार्यालय गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में खोलना है।

गंगापुर एवं रायपुर में बस डिपो स्वीकृत कराना है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, आरटीओ खुलाना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक सैकण्ड।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर

सामान्य वाद-विवाद

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): हमारे गंगापुर एवं रायपुर में कृषि भवन खोला जाए। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की हमारी जनता पूरे भारत के सब जिलों एवं तहसीलों में रहती है। सब जगह आइसक्रीम का व्यापार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के खांखला में रीको एरिया है, वहां सरकार कोई भी फैक्ट्री खोले तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। सहाड़ा से जो माइनिंग एरिया है, उधर से पाउडर बनकर मोरबी में जाता है और उधर से ही वापस टाइल बनकर सब जगह आती है।

(श्री लादु लाल पितलिया)

रीको एरिया में हमारे इधर फैक्ट्रियां खुल जाएंगी तो हमारी सहाड़ा विधान सभा की जनता को इसमें रोजगार मिलेगा। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की उधर से डेली 100 बसें यानी सूरत, अहमदाबाद, बम्बई, पुणे, कोल्हापुर इतने सालों से डेली जा रही हैं, जो रूट अलग है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भीलवाड़ा से बागोस्रायपुर होते हुए बसें जाएंगी तो हमारे लोगों को काफी रोजगार मिलेगा और आने-जाने में उनको तकलीफ कम होगी, सुविधा मिलेगी।

गंगापुर में सालों से बंद पड़ी स्पिनफैड मिल को पुन: चालू किया जाए, ताकि हमारी जनता को रोजगार मिले। रायपुर, गंगापुर में बी.एड. और बी.एस.टी.सी. कालेज खोला जाए। खजूरिया श्याम, बाड़्या का माताजी, बरख माताजी और बांसड़ा में देवनारायण भगवान के मन्दिर के विकास के लिए 08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष: वाइंड अप कीजिए।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): इसी के साथ मेरी बात यही विराम करता हूं। मुझको बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय-जय श्री राम। गौ माता की जय। खजूरिया श्याम की जय।

श्री अध्यक्ष: श्री भीम राज भाटी।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का उप-मुख्य मंत्री जी का कि पाली विधान सभा क्षेत्र के लिए इन्होंने और विशेषकर जोराराम जी कुमावत साहब का कि जवाई बांध से जोधपुर जो नहर थी, वह क्षतिग्रस्त हो गयी थी पूरी, तीन साल में 194 किलोमीटर लम्बी उस नहर के जीर्णोद्धार के लिए 2,280 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री भीम राज भाटी (पाली): रोहट और कलाली में जो इण्डस्ट्रियल एरिया बनने वाला है, आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किये। वहां 9 गांवों की हज़ारों बीघा जमीन जा रही है, उसकी डी एल सी रेट पिछले कई सालों से नहीं बढ़ी, उस डी एल सी रेट के लिए, काश्तकारों को मिलने वाला रीको का कम्पन्सेशन है, मेहरबानी करके उसके लिए भी कुछ न कुछ प्रावधान करें।

(श्री भीम राज भाटी)

झाबरसिंह जी का भी मैं आभारी हूं कि पाली नगर परिषद् को इन्होंने नगर निगम में कन्वर्ट किया, मैं हृदय से इनका आभारी हूं। मैं डेयरी मंत्री का भी आभारी हूं कि इन्होंने पाली में मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 95 करोड़ रुपये मंजूर किये। न सिर्फ इतना, पाली में प्राचीन सोमनाथ मन्दिर है, ओरिजनल शिवलिंग पाली में स्थापित है, उस सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी इस राजस्थान की सरकार ने और मुख्य मंत्री ने पैसा मंजूर किया, उसके लिए भी मैं हृदय से आभारी हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है मैंने जसवंत जी को भी कहा था कि मैं इसके बारे में विधान सभा में खुले दिल से मुख्य मंत्री जी का और दिया कुमारी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं।

मैं इस मौके पर मुख्य मंत्री जी को और दिया कुमारी जी को सैल्यूट करना चाहता हूं। इन्होंने महिला होते हुए और रईस परिवार से आते हुए भी तीन घंटे खड़े रहकर बजट भाषण दिया। बजट के लिए एक महिला उप मुख्य मंत्री और रईस परिवार से आते हुए भी, खड़े होकर बजट को प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मुख्य मंत्री जी को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसे वित्त मंत्री को राजस्थान की सरकार में जगह दी। (व्यवधान) ताली बजाओ भले ही, कोई तकलीफ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पाली में प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। हमीर सिंह जी साहब भी इस समस्या से वाकिफ हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये दिए, स्टेट गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये सब्सिडी दी। उस ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने के लिए जो पदाधिकारी है, वह पदाधिकारी किसी नेता विशेष का मर्जीदान है। सी ई टी पी के अध्यक्ष महोदय ने अभी तक सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला किया है और हर महीने किया जा रहा है। मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मिला, उन्होंने कहा कि मैं पेनल्टी लगा देता हूं। 50 लाख रुपये की पैनल्टी भी लगाई, लेकिन पैनल्टी कोई सोल्यूशन नहीं है। वाटर एक्ट में पुलिस केस करने का, प्रोसीक्यूशन का केस करने का भी स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश कर रखा है, किसानों की हज़ारों बीघा जमीन खराब हुई, उस हज़ारों बीघा जमीन का मुआवजा देने के लिए। कई साल हो गए हमीर साहब, उस राजस्थान हाईकोर्ट के आर्डर की कोई पालना नहीं की। किसी भी सरकार ने नहीं की, चाहे कोई भी सरकार आई, कोई भी सरकार

(श्री भीम राज भाटी)

गई। किसानों की हज़ारों बीघा जमीन खराब हुई, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आज दिन तक कोई भी मुआवजा जमीनों का नहीं दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो बहुत कुछ दिया, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता को पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी करके दें क्योंकि पेट्रोल-डीजल की रेट की वजह से महंगाई डायरेक्ट रिलेटेड है। पेट्रोल और डीजल की रेट की कमी होती है तो महंगाई पर सीधा असर पड़ता है, महंगाई आटोमेटिक कम होती है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी को निर्देश दें कि पेट्रोल और डीजल की रेट, आपकी सरकार का वादा है कि पेट्रोल-डीजल की रेट हम घटाएंगे, रेट नहीं घटाई है ...(व्यवधान) दो परसेंट से कुछ नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: बोलने दीजिए।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मैं बोलता हूं, अच्छी बात बोलता हूं तो ताली बजाते हो ...(व्यवधान) मेहरबानी करके और घटाओ।

श्री अध्यक्ष: बोलने दीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): भीम राज जी, आप इधर आ जाइये, और घटा देंगे। इधर आ जाओ। (व्यवधान)

श्री भीम राज भाटी (पाली): मेरे इधर आने की जरूरत नहीं है। 1993 में भी मेरे को इधर आने का बहुत बोला था, बहुत प्रलोभन दिया था, लेकिन मेरे पिताजी कांग्रेस की सफेद टोपी लगाते हैं इसलिए मैं उस वक्त भी उधर नहीं आया। अब मैं क्यों आऊंगा? क्यों धोलों में धूल डालूं? (व्यवधान)

आपकी सरकार ने पांच सालों में 4 लाख नौकरियां दिलाने का वादा किया है। मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, वे नौकरियां भी अभी तक नहीं मिली हैं। आप 4 लाख नौकरियां तो देंगे, लेकिन पांच साल में कितने गर्वनमेंट सर्वेंट रिटायर होंगे, उन रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के बदले में यह 4 लाख हैं या 4 लाख नई नौकरियां देंगे, इसके बारे में भी मेहरबानी करके खुलासा करें। पाली में नगर परिषद् की जगह नगर निगम बनाई, उसके लिए मैं धन्यवाद दे चुका हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिंचाई मंत्री जी से एक निवेदन है। पाली में सबसे ज्यादा बांध हैं। सरदार समंद बांध है, खारड़ा बांध है, हेमावास बांध

(श्री भीम राज भाटी)

है, बानियाबास बांध है, इन नहरों को मेहरबानी करके, मैं पिछली बार जब विधायक था तो चार करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से लाया था, वह चार करोड़ रुपये, मेरे को वापस मौका नहीं मिला ...(व्यवधान)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): नेहड़ा बांध।

श्री भीम राज भाटी (पाली): हां, नेहड़ा बांध है। वह मैंने ही बनाया। मैं नेहड़ा बांध के 9 करोड़ रुपये फेडरेल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ जर्मनी से लाया था। उस नेहड़ा बांध की इन पाली के उद्योगपतियों ने हालत खराब कर दी। हमीर सिंह जी साहब उस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। इनका एरिया भी नेहड़ा बांध के डाउन स्ट्रीम में आता है। उस नेहड़ा बांध में फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी इकट्ठा होता है। प्रदूषित पानी इकट्ठा होने से हज़ारों बीघा जमीन, सैकड़ों किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ। सरदार समंद बांध हेमावास बांध, बानियाबास बांध, नेहड़ा बांध, कालड़ा बांध की नहरों को अगर पक्का कर दिया जाए तो इससे लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। पानी ज्यादा उपलब्ध होगा तो सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में रेवेन्यू की रिकवरी बहुत ज्यादा पेंडिंग है। बजरी माफियाओं के खिलाफ कई केसेज हैं, करोड़ों रुपये की रिकवरी पेंडिंग है, पेनल्टी पेंडिंग है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उस रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को निर्देशित करें कि राजस्थान में इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज की रेवेन्यू पेंडिंग है, पेनल्टी पेंडिंग है, उसको रिकवर करने के लिए ठोस कदम उठाये जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, इस पर बहस नहीं होती।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आदरणीय भीम राज जी ने बोला, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान) यह कौनसा तरीका है?

श्री अध्यक्ष: आपका कौनसा तरीका है? यह आपका तरीका भी नहीं है, बैठिए। (व्यवधान) यह आपका तरीका नहीं है, बैठिए। आप बैठिए, यह मेरा काम है। श्री जब्बर सिंह, बोलिए। आप बोलिए। कोई अंकित नहीं। (व्यवधान)

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान की यशस्वी सरकार ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री ने, उप मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने कल बजट पेश किया। मेरे हिसाब से इस सदन में बोलने को कुछ बचा नहीं है, जब विपक्ष वाले मानने लग गए कि यह बहुत अच्छा बजट है। सदन के बहुत ही सीनियर नेता जिनका हम सब लोग सम्मान करते हैं, उन्होंने भी इस बजट को सराहा है। इनसे पहले रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यहां कहा कि इतनी जल्दी क्या थी इस सरकार को इस तरह का बजट पेश करने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगो ने कभी ऐसा बजट देखा ही नहीं है। (व्यवधान) आपके माननीय सदस्य ने बोला है कि चुनाव में जाने वाले हो, चुनाव की वजह से यह बजट पेश किया है। आपने ऐसा बजट कभी देखा नहीं है। आप इस तरह का बजट चुनाव में जाते समय, लास्ट के समय पांचवें वर्ष में लाते हैं और वह धरातल पर नहीं उतरता है, केवल घोषणा होती है। मैं पिछली बार भी इस सदन में था। आपने थोथी घोषणाएं की हैं, एक भी घोषणा आपकी धरातल पर नहीं उतरी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर वर्ग को राहत दी है, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो, चाहे वृद्धजन हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, मजदूर हो, चाहे खिलाड़ी हो, पशुपालक हो या ऊंटपालक हो, चाहे कर्मचारी हो या पूर्व कर्मचारी हो, हर वर्ग को इस सरकार ने साधने का काम किया है, हर वर्ग को राहत देने का काम इस सरकार ने किया है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का और उनका जो मंत्रिमंडल है, उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।

सबसे बड़ी बात इस सदन में यह मेरा छठा साल है, लेकिन पहली बार मुझे यह गर्व होता है कि मैं हिंदू समाज से हूं। इस सरकार ने प्रदेश के

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

600 मंदिरों के लिए 13 करोड़ रुपये की जो घोषणा की है। केवल साज-सज्जा के लिए 13 करोड़ रुपये की घोषणा राजस्थान प्रदेश के 600 मंदिरों में जो हमारे हिन्दू समाज के त्योहार होते हैं उन त्योहारों पर केवल साज-सज्जा के लिए 13 करोड़ रुपये की घोषणा। की है तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी, हमारे वित्त मंत्रीजी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने पांच सालों में केवल थोथी घोषणाएं की हैं, घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया है और मैंने पांच सालों में इस सदन में बैठकर यह देखा है। जो इन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में नन्दीशाला खोलने की इन्होंने घोषणा की थी पर आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने एक भी नहीं देखी है। दो लाख रुपये तक का किसान का सम्पूर्ण कर्जा इन्होंने माफ करने का वादा किया था पर एक रुपया भी इन्होंने माफ नहीं किया था। 100 से 200 यूनिट बिजली फ्री देने की इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन इनके पास बिजली ही नहीं थी। बिजली ही नहीं थी। कोरोना काल में एक-एक लाख रुपये की खाद्य सामग्री विधायक कोटे से, विधायक फंड से इन्होंने बटवाने की घोषणा की थी पर जो खाद्य सामग्री थी, उसमें विधायकों को दूर रखा गया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के जो परिवार हैं, उनको जा-जाकर खाद्य सामग्री दी थी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की आपने स्कूलें खोली हैं पर आपके पास इंग्लिश के टीचर नहीं थे। आपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें खोली थीं, आज उनकी स्थिति क्या है, यह आप राजस्थान में जाकर देख लीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह बजट बहुत ही अच्छा बजट है इस बजट को प्रदेश की सारी जनता ने, प्रत्येक व्यक्ति ने सराहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, अख़बार की न्यूज़ में चल रहा है पर केवल और केवल मात्र कुछ लोग, मुख्य मंत्रीजी ने हर विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कम दिया है और विपक्ष वालों को ज्यादा दिया है, यह मैं कह रहा हूं इस सदन से, लेकिन ये यह भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने तो एक हैंडपम्प तक नहीं दिया था हम लोगों को उस समय पिछले पांच साल में।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मेरी जो कुछ मांगें हैं। तीन काम मेरे विधान सभा क्षेत्र को आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं। मेरे एक गुर्जर समाज का अन्तरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल है सवाई भोज मन्दिर, उसमें एक प्रेम सागर तालाब है, उसके सौन्दर्यीकरण के लिए आपने जो फंड की घोषणा की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही गुलाबपुरा में एक कालेज की घोषणा आपने की है तो इसके लिए भी मैं और मेरे क्षेत्रवासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे एक जाली चौराहा है, जहां पर पुलिस चौकी की घोषणा की है, उसके लिए भी मैं हृदय की गहराइयों से मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कुछ काम मेरे बच गये हैं, मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा।

इंटरलिंकिंग आफ रिवर द्वारा माही-जवाई-राजसमन्द योजना की डी.पी.आर. बन रही है उसमें भीलवाड़ा के बांधों को भरने की योजना आपने बनाई है। उसमें मेरा यह निवेदन है कि दिवेर जो गांव है राजसमन्द में, दिवेर से खारी नदी पैदा होती है और राजसमन्द से जो माही पानी जायेगा, उसमें मेरा यह निवेदन है कि जो सरप्लस पानी है, उसमें केवल 30-32 किलोमीटर की दूरी है तो दिवेर में उस पानी को डाला जाये जिससे खारी बांध भी भर जायेगा और खारी बांध अगर भरता है तो 200 किलोमीटर के हजारों गांवों के लाखों किसानों को फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

बदनोर में भोजपुरा फीडर का काम पिछले 45 सालों से चल रहा है, लेकिन वह अभी अधूरा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह रहेगा कि भोजपुरा फीडर का भी एक बार आप अपने अधिकारियों को कहकर, उसकी जांच करवाकर उस फीडर को पुन: चालू करवाकर वहां की जनता को राहत दिलवाने की कृपा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा की स्थिति बहुत ही खराब है। मैंने पिछले पांच वर्ष तक ब्राह्मणों की सरेरी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में कंवलियास पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में और दौलतगढ़ पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की मांग की थी, लेकिन उस सरकार ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा अब माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह है कि जब आप

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

रिप्लाई दें तो मेरी इन तीनों पी.एच.सीज. को आप सी.एच.सीज. में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें। बरसडी, कतार और भादसी, वहां पर सब सेंटर है तो उन सब सेंटर्स को आप पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा का उप खण्ड क्षेत्र बदनोर का पूरा एरिया पहाड़ों पर बसा हुआ है, वहां की 21 पंचायतें हैं और पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ पूरा एरिया है, वहां पर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को बहुत दूर ब्यावर या भीलवाड़ा जाना पड़ता है, यह मेरा उप खण्ड क्षेत्र है तो मेरी आपके माध्यम से यह मांग रहेगी कि बदनोर में इसी बजट में आप कालेज खोलने की घोषणा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही मोड़ का निम्बाहेड़ा में एक सिरेमिक जोन की घोषणा पिछली सरकार ने की थी, लेकिन वह आज भी अधूरी पड़ी है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है तो मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह रहेगा कि सिरेमिक जोन की घोषणा जो पिछली सरकार ने की थी, उस सिरेमिक जोन प्लांट को भी आप चालू करवाने की कृपा करेंगे तो वहां के लाखों जो बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार मिल सकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्रीराम।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीना।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हमारे बजट 2024-25 पर वाद-विवाद में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब राजस्थान में माननीय भजन लाल जी की सरकार बनी, शपथ ली तो जनवरी में इस राजस्थान में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मेरे गरीब सहरिया परिवारों को लगभग 13 हजार घरों का तोहफा माननीय प्रधान मंत्रीजी ने दिया और आज इस बजट के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और उप मुख्य मंत्रीजी ने अथाह बजट वर्तमान में मुझे दिया है। 13 हजार आवास जो वर्तमान में बन रहे हैं, जो गरीबों के आवास हैं, जिनमें 02 लाख 40 हजार एक आवास पर खर्च होंगे,

(श्री ललित मीना)

उन गरीब परिवारों को मिलेंगे, उनका वर्तमान में काम चल रहा है। 17 हजार बिजली के कनेक्शन फ्री में हमारे जनमन के अंतर्गत दे रहे हैं। वहीं सहरिया आदिवासी जो बस्तियां हैं उनमें रोड और पानी की व्यवस्था का विशेष प्रावधान प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत किया है।

मैं हमारे राजस्थान के बजट की बात करूं तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर सरकार बनने के बाद इस राजस्थान में गरीब परिवारों को 450 रुपये में एल.पी.जी. गैस सिलेंडर, देने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का काम, आठ हजार रुपये करने का काम किया। गेहूं की एम.एस.पी. में 125 रुपये की बढ़ोतरी करने का काम किया है।

सबसे बड़ा जो वर्षों पुराना ई.आर.सी.पी. का प्रोजेक्ट था, उसको इन्होंने इसमें सैंक्शन करके और उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करने का काम वर्तमान इस बजट में किया है। वहीं पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही थीं, जो युवा ठगा सा महसूस कर रहा था, उसको रोकने का काम वर्तमान में पिछले छह महीने में किया और उसमें 100 से अधिक लोग तो आज वर्तमान में गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे हैं। वहीं पेंशन को बढ़ाने का काम, 1,150 रुपये करने का काम हमारे प्रधान मंत्रीजी ने किया। इस बजट में सिंचाई के क्षेत्र में जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 410 करोड़ रुपये की बजट में घोषणा की, उसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

मेरे यहां कुजाई कराई बमनगवां पर कूनो नदी पर स्प्रिंकलर से जो उन्होंने विशेष नई टेक्नोलोजी से सिंचाई के लिए व्यवस्था की, उसके लिए बहुत-बहुत आभार और ईआर.सी.पी. के माध्यम से, जहां से ई.आर.सी.पी. इस राजस्थान में शुरू हो रही है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ और महलपुर जो बैराज है, वहां पर जो डैम बनेगा, उसके लिए उन्होंने जो वित्तीय स्वीकृति दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उस डैम के माध्यम से सिंचाई भी हो। उसमें से पेयजल की व्यवस्था तो है।

वहीं हमारी बहुत वर्षों पुरानी हमारी वृहद् अकावद सिंचाई परियोजना जो बारां जिले की 2017 में हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी बी.जे.पी. के थे, उनकी पिछली सरकार के समय स्वीकृत हुई थी, उसको बजट देने का काम, जो उस समय 7,355 करोड़ रुपये का 2017 में दिया, उसको इस बजट में जब मुख्य

(श्री ललित मीना)

मंत्रीजी रिप्लाई दें तो इसको भी बजट देने का काम करें। इससे हमारे 637 गांवों को सिंचाई वर्तमान में आने वाले समय में होगी और 1821 गांवों की पेयजल, मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था भी इससे होगी। प्रथम चरण जो हुआ उसमें 2,170 करोड़ रुपये उस समय उसमें दिये गये थे। 2024 तक उसको पूर्ण करने का कार्य करना था, वह पिछली सरकार के बजट नहीं देने के कारण आज वर्तमान में बजट की बाट जोह रहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से और हमारे वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पिछले 2018 के समय में देवरी का जिना तालाब मेरे विधान सभा क्षेत्र का है, जिसका 8 करोड़ रुपये स्वीकृत था, सर्वे हुआ, मुआवजा दे दिया लेकिन आज पिछले पांच साल से वह बजट की बाट जोह रहा तो उसको भी स्वीकृत करवाने का काम करें। इसी तरह मझोला का झका तालाब, उसका चार करोड़ से काम हो गया और उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, लोगों को, किसानों को मुआवजा मिल गया, लेकिन उसका आधा मुआवजा रुका हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी से जब रिप्लाई करें तो इसको विशेष ध्यान में रखते हुए बजट देने का आग्रह मैं करता हूं। वहीं राड़ी, नवेली सिंचाई के लिए बरसों पुरानी मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों की डिमांड है, उसकी घोषणा करने का काम करें।

ऊर्जा के क्षेत्र में, मैं हमारे ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति की इस बजट में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। वर्तमान में 220 के वी जी एस एस 2018 से सैंक्शन थे, 5 साल से नहीं बने, उसका अभी टेंडर करके हमारे ऊर्जा मंत्री ने काम चालू कराया है। 132 के वी जी एस एस जो सैंक्शंड था, वह भी सफर कर रहा था। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक तरह से लाटरी ऊर्जा मंत्री जी की तरफ से लगी है। मैं पूरी सरकार का, हमारे ऊर्जा मंत्रीजी का और पूरे कैबिनेट का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ-साथ 33 केवी जी एस एस की मैंने डिमांड की थी, संतोकड़ा, दुर्जनपुरा, सवांस, उनको भी स्वीकृत कराने का काम करें।

मैं हमारी सरकार और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे रामगढ़ कृष्णाय माता मन्दिर की घोषणा इस बजट में की है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। वहीं सीताबाड़ी, वर्षों से आदिवासी सहरिया कुंभ जो भरता है, बजट में यात्रियों के लिए, उसके विकास के लिए जो घोषणा की है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

(श्री ललित मीना)

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई रोड और पुलियाएं बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं। उनके लिए पिछले पांच साल से बजट नहीं मिला था। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि होड़ापुरा, हरिया नगर, सनवाड़ा, करौरी कलां, सेमली फाटक, कई सारी ऐसी पुलियाएं हैं जो वर्तमान में बजट के अभाव में क्षतिग्रस्त हैं, वे बन नहीं पाई हैं।

इसके साथ-साथ मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां सहरिया आदिवासी परिवारों के कुपोषित होने के कारण उनके लिए एम टी सी वार्ड, पिछली सरकार में 2013 से 2018 तक चलते थे वे पिछले पांच साल में कई जगह बंद कर दिये गये हैं। आपके माध्यम से मैं हमारे मुख्य मंत्री जी से, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी से निवेदन करूंगा कि देवरी में पी एच सी से सी एच सी क्रमोन्नत करें, ताकि हमारे वहां चिकित्सा की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। वहीं शाहबाद में सी एच सी को क्रमोन्नत करते हुए उप जिला चिकित्सालय घोषित करने की कृपा करें।

मेरा पूरा क्षेत्र एम पी बोर्डर से लगा हुआ है। मेरा विधान सभा सत्र का पहला क्वेश्चन भी यही था कि पारदी गिरोह एम पी से आता है, उसके लिए मैंने हमारे मंत्री जी से बटालियन मांगी थी। मेरा निवेदन है कि मेरे यहां पर जो देवरी चौकी है, उसको थाने में क्रमोन्नत करने का काम करें, ताकि मेरा जो बोर्डर इलाका है उसमें अपराध की जो बहुत ज्यादा संख्या है किडनैप करके एम पी में ले जाते हैं, तो वे घटनाएं कम हों।

पिछले पांच साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की जो समस्या थी, वह इस बजट से आज पूर्ण हो गई।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आदिवासी क्षेत्र की बात चल रही है और उप मुख्य मंत्री, मंत्री सारे बातों में लग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप गंभीर हो, इसलिए अच्छा है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मैं मेरे क्षेत्र की डिमांड रख दूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता बड़े शांत भाव से, पूरे मगन होकर सुन रहे हैं। बाकी और कोई साथी होता तो न इनको सुनने देता और न इनकी बात सुनता, इसलिए आज ये बहुत खुश हैं।

श्री अध्यक्ष: सबको बधाई। चलिये, पूरा करिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आज डोटासरा जी नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सुन रहा हूं, सारी कसर निकाल दूंगा 16 तारीख को, चिंता मत करो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): यह देखकर अच्छा लगा कि आज आपको कोई चैलेंज नहीं है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): उस कृषि उपज मंडी को भी बजट देने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: इस तरह से आप रोज चुपचाप सुनते रहें तो आपको धन्यवाद भी देता रहूंगा।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब उप मुख्य मंत्री जी इसका रिप्लाई करें तो मेरे यहां समरानियां में कृषि उपज मंडी है, जिसको 2016 में खोला था, उस समय 240 करोड़ रुपये देना था पर आज तक वह बजट का इंतजार कर रही है इसलिए इसको भी बजट में लेकर स्वीकृत कराने का काम करें।

मेरा विधान सभा क्षेत्र बारां जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। किशनगंज मुख्यालय पर स्टेडियम के लिये जो बजट दिया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ई आर सी पी जो पूरे राजस्थान की, हमारी पार्टी की और हमारे मुख्य मंत्री जी की बहुत बड़ी संकल्पना थी, उसमें मेरे विधान सभा में डैम बन रहा है। बजट में नाहरगढ़ में सर्वे के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की है। ई आर सी पी में भी मेरी विधान सभा क्षेत्र को सिंचाई के लिए जोड़ा जाये। वहीं अकावद सिंचाई परियोजना को बजट देवें, ताकि उससे पेयजल के लिए 1827 गांवों को इस बजट में पैसा देने के बाद, दूसरे चरण में उसको पैसा दें। उससे पूरे बारां जिले को और मेरे विधान सभा क्षेत्र को पानी मिल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी को और मंत्रिमंडल को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैं दो मिनट में पूरा करूंगा। वैसे भी अध्यक्ष जी, लास्ट में मैं ही हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी

(श्री ललित मीना)

ने इस बजट में राजस्थान को बहुत बड़ी उपलब्धि दी है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए बहुत शानदार घोषणाएं की हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, गरीब तबके के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। आने वाले समय में यह बजट आमजन को राहत देने वाला होगा। चाहे मेट्रो ले लें, चाहे पथ परिवहन निगम ले लें, चाहे हम इन्फ्रास्ट्रक्चर को ले लें, इसमें मुख्य मंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। हमारे उप मुख्य मंत्री जी ने इंडस्ट्रीज को सुदृढ़ करने के लिए इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए प्रावधान किया है।

प्रतिपक्ष के सभी लोग यहां बैठे हैं। उनके यहां भी मुख्य मंत्री जी ने हर विधान सभा में एक मॉडल सी एच सी बनाने के लिए घोषणा की है। उनको भी प्रत्यक्ष रूप से इस बजट में दिया है। आप भी इस बजट में जो आपको दिया है उसके लिए तो हां भरें, ताकि पूरे राजस्थान को लगे कि आप भी आमजन के लिए यहां पर बात रख रहे हैं।

पिछले पांच साल में पेपर लीक के मामले में युवा ठगा सा महसूस कर रहा था। उसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने इतनी बड़ी ...(व्यवधान) आपके वरिष्ठ सदस्य खुद कह रहे थे इस चीज के लिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भी करें। हमारे मुख्य मंत्री जी ने आते ही हमारी सरकार का जो मेनिफेस्टो था, उस पर काम करने का काम किया, इस राजस्थान की आम जनता को राहत देने का काम किया।

केन्द्र सरकार, डबल इंजन की सरकार के लिए आप बार-बार कहते हैं, तो मैं यह कहूं कि किसान की आय को दुगुना करने के लिए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो कह रहे थे, उसको बढ़ाने का काम किया। जो 8 हजार रुपये की घोषणा हमारे मेनिफेस्टो में थी, उसको भी रखकर के किसान का भी ध्यान रखा, युवा का भी ध्यान रखा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 8 हजार कहां, दो हजार की घोषणा की और हजार ही दिया है। हजार भी 500-500 की 2 किस्तों में दोगे।

श्री अध्यक्ष: बोलने दो।

श्री ललित मीना (किशनगंज): पूर्व में बारां जिले से जो आपके मंत्री आते थे, उन मंत्रियों का क्या हाल है? आप खुद देखते हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट में बारां जिले को जो मिला और राजस्थान को जो दिया है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर तारीफ करें, वह कम है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो ऊर्जा और अन्य सब क्षेत्रों में उपलब्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबके माध्यम से हमारे मुख्य मंत्री जी को और हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो सरकार बनते ही 13 हजार घरों की बहुत बड़ी सौगात प्रधान मंत्री जी ने दी। मेरे आदिवासी सहरिया परिवारों के लिए केन्द्र सरकार से डूंगरपुर, बांसवाड़ा में और किशनगंज शाहबाद के लिए तो जो खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवार थे, उनके लिए भी वर्तमान में पोर्टल चालू कर दिया है। इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे विधान सभा क्षेत्र को हुई है।

हमारे जो वादे थे, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में किया है। सरकार आने के पहले जो संकल्प लिया था, उस समय भी हमने जो वादे किये थे, उनको पूरा करने के लिए इस बजट में सारी चीजें हमने रखी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19:00 बजे शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2024 के 11.00 तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

कपासन के विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की योजना

24. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की कोई नीति व मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाशमा, आकोला, पहुंना, सिंहपुर, सुरपुर एवं भादसोड़ा में कृषि संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केवल कृषि संकाय खोलने की कोई नीति एवं मानदण्ड निर्धारित नहीं है, बल्कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय के रूप में मानदण्ड पूर्ण होने पर विज्ञान, वाणिज्य, कला अथवा कृषि विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान है।

विभाग के पत्र दिनांक 15.01.2020 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.10.2020 के द्वारा अतिरिक्त संकाय के लिये जारी मानदण्ड एवं निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट-क और ख पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाशमा, आकोला, सिंहपुर एवं भादसोड़ा के प्राप्त प्रस्तावानुसार इन विद्यालयों में तथा शेष दो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहुंना एवं सुरपुर में भी नवीन अतिरिक्त संकाय खोले जाने के निर्धारित विभागीय मानदण्ड पूर्ण नहीं किये जाने के कारण इनमें कृषि संकाय नहीं खोले जा सके।

विभाग को निदेशालय से पुन: प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानदण्डानुसार/ आवश्यकता के अनुपातानुसार आकलन किया जाकर तथा वित्तीय प्रावधान होने पर ही उक्त विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पाली के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

38. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में संस्कृत शिक्षा के कितने उच्च प्राथमिक प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कक्षावार व विद्यालयवार नामांकन का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? विद्यालयवार व श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में संस्कृत शिक्षा के 21 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 03 प्रवेशिका एवं 04 राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों की विद्यालयवार, कक्षावार नामांकन सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त विद्यालयों में प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापक लेवल वन और लेवल टू के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार, विषयवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। प्राध्यापक (विभिन्न विषय) के 52 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 25.01.2024 को विज्ञापन जारी कर दिनांक 17-21 नवम्बर, 2024 के मध्य परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) के 885 पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनमें से 538 पदों हेतु दिनांक 12 से 16 फरवरी, 2023 तक परीक्षा आयोजित कर अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से अभिस्तावना प्राप्त होने उपरान्त नियुक्ति दी जानी है तथा 347 पदों हेतु दिनांक 31.01.2024 को

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञापन जारी कर दिनांक 28-31 दिसम्बर, 2024 के मध्य परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है।

अध्यापक लेवल-1 के 97 पद एवं अध्यापक लेवल-2 के 1,747 पदों, कुल 1,844 पदों को भरने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। नियमों में संशोधन के उपरान्त अर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित तारांकित

वैज्ञानिक सहायकों के पदों पर भर्ती

22. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2022 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान द्वारा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब? विज्ञप्ति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पदों की परीक्षा अब तक आयोजित नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त परीक्षा कब तक आयोजित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2022 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविधालय, जोधपुर द्वारा भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति दिनांक 19.09.2022 को जारी की गई है। प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बजट के अभाव में उक्त पदों की परीक्षा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आयोजित नहीं की जा सकी थी। वर्तमान में बजट आबंटित कर दिया गया है।

(3) उक्त भर्ती प्रक्रिया का आयोजन अगस्त, 2024 तक करवा दिया जावेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां में फायरिंग की घटनाएं

23. श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां शहर में विगत पांच वर्षों में फायरिंग की कितनी घटनाएं हुईं? उक्त मामलों में कितने अपराधी गिरफ्तार हुए व कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम बैरवा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में फायरिंग के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकार्ड है? यदि हां, तो ऐसे अपराधियों को स्थायी रूप से जेल में रखने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक बारां शहर में फायरिंग के 11 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरणों में कोई आरोपी गिरफ्तार करना शेष नहीं है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक बारां शहर में फायरिंग के मामलों में चिन्हित/गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकार्ड का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

ऐसे आदतन अपराधियों को स्थायी रूप से जेल में रखने सम्बन्धी कोई योजना/आदेश/परिपत्र नहीं है, परन्तु अपराधी जमानत पर आसानी से नहीं छूटने के संबंध में जारी विभिन्न परिपत्र/आदेश की छाया प्रति परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

आदतन अपराधियों को जेल में रखने के लिए पुलिस द्वारा निम्न प्रयास किये जाते हैं :-

1. आदतन अपराधियों पर अंकुश रखने के लिए एच.एस. खोली जाकर निगरानी की जाती है।
2. समय-समय पर इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही कर अंकुश लगाया जाता है।
3. आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रकरणों को केस आफिसर स्कीम में लिया जाकर उनकी जमानत नहीं हो, इसके लिए प्रयास किये जाते हैं।
4. राजपासा एक्ट के तहत अपराधियों के खिलाफ इस्तगासा पेश किया जाता है, ताकि अपराधी अधिक समय तक जेल में ही रहे।
5. गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।
6. इनके विरुद्ध 110 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जाती है।
7. जो आदतन अपराधी जेल में चल रहे हैं उनकी जमानत नहीं हो

(गृह मंत्री)

सके, इसके लिए सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालय में उपस्थित रहकर प्रकरण में पैरवी की जाती है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परबतसर कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों की मरम्मत

24. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर की कृषि उपज मण्डी में विगत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र परबतसर के कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं करवाया गया है।

(2) विभागीय आदेश दिनांक 31.12.2014 के अनुसार सम्पर्क सड़कों की मरम्मत व रखरखाव का कार्य अनुमत नहीं है। परिपत्र की छाया प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी में आवंटित दुकानें

25. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कृषि उपज मण्डी परिसर में व्यापारियों को व्यापार करने हेतु दुकानों के आबंटन की क्या प्रक्रिया है और कितने समय के लिए आबंटित की जाती हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या व्यापारी द्वारा मण्डी में व्यापार बन्द करने के उपरांत आबंटित दुकान को निरस्त करने के प्रावधान निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्या सरकार नियमों में प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान की कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगणों में 'अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005' के तहत दुकानों/भूखण्डों का आबंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति पर निर्धारित प्रावधान अनुसार किया जाता है। अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 एवं संशोधित प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य के मण्डी प्रांगणों में 'अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005' के तहत 99 वर्षीय लीज पद्धति पर आबंटित दुकानों के संबंध में व्यापारी द्वारा मण्डी में व्यापार बन्द करने के उपरान्त आबंटित दुकान को निरस्त करने का प्रावधान निर्धारित नहीं है।

नियमों में प्रावधान किया जाना विचाराधीन नहीं है क्योंकि वर्तमान में व्यापारी द्वारा मण्डी में अपना व्यापार बन्द करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लीज की शर्तों के बिन्दु संख्या 11 में प्रावधान है कि "द्वितीय पक्ष यदि द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में आबंटित भूखण्ड पर निर्मित दुकान/दुकान मय गोदाम/गोदाम आदि पर विज्ञप्त कृषि जिन्सों का व्यवसाय करने हेतु उपयोग नहीं करता है और मण्डी समिति द्वारा जारी अनुज्ञापत्र मण्डी समिति को समर्पित कर देता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वो उसके द्वारा अनुज्ञापत्र समर्पित करने के तीन माह के अन्दर ऐसे व्यक्ति/फर्म को भूखण्ड हस्तान्तरित कर सकेगा जो कि मण्डी समिति का अनुज्ञापत्रधारी हो तथा विज्ञप्त कृषि जिन्स का व्यवसाय करता हो, परन्तु ऐसा हस्तान्तरण प्रथम पक्ष की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। ऐसे परिवर्तन के समय देय वार्षिक लीज राशि की दस गुना राशि के समतुल्य राशि परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी। ऐसा हस्तान्तरण पट्टे की शेष अवधि के लिये ही विधि-मान्य होगा तथा ऐसे हस्तान्तरिती पर इस पट्टा विलेख की सभी शर्तें लागू होंगी।" राज्य सरकार से अनुमोदित लीज की शर्तों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

शेरगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

26. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला जोधपुर में विगत पांच वर्षों में कितने नये

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा जोधपुर जिले में विगत पांच वर्षो में कोई नये आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(2) उक्त जिले में पिछले पांच वर्षों में विभागीय मद से कोई भी आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं करवाया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जोधपुर जिले के 34 आंगनबाड़ी केन्द्रों के नरेगा कन्वर्जेस से भवन निर्माण करवाने के लिये विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की गई है तथा वर्तमान में जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ करवाया जाना प्रकियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अधीन चार बाल विकास परियोजनाएं क्रमशः शेरगढ़, बालेसर, सेखाला एवं चामू संचालित हैं जिनमें संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स.	परियोजना का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र
1	शेरगढ़	154
2	बालेसर	124
3	सेखाला	76
4	चामू	92
	कुल योग	**446**

संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु सरकार द्वारा परीक्षण करवाया जावेगा। परीक्षण के दौरान गुणावगुण एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में सड़कों का नवीनीकरण

27. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक कितनी सड़कों का नवीनीकरण किया गया? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर, खेरवाड़ा व उदयपुर ग्रामीण सहित वल्लभनगर क्षेत्र से गुजरने वाले मेगा हाईवे 32ए ऋषभदेव से वाया सराड़ा, केजड़, डींगरी, जयसमंद, जगत होकर झामर कोटड़ा तक बनाने के लिए केन्द्र सरकार से बजट आबंटित होने के उपरान्त भी नहीं बना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त हाईवे अभी तक नहीं बनने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त हाईवे को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत वर्ष 2018 से 2023 तक विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विभिन्न योजनाओं के तहत नवीनीकरण की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) एस.एच.-32ए ऋषभदेव, सराड़ा, केजड, डीगरी, जयसमन्द, जगत सड़क की कुल लम्बाई 102 किमी. है। इस सड़क का विभिन्न योजनाओं में चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इस हाईवे के 25 किमी. (22/0 से 47/0) में केरिजवे 3 से 5.50 मीटर चौड़ाई में है, जिसे 2 लेन चौड़ाई में केन्द्र सरकार की सी आर आई एफ योजना में चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2021-22 में 25 किमी. लम्बाई हेतु राशि रु. 24.88 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर संवेदक को दिनांक 14.01.2022 को कार्यादेश जारी किया गया,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

परन्तु संवेदक द्वारा अनुपातिक प्रगति नहीं बनाए जाने के कारण अनुबंधों की शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 16.05.2023 को कार्य को विथड्रा कर पुन: निविदा आमंत्रित की गई। वर्तमान में द्वितीय संवेदक द्वारा दिनांक 21.09.2023 को कार्य प्रारम्भ कर 25.00 किमी. में से 10.00 किमी. लम्बाई में डामरीकरण की प्रथम परत व 750 मीटर लम्बाई में सी.सी. कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में शेष कार्य प्रगतिरत है जिसे दिनांक 31.10.2024 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

इस सड़क के शेष लम्बाई में से 72 किमी. राज्य मद योजनाओं में स्वीकृति जारी होकर कार्य प्रगतिरत है एवं 5 किमी. लम्बाई वाइल्ड लाइफ में होने के कारण स्वीकृत नहीं है।

(3) प्रथम संवेदक के असफल होने से अनुबंधों की शर्तों के अनुसार कार्य को विथड्रा कर पुन: टेण्डर प्रक्रिया करने से देरी हुई। दोषी संवदेक पर अनुबंधों की शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई।

पुन: निविदा उपरान्त नये संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं दिनांक 31.10.2024 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मातृकुण्डिया (कपासन) में पुलिया का निर्माण

28. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में बनास नदी में अत्यधिक बहाव से मातृकुण्डिया-गंगापुर मार्ग बन्द हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार मातृकुण्डिया में पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। कपासन विधान सभा, क्षेत्र में सम्पर्क सड़क डिण्डोली-मातृकुण्डिया-आरनी-गंगापुर (वीआर-12) 15.00 किमी. लम्बाई की सा.नि.वि. की सड़क है। वर्तमान में मातृकुण्डिया गंगापुर मार्ग पर बनास नदी के ऊपर 300.00 मीटर लम्बाई में फ्लश कॉजवे बना हुआ है।

वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने पर कॉजवे की ऊंचाई कम एवं

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मातृकुण्डिया बांध के डाउनस्ट्रीम में होने के कारण उसके ऊपर 6 से 7 फीट पानी का बहाव रहता है जिसकी वजह से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है।

वर्तमान में उक्त पुलिया निर्माण कार्य हेतु विभाग की किसी भी योजना में स्वीकृति प्राप्त नहीं है। उक्त कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के ऊपर निर्भर करती है।

प्रदेश में गठित जिला बाल कल्याण समितियों में दर्ज प्रकरण

29. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या महिला एवं बाल अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जिला स्तर पर गठित जिला बाल कल्याण समिति में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक बच्चों के कितने प्रकरण पेश हुए तथा कितने प्रकरणों में समिति द्वारा कार्यवाही की गई? वर्षवार व जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाल कल्याण समिति में बच्चों से संबंधित कितने प्रकरण किस-किस प्रकृति के प्रस्तुत किये गये या समिति ने स्वयं के प्रसंज्ञान से दर्ज किये हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में बाल कल्याण समिति, जयपुर में कितने बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त कराकर देखभाल एवं संरक्षण के लिए भेजा गया? उक्त में से कितने बच्चों को बंधुआ श्रमिक मानते हुए बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण-पत्र जारी कर माता-पिता को सुपुर्द किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जिला स्तर पर गठित जिला बाल कल्याण समिति में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में बच्चों के 29,883 (इनमें से 144 समिति ने स्वयं के प्रसंज्ञान से दर्ज किये) प्रकरण पेश हुए तथा 29,254 प्रकरणों में समिति द्वारा कार्यवाही की गई। वर्षवार व जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न हैं।

(2) बाल कल्याण समिति में देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक-बालिकाओं यथा- बेघर, बाल श्रमिक, स्ट्रीट चाइल्ड, उपेक्षित, शोषित, असक्षम, असक्षम माता-पिता की संतान, गुमशुदा, अनाथ, परित्यक्त,

(महिला एवं बाल अधिकारिता मंत्री)

पोक्सो पीड़ित, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं तस्करी में लिप्त, बाल विवाह, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित आदि से संबंधित बालक-बालिकाओं के 29,883 प्रकरण प्रस्तुत किये गये। उक्त में से समिति ने स्वयं के प्रसंज्ञान से 144 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) बाल कल्याण समिति जयपुर में इस दौरान 1205 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त करा कर देखभाल एवं संरक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया। उक्त में से 385 बच्चों को बंधुआ श्रमिक मानते हुए बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करवाकर माता-पिता को सुपुर्द किया गया। अवमुक्ति प्रमाण पत्र का वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान

30. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कृषि को बढ़ावा देने की योजनाओं के माध्यम से विगत तीन वर्षों में कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कौन-कौनसे कृषि यंत्रों पर कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया जा रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में कृषि को बढ़ावा देने हेतु कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से विगत तीन वर्षो में कुल 6,32,309 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। जिला नागौर में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा योजनाओं के माध्यम से विगत तीन वर्षों में लाभान्वित किये गये कृषकों का विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) कृषि विभाग द्वारा केन्द्र प्रवर्तित सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों के क्रय पर कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिसका कृषक श्रेणीवार तथा यंत्रवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जमवारामगढ़ में कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन

31. श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कृषि पर्यवेक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा नवीन ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पद सृजित करने की सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कृषि पर्यवेक्षकों के 39 पद स्वीकृत हैं।

क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर नवीन पदों एवं मुख्यालयों का सृजन किया जाता है। नवीन ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पद सृजन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु पोर्टल प्रारम्भ करने की योजना

32. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल किन कारणों से व कब से बंद है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु उक्त पोर्टल को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ने हेतु पोर्टल की अंतिम तिथि 07.03.2019 ही निर्धारित की गयी थी, तदुपरान्त भारत सरकार द्वारा पोर्टल बन्द कर दिया गया।

(2) उक्त योजना से वंचित पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त पोर्टल को पुन: प्रारम्भ कराने हेतु राज्य सरकार स्तर से निम्न प्रयास किये गये:-

भारत सरकार स्तर से आवास प्लस में अपलोड कराने के क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 06.03.2019, 08.03.2019 एवं निर्धारित अवधि तक

(ग्रामीण विकास मंत्री)

आवास प्लस पर अपलोड होने से शेष रहे परिवारों की सूची विभागीय पत्र दिनांक 19.03.2019 द्वारा विशेष वाहक के साथ प्रेषित की गई। इसी क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 19.9.2019, 13.05.2020 द्वारा आग्रह किया गया।

उक्त संबंध में माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान के अ.शा. पत्र दिनांक 29.09.2020 द्वारा आवास प्लस एप पर अपलोड होने से शेष वंचित पात्र परिवारों को योजना की वरीयता सूची में शामिल कराने हेतु माननीय केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह किया गया। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से विभागीय पत्र दिनांक 09.07.2021, 22.07.2021, 03.09.2021, 01.12.2021, 06.01.2022 एवं 25.01.2022 द्वारा आग्रह किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.03.2022 द्वारा किसी भी राज्य के प्रस्ताव पर विचार नहीं किये जाने बाबत अवगत कराया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी भी राज्य के प्रस्ताव पर विचार नहीं किये जाने के क्रम में पुनः विचार हेतु माननीय मंत्री महोदय के अ.शा. पत्र दिनांक 15.04.2022, 22.01.2023 एवं 06.03.2024 एवं विभागीय पत्र दिनांक 18.05.2023, 12.12.2023, 31.01.2024 व 13.02.2024 द्वारा भारत सरकार से पुन: आग्रह किया गया है। पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

लखपति दीदी योजना के तहत कार्य

33. श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत दिनांक 08 फरवरी, 2024 से माह मई, 2024 तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भारत सरकार के द्वारा राजस्थान प्रदेश 11.27 लाख महिलाओं को चरणबद्ध रूप से 3 वर्ष में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। अब तक राजस्थान प्रदेश में 2.81 लाख लखपति दीदी (2021-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

2022 के NRLM इनकम सर्वे अनुसार) बनाई जा चुकी है जिनकी वर्तमान में संख्या बढ़ कर 4.85 लाख पहुंच गई है।

193 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 13,696 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) को प्रशिक्षित किया गया है तथा विभिन्न जिलों में नये 212 लखपति मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है। इस तरह कुल 405 मास्टर ट्रेनर कार्य कर रहे हैं। जिलेवार मास्टर ट्रेनर की संख्या की सूची परिशिष्ट-अ पर सलग्न है।

इन प्रशिक्षित CRP द्वारा चिन्हित 11.27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जायेगा तथा 11.27 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 14.04 लाख संभावित लखपति दीदी का चिन्हीकरण किया। जिलेवार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या की सूची परिशिष्ट-ब पर सलग्न है।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल आजीविका रजिस्टर का पायलट हेतु प्रदेश के पांच ब्लाक का चिन्हीकरण किया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-स पर सलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सरदारशहर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

34. श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में संचालित उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप जिला चिकित्सालय में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का केन्द्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में कौन-कौनसे संवर्ग के पद कहां-कहां, कब-कब से रिक्त हैं? केन्द्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में संचालित चिकित्सा संस्थानों में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विशेषज्ञ/चिकित्सक एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ, ब पर संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या (1) के अनुसार।

(3) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी ए सी पी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के 1,220 एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 209 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग आफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,067 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जाएगा तथा सहायक रेडियोग्राफर के 863, लैब टेक्नीशियन के 1,888 पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को आगामी वित्तीय वर्षों में की जाने वाले भर्तियों से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

डूंगरपुर के चिकित्सालयों में सफाईकर्मियों की भर्ती

35. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर के जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने-कितने पद? चिकित्सालयवार रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गणेश घोगरा)

(3) क्या सरकार राजकीय चिकित्सालयों में स्थाई सफाईकर्मियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला डूंगरपुर में संचालित चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ/चिकित्सक एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी ए सी पी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के 1,220 एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 209 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भिजवाई जा चुकी है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा एवं विभाग में फार्मासिस्ट के 3,067 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847, के पदों पर नियमित भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जाएगा तथा सहायक रेडियोग्राफर के 863, लैब टेक्नीशियन के 1,888 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को आगामी वित्तीय वर्षों में की जाने वाले भर्तियों से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जायेगा।

(3) राजकीय चिकित्सालयों में सफाई कर्मचारी के सृजित किये जाने वाले नवीन पदों के संबंध में सफाई कर्मचारी का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब बेसिस पर RTTP ACT/RULES के प्रावधानों के अनुसार करवाया जाता है। अत: राजकीय चिकित्सालयों में सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चिरंजीवी चिकित्सा बीमा योजना

36. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना लागू की गई थी? क्या उक्त बीमा योजना से 25 लाख रुपये तक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती थी?

(2) क्या वर्तमान में चिरंजीवी चिकित्सा बीमा योजना को बन्द कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त योजना हेतु कितने निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदेश में दिनांक 01 मई, 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी। वर्तमान में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित की जा रही है।

उक्त संचालित बीमा योजना में 25 लाख रु. तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाता था। यह सुविधा वर्तमान में संचालित योजना में भी निरंतर जारी है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में संचालित योजना में 882 निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं।

उदयपुर ग्रामीण में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

37. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर कितने-कितने पद, किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर 24 घंटे सेवा प्रारम्भ कर ग्रामीणों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवाली
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पई
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बछार
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलसीगढ़
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चनावदा
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारापाल
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांसदा
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सबीनाखेडा
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडी,
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धार

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक व अराजपत्रित सवंर्ग के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ, ब पर संलग्न है।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपातकालीन परिस्थिति में 24x7 सेवा देने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

निवाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

38. श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई को उप-जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कस्बा निवाई पंचायत समिति, निवाई, जिला टोंक में वर्तमान में 75 शय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। स्वीकृत शय्याओं का वर्ष

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

2023 में शय्याओं की उपयोगिता दर (बीओआर) 41.38 प्रतिशत ही रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

धोद के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

39. श्री गोरधन (धोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धोद में विद्यालय क्रमोन्नत करने व अन्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र धोद के विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत कितने छात्रों को दूध व कितना पोषाहार किस फर्म के द्वारा वितरित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र धोद में प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत सत्र 2019-20 से 2023-24 तक 04 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षान्तर्गत विगत 05 वर्षों में 29 रा.उ.प्रा.वि./रा.मा.वि. को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है तथा 08 रा.उ.मा.वि. में अतिरिक्त संकाय स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ख व ख1 पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त 02 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में एवं 04 रा.उ.प्रा.वि. को उ.मा.वि. में क्रमोन्नत किये जाने तथा 03 रा.उ.मा.वि. में अतिरिक्त संकाय खोले जाने हेतु निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों (संलग्न परिशिष्ट-ग व ग1) का निर्धारित मानदण्डानुसार/आवश्यकता के अनुपातानुसार आकलन किया जाकर वित्तीय प्रावधानान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत अध्यापक भर्ती, 2022 अन्तर्गत अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 के कुल 48,000 पदों में से चयनित 42,042 अभ्यर्थियों को जिला आबंटन कर दिया गया है। शेष पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती से पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जा सकेगा।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षान्तर्गत विद्यालयों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र धोद के राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में पोषाहार वितरण का कार्य क्रय-विक्रय सहकारी समिति सीकर, मैसर्स राधा गुप्ता जनरल सप्लायर्स एवं ट्रांसपोर्टर, कोटा एवं श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, श्यामपुरा, धोद द्वारा किया गया है। वितरित पोषाहार एवं लाभान्वित विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनान्तर्गत उक्त क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में दूध की आपूर्ति अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड, अजमेर एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गोविन्दगढ़ द्वारा की गई है। वितरित दूध एवं लाभान्वित विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट-घ1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आसीन्द में संचालित विद्यालयों में रिक्त पद

40. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हुरड़ा व बदनोर में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त पदों में से कितने पद रिक्त व प्रतिनियुक्ति से भरे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में संचालित विद्यालयों में स्वीकृत व रिक्त पदों का ब्लाकवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभागान्तर्गत मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हुरड़ा व बदनोर में स्वीकृत, कार्यरत एवं प्रतिनियुक्ति/कार्य व्यवस्थार्थ पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में प्रारम्भिक शिक्षा विभागान्तर्गत 278 राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा 114 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल 392 राजकीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत 119 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विधान सभावार ब्लाकवार एवं विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शिव में संविदाकर्मियों को भुगतान

41. श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में विभाग में विभिन्न श्रेणी के संविदा कार्मिकों को किस फर्म के माध्यम से संविदा पर रखा गया? उक्त फर्म को कितना भुगतान किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में पंचायती राज विभाग के तहत कुल 461 पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में 161 पद रिक्त हैं।

पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शिव में विगत तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणी के संविदा/निविदा फर्म के माध्यम से संविदा पर रखे जाने एवं किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पशु मित्रों के चयन की प्रक्रिया

42. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पशु मित्र योजनान्तर्गत प्रत्येक संभाग में कितने पशुधन सहायक व पशु चिकित्सकों को नियोजित किया गया तथा उक्त का मानदेय क्या है?

(2) उक्त पशु मित्रों का चयन का आधार व प्रक्रिया क्या है? उक्त के कार्यों के पर्यवेक्षण की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पशु मित्र योजनान्तर्गत नियोजित पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशुधन सहायकों का संभागवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**संभाग का नाम**	**पशु चिकित्सा अधिकारी**	**पशुधन सहायक**
1.	अजमेर	4	697
2.	भरतपुर	2	324
3.	बीकानेर	1	387
4.	जयपुर	8	1370
5.	जोधपुर	3	509
6.	कोटा	1	323
7.	उदयपुर	4	597

पशु मित्रों को किसी भी प्रकार का मासिक मानदेय देय नहीं है। इन्हें इनके कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पशु मित्रों के चयन का आधार व प्रक्रिया तथा कार्यों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डीडवाना में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना

43. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री यूनुस खान)

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में किस-किस श्रेणी के कहां-कहां पर पशु चिकित्सालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से कई चिकित्सालय किराये के भवनों में संचालित हैं?

(3) क्या सरकार भवनविहीन व किराये के भवनों में संचालित पशु चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु विशेष बजटीय प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित 57 पशु चिकित्सा संस्थाओं का श्रेणीवार एवं स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की कोई भी पशु चिकित्सा संस्था किराये के भवन में संचालित नहीं है।

(3) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाये जाते हैं।

(4) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली/स्वीकृत की जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाजूवाला के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर भर्ती

44. डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कहां-कहां व कितने पशु चिकित्सालय एवं उप-केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्मिक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डॉ. विश्वनाथ मेघवाल)

(2) उक्त चिकित्सालयों में भवनों की क्या स्थिति है? क्या सरकार भवन विहीन चिकित्सालयों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त चिकित्सालयों में कितने रिक्त पद हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कुल 74 पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं, जिनमें स्वीकृत एवं कार्यरत कार्मिकों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों के भवनों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाये जाते हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)